राजस्थान विधान सभा

ग्यारहवीं बैठक, बुधवार, दिनांक १४ मार्च, सन् १९५६ ई०

(प्रातःकालीन बैठक)

विधान सभा की बैठक सभा भवन, जयपुर, में प्रातः ८ बज कर
३५ मिनट पर प्रारम्भ हुई।

(श्री नरोत्तमलाल जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

प्रश्न संख्या ७५

एस. आई. पुलिस ट्रेनिंग हेतु चुनाव का आधार

श्री चांदमल मेहता—क्या गृह मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) एस. आई. पुलिस की ट्रेनिंग के लिये चालू वर्ष में कुल कितने कर्मचारियों का सिलेक्शन किया गया ?

(२) उक्त कर्मचारियों के नाम योग्यता व लेन्थ आफ सर्विस कितनी है और उक्त कर्मचारी किस किस स्थान पर काम करते थे ?

(३) उक्त ट्रेनिंग के लिये कुल कितने आवेदन पत्र आये ?

(४) जिन व्यक्तियों के आवेदन पत्र अस्वीकृत किये गये उनके नाम, योग्यता व लेन्थ ऑफ सर्विस कितनी कितनी है ?

(५) उक्त सम्मेलन किस आधार पर किसके द्वारा किया गया है ?

श्री रामकिशोर व्यास—(१) सब इन्सपेक्टर पुलिस की ट्रेनिंग के लिये चालू वर्ष में कुल ८ विभागीय कर्मचारियों का सिलेक्शन हुआ।

उनके नाम और योग्यता इस प्रकार है।

Page No.2

[श्री रामकिशोर व्यास]

नाम	नं० और ओहदा	जिला	योग्यता	अर्सा सर्विस
सूरजराम	एल. सी. ७७	बीकानेर	मैट्रिक	लगभग दो वर्ष
मोती खां	एच. सी. १	चूरू	मिडिल	१४ साल
लक्ष्मणसिंह	एच. सी. २०४	उदयपुर	मैट्रिक	लगभग दो साल
रामनारायण	एच. सी. ४	झालावाड़	,,	साढ़े तीन साल
मोतीसिंह	एच. सी ७६	जोधपुर	लॉ ग्रेजुएट	३ साल
गोविन्दसिंह	एच. सी. १५८०	जयपुर	मैट्रिक	४ साल
निरन्दरचन्द जौहरी	एच. सी. ११५०			
	ए. एस. सी. आई. डी.		बी० ए०	सवा दो साल
निरन्जनप्रकाश गुप्ता	एच. सी. १५४	जोधपुर	मैट्रिक	चार साल

(३) २७४ आवेदन पत्र ।

(४) इसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये ।)

(५) उक्त सिलेक्शन का आधार लिखित परीक्षा तथा इन्टरव्यू है ।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि जो ग्रेजुएट थे और जिनकी सर्विस अधिक थी उनको छोड़ दिया गया और मिडल योग्यता वाले व्यक्तियों को सिलेक्शन में लिया गया ?

श्री रामकिशोर व्यास—यह ठीक है इसमें टैक्स होता है और जो पास होते हैं उनको लिया जाता है ।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि टेस्ट में उन आदमियों का भी ख्याल रखा जाता है जो सस्पेन्ड होने की योग्यता हासिल किये हुए होते हैं ?

श्री अध्यक्ष—आर्डर

श्री रामकिशोर व्यास—ससपेन्ड होने के बाद अगर कोई रिइनटेस्ट होता है उनका कसूर नहीं माना जाता और वे आ सकते हैं ।

श्री चांदमल मेहता—यह परीक्षा लेने में कौन कौन आदमी थे ?

श्री रामकिशोर व्यास—यह रिटन टेस्ट होता है इसमें पेपर्स जाते हैं, बाकायदा इम्तिहान होता हैं और इन्टरव्यू में कलेक्टर डी. आ. जी और एस. पी. होते हैं ।

श्री चांदमल मेहता—रिटन टेस्ट किसने लिया था ?

श्री रामकिशोर व्यास—पर्चे आते हैं डिवीजनल हैडक्वाटर से।

श्री चांदमल मेहता—यह पर्चे कौन तैयार करता है।

श्री रामकिशोर व्यास—पुलिस के कर्मचारी तैयार करते हैं?

श्री चांदमल मेहता—पुलिस के कौन अधिकारी पेपर बनाते हैं?

श्री रामकिशोर व्यास—पेपर्स सेट कौन करता है, यह बताना मुनासिब नहीं।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि पर्चे की जांच एक व्यक्ति द्वारा नहीं की गई?

श्री रामकिशोर व्यास—हो सकता है, कॉपीज ज्यादा हों तो दूसरे के पास भी भेजी जा सकती हैं।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि अलग अलग व्यक्तियों से कॉपीज की जांच कराने की वजह से जो नम्बर देने के बारे में तरीका अख्त्यार किया जाना चाहिये जो मार्कस के लिये क्राइटेरिया होना चाहिये था नहीं रहा?

श्री रामकिशोर व्यास—यूनीवर्सिटिज में भी यही तरीका होता है।

श्री चांदमल मेहता—एक ही विषय की कॉपियां अलग अलग व्यक्तियों के पास भेजे जाने का क्या कारण है?

श्री रामकिशोर व्यास—पांच पांच, दस दस व्यक्तियों को दी जाती हैं।

श्री चांदमल मेहता—इसका क्या कारण है?

श्री अध्यक्ष—Obvious reasons. One man can not cope with the work. So they are sent to different persons.

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि जो व्यक्ति बताये गये हैं उन्हीं के जरिये यह क्लास चलाई जावेगी और प्राइवेट केन्डीडेट नहीं लिये गये हैं?

श्री रामकिशोर व्यास—यह तो मैंने शुरू में ही बताया था।

श्री चांदमल मेहता—मैं यह जानना चाहता हूँ कि अब तक यह तरीका था कि विभागीय और प्राइवेट केन्डीडेट दोनों लिये जाते थे। पर, इस साल विभागीय आदमियों द्वारा ही यह चलाई जावेगी इसका क्या कारण है?

श्री रामकिशोर व्यास—वेकेन्सीज कम हैं इसलिये इतने ही रक्खे गये।

श्री चांदमल मेहता—क्या क्लासेज चलाने के लिये सिर्फ यही ख्याल किया जाता है कि कितनी वेकेन्सीज हैं और उन्हीं के आधार पर क्लास चलाई जावे और अगर कोई प्राइवेट केन्डीडेट आना चाहे तो उसे नहीं लिया जावे ?

श्री रामकिशोर व्यास—नहीं, ऐसी बात नहीं है। आठ तो विभागीय केन्डीडेट थे और ७ ओपन मार्केट से लिये हैं। १५ ये हैं और मैं समझता हूँ कि क्लास के लिये पर्याप्त हैं।

श्री चांदमल मेहता—ये सात कौन कौन से हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास—प्रोसीक्यूटिंग सब इन्सपेक्टरर्स हैं।

प्रश्न संख्या ७६

१५ जनवरी १९५६ को अलवर शहर से मोहेड़ा ग्राम (त० बहरोड़) में तहसील कांग्रेस कमेटी को बैठक नियतन्त्र हेतु सशस्त्र पुलिस की नियुक्ति

श्री भोलानाथ—क्या गृहमन्त्री निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(क) क्या ता० १५ जनवरी, ५६ को अलवर शहर से मोटेडा गांव (तहसील बहरोड़) में तहसील कांग्रेस कमेटी की बैठक के नियन्त्रण के लिये सशस्त्र पुलिस भेजी गई थी ?

(ख) इस सशस्त्र पुलिस में कितने जवान थे और यह जवान किस तारीख को इस गांव में भेजे गये थे व उसे भेजने का क्या कारण था ?

(ग) क्या इसी दिन सशस्त्र पुलिस के अलावा इस तहसील के उच्चाधिकारी व अन्य कर्मचारी भी वहां भेजे गये थे ? यदि हां तो कौन कौन ?

(घ) क्या यह सच है कि इस गांव में सशस्त्र पुलिस भेजने की तारीख अथवा उससे पहिले कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ जिसके कारण पुलिस भेजने की आवश्यकता होती ?

(ङ) यदि हां तो फिर उपरोक्त दिन वहां अफसर भेजने का स्पष्ट कारण क्या था ?

(च) क्या इस बैठक से दो दिन पहले स्वायत्त शासन मन्त्री इस तहसील के हैडक्वार्टर पर मौजूद थे ?

(छ) क्या इससे पहले भी अन्य किसी कांग्रेस की बैठक के अवसर पर इस प्रकार पुलिस व अफसर भेजे गये थे ? यदि हां तो नाम बताने का कष्ट करें।

श्री रामकिशोर व्यास—(क) जी हां।

(ख) इस सशस्त्र पुलिस में एक हैडकांस्टेबिल तथा ६ कांन्स्टेबिल थे। वे ता० १४-१-५६ को भेजे गये थे।

(ख) वहां शांति भंग होने का अन्देशा था।

(ग) जी हां।

(घ) जी हां।

(ङ.) जी नहीं, यह बात नहीं थी। वहां की शांति भंग न हो, केवल इस कारण से ही पुलिस भेजी गई थी।

(च) जी हां।

(छ) जी नहीं।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी—यह कैसे समझा गया कि शांति भंग होने का अन्देशा है?

श्री अध्यक्ष—This is the discretion of the Government. But there should be some basis.

श्री रामकिशोर व्यास—मैं अर्ज करदूं। सबइन्सपेक्टर, बहरोड़ ने एस. पी. अलवर को रिपोर्ट लिख कर भेजी कि वहां कांग्रेस की मीटिंग है, उसमें दो पार्टियां हैं और मीटिंग के अवसर पर शांति भंग होने का अन्देशा है।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—यह मीटिंग किसकी थी?

श्री रामकिशोर व्यास—तहसील कांग्रेस कमेटी की थी।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—शांति भंग का अन्देशा किससे था?

श्री रामकिशोर व्यास—आपस में ही दो पार्टियां थीं।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—Thank you very much,

(हंसी)

श्री रामकिशोर व्यास—इसलिये फोर्स भेज दी गई थी।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—क्या यह कांग्रेस का झगड़ा होता है?

श्री रामकिशोर व्यास—लड़ाई की बहुत सी बातें सीखनी पड़ती हैं आपसे।

(हंसी)

कुं श्री जसवन्तसिंह— कांग्रेस ने स्पेशलाइज कर लिया है।

श्री अध्यक्ष— आप तो इन्फोर्मेशन पूछिये न।

श्री विशम्भरनाथ जोशी— आपको मालूम होना चाहिये कि कांग्रेस संस्था नान वाय-लेन्स को मानती है उसमें चाहे कितनी ही मतभिन्नता हो लाठियां और डंडे चलने की नौबत नहीं आ सकती। ऐसी स्थिति में पुलिस को वहां भेजना क्या उचित था?

श्री रामकिशोर व्यास— पर हमें तो इन्तजाम तो करना ही पड़ता है।

श्री गुरदयाल सिंह सन्धु— आपसी पर्टियों में झगड़ा होने का अन्देशा था या दूसरे लोग थे?

श्री अध्यक्ष— कह तो दिया। आपस में था।

कुं० श्री जसवन्तसिंह— कांग्रेस के ये आदर्श क्या कागजों में रखने के लिए ही हैं या व्यवहार में भी लाने के लिये हैं?

श्री रामकिशोर व्यास— व्यवहार में लाने के लिये।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी— क्या यह रिपोर्ट किसी सम्बन्धित व्यक्ति के द्वारा पुलिस को दी गई?

श्री रामकिशोर व्यास— इसका मुझे पता नहीं। मेरे पास तो यह सूचना है कि सब इन्स-पेक्टर ने रिपोर्ट की एस. पी. को और उसने यह प्रबन्ध किया।

श्री भोला नाथ— प्रश्न के भाग (ग) का उत्तर नहीं आया पूरा। उच्च अधिकारी कौन कौन से भेजे गये?

श्री रामकिशोर व्यास— वैसे एस. डी. ओ. था वहां।

श्री अध्यक्ष-- और कोई हो तो बता दीजिये।

श्री रामकिशोर व्यास— एस.डी. ओ, सी. आई, एस. डी. एम. थे और तहसील-दार भी थे।

श्री भोलानाथ— तहसीलदार के जाने की क्या आवश्यकता पड़ गई उसका तो रेवेन्यू से ताल्लुक रहता है?

श्री रामकिशोर व्यास— वह मजिस्ट्रेट भी है।

श्री भोलानाथ— फिर एस.डी. एम. को भेजने की बात क्यों आई ? क्या वहां सिर फूटने की बात सामने आई, हाथ पैर टूटने की खबर लगी ? क्या बात थी ?

श्री रामकिशोर व्यास— तीन चार साल पहले भी वहां एक झगडा हो गया था। इसको देखते हुए सम्भव है वे चले गये वहां।

श्री भोलानाथ— आज तक इस प्रकार की रिपोर्ट वहां से नहीं आई कि कभी एस. डी.-ओ, एस. डी. एम, तहसीलदार और सी. आई. इतने सारे पुलिस के अधिकारी वहां भेजे गये हों ? फिर उस वक्त ही इनकी सब की वहां क्या जरूरत हो गई ?

श्री रामकिशोर व्यास— यह तो जैसी जरूरत जब समझी जाती है वहां वैसा ही इन्तजाम किया जाता है। कोई उनके काम में वे इन्टरफीयर तो करते नहीं।

श्री भैरूं सिंह (१६)—क्या यह भी आवश्यक समझा पुलिस ने कि दोनों पार्टी के लोगों को झगड़े के अन्देशे में १०७ की कार्यवाही में जमानत मुचलके पर पाबन्द कर दिया जाता ?

श्री अध्यक्ष— क्यों नहीं समझा गया, यह पूछिये। (हंसी)

श्री रामकिशोर व्यास— आप तो खुद पुलिस में सब इन्सपैक्टर रह चुके हैं। खुद ही सब जानते हैं।

श्री भैरूं सिंह— इसीलिये तो पूछता हूं कि वह कार्यवाही की या नहीं ?

श्री रामकिशोर व्यास— जी नहीं।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी— वे अलवर जिला कांग्रेस कमेटी के मेम्बर हैं उन्हों ने या उनमें से किसी ने जिला कलक्टर को पुलिस अधिकारी वहां भेजने के लिए कहा था क्या ?

रामकिशोर व्यास— मुझे मालूम नहीं। पर जहां तक समझता हूं ऐसी कोई बात नहीं है।

कुं० **श्री जसवन्तसिंह**— स्वायत शासन मंत्री वहां मोजूद तो थे। क्या उनकी हाजिरी काफी नहीं समझी गई ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता— जी, हाजिर नहीं था मैं।

श्री भोलानाथ— पहले रोज मौजूद थे।

Page No.8

श्री अध्यक्ष—He was wise by his absence.

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता—I was not there on the 14th and 15th.

श्री भोलानाथ— क्या यह सही है कि उनके इशारे से पुलिस वहां भेजी गई थी ?

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता— इशारे का क्या सवाल है ? यह बिलकुल गलत है कि मैंने कोई पुलिस भेजी।

श्री भैंरू सिंह— मूल कारण क्या था झगड़े का ?

श्री रामकिशोर व्यास— झगडा कोई नहीं हुआ। झगड़े का अन्देशा था।

श्री भैरूसिंह— स्वायत शासन मंत्री वहां प्राइवेट तरीके से गये थे या आफिस के कार्य से गये थे ?

श्री अध्यक्ष— यह आपको अभी नही बतायेगे, बाहर पूछ लीजियेगा।

(हंसी)

श्री भवानी सहाय— जब वहां मंत्री महोदय एक दिन पहले पहुचे थे तो जनता की ओर से या नेता की ओर से या किसी एक नये आदमी की ओर से यह कहा गया था कि यहां झगड़ा होने वाला है !

श्री रामकिशोर व्यास— मंत्री महोदय को कहा गया या नहीं कहा गया इससे मुझे कुछ नहीं कहना। मुझे नहीं मालूम कि क्या कहा गया क्या नहीं कहा गया। पर पुलिस ने अपना काम रिपोर्ट आने पर जो होता है वह किया।

श्री अध्यक्ष—यह तो स्वायत शासन मंत्री महोदय से पूछना चाहते हैं। पुलिस से इनको मतलब नहीं।

(हंसी)

नेक्सट।

प्रश्न संख्या ७७

जयपुर कोटा के बीच बस सर्विस चलाने की शासकीय योजना

श्री चांदमल मेहता—क्या यातायात मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि जयपुर और कोटा के बीच कोई डाइरेक्ट बस सर्विस नहीं है ?

[श्री चांदमल मेहता]

(२) क्या उक्त रेट पर बस सर्विस चालू करने की योजना है ?

(३) यदि हां, तो कब तक सर्विस चालू हो जावेगी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री रामनिवास मिर्धा, यातायात मन्त्री—(१) जी हां। यह सही है।

(२) जी हां।

(३) मामला रीजनल ट्रान्सपोर्ट ऑथोरिटी, जयपुर के विचाराधीन हैं।

श्री चांदमल मेहता—यह बस सर्विस अब तक चालू न करने का क्या कारण है ?

श्री रामनिवास मिर्धा (यातायात मन्त्री)—यह मामला आर० टी० ओ० और एस० टी० ओ० से सम्बन्ध रखने वाला है। एक ने यह कहा है कि टेम्पेरेरी परमिट दे दिया जावे। दूसरे अधिकारी यह कहते हैं कि नान टेम्पेरेरी दिये जावें। तो दोनों ऑथोरिटीज उदयपुर और जयपुर दोनों की भी राय इसमें लेना जरूरी है। इसलिये यह मामला अभी विचाराधीन है। जल्दी ही कुछ कदम उठाया जावेगा।

श्री चांदमल मेहता—यह मामला कब से विचाराधीन है ? यह इतनी महत्वपूर्ण रूट है कोटा से जयपुर की वह कब से विचाराधीन है ?

श्री रामनिवास मिर्धा—मेरा ख्याल है कि आज से नवें महीने से।

श्री कंवरलाल जेलिया—यह कहां तक सही है कि एक अक्तूबर १९५५ से राजस्थान सरकार इस रूट पर अपनी सरकारी बस चलाने वाली थी ?

श्री रामनिवास मिर्धा—ऐसी बात नहीं है।

श्री कंवरलाल जेलिया—क्या सरकार की यह जानकारी है कि कोटा से जयपुर बस नहीं होने से जनता को काफी असुविधा रहती है ?

श्री रामनिवास मिर्धा—थोड़ी बहुत असुविधा जरूर रहती है।

श्री कंवरलाल जेलिया—उक्त असुविधा को दूर करने के लिये राजस्थान सरकार द्वारा दोनों रीजनल ट्रान्सपोर्ट ऑथोरिटीज को कोई निश्चित रूप से निर्देशन दिया गया ?

श्री रामनिवास मिर्धा—सरकार निर्देशन नहीं दे सकती है। अगली मीटिंग में मामला रखने की व्यवस्था है।

श्री कंवरलाल जेलिया—क्या राजस्थान सरकार इस सम्बन्ध में कोई विचार करने की स्थिति में है जब कि इस सदन में इस संबंध में बार बार सरकार का ध्यान दिलाने पर भी उक्त व्यवस्था अभी तक संभव नहीं हो सकी है ?

श्री अध्यक्ष--यह सरकार के अधिकार में नहीं है यह तो आर० टी० ए० और एस० टी० ए० के आधीन है जो कि आटोनामस बोर्डीज हैं।

श्री कंवरलाल जेलिया—क्या सरकार जब कि स्टेट ट्रान्सपोर्ट ऑथोरिटीज जयपुर और उदयपुर इस संबंध में विचार नहीं कर रही है तो कोई निश्चित नीति इस संबंध में निर्धारित करेगी ?

श्री रामनिवास मिर्धा—अगली मीटिंग में वह मामला लिया जायगा और आशा की जाती है कि वह मामला तय हो जायगा।

श्री कंवरलाल जेलिया—यह मीटिंग कब तक की जायगी ?

प्रश्न संख्या ७८।

राजस्थान में गायों की नस्ल सुधार केन्द्र

श्री प्रभूदयाल—क्या कृषि मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे।

(क) राजस्थान में कहां कहां गायों की नस्ल सुधारने के केन्द्र हैं ?

(ख) क्या यह सही है कि बीकानेर डिवीजन में राठी गायें अधिक दुधारू होती हैं ?

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार यहां राठी गायों का नस्ल सुधार केन्द्र खोलने का विचार रखती है ?

(घ) यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों नहीं।

श्री रामनिवास मिर्धा (कृषि मन्त्री)—(क) बसी, नागोर और अलवर।

(ख) हां।

(ग) हां।

(घ) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

श्री प्रभूदयाल—यह कब तक हो जायगा ?

श्री रामनिवास मिर्धा—इस साल इसमें कुछ किया जा रहा है। वेटेनरी कॉलेज बीकानेर जो है वहां पर एक डेरी फार्म स्थापित किया जायगा। जिसकी जांच हो रही है।

श्री प्रभूदयाल—यह काम इसी साल हो जायगा या और टाइम लगेगा ?

श्री रामनिवास मिर्धा—जांच होने पर इसी साल लगेगा ।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट ।

श्री भैरू सिंह—एक प्रश्न और है साहब ।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या ७६ ।

राजस्थान में पीलिये के प्रकोप के विशिष्ट स्थान एवं कहां उनकी रोकथाम की शासकीय कार्यवाही

श्री चांदमल मेहता—क्या स्वास्थ्य मन्त्री निम्न प्रश्नों का उत्तर देने की कृपा करेंगे ।

(१) चालू वर्ष में राजस्थान के किस किस जिले में पीलिये का प्रकोप रहा ?

(२) उक्त जिलों में कितने कितने व्यक्ति पीलिये के शिकार हुये और उनमें से कितने कितने व्यक्ति मृत्यु के शिकार हुये ?

(३) सरकार द्वारा पीलिये की रोकथाम के लिये क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—(स्वास्थ्य मन्त्री) जयपुर, भरतपुर, अलवर, सीकरी, धौलपुर, जोधपुर, जालौर, बीकानेर, गंगानगर, चुरू, कोटा, उदयपुर, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, टोंक, बूंदी ।

(२) रोग ग्रस्तों की संख्या इस प्रकार है :—

नाम	मरीजों की संख्या एलोपेथिक विभाग में	मरीजों की संख्या आयुर्वेदिक विभाग में ।
जयपुर	५६०	६४
भरतपुर	२४०	६८
अलवर	३३	१००
सीकरी	६३	....
धौलपुर	७	....
जोधपुर	२००	....
जालौर	१०	....
बीकानेर	६	....
गंगानगर	६४	१२

[श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता]

चूरू	२६	....
कोटा	२३	....
उदयपुर	१२६	१४
डूंगरपुर	२७	....
भीलवाड़ा	२	....
टोंक	....	३६
बूंदी	....	२०

इस रोग से मृत मनुष्यों की कोई सूचना नहीं मिली है।

(३) इस रोग की रोक थाम के लिये अस्पताल व औषधालय में प्रबन्ध कर दिया गया है। और एक विज्ञप्ति इस संबंध में समस्त जिलों में वितरण कर दी गयी है जिसमें इस रोग के लक्षण तथा रोक थाम आदि के उपाय बताये गये है।

श्री चांदमल मेहता—पीलिये के रोग के होने के कारणों के सम्बन्ध में क्या सरकार ने कोई जांच की है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—यह तो पीलिया नाम से ही मालूम पड़ता है कि वह पीली बीमारी हो जाती है।

श्री अध्यक्ष—नैक्स्ट श्री केसरी सिंह।

प्रश्न संख्या ८०

श्री अध्यक्ष—महाराज श्री केसरी सिंह

(प्रश्न कर्ता अनुपस्थित-कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

प्रश्न संख्या ८१

राजस्थान में चलते फिरते पशु चिकित्सालय

श्री प्रभूदयाल—क्या कृषि मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) राजस्थान में शुरू से चलते फिरते कितने पशुचिकित्सालय हैं व कहां कहां हैं ?

(ख) बीकानेर डिविजन में कितने हैं ?

(ग) क्या इसके लिये कोई प्रोवीजन रखा गया है ?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री रामनिवास मिर्धा (कृषि मन्त्री)—(क) कुल आठ हैं और वे निम्न लिखित स्थानों पर हैं

१. जयपुर, २. कोटा, ३. उदयपुर, ४. पाली, ५. सवाई माधोपुर, ६. जालोर, ७. जैसलमेर, ८. भरतपुर।

(ख) एक भी नहीं है।

(ग) सन् ५६-५७ के बजट में एक नया चलता फिरता चिकित्सालय खोलनेके लिये २६,६३० रूपये का प्रोवीजन किया गया है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री गुरुदयालसिह संधु—बीकानेर डिविजन में आज तक ऐसा अस्पताल कायम नहीं करने के क्या कारण हैं ?

श्री मिर्धा—अगले साल कायम किया जायगा।

श्री संन्धु—आज तक क्यों नहीं कायम किया गया ?

श्री अध्यक्ष—क्योंकि अगले साल कायम किया जायगा इसलिये इस साल नहीं हो सका।

(हंसी)

प्रश्न संख्या ८२

मनिथ पंचायत (तहसील धौलपुर) के हिसाब की जांच

श्री भोपालसिंह—क्या स्वायत शासन मन्त्री निम्न, प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे।

(क) क्या यह सच है कि मनिया पंचायत, तहसील धौलपुर, जिला भरतपुर के कोष से पंचों को बीड़ी व मिठाई आदि का खर्च किया जाता है ? यदि हां, तो क्या यह पंचायत रूल्स के आधार पर है ?

(ख) क्या सरकार मनिया ग्राम पंचायत के एकाउन्टस की जांच करवाने को तैयार है ?

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता—(स्वायत्त शासन मन्त्री)—(क) जी नहीं।

(ख) जांच के लिए Regional Inspector को आदेश दे दिये गये हैं।

श्री भोपालसिंह—क्या प्रश्न करने के बाद जांच नहीं कराई गई ?

Page No.14

श्री गुप्ता—आदेश दिये गये हैं ।

श्री भोपालसिंह—जांच होकर नहीं आई है अभी तक ?

श्री गुप्ता—अभी जांच हो रही है ।

श्री भोपालसिंह—क्या इन्सपेक्टर नागोर को वहां नहीं भेजा गया खास तौर से जांच के लिए ?

श्री गुप्ता—जांच के लिए प्रश्न अभी आया अभी आदेश दिये गये हैं ।

श्री भोपालसिंह—क्या प्रश्न के आने के बाद नागोर के इन्सपेक्टर को वहां स्पेशल तौर पर नहीं भेजा गया ?

श्री अध्यक्ष—वह कह रहे हैं कि जांच के लिए भेजा है ।

श्री भोपालसिंह—उसका क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष—आ रहा है जांच होकर ।

(**विराम**)

नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या ८३

ग्राम मोंगूड़ा (त० अराई) के तालाब की आव पर व्यय हुई राशि की जांच ।

श्री चांदमल मेहता—क्या सिंचाई मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे ।

(क) ग्राम मोगूड़ा तहसील अराई के तालाब की आव पर पिछले ३ वर्ष में कब कब कितना कितना रुपया खर्च किया गया और उसकी जांच कब किसके द्वारा कराई गई ?

(ख) इस वक्त उक्त आव की क्या हालत है ?

(ग) उक्त ग्राम के तालाब की मोरियों पर कब कब कितना कितना रुपया खर्च किया गया और उसकी जांच कब कब किसके द्वारा कराई गई ?

(घ) उक्त मोरियों की तथा तालाब की चद्दर की इस समय क्या हालत है ?

श्री रामनिवास मिर्धा—(सिंचाई मन्त्री) (क) पिछले तीन वर्षों में कोई रुपया खर्च नहीं किया गया।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) संतोषजनक है।

(घ) उक्त ग्राम के तालाब की मोरियों पर सन् १६५४-५५ में करीबन ५०० रु० खर्च किया गया।

(ङ) काम सिंचाई विभाग के अधिकारियों द्वारा करवाया गया था। जांच सम्बन्धित ओवर सीयर व इन्जीनियर ने की है।

(च) संतोषजनक है।

(छ) उक्त ग्राम के तालाब के कोई चद्दर नहीं है।

श्री चांदमल मेहता—(ख) के बारे में कहा गया है कि "प्रश्न नहीं उठता है" तो क्यों नहीं उठता है। जब हालत खराब है तो प्रश्न क्यों नहीं उठता है।

श्री मिर्धा—सवाल यह है कि उसकी हालत कैसी है तो जब हालत संतोषजनक है तो प्रश्न नहीं उठता है।

श्री चांदमल मेहता—क्या सही है कि गोंगूंदा ग्राम के रहने वालों ने सिंचाई विभाग के मन्त्री महोदय के पास इस बात की शिकायत की है कि इस तालाब की मोरियां और इस तालाब की आव बिल्कुल खराब हो गई है ?

श्री मिर्धा—मैंने अभी आप से कहा कि उनकी आव बिल्कुल ठीक हालत में है; संतोषजनक है।

श्री चांदमल मेहता—मैं अपने प्रश्न का जवाब चाहता हूँ। क्या यह बात सही है कि इस बात की शिकायत गोंगूंदा ग्राम के किसानों की थी कि तालाब की मोरियां खराब हैं ?

श्री मिर्धा—मैं निश्चित तौर से नहीं कह सकता, लेकिन अभी जो स्थिति है उसके बारे में जवाब दे दिया गया।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि इस प्रश्न का जवाब देने से पहले इस तालाब की जांच करने के सम्बन्ध में कोई व्यक्ति नहीं गया ?

श्री मिर्धा—जवाब देने से पहले पूरी जांच कराई गई है।

श्री चांदमल मेहता—यह जानकारी किस अधिकारी द्वारा कराई गई ?

श्री मिर्धा—वहां के संबंधित अधिकारी जो वहां रहते हैं उन्होंने सूचना दी है कि तालाब की क्या हालत है ।

श्री चांदमल मेहता—सम्बन्धित अधिकारी गो.,टा में कौन कौन

श्री मिर्धा—उस इलाके में जो सिंचाई के अधिकारी हैं उन्हीं ने दी है ।

श्री चांदमल मेहता—वह कौन हैं और किस ओहदे के हैं ?

श्री अध्यक्ष—It is not expected from a minister to know the name.

श्री प्रभूदयाल—किशनगढ तहसील में मोरियां कितनी हैं और मोरे कितने हैं ?

श्री अध्यक्ष—Order please Next

प्रश्न संख्या ८४

ग्राम पंचायत मनिया (त० धौलपुर) द्वारा प्रकाश स्तम्भ गाड़ने का ठेका उप सरपंच के पुत्र को

श्री भोपालसिंह—क्यां स्वायत्त शासन मंत्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि ग्राम पंचायत मनिया, तहसील धौलपुर, जिला भरतपुर द्वारा प्रकाश स्तम्भ गाड़ने का ठेका वहां के उप सरपंच के लड़के श्री कालीचरण को दिया गया था ?

(ख) यदि हा तो क्या यह पंचायत रूल्स के विरुद्ध नहीं है ? यदि है, तो सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मंत्री)—(क) जी नहीं। पंचायत की रोकड़ से ठेके की रकम हीरालाल नत्थीलाल को चुकाई जाना पाया जाता है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न संख्या ८५

सार्वजनिक निर्माण विभाग में सड़क का कार्य करने वाले गेंग्स के विभिन्न डिविजनों में वेतन व ग्रेड

श्री चांदमल मेहता—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) सार्वजनिक निर्माण विभाग में सड़कों पर काम करने वाले गेंग के मजदूरों को किस किस डिविजन में किस किस ग्रेड में वेतन दिया जाता है ?

(ख) किशनगढ़ सब डिविजन में गेंग में काम करने वाले व मजदूरों की ग्रेड क्या है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी (सार्वजनिक निर्माण मंत्री)—(क) जोधपुर विभाग में सड़कों पर काम करने वाले गेंग के मासिक वेतन वाले मजदूरों को निम्न लिखित ग्रेडों में वेतन दिया जाता है:—

गेंगमेन ४०-१-५०

गेंगवीमन ३०-१-५०

मेट ५५-१-६५

अन्य स्थानों पर श्रमिकों की कोई ग्रेड स्वीकृत नहीं है।

(ख) कोई नहीं है।

श्री चांदमल मेहता—कोई ग्रेड मुकर्रर नहीं करने के क्या कारण हैं ?

श्री रामचन्द्र चौधरी—आम तौर पर सड़कों पर जहां जहां जितने मजदूरों की जरूरत होती है तो वे वर्कचार्ज पर रखे जाते हैं। उनकी कोई परमानेन्ट स्ट्रेन्थ नहीं है।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि सड़कों के ऊपर किशनगढ़ में परमानेन्ट गेंग रहता है ?

श्री रामचंद्र चौधरी—नहीं वह वर्कचार्ज बेसिस पर रहता है।

श्री चांदमल मेहता—वहां परमानेन्ट गेंग है या नहीं ? इस सवाल के जवाब की जरूरत है।

श्री रामचन्द्र चौधरी—उनकी कोई ग्रेड मुकर्रर नहीं है।

श्री चांदमल मेहता—आपने यह कहा कि परमानेन्ट गेंग नहीं रहता है तो मैं दुबारा यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि किशनगढ़ में परमानेन्ट गेंग रहता है या नहीं ?

श्री रामचंद्र चौधरी—उनको वर्क चार्ज सिस्टम पर रखते हैं और जरूरत के मुताबिक कमी बेशी की जा सकती है।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि इस तरह के परमानेन्ट गैंगों को कमी बेशी करने का कायदा नहीं है ?

श्री रामचंद्र चौधरी—कायदा है।

श्री चांदमल मेहता—तो क्या यह सही है कि जो गैंग रखा जाता है वह पूरे वर्ष के लिए नहीं रखा जाता है।

श्री रामचंद्र चौधरी—वह पूरे वर्ष के लिए होता है लेकिन वह वर्क चार्ज सिस्टम पर होता है।

श्री चांदमल मेहता—यदि पूरे वर्ष के लिए रखते हैं तो फिर उसके अन्दर कमी बेशी क्यों की जाती है और उनको निकालने और रखने की जरूरत क्यों पड़ती है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी—जरूरत के मुताबिक कमी बेशी की जाती है।

श्री चांदमल मेहता—एक व्यक्ति को निकाल कर उसके स्थान पर दूसरे को रखने की कार्यवाही क्यों की जाती है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी—जब कोई ठीक तरह से काम नहीं करता है तो उसको निकाल भी दिया जाता है।

श्री चांदमल मेहता—जब ठीक काम नहीं करने की हालत में हटाने की बात दूसरी है पर आप परमानेन्ट नहीं मानते इसलिए एक को हटाकर दूसरे को रख देते हैं, ऐसा क्यों होता है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी—वे परमानेन्ट नहीं हैं।

श्री हिम्मतसिंह—क्या नोन परमानेन्ट गैंग को वर्दी दी जाती है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी—यह अलग सवाल है। उनको वर्दी नहीं दी जाती है।

श्री संतोषसिंह—सड़कों पर जो गैंग काम करती है उनको छुट्टी दी जाती है क्या ?

श्री रामचन्द्र चौधरी—उनको सप्ताह में एक दिन की छुट्टी मिलती है,

श्री संतोषसिंह—क्या उनको उस दिन के पैसे दिये जाते हैं ?

श्री रामचन्द्र चौधरी—जी हां उनको पैसे दिये जाते है।

Page No.19

श्री संतोषसिंह—क्या मंत्रीजी को यह मालूम है कि जोधपुर में गैंग को छुट्टी के दिन पैसे नहीं दिये जाते हैं ?

श्री अध्यक्ष—यह अब जोधपुर बीच में आ गया ? Next question.

प्रश्न संख्या ८६

ग्राम पंचायत मनिया, तहसील धौलपुर के आय व्यय के निरीक्षण का प्रतिवेदन

श्री भोपालसिंह—क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या ग्रामपंचायत मनिया, तहसील धौलपुर, जिला भरतपुर के आय-व्यय का निरीक्षण हो चुका है ? यदि हां, तो क्या उपरोक्त निरीक्षण की रिपोर्ट सरकार सदन की मेज पर रखेगी ?

(ख) इस रिपोर्ट पर सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मंत्री)—अभी जांच जारी है।

(ग) रिपोर्ट आने पर सदन की मेज पर रखी जा सकती है।

(घ) प्रश्न नहीं उपस्थित होता।

श्री भोपालसिंह—जांच कब तक पूरी हो जायगी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मैंने अभी निवेदन किया कि जांच हो रही है। इन्सपेक्टर गया हुआ है जांच की रिपोर्ट अभी नहीं आई है।

श्री भोपालसिंह—क्या जांच पूरी होने के बाद मुझे इतला दी जायगी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—यदि आप चाहेंगे तो अवश्य दी जायगी।

श्री भोपालसिंह—चाहता हूं इसीलिये तो मैंने प्रश्न पूछा है ?

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता—आप कष्ट करेंगे तो अवश्य इतला दी जायगी।

प्रश्न संख्या ८७

श्री अध्यक्ष—महाराज श्री केसरीसिंह।

(प्रश्न कर्ता अनुपस्थित कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

Page No.20

प्रश्न संख्या ८८

प्रथम पंचवर्षीय योजना के पूर्व एवं उसके पश्चात समस्त कृषि योग्य कृषि किए हुए एवं सिंचाई वाले क्षेत्र-

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी—Will the Minister for Agriculture and Irrigation please state :—

What was the total cultivable area, the total cultivated area, the total irrigated area prior to the initiation of the First Five Year Plan, and the total amount spent on the various kinds of irrigation works, during the First Five Year Plan, in respect of each of the districts in Rajasthan ?

श्री रामनिवास मिर्धा (कृषि एवं सिंचाई मंत्री)—The area prior to the formation of Rajasthan is as below :—

The total cultivable area...42.26 million acres.

Total cultivated area......23.62 million acres.

Total irrigated area...... 2.84 million acres.

District-Wise list of expenditure incurred during the First Five Year Plan is appended.

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री बी. एन. जोशी—I wanted district-wise figures in respect of the total cultivable area, total cultivated area and total cultivated area and total irrigated area as well ?

श्री रामनिवास मिर्धा—जैसा हमने समझा था वह यह कि इर्रिगेशन पर जितना रुपया खर्च किया गया है उसकी डिस्ट्रिक्टवाइज लिस्ट चाहते हैं इसलिये उसकी लिस्ट पेश की गई है।

श्री विश्वंभरनाथ जोशी—मैंने डिस्ट्रिक्टवाइज़ एरिया सब का पूछा था। क्या यह बतलाया जा सकता है ?

श्री रामनिवास मिर्धा—यह अलग सवाल है, पूछेंगे तो जरूर बतायेंगे।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी—प्रश्न जिस सूरत में अभी है उसका मतलब भी यही निकलता है।

श्री अध्यक्ष—This is English language.

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी—It has been misunderstood.

श्री अध्यक्ष—May be. There can be two interpretations

श्री रामनिवास मिर्धा—This information can be supplied even now.

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी—Let me have it.

श्री रामनिवास मिर्धा—We will collect the information and supply it to you.

प्रश्न संख्या ८६

राजस्थान सार्वजनिक निर्माण विभाग के रोड़ मोहर्रिर—विशेषतया किशनगढ़ में

श्री चांदमल मेहता—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे ?

(क) राजस्थान में रोड़ मोहर्रिर के लिये सार्वजनिक निर्माण विभाग में कितने स्थान किस किस रोड़ के स्वीकृत हैं ?

(ख) उक्त रोड़ मोहर्रिर में सेन्ट्रल पी. डब्ल्यू. डी. के कितने स्थान हैं ? तथा उन्हें वेतन किस ग्रेड में दिया जाता है ?

(ग) क्या किशनगढ़ में कोई रोड़ मोहर्रिर का स्थान स्वीकृत है ?

(घ) यदि हां, तो उसको वेतन किस ग्रेड में दिया जाता है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी (सार्वजनिक निर्माण मंत्री)—(क) राजस्थान में रोड़ मोहर्रिरों के लिये सार्वजनिक निर्माण विभाग में कोई भी स्थाई स्थान स्वीकृत नहीं हैं। रोड मोहर्रिरों को केवल वर्क चार्ज पर आवश्यकतानुसार रखा जाता है।

(ख) कोई नहीं है।

(ग) कोई ग्रेड निर्धारित नहीं है।

(घ) जी नहीं। मोहर्रिरों में कोई ग्रेड नहीं है।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न संख्या ६०

मड़ता से पाडुरीयां, थावला रेलवे लाइन का निर्माण कार्य

श्री भोपालसिंह—क्या यातायात मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

[श्री भोपालसिंह]

(क) क्या सरकार के ध्यान में यह बात है कि मेडता से पाडुरीयां, थावला रेलवे लाइन बनाना जोधपुर रेलवे के समय तय हो चुकी थी ?

(ख) क्या सरकार से इस कार्य के कराने की सिफारिश की है ?

(ग) यदि हां, तो इस कार्य के शुरू हो जाने में कितना समय और लगने की आशा है ?

श्री रामनिवास मिर्धा (यातायात मंत्री)—जी हां, सर्वे हो चुकी थी।

(ख) जी हां।

(ग) यह निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता।

प्रश्न संख्या ६१

श्री अध्यक्ष—महाराज श्री केशरीसिंह।

(प्रश्नकर्ता अनुपस्थित–कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

प्रश्न संख्या ६२

द्वितीय पन्चवर्षीय योजना के अन्तर्गत विभिन्न डिवीजनों में बनाये जाने वाले बांध

श्री सज्जनसिंह—क्या मन्त्री सिंचाई विभाग निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(अ) क्या आगामी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जिन जिन डिवीजनों में और नये बांध बनाये जा सकते हैं उसकी सूची सरकार ने उपलब्ध करली है ?

(ब) यदि हां, तो किन किन डिवीजनों में अब द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कौन कौन से नये बांधों का निर्माण होगा ?

(स) क्या इस कार्य के लिये सर्वे सब डिवीजन्स कायम किये गये हैं ?

(द) यदि हां, तो कहां कहां के लिये ?

श्री रामनिवास मिर्धा—(सिंचाई मंत्री)—(अ) हां।

(ब) सूची संलग्न है।

(स) (द) हां, एक डिवीजन और चार सब डिवीजन उदयपुर सर्कल के लिये कायम हैं। एक सब डिवीजन अभी हाल ही में जयपुर सर्कल में भी खोल दिया गया है।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

श्री सज्जनसिंह—क्या कोटा डिवीजन के लिये सर्वे डिवीजन खोलने का विचार है ?

श्री रामनिवास मिर्धा—अभी तो जहां पर ज्यादा जरूरत थी वहां पर सर्वे का काम शुरू किया गयाहै लेकिन ज्यों ज्यों द्वितीय पंचवर्षीय योजना आगे चलेगी, हम ज्यादा सर्वे डिवीजन चलायेंगे ।

श्री सज्जनसिंह—आपने यह किस आधार पर मान लिया कि कोटा डिवीजन में अभी इसकी आवश्यकता नहीं है ?

श्री रामनिवास मिर्धा—कोटा डिवीजन में अभी काफी सिंचाई के साधन हैं । जहां पर बिल्कुल काम नहीं हुआ है उनको प्राथमिकता दी गई है ।

प्रश्न संख्या ६३

प्रथम पन्चवर्षीय योजना के अन्तर्गत राजस्थान में नये खोले गये आयुर्वेदिक औषधालय

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी—Will the Minister for Public HealthDepartment Please state—

(a) What is the total number of new Ayurvedic and Allopathic dispensaries opened by the Government during the period of the First Fivo Year Plan throughout Rajasthan, excluding the dispensaries opened by District Boards and other local bodies ?

(b) what is the total non-recurring and annual recurring cost incurred and being incurred by the Government on these dispensaries ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—(स्वास्थ्य मन्त्री)—(क) ५१ एलोपेथिक ऐंड पोस्टस व डिस्पेन्सरीज तथा १४३ आयुर्वेदिक औषधालय खोले गये हैं ।

(ख) ऐलोपेथिक का कुल नान रेकरिंग खर्चा करीब २०,००० रुपये

आयुर्वेदिक का कुल नान रेकरिंग खर्चा करीब ५०,००० रुपये

ऐलोपेथिक का वार्षिक रेकरिंग खर्चा ३,११,६०० रुपये

आयुर्वेदिक का वार्षिक रेकरिंग खर्चा २,००,००० रुपये

प्रश्न संख्या ६४

जालौर जिले के जसवन्तपुरा गांव में अस्पताल की स्थापना सम्बन्धी शासकीय योजना

श्री छतरसिंह—क्या जन स्वास्थ्य मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

[श्री छतरसिंह]

(क) क्या जालोर जिले के जसवन्तपुरा ग्राम में पहले होस्पिटल था ?

(ख) क्या यह सही है कि होस्पिटल की बिल्डिंग में अब पुलिस थाना है ?

(ग) क्या सरकार वहां वापिस होस्पिटल खोलने का विचार कर रही है ?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों और यदि हां, तो कब तक ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (जन स्वास्थ्य मंत्री)—(क) जहां तक पता चला है एक अस्पताल इस गांव में सन् १८६७ से पहले था जिसमें एक कम्पाउन्डर रहता था। जब महाराजा साहब, जोधपुर वहां पधारते थे तो एक डॉक्टर अस्थाई तौर पर वहां चला जाता था।

(ख) इस अस्पताल की बिल्डिंग में अब एक पुलिस थाना है।

(ग) व (घ) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इस गांव में अस्पताल खोला जायगा।

प्रश्न संख्या ६५

ग्राम नगर (त० दूनी,) के ग्राम पंचायत के सरपंच का चुनाव

रावराजा श्री सरदारसिंह—क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि ग्राम नगर, तहसील दूनी, जिला टोंक के ग्राम पंचायत के सरपंच का चुनाव हो चुका है ?

(ख) यदि हां, तो कब और कौन सी तारीख को ?

(ग) क्या उसका नाम राजस्थान राज-पत्र में प्रकाशित होने के लिए भेजा गया था ?

(घ) यदि हां, तो कब और कौन सी तारीख को ?

(ङ) सफल सरपंच को शपथ ग्रहण कराई जाकर कार्य भार संभला दिया गया है या नहीं ?

Page No.25

[redacted]

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मंत्री)—(क) जी हां।

(ख) दिनांक १७ जनवरी १९५९।

(ग) जी हां।

(घ) दिनांक ९-३-५९ को।

(ङ) तहसीलदार को शपथ ग्रहण कराने को एवं सरपंच को कार्यभार संभालने के लिए परिपत्र भेजा जा चुका है।

रावराजा श्री सरदारसिंह—धन्यवाद।

प्रश्न संख्या ९६

जसवन्तपुरा तहसील में बांध बनाने की योजना वाले स्थान

श्री छतरसिंह—क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

जसवन्तपुरा तहसील में किस किस जगह बांध बांधने की योजना सरकार के विचाराधीन है ?

श्री रामनिवास मिर्धा—जसवन्तपुरा तहसील में निम्नलिखित योजनाएं सिंचाई विभाग के विचाराधीन हैं :

(१) देहपुरा।

(२) रामदीन बीघान।

(३) मध्यम श्रेणी की योजनायें :

(४) सागी नदी योजना।

(५) बांधी नदी योजना।

प्रश्न संख्या ९७

कस्बा–तारानगर में अस्पताल में नर्सों और कम्पाउन्डरों के क्वार्टर्स बनाने सम्बन्धी शासकीय योजना

श्री प्रभूदयाल—क्या स्वास्थ्य मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) कस्बा तारानगर, जिला चूरू, होस्पीटल में नर्सों व कम्पाउन्डरों के रहने के लिए कुल कितने क्वार्टर हैं ?

[श्री प्रभूदयाल]

(ख) क्या यह सही है कि कम्पाउन्डर के क्वार्टर में नर्स रहती है ?

(ग) क्या सरकार का वहां क्वार्टर बनाने का विचार है ? यदि हां, तो कब तक ?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (जन-स्वायस्थ्य मंत्री)—(क) एक।

(ख) जी हां।

(ग) जैसे जैसे अर्थ उपलब्ध होता जावेगा, केवल तारानगर ही नहीं परन्तु अन्य स्थानों पर भी क्वार्टर बनाये जावेंगे।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

श्री प्रभूदयाल—कब तक यह बन जाने की उम्मीद करनी चाहिये ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मैंने निवेदन किया कि जब से फाइनेन्स उपलब्ध होगा तब क्वार्टर्स बनाये जायेंगे।

श्री प्रभूदयाल—वहां तो सिर्फ एक क्वार्टर बनाने का सवाल है ज्यादा फाइनेन्स का सवाल नहीं है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—सारे राजस्थान का सवाल है। जबकि डिसपेन्सरीज भी नहीं खुल पाती है तो क्वार्टर का सवाल तो दूर है।

श्री प्रभूदयाल—क्या वहां के कम्पाउन्डर के क्वार्टर में नर्स रहती है ?

श्री बद्रीप्रसादगुप्ता—जी हां।

श्री प्रभूदयाल—वहां के कम्पाउंडर और नर्स दो रहते हैं इसलिए कम्पाउंडर के लिए अलग इंतजाम क्यों नहीं होता ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—कम्पाउंडर किराये के मकान में रहता है।

श्री चंदनमल वैद—क्या वहां ऐसा प्रबंध करेंगे कि नर्स और कम्पाउंडर पति-पत्नी हों ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—ऐसे कम्पाउंडर और नर्स हैं नहीं।

श्री प्रभूदयाल—क्या यह सही है कि वहां रहने का साधन नहीं होने के कारण कोई जाना नहीं चाहता ?

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता—वहां पर कम्पाउंडर किराये के मकान में रहता है ।

प्रश्न सख्या ६८

ग्राम नीवली (त० खारची) के काश्तकारों द्वारा तेजिया डाकू को पकड़ने पर चार राइफलों का पारितोषिक

श्री छतरसिंह—क्या गृह मंत्रीजी यह बताने की कृपा करेंगे :

क्या खारची तहसील जिला पाली के नीवली ग्राम के काश्तकारों ने तेजिया डाकू को पकड़ा था ?

(ख) क्या उनको ४ राइफलें जयपुर में इनाम में दी गई थी ?

(ग) क्या उनसे चारों राइफलें पाली पुलिस द्वारा वापिस ले ली गई हैं ?

(घ) क्या उनको जयपुर आने जाने का खर्चा भी मिला है ?

रामकिशोर व्यास (गृह मंत्री)—(क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) जयपुर में ही यह राइफलें वापिस ले ली गईं थीं ।

(घ) जी हां ।

श्री भोपालसिंह—क्या उनको राइफलें वाकई में दी गई थीं या केवल देखने के लिए ही दी गई थीं ।

श्री रामकिशोर व्यास—वाकई दी गई थीं ।

श्री छतरसिंह—वे कब तक वापिस दे दी जायेंगी ?

श्री रामकिशोर व्यास—एस. डी. ओ. पाली के पास भेज दी गई हैं उनको देने के लिए ।

अभिभाषण पर दिये गये धन्यवाद पर श्रीमन् राजप्रमुख का संदेश

श्री अध्यक्ष—मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि श्रीमन् राजप्रमुख का निम्न-लिखित संदेश प्राप्त हुआ है :

"I have received with great satisfaction the expression of thanks by the Members of the Assembly for the Address that I delivered to them on the 5th March 1956."

(राज्य पक्ष द्वारा करतल-ध्वनि)

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के प्रारूप पर वाद-विवाद करने सम्बन्धी

श्री अध्यक्ष—द्वितीय पंचवर्षीय योजना के विषय में जो ड्राफ्ट कोपीज़ हैं वे माननीय सदस्यों को सम्भवतः भेज दी गई हैं, नहीं तो उनके पास अभी पहुँच जायेंगी। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस पर सदन के माननीय सदस्य कुछ वाद-विवाद करना चाहेंगे क्या ?

कई माननीय सदस्य—जरूर चाहेंगे।

श्री बृजसुन्दर शर्मा (वित्त मन्त्री)—अपने यहां द्वितीय पंचवर्षीय योजना पर पहले बहस हो चुकी है।

श्री अध्यक्ष—इसके अनुसार एडजस्ट करलें।

श्री भैरूसिंह—बजट पर जो वाद-विवाद हो रहा है उसको छोड़ कर और दिन वाद-विवाद होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—किसी रोज रख दिया जायगा। Some day will be fixed and Members should get prepared.

आय व्ययक भाषण पर सामान्य वाद-विवाद

रावराजा श्री सरदारसिंह—अध्यक्ष महोदय, जो बजट सन् ५६-५७ का वित्त मन्त्रीजी ने पेश किया है। उसके बारे में मेरे पूर्व वक्ताओं ने काफी प्रकाश डाला है और मैं भी अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, जो बजट माननीय फाइनेन्स मंत्री ने समाजवादी भावना को लेकर सदन में पेश किया है उसमें समाजवादी भानाएं नहीं हैं लेकिन क्षेत्रीय भावना तो बिलकुल ही नहीं है, और उसका तो नामोनिशान ही नहीं है।

श्री वेदपाल त्यागी—हानी का बजट है।

श्री सरदारसिंह—मैं जिस क्षेत्र से आया हूँ उसके बारे में निवेदन करना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष, समाजवाद का अर्थ मैं जहां तक लगा सका हूँ वह यह लगाया जावे कि सबको समान न्याय मिले, समान व्यवस्था हो और सबको एवरीथिंग (Everything) समान होनी चाहिये लेकिन आज हम देखते हैं कि उल्टी गंगा बह रही है। माननीय अध्यक्ष, आप जानते हैं कि उनियारा ठिकाना जिसके बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूँ और जो ठिकाना मेरे अधिकार में था और जहां पर आज उनियारा कोन्स्टीटुएन्सी है पहले वहां पर पब्लिक को कितनी सुविधायें थीं और अब कितनी असुविधायें कर दी गई हैं यह क्यों किया गया यह मेरे समझ में नहीं आता। वहां से न्यायालय और तहसील भी हटा दी गई है। यहां तक की वहां से हाई स्कूल भी हटाई जा रही थी लेकिन मैं हमारे राजस्व मंत्री को इसके लिये धन्यवाद दूंगा कि उनके प्रयत्नों से अभी श्री माणकलालजी वर्मा वहां पर पधारे थे वहां पर हाई स्कूल का शिलान्यास रखा गया। यह आपके प्रयत्नों का ही फल है वरना वहां से पटवारी भी हटा दिया जाता।

श्री अध्यक्ष—हाई स्कूल का न्यायालय रखा गया है।

श्री सरदारसिंह—हमतो इसको न्यायालय ही समझेंगे क्योंकि लोग पढ़ लिख कर न्याय प्राप्त कर सकेंगे। इसके अलावा मैं यह कहूँगा कि उनियारा से होती हुई मोटर सर्विस इन्द्रगढ़, माधोपुर जाती थी वह भी आज कल उनियारा से होकर नहीं जाने लगी है यह तो आपके समाजवाद की बात है। इसके अलावा बहुत सी बातें पंच वर्षीय योजना में कही गई हैं। प्रथम पंच वर्षीय योजना में जो कार्य नहीं हुआ था, लोगों को यह आशा थी कि वह कार्य द्वितीय पंच वर्षीय योजना में पूरा हो जावेगा मगर माननीय राजस्व मंत्री अच्छी तरह से जानते हैं कि टोडा से नासिरदा और थांवला से जो रोड है वह ऐसी है कि जिससे बरसात में नासिरदा नहीं जा सकते और पहले इसको ठीक करने के लिये मंजूरी भी हो गई थी मगर कुछ नहीं हुआ। दूसरी बात यह है कि दूनी से आंवा और नगर रोड़ के लिये पहले भी कहा गया था। दूसरी रोड़ के लिये अलीगढ़ से बरवाड़ा के लिये भी कई बार कहा गया, मगर अभी तक नहीं हुई। मगर एक बहुत महत्व की बात मैं निवेदन करना चाहता हूँ और व यह है कि दूनी तहसील में आंवा गाव है उसमें राजकोट नाम का ग्राम है वहां पर, वह पहले मेरी तहसील के आधीन था उसमें एक तालाब है। वहां पर श्री माणिकलालजी के बाड़ी इलेक्शन के मेले के वक्त वहां के लोगों ने कहा कि हमारे यहां तालाब बनाओ और वोट ले जाओ। राजस्व मंत्री इस बात को जानते हैं। माननीय मंत्री ने उस वक्त उसको बनवाने का आश्वासन दिया और हम लोगों ने भी आश्वासन दिया था यह बात मणिकलालजी के इलेक्शन के समय की बात है और उस वक्त डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी टोंक से भी उसके लिये सिफारिश हो गई थी कि राजकोट का तालाब बनवा दिया जावे यह क्षेत्र खारोड़ कहलाता है। इस पर मंजूरी हो गई बताई मगर आज तक कोई उसकी सर्वे तक करने के लिये नहीं आया। मैं समझता हूँ कि इसको माननीय राजस्व मंत्री महसूस करते होंगे कि वहां का तालाब जरूर बनना चाहिये। इसके अलावा बहुत सी बातें ऐसी हैं जिनको मैं समय के अभाव से कहना नहीं चाहता और आपका समय जाया नहीं करना चाहता मैं मुख्य मुख्य बातों को ही कहना

[श्री सरदारसिंह]

चाहता हूँ और आपका ध्यान उस ओर आकर्षित करना चाहता हूं। माननीय राजस्व मंत्री उनियारा पधारे थे और मकानों की असुविधा भी वो देख कर आये हैं और सब दूसरी बातें भी देख कर आये हैं। मैं आपसे यह नम्र निवेदन करूंगा कि जो उनियारे से हेड क्वार्टर तहसील का चेंज किया है वह वापिस उनियारा में कर दिया जावे। मैं वहां से वापिस आयेन्दा चुनावों में आऊं या न आऊं मुमकिन है आप भी वहां से आ जावें इससे जनता को जो असुविधा हो रही है उसे दूर किया जावे।

श्री वेदपाल त्यागी—माननीय अध्यक्ष, यह एक महत्वपूर्ण बजट महत्वपूर्ण समय पर रखा गया है कि जिसके लिये हम लोगों ने बहुत बड़ी आशाएं बांधी थी क्योंकि प्रथम पंच वर्षीय योजना समाप्त हो रही है और द्वितीय पंच वर्षीय योजना में हम पदार्पण कर रहे हैं इसलिये ऐसे समय में हमको आशा थी कि जो काम प्रथम पंच वर्षीय योजना में पूरे नहीं हुए संभवतः उसकी समालोचना इसमें मिले मगर हमारी आशाएं निराशा में परिवर्तित हुई। जैसा कि कल एक माननीय सदस्य ने बोलते हुए कहा कि जिस वक्त बजट पेश किया जा रहा था उस समय भगवान इन्द्र भी प्रसन्न हो रहे थे क्योंकि उनकी स्पीच में कहा जा रहा था कि नये कर नहीं लगाये जावेंगे लेकिन मैं यह निवेदन करूं कि भगवान इन्द्र की प्रसन्नता उस वक्त होती जब उस समय वर्षा की जाती जिस समय लोगों को उसकी जरूरत हो जिससे उनको फायदा हो। लेकिन जब वर्षा की जरूरत नहीं हो और वर्षा हो या अधिक वर्षा होती है तो लोगों को उससे नुकसान होता है। इसलिये उसको आसूं बहाना कहा जाता है। इसलिये मैं यह कहूँगा कि जिस समय फाइनेन्स मिनिस्टर बजट के स्पीच को पढ़ रहे थे उस वक्त भगवान इन्द्र भी रो रहे थे और कह रहे थे कि इस समय में किस प्रकार का बजट पेश किया जा रहा है। कहा यह जाता हैं कि हमने कोई नये कर नहीं लगाये हैं लेकिन दूसरे ही पन्ने को जब हम देखते हैं तो यह कहा जाता है कि जरूरत होगी तो कर भी लगावेंगे। घाटे का बजट पेश किया जाता है और नये करों के लगाने के लिए हमें कोई संकेत नहीं दिया जाता है कि उस घाटे को इस तरह से पूरा किया जायगा। जैसे एक माननीय सदस्य ने बोलते हुए कहा था कि सम्भव है कि या तो वित्त मंत्री का विचार यह हो कि बड़ी बड़ी रकमें खर्च में दिखा दी जांय और बजट घाटे का दिखा दिया जाय, खर्चा करना किसको है ? इसलिए नये कर लगाने की आवश्यकता क्या है ? अगर आवश्यकता प्रतीत हुई तो कर उस उक्त भी लगाये जा सकते हैं, अपने लोगों से मंत्रणा कर लेंगे कि कितना कर लगावें, हमें निजी फायदा क्या हो सकता है, सरकार को कितनी जरूरत हो सकती है, उसके बाद सांठ गांठ करके कर लगाये जावेंगे।

अध्यक्ष महोदय, बजट बनाने का सिद्धांत यह नहीं है। सिद्धांत तो यह है कि यदि ज्यादा खर्च करना है तो लोगों पर उसको डालना होगा, पैसा बनता तो नहीं है लोगबाग ही उसको पे करते हैं। पहले ही गवर्नमेंट को स्कीम बतानी चाहिए कि उस घाटे को इस तरह से पूरा करना चाहते हैं। स्कीम की एबसेन्स इस बात की द्योतक है कि वित्त मंत्री जो खर्चा करना चाहते हैं

[श्री वेदपाल त्यागी]

वे केवल बड़े बड़े आंकड़ों में ही बताना चाहते हैं। करों के बारे में जैसा कहा गया है कि सांठ-गांठ करके अपने विचार बना पावेंगे। अभी बात नहीं की है इसलिए विचार नहीं बनाये हैं।

मैं यह निवेदन करूं कि जहां यह कहा जाता है कि सोशलिस्टिक स्टेट का यह बजट है। जैसा मुख्य मंत्री महोदय ने श्रीमन् राजप्रमुख के अभिभाषण का उत्तर देते हुए कहा था कि सोशलिस्टिक पेटर्न और सोशलिस्टिक स्टेट के क्या माने समझते हैं, और क्या अर्थ समझते हैं, मुझको तो कम से कम अजीब प्रतीत हुआ। मैंने भी सोशलिज्म के बारे में अध्ययन किया है। मैं भी जानता हूँ कि उसके क्या माने हैं। उन्होंने तो जो माने बताये उससे तो सोशलिज्म की परिभाषा को ही बदलना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि जितनी जरूरीयात की चीजें हैं वे जितने ज्यादा लोगों को उपलब्ध कर सकेंगे वही सोशलिस्टिक स्टेट का पेटर्न होगा। सोशलिस्टिक स्टेट में जो मुख्य बात है और जो फन्डामेन्टल, बुनियादी चीज़ है वह यह है कि असमानता को जितना कम कर सकें उतना ही कम करना चाहिये। आज यह कहा जाता है कि हमने नये वेतन दर इस तरह से प्रसारित किये हैं कि उसके आधार पर हम अपने आपको सोशलिस्टिक पेटर्न की सरकार कह सकते हैं। मैं निवेदन करूं कि यह बिलकुल भ्रमात्मक चीज़ है। यह ठीक है कि इस तरह से भ्रम पैदा होता है लेकिन यह भी ठीक है कि यह भी भ्रामक है कि हम सोशलिस्टिक पेटर्न इस तरह से कायम करना चाहते हैं। बजट के आंकड़े ऊपर से नीचे तक देखें हैं उनमें सोशलिज्म लेश मात्र भी कहीं नजर नहीं आता है। कहां है सोशलिज्म? सोशलिस्टिक स्टेट में असमानता को कम करना पड़ेगा और उस असमानता को कम करने के लिए उसके लिए एक माप दण्ड कायम करना पड़ेगा, कि कितनी असमानता रख सकेंगे। जहां सोशलिस्टिक पेटर्न पर आधारित स्टेट्स हैं वहां पर असमानता का मापदंड है कि २० गुना, ५० गुना या १०० गुना। लेकिन यहां हम देखते हैं कि किस तरह वेतन दरें बढ़ाई गई हैं। उन वेतन दरों को देखने से पता लगता है कि वे किस तरह से असमानता को दूर करना चाहते हैं, या असमानता बढ़ाना चाहते हैं। माननीय अध्यक्ष, जब हम देखते हैं कि चपरासियों का वेतन, चपरासियों की ग्रेड में पांच रुपये की तरक्की की गई और उनके वेतन में १) रुपये की तरक्की की गई है। लेकिन मिला क्या? मिला यह, एक रुपये की तरक्की जरूर उनको मिल जायगी, पांच रुपये ग्रेड में बढ़ जावेंगे लेकिन जब हम दूसरी तरफ देखते हैं, आर. ए. एस. और दूसरी सर्विसेज को देखते हैं तो हमें पता लगता है कि उनके वेतन में जो वृद्धि की गई है चपरासियों से कहीं ज्यादा है, अगर प्रपोरशन लगावें तो प्रपोरशन कहीं ज्यादा जाकर पड़ता है। चपरासियों को २५. १. ३५. में पांच रुपये की ग्रेड में तरक्की और १) वेतन में तरक्की मिली है तो आर. ए. एस को जिनकी ग्रेड पांच सौ तक थी और किसी की ग्रेड ७०० तक जाती थी तो उनकी ग्रेड १२०० तक पहुँच गई है। यह है असमानता को दूर करने का छोटा सा नमूना जो पेश करना चाहता हूँ और इस आधार पर कहा जाता है कि सोशलिस्टिक पेटर्न के आधार पर सोशलिस्टिक स्टेट बनाने जा रहे हैं और इसी तरह से यह सोशलिस्टिक स्टेट बन रही है। मैं निवेदन करूं कि इन स्लोगन्स से कोई फायदा नहीं है। हमको तो इन चीजों को कार्य रूप में परिणित करना चाहिए कि सोशलिस्टिक पेटर्न के आधार पर वेलफेयर स्टेट है या नहीं? वास्तव में हम ठीक जा रहे हैं या नहीं? सोशलिस्टिक पेटर्न

[श्री वेदपाल त्यागी]

में जहां तक हो सकता है एडमिनिस्ट्रेशन पर कम खर्च किया जाता है और वेलफेयर पर ज्यादा, और यही वेलफेयर स्टेट का मकसद है।

अध्यक्ष महोदय, मैं बताऊं कि अगर आंकड़े देखें जायं तो पता लगेगा कि बराबर पुलिस पर बजट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और बढ़ता ही चला जा रहा है। दूसरे जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट हैं उन पर भी बजट बढ़ता ही चला जा रहा है। आज हम पंचवर्षीय योजनाओं से गुजर रहे हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना समाप्त कर रहे हैं और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में पदार्पण करने वाले हैं, नई नई योजनाओं पर रुपया खर्च करना दिखाया गया है लेकिन जब उन को एडमिनिस्ट्रेशन से कम्पेयर करते हैं तो रकमें बढ़ती ही चली जा रही हैं और खास कर पुलिस पर। वेलफेयर स्टेट में लोगों की आर्थिक उन्नति करना और नैतिक उन्नति करना होता है और लोगों की उसी हालत में नैतिक उन्नति कर सकेंगे जब हम पुलिस का बजट कम कर सकेंगे क्योंकि उसमें पुलिस की कम जरूरत आवेगी। लेकिन यह नहीं है। जहां तक नैतिकता का प्रश्न है खुले आम मिसालें मौजूद हैं। वैसे तो माननीय मुख्य मन्त्री हंसते हुए जवाब देने के आदी हैं और आज वे हैं नहीं वरना मैं निवेदन करता कि कुशल वकील अगर वे होते तो, बड़ी कुशलता से वकालत कर सकते थे। अदालत में होते और अगर ऐसा करते तो सोसाइटी में स्थिति खराब होने वाली नहीं थी। वहां पर बड़े बड़े चोर, डाकू और अपराधियों का मुकदमा लड़ते और उन्हें बचाते क्योंकि आज के हमारे समाज में जैसी व्यवस्था है, वकीलों को अधिकार दे रखा है कि चाहे अपराधी हो या निरपराधी हो सब की वकालत करें। लेकिन यदि इस कुर्सी पर बैठ कर ऐसों की वकालत करते हैं तो यह घोर पाप है। वे सरमेनाइज करते हैं, हम यह नहीं करते हैं, वे करते हैं। वे कहते हैं कि ऐसा मत करो। मैं यह बताऊं कि आपके ये अभाव हैं, जो जनतन्त्र में नहीं रहने चाहिये। वे कहते हैं कि उनका कोई असर नहीं होता है। मुझे भर्तृहरि का श्लोक याद आ गया है। उन्होंने कहा कि कोई चाहे जितना संताप देवे लेकिन ऐसा संताप नहीं देवे कि मुझे श्लोक ऐसे आदमियों को सुनाना पड़े जो उसको समझते न हों। आज जो संताप लोगों को है, ऐसे लोगों को उनके अभाव बताते हैं लेकिन उन पर उनका असर नहीं होता। वे ऐसे बहरे कान हैं कि कितना ही गरम तेल डालें लेकिन कान खुलते ही नहीं। पिछली दफा साफ कह दिया था कि हम पर असर नहीं होने वाला है, आप बारबार जनतन्त्र की दुहाई देते हैं। शायद उन पर असर हुआ हो। यह एक तरीका होता है डेमोक्रेसी का, डेमोक्रेटिक सोसाइटीज की परम्परायें होती हैं कि जहां गवर्नमेंट की कमजोरियां हों वहां उनको बताया जाय कि फलां मन्त्री ने घोर अपराध किया, यह किया है वह किया है। सदन में ऐसा होता है, सदन में ही नहीं लोगों ने उनको बताया अखबारों में छपा है, उसका भी कोई असर न हुआ। अगर मैं भी उस स्टैंडर्ड पर आकर बात कह देता तो स्वभावतः कोई असर नहीं होता लेकिन ओपोजिशन में बैठने वालों के लिए परम्परायें चली आ रही हैं और जो कि आवश्यक परम्परायें हैं और अगर वे मैं समझता हूं कि अपनी ड्यूटी को ठीक तरह से अन्जाम न दें तो जनता के प्रति और अपने प्रति घोर अपराध करेंगे। इसीलिए हमारा कर्तव्य हो जाता है कि आपके जो अभाव हैं हम उनको बतावें।

[श्री वेदपाल त्यागी]

मैं यह निवेदन कर रहा था कि सोशलिस्टिक पेटर्न के आधार पर आधारित स्टेट के सामान्य प्रशासन, पुलिस पर कम खर्च करना चाहिये और लोगों की वेलफेयर के लिए अधिक। जब कि मुझे लगता है कि सामान्य प्रशासन पर दिन ब दिन खर्चा बढ़ता चला जा रहा है और खास कर पुलिस पर तो उसका एक मात्र कारण है कि नैतिक स्तर दिन ब दिन नीचे गिरता चले। नैतिक स्तर क्यों गिरता चला जा रहा है यह मैं आज आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहूँगा। माननीय मुख्य मन्त्री महोदय को गुस्सा आ गया था जब एक माननीय मित्र बोले थे कि हमारे यहां बलवन्त सिंह बैठे हुए हैं। मैं आज नाम बताना चाहता हूँ और स्पष्ट बताना चाहता हूं कि लोग बलवन्तसिंह क्यों समझते हैं ? यह ठीक है कि बलवन्त सिंह का अपराध यह है कि वह कानून को तोड़ता है और इस प्रकार से तोड़ता है कि वे लोगबाग उस को असामाजिक मानते हैं या एन्टी-सोशल मानते हैं। आप लोग भी कानून तोड़ते हैं लेकिन इस प्रकार तोड़ते हैं कि आपको कोई पकड़ न सके।

इसलिये अगर कोई फर्क हो सकता है तो यह फर्क हो सकता है वे एक असभ्य डाकू हैं और यहां बैठने वाले हैं वे सभ्य डाकू हैं।

कल एक महानुभाव ने बताया और उन्होंने यह चार्ज लगाया कल ही नहीं बल्कि इस सदन की फ्लोर पर यह चार्ज कई बार लग चुका है लेकिन माननीय अध्यक्ष, मुझे बड़ा खेद है कि माननीय मुख्य मन्त्री ने भी इस पर अपने विचार प्रकट नहीं किए कि आया जो चार्ज लगाया गया है वह सत्य है या असत्य। जिस वक्त यहां सदन में एक पत्र पेश किया गया था उस समय उन्होंने जरूर यह कहा था कि अगर वे पत्र मुझे देते तो मैं जानकारी करता। यह तो ठीक है कि आपको वह पत्र मिल जाता तो आप जानकारी करते। लेकिन यदि किसी ने वह पत्र हाउस में रख दिया या अन्य किसी तरह से आपको मालूम हो जाय तो क्या आप उसकी जानकारी करना पसन्द नहीं करेंगे ? क्या अजीब लॉजिक है यह मेरी समझ में नहीं आया। किसी भी तरह से आपके इल्म में अगर कोई बात आती है तो आपका कर्तव्य हो जाता है कि आप उस विषय में मालूम करें कहां तक उसमें सत्यता है और कहां तक असत्यता। दुनियां को धोखा देने के कई तरीके हो सकते हैं और वही तरीका यहां भी अपनाया गया उसी दिन मुख्य मन्त्री ने कहा एक मुकदमा चल रहा है वह किस बात का चल रहा है यह तो पता लगाने की कोशिश की है क्या ? मुकदमा सन् ५५ के मार्च के महिने में जब पत्र प्रकाशित हुआ जिस पर गरमा गरम बहस इस सदन में और इस सदन के बाहर भी हुई और उसी के फल स्वरूप हाई कोर्ट में नोटिस देते हैं। उस का नतीजा क्या होता है यह तो आप सब लोगों के सामने हैं वे महानुभाव मन्त्री पद से हटा दिए गये। और उस के बाद क्या होता है कि सदन में इस पर गरमा गरम बहस न हो इसलिये दफा ५०० की तहत मुकदमा दायर कर दिया जाता है। जिसकी पहली सुनवाई मार्च के प्रथम सप्ताह में होने को थी उसमें नोटिस पहुंचता है कि मुलजिम और गवाह हाजिर हों। होता क्या है जिन व्यक्ति ने मुकदमा दायर किया है वे गैर हाजिर होते हैं और इस कारण तारीख बदलदी जाती है। यह एक तरीका अपनाया गया है ताकि उस पर विचार

[श्री वेदपाल त्यागी]

विनिमय न हो सके ताकि सदन में या बाहर हम उस पर कुछ नहीं कह सकें इसी लिए यह तरीका अपनाया गया है। यह मुकदमा इस तरह से पांच साल चलेगा जितने दूसरे इलेक्शन भी आजायेंगे और उन महाशय को यदि टिकट नहीं मिलेगा तो पहले की तरह बिना कांग्रेस का टिकट मिले पहले जैसे चले आये वैसे फिर आजायेंगे। यह है नैतिक स्तर उन लोगों का जो आज राज्य की सत्ता अपने हाथ में लिये बैठे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूं वास्तव में सोशिलिस्टक पेटर्न के उसूलों पर अगर हम अपने राज्य का निर्माण करने जा रहे हैं तो आपको सबसे पहले अपने अन्दर छटनी करनी पड़ेगी और यह देखना पड़ेगा कि आपनें ऐसे लोग तो नहीं। जब आप विश्वास कर लें कि इस प्रकार के आदमी हैं जिसके पास सता रही तो अपना ही फायदा करेंगे ऊटपटांग काम करेंगे। इससे हमारा कोई फायदा नहीं होगा।

मैं यह निवेदन करूं कि डेमोक्रेसी में पुलिस के बल पर सरकार नहीं चला करतीं। जब तक लोगों को सरकार के प्रति विश्वास न हो, लोगो की सहानुभूति न हो, तब तक कोई भी सरकार कायम नहीं हो सकती खास तौर से उस सूरत में जब कि हम पन्चवर्षीय योजना को कार्यान्वित करने जा रहे हैं, जनता का करोड़ों रुपया पानी की तरह बहा रहे हैं तो ऐसे समय यह बहुत आवश्यक है कि लोगों की सरकार विश्वास सम्पादन करें लेकिन जब उन लोगों के सामने इस प्रकार की कहानियां आती हैं और सदन के समक्ष इस प्रकार की बातें आती हैं कि फलां फलां आदमी के जरिये फलां आदमी के लड़के को उड़ाया गया उसमें इतना रुपया लिया गया तो यह बातें ऐसी है जिनके कारण लोगों को आप पर विश्वास नहीं होता। इस तरह से आज हमारी सरकार लोगों का दिन प्रतिदिन विश्वास खोती जा रही है नतीजा इसका यह हुआ है कि लाखों करोड़ों रुपया जो योजनाओं पर व्यय कर रहे हैं वह बरबाद जाने वाला है।

पहली पंचवर्षीय योजना का विकास हमारे सामने है यह कहा जाता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में बहुत पैसा खर्च किया गया यह हम भी मानते हैं कि पैसा बहुत खर्च किया गया लेकिन सोचना यह है कि उस पैसे का रिटर्न क्या हुआ जो व्यय किया गया है उससे कितने लोगों को लाभ पहुंचा किसी ने आंखें खोल कर देखा या नहीं। चांदमलजी मेहता ने कल अपने भाषण में कहा कि यह पैसा इतना जो व्यय हो रहा है वह ताऊ, चचा, मामा, भतीजों और रिश्तेदारों में बांटा जा रहा है। मैं इससे भी अधिक यह कहना चाहता हूँ अगर वे अपने रिश्तेदारों को ही इसमें ले लेते तो हम समझ लेते कि राजाओं के राज में जिस प्रकार राजा लोगों के जितने भी रिश्तेदार होते थे उनका भरण पोषण उन्हीं के द्वारा होता था उसी प्रकार आज के ये ही हमारे राजा हैं यदि ये अपने रिश्तेदारों के भरण पोषण के लिये करते हैं तो इसमें एतराज़ ही क्या? लेकिन पोलिटीकल लेवल पर जो यह व्यय हो रहा है, उसे कभी उचित नहीं कहा जा सकता। मैं कोटा की बात जानता हूँ राजस्थान के चारों तरफ का हाल मुझे मालूम नहीं इसलिये मैं यह नहीं कह सकता अन्य हिस्सों में प्रोपोर्शनेटली काम ठीक हुआ है या नहीं यह मैं नहीं कह सकता। कोटा के लिये कह सकता हूं। पंच वर्षीय योजना में सरकार ने एक रोड रखी जब कोटा स्टेट थी उस समय

[श्री वेदपाल त्यागी]

से इस रोड की बहुत मांग थी अगर उस सड़क को बना देवें तो उससे हमारे कोटे का कनेक्शन एक ग्रेनरी वाले हिस्से से हो जाता है। जिस प्रकार की पैदावार गंगानगर के हिस्से में नहीं होती, जैसी इस इलाके में है, लेकिन प्रथम पंच वर्षीय योजना में वह रोड रखी थी जो ४८ मील की सड़क हैं जिसका १२ मील तक तो पहले से ही बना हुआ है ३६ मील और बनानी थी। पांच साल में इस रोड में केवल तीन मील की एडीशन हुआ है जो इटावा से दीपक तक बनी है यह हमारे इलाके में पंच वर्षीय योजना की सफलता है। जिस रोड की काफी अरसे से बराबर मांग रही है उसके प्रति हमारा रुख क्या है ? यदि माननीय मंत्री या उनके साथ बैठने वाले यदि कोई इसमें इन्टरेस्टेड होते तो यह रोड कभी की बन गई होती।

श्री सरदारसिंह—तीन मील तो बन गई यह भी गनीमत समझिये।

श्री वेदपाल त्यागी—क्योंकि उस इलाके से जो प्रतिनिधि आए हैं वे उनके साथ वाले नहीं, यह हमें साफ बताता है कि आपने प्रथम पंच वर्षीय योजना में किस प्रकार का रुख रखा है आपने हर कार्य में अपनी पोलिटिकल भावना का अपनी गुटबन्दी का ध्यान रखा है और उसी के अनुसार रुपये का व्यय भी किया है। अब मैं आपको यह भी बताऊंगा कि किस प्रकार की होती है पोलिटीकल गुटबन्दी और क्षेत्रीय भावना के आधार पर किस तरह रुपया खर्च किया जाता है वह रुपया इतना कारगर नहीं होता जितना रुपये के लगाने के बाद जितनी, सुविधा मिलनी चाहिये वह नहीं प्राप्त होती। इसका कारण यह है कि हमारी सरकार में ढीलापन आ गया हमारी सरकार इतनी मजबूत नहीं, उसमें इतनी नैतिकता नहीं इसलिये राज कर्मचारियों पर न तो उनका किसी प्रकार प्रभाव पड़ता है न वे नैतिक प्रभाव ही डाल सकते हैं आज एडमिनिस्ट्रेशन में इस कारण चारों तरफ ढिलाई ही ढिलाई नजर आ रही है। एक ओवरसियर एक दिन मेरे पास आए और मुझसे कहा कि आप गुलाबचन्द जी को कह दीजिये कि वे मुझे प्लाट दे दें। मैंने उनसे कहा आप शरणार्थी हैं और आपने पहले ही एक प्लाट तो बना लिया है फिर आप दूसरा प्लाट मांग रहे हो इतना रुपया आपके पास कहां से आया। तो उन्होंने जवाब दिया वे व्यक्ति मेरे एक मित्र के बहुत नजदीकी सम्बन्धी हैं वे मिलने वाले थे उन्होंने जवाब दिया और बताया कि उधर पंच वर्षीय योजना पं० जवाहरलाल नेहरू बनाते हैं इधर हमारी पांच पीढ़ियों की हम योजना तैयार कर लेते हैं। यह चीज हमें यह बताती है कि कितना अपव्यय हो रहा हैं जहां एक पंच वर्षीय योजना से पांच पीढ़ियों की योजनायें तैयार होती है तो अन्दाज लगा लिया जाय कितना व्यय होता होगा जिस काम के लिये रुपया दिया जा रहा है उसमें।

अब हम प्रथम पंच वर्षीय योजना समाप्त कर दूसरी पंच वर्षीय योजना में प्रवेश करने वाले हैं, तो हमारे सामने यह नक्शा होना आवश्यक है कि प्रथम पंच वर्षीय योजना में हमने यह तरक्की की इतने आगे बढ़ गये इससे हमारी आमदनी इतनी बढ़ गई। जहां मैं देखता हूं आमदनी तो कुछ बढ़ी नहीं पैसा खूब खर्च हुआ। बड़ी बड़ी योजनायें जरूर चल रही है जिनका कि लाभ हमें दस साल बाद मिलेगा। लेकिन माइनर इर्रिगेशन के जो वर्क हैं उससे तो तुरन्त लाभ

[श्री वेदपाल त्यागी]

मिल सकता है, उस पर तो लीपापोती तो नहीं हो सकती। जो रुपया व्यय कर रहे हैं उसमें बड़ा संकुचित दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है इसी लिये जितना नतीजा उस रुपये से मिलना चाहिये वह नहीं मिल पा रहा है।

अध्यक्ष महोदय, एक कांग्रेस के प्रमुख सदस्य ने कहा आज इतना ज्यादा भ्रष्टाचार फैला हुआ है कि जिधर भी आंख मीचकर हाथ बढ़ाता हूँ तो भ्रष्टाचारी के हाथ पर हाथ पड़ेगा। जब वे बोल रहे थे तो एक मंत्री महोदय जो उनके पास बैठे हुए थे कहा कि आप हाथ समेट कर रखिये तो उन माननीय सदस्य ने कहा अगर हाथ नहीं भी बढ़ाता हूँ और यदि आंखें मीचकर बैठता हूं और आंख खोलकर यदि सामने देखता हूँ तो पहले नजर भ्रष्टाचारी पर ही पड़ेगी।

मैं यह निवेदन करूं कि भ्रष्टाचार वास्तव में बहुत ज्यादा फैल रहा है और इसका कारण यह है कि हमारे मन्त्री मन्डल के कृत्य जो हैं वे ऐसे हैं इस प्रकार के हैं कि वे लोगों को प्रोत्साहन देते हैं कि वे स्वयं भ्रष्टाचार को प्रश्रय दें क्योंकि वे खुद भी भ्रष्टाचार में फंसे हैं। नाथद्वारा का मामला सामने आया। कुछ दिन पहले वहां के महाराज जिनसे कि उनके अनुयायी सख्त नाराज थे उन अनुयायियों ने तै किया कि महाराज के हाथ से प्रबन्ध हटा लिया जाना चाहिये, और एक प्रबन्धक कमेटी के हाथ में उसे दे देना चाहिये। सरकार के पास भी एक दो महानुभाव एप्रोच हुए। सरकार कस्टोडियन हैं उन ट्रस्टों की जो पब्लिक ट्रस्ट हैं। उन्होंने यह देखा कि हां यह ठीक है, वहां जो श्रद्धालु लोगों का रुपया आता है उसका अपव्यय होता है, जो पैसा मन्दिरों में श्रद्धालु लोगों से भेंट में आता है उसका दुरुपयोग होता है इसलिये कमेटी बनाई गई। उसमें वे लोग रखे गये जो उस मूर्ति के माने हुए भक्त हैं, उस मूर्ति के जो नाथद्वारा की मूर्ति कहलाती है। हमारे मुख्य मन्त्री नाथद्वारे से आते हैं इसलिये मैं यह नहीं मान सकता कि वे वहां की चीजों से पूर्णतया परिचित होंगे। किस प्रकार से लोग रुपया देते हैं, उसका किस तरह से उपयोग, सदुपयोग या दुरुपयोग होता है और भक्तजन प्रबन्ध में हाथ बटाते हैं यह वे जानते होंगे। पर थोड़े दिन हुए, सुना, वह प्रबन्ध कमेटी हटा दी गई। दूसरी कायम की गई और महाराज को जो अलाउन्स वगैरह मिलता था वह भी बढ़ा दिये गये। हो सकता है कि महाराज का अलाउन्स कम हो और उनको ज्यादा की आवश्यकता हो तो वह भी उस कमेटी में तै करते और बढ़ाना जरूरी था तो बढ़ा देते। किसी को इसके लिए कोई एतराज नहीं होता। पर ऐतराज तब होता है जब कि वह प्रबन्धक कमेटी तोड़ दी गई और उसके स्थान पर इस प्रकार की प्रबन्धक कमेटी बना दी गई कि उस संस्था की व्यवस्था पर महाराज पूर्णतया अपना स्वत्व हांसिल कर ले और जिस तरह से चाहे उस संस्था का धन बरबाद करें, उस पर कोई अंकुश नहीं रहे। तो ये ऐसी चीजें हैं जिनमें मुझे भी दुर्गन्ध आती है पास जाने पर। और यह सोचने को मजबूर होना पड़ा कि यह हुआ कैसे? उन लोगों को जो कट्टर भक्त थे प्रबन्ध समिति से निकाल किस तरह से दिये गये? तो उन लोगों को हटाकर दूसरे लोगों को बनाना और ऐसे लोगों को बनाना जिससे कि महाराज को पूर्ण स्वत्व मिलजाय उस धन को दुरुपयोग करने का, तो यह बात मेरी समझ में नहीं आई। नतीजा यह हुआ कि उनके वे भक्त जो बाहर रहते हैं और

[श्री वेदपाल त्यागी]

बहुत बड़ा हिस्सा भेंट के रूप में देते हैं और काफी असर रखते हैं, घबराये, उन्होंने पुकार की। और उनकी पुकार पर। इसमें गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया ने हस्तक्षेप किया और वह की वह कमेटी कायम रक्खी गई जो पहले थी। तो ये इस प्रकार की चीजें हैं जिनमें बू नजर आती है कि ऐसा होता क्यों है ? हमारे सामने शिकायतें आती हैं कि फलां कर्मचारी बहुत खराब है। उसके खिलाफ जांच होती है, जांच से कुछ नतीजा पाया जाता हैं उस वक्त सरकार निर्णय लेती है। चार्ज शीट बनाई जाती है, इसके बाद सरकार बदलती है और वह चार्ज शीट साफ बदल दी जाती है। उस आदमी का कुछ नहीं होता। बल्कि उसे वहां रख दिया जाता है जहां रह कर पहले कम खाता था पर वहां जाकर उससे ज्यादा खाता है और ज्यादा नाजायज फायदा उठाता है। तो ये बातें ऐसी होती हैं जिससे लोगों को शंका करने पूरी गुंजाइश मिलती हैं कि सरकार की नैतिकता और ईमानदारी की क्या कसौटी है ? बेईमानियां और भ्रष्टाचार ऊपर से चलता है जो ऊपर से नीचे की तरफ बहता है और फैलता है। ईमानदारी भी ऊपर से चलती है। पर अगर आप पटवारी को एक को पकड़ उसे सजा दे दें और यह सोचने लगें कि इससे रिश्वत रुकेगी और यह समझें कि रिश्वत को रोकने का काम कर दिया तो यह सही नहीं है। जिन लोगों की दूसरे लोग कापी करते हैं अगर उनमें सुधार करेंगे तो वास्तव में वह सुधार कहलावेगा और चलेगा।

हमने देखा कि यहां कुछ किताबों के लिए यह तय किया गया कि उनको नेशनेलाईज़ किया जावे। नेशनेलाइज को करने के बहाने यह बात प्रचारित की गई कि किताबों का नेशनेलाईज किया जावेगा। अब जो लोग उन किताबों से हजारों हजार रुपया सालाना फायदा उठाते थे वे घबराये यह खबर सुनकर और भागे भागे आये सरकार के पास। साठ हजार रुपया, सुना जाता है कि, दिये गये और नेशनेलाइजेशन खत्म हो गया। अब आप यह कहिये कि एक आदमी ने एक लड़के को उड़ाकर पचास हजार रुपये वसूल कर लिये और दूसरे ने यह प्रचारित करके कि नेशनेलाइजेशन करके तुम्हारी पचास हजार, साठ हजार या लाख रुपये सालाना की आमदनी को खत्म कर देंगे और ६० हजार रुपये वसूल कर लिये और नेशनेलाइजेशन की बात को खत्म कर दिया वह साठ हजार रुपया पकडा नहीं जाता। वह पचास हजार रुपया लड़के को उड़ाकर ले गया वह बलवन्तसिंह कहलाता है और अगर वास्तव में कहलाया जावे तो सभ्य बलवन्तसिंह इस तरह के यहां भी बैठे हैं। पर इन के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जाती। बल्कि इन्हें प्रोटेक्शन देने से ही यह सरकार कायम रह रही है। जब कि उस बलवन्तसिंह के खिलाफ सारी पुलिस फोर्स लगी हुई है।

मैं बताऊं पिछले बजट अधिवेशन में प्रस्ताव रक्खा गया था माथुर साहब के खिलाफ। उनके खिलाफ जब चिट पेश हुई तो प्रस्ताव रखा गया कि इसकी खुली जांच होनी चाहिये और सरकार की कमेटी के द्वारा जांच होनी चाहिये जिसमें संसदीय परमम्पराओं को कायम रखने के लिये माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने आश्वासन दिया कि इस मामले की जांच करके और अध्यक्ष महोदय को कॉनफिडेन्स में लेकर सदन के सामने उस जांच का परिणाम रक्खेंगे। पर निवेदन करूं कि साल भर का अरसा गुजरने को आया, न जांच की गई न कुछ किया गया। हां एक चिट्ठी जरूर आई थी

[श्री वेदपाल त्यागी]

मेरे पास और मैंने उसका जवाब भी दे दिया कि आप फाइल देख लीजिये। मैं फाइल से ही साबित कर दूंगा। एक्स इविडेन्स की जरूरत नहीं। फाइल ही सब कुछ बोल रही है आप जो कारण देते हैं वह तो पहले ही रिपोर्ट आ चुकी थी लैटर बाद में लिखा गया। जब रिपोर्ट पहले ही आ गई थी तो फिर लैटर लिखने की क्या जरूरत पड़ी, मैं यह नहीं समझ पाया। लैटर लिखा गया फिर किस उद्देश्य से। पर आज यह सारा मामला दबाया जाता है और अगर कोई शिकायत करता है तो उनसे कहा जाता है कि यह शिकायत बेजा है। मैं निवेदन करूं उस दिन एक सज्जन ने बोलते हुए, यद्यपि मैं यह कहूंगा कि वह आवेश में या रोष में बोल रहे थे, इस सरकार को नाज़ी सरकार कह दिया और उस पर मुख्यमंत्री महोदय ने जवाब देते हुए यह कहा कि नाजी सरकार कहने से पहले वे नाजीज्म को स्टडी कर लेते तो नाजी सरकार इसे नहीं कहते लेकिन जवाब में जो कहा वह यह बात कही कि आप हमको नाजी सरकार बताते हैं पर हमारे यहां इतने एजीटेशन हुए पर हमने एक बार भी गोली नहीं चलाई। अगर गोली न चलाना ही सिर्फ इस बात का द्योतक है कि आप नाजी नहीं हैं और जहां गोली चले वह नाजी सरकार है तो पं० जवाहरलाल नेहरू की सरकार के लिए आप क्या कहेंगे जिसने सन् ४६ में कबायलियों पर बम बरसाये थे। मैं समझता हूँ कि सरकार जो लोग चलाते हैं उनको मौका पड़ने पर गोली भी चलानी पड़ती है।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—आज बम्बई में बड़ी गोलियां चलीं, और और जगह भी काफी चली हैं।

श्री वेदपाल त्यागी—हां तो इस माने में तो मुरारजी तो सबसे बड़े नाजी कहलावेंगे जो कि बम्बई में काफी गोली चलवाते हैं। पर यह नाजी सरकार होने न होने का मापदण्ड नहीं है कि किसने कितनी बार गोली चलाई। आप गोली तो इसलिये भी नहीं चलाते कि आप हर मौके पर दब जाते हैं, एजीटेशन का मुकाबला करने की आप में हिम्मत ही नहीं है। आप एजीटेशन का का मुकाबला नहीं कर सकते। जयपुर में एजीटेशन हुआ उसमें दबे, हाउस टैक्स और आक्ट्राय के लिये। जयपुर में आपने फिर एक बार यह विज्ञप्ति जारी की कि धन तेरस से आक्ट्राय लगेगी। पर नहीं लगी उस दिन और आप फिर दब गये और उसे पोस्टपोन कर दिया। तो यहां गोली न चलने का कारण तो यह है कि एजीटेशनों का मुकाबला आप सरकार के स्तर से नहीं करते। हमेशा इस बात की कोशिश करते हैं कि किसी तरह से मामला दबा रहे तो अच्छा है।

तो जैसा मैं निवेदन कर रहा था वह चिट्ठी जो माननीय हमारे विरोधी दल के नेता ने पेश की उसके लिये पहले यह कहा गया कि ऐसी कोई चिट्ठी नहीं लिखी गई पर जब वह चिट्ठी सदन में पेश हो गई तो तब भी बड़े कुशल वकील की भांति मैंने लिखा है या नहीं यह साफ नहीं कहा केवल उसको एक्सप्लेन किया गया, और बाद को जब रेजोल्यूशन पेश हुआ तो उसी प्रकार एक्सप्लेन फिर किया गया और कहा गया कि यह मामला इस प्रकार का है कि जिस पर चर्चा नहीं की जा सकती थी। न करते चर्चा आप। चिट्ठी जब लिख दी थी तो आपकी नैतिकता का यह तकाजा था कि आपको स्वीकार करना चाहिए था कि चिट्ठी मैंने लिखी है और इन हालातों में लिखी है।

[श्री वेदपाल त्यागी]

पहले मना कर देना, फिर एक्सप्लेन करना, और उस वक्त भी यह नहीं कहना कि मैंने लिखी है या नहीं यह सब इस बात के द्योतक हैं कि आप दल चलाने के योग्य नहीं है। पर जिस सरकार में हमारे उन अधिकारों पर, उन बुनियादी अधिकारों पर, जिन अधिकारों की रक्षा की गई है हमारे संविधान में, अगर हमला होता है तो वह नाजी से भी बदतर सरकार है। क्योंकि बुनियादी अधिकारों की रक्षा करना सरकार का परम कर्तव्य है।

मैं यह निवेदन करूंगा कि चाहे उन्होंने आवेश में कह दिया हो लेकिन जिस प्रकार के कृत्य हमारी सरकार के हमारे सामने आते हैं उन पर सरकार को किसी तरह से कोई भी कांग्रेच्युलेट करने वाला नहीं है, बधाई नहीं दे सकता। उस दिन हमारे मुख्य मंत्रीजी ने मुझ पर कहा कि मैं उसका भी उल्लेख कर देना चाहता हूँ कि मैं वह व्यक्ति हूँ कि जिसने जयनारायणजी को कटहरे में खड़ा किया था, और आज मैं उनको मुबारकबाद दे रहा हूँ। आप शायद मेरी बात को समझ नहीं पाये। उनके इस परीक्षण से मैं तो पहले ही सहमत नहीं था और न मैं आज हूँ। मैं चाहता हूं कि एन्टी शोसल एलीमेन्टस के साथ में इस प्रकार का बर्ताव नहीं होना चाहिए कि जिससे दूसरे लोगों को गलत प्रेरणा मिलती हो। जो उन्होंने परीक्षण किया है यदि उसमें उनको सफलता मिलती है तो वे जरूर बधाई के पात्र होंगे। शायद आपस के जो आजकल सम्बन्ध हैं, यद्यपि वे व्यासजी को समादृत करते हैं पूजनीय व्यासजी, लेकिन जो उनके सम्बन्ध है उस बात को टालरेट नहीं कर सकते हैं कि उनको सफलता मिले। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यदि आप भी अच्छा काम करेंगे तो हम आपको बधाई देंगे और खराब काम करेंगे तो आपका भी इसी तरह से विरोध करेंगे जैसा कि व्यासजी का विरोध कर रहे हैं।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—व्यासजी के जाने के बाद।

श्री वेदपाल त्यागी—यह बृजसुन्दरजी अच्छी तरह से समझते हैं, जैसा कि उन्होंने कहा है। माननीय अध्यक्ष, मैं आपसे एक दो बातें और कह देना चाहता हूँ और वह यह है कि यह कहा जाता है कि हम बड़े व्यापक दृष्टिकोण से इन योजनाओं को बना रहे हैं और योजनाओं को क्रियान्वित कर रहे हैं। मैं ही नहीं वरन् यहां के बहुत से लोग इस बात के लिये साक्षी हैं कि व्यापक दृष्टिकोण नहीं है, बल्कि ग्रुप पेटर्न के आधार पर यह बनी है, ग्रुप भावना से यह बनी है। एक मिसाल आपको देना चाहता हूँ। पहली पंचवर्षीय योजना हम समाप्त कर रहे हैं लेकिन उस कन्स्टीटुएन्सी में जिससे कि मैं आया हूँ माननीय मुख्य मंत्रीजी भी शायद इस बात की गवाही देंगे कि आपने एक पाई भी वहां खर्च नहीं की। हालांकि छबड़ा एक सब-डिवीजन का हैडक्वार्टर है और यह वह स्थान है जहां से काफी अनाज हमें मिलता है वहां एक ९ मील की सड़क बनाने की योजना थी लेकिन वह इसलिये नहीं बनी कि वहां से मैं रिटर्न होकर आया हूं। मैं इस बात को इसलिये कहना चाहता हूं कि हमारी कांग्रेस के प्रेसीडेन्ट पी. सी. सी. के वहां गये और कहा कि आपने एक गलत आदमी को वोट दे दिये। हमारे वित्त मंत्री भी कहते हैं कि आपने गलत वोट दे दिये। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि वह गलत आदमी भी आपके द्वारा मनोनीति किया गया था। अगर

Page No.40

[श्री वेदपाल त्यागी]

आज आप उसको नहीं चाहते हैं तो उसका आप उन लोगों को दंड क्यों देना चाहते हैं जिन्होंने कि आपके कहने पर कांग्रेस को वोट दिये। अगर यह मान लिया जाय कि वे कांग्रेस को वोट नहीं देते, तो क्या यह बर्ताव ठीक है कि आप कोई भी ऐसा काम वहां नहीं करें और इसलिये नहीं करें कि वहां से जो भी आदमी रिटर्न होकर आया है वह आपकी कमियों को खुले रूप से आपके सामने रखता है, और बताता इसलिये नहीं कि आपसे दुश्मनी है, बल्कि इसलिये कि वह उसका कर्तव्य है। अगर डेमोक्रेसी में अगर अपोजिशन भी इस तरह से आप लोगों की खुशामद करने और अपनी जबान को दबा बैठे तो मैं समझता हूं कि फिर तो आप कामयाब हो गये। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि यह जो ग्रुप पेटर्न है, यह जो संकुचित भावना है इसको आपको दूर करना चाहिए और दूर करके व्यापक दृष्टिकोण अपना कर काम करना चाहिए। यह कहा जाता है कि मैं सेरेमोनाइज करने का आदी हूँ, लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि माननीय मुख्य मंत्रीजी सेरेमोनाइज करते रहते हैं और इस रूप में करते रहते हैं कि उस दिन की बात भी साफ कर दूं कि मैंने जाट का नाम नहीं लिया, अलबत्ता यह जरूर है कि मैंने तहसीलदार को मारने वाले दो आदमियों का नाम जरूर लिया है। वह कौन हैं और कौन नहीं, यह मैं नहीं जानता, लेकिन चोर की दाढी में तिनका हुआ करता है। इसलिये वह हमेशा इस तरह से जो भी बात कही जाती है कि 'जाट' का नाम लेते हैं तो इससे बहुत बड़ी खिलाफत फैलती है, इसकी प्रतिक्रिया होती है इसलिये नहीं कहना चाहिए। मैं निवेदन करूंगा कि मैंने यह कहा या नहीं कहा, उसकी प्रतिक्रिया हो या न हो, लेकिन आप जो काम करते हैं वह इस भावना से करते हैं और उसकी प्रतिक्रिया होती है, बल्कि उन लोगों में होती है जो इसके शिकार होते हैं। पंचायत क्षेत्रों में, मैं मानता हूँ कि पंचायत मिनिस्टर साहब जो हैं वे भी इस बात से डिससेटिसफाइड होंगे कि वहां पर जो काम हो रहे हैं वह इस प्रकार की भावना से हो रहे हैं लेकिन चूंकि वह आपको सूट करती हैं इसलिये आप उच्च स्तर पर उसको सुरक्षा देकर दबाना चाहते हैं। मैं यह नहीं कहता लेकिन वह बात जरूर कही जायगी जो महसूस होगी। वह हरेक व्यक्ति को कहना चाहिए चाहे उसका नतीजा कुछ भी हो। आपने कहा कि लोगों में दुश्मनी फैल सकती है तो वह दुश्मनी तो आपके कृत्यों के आधार पर पहले ही फैल चुकी है। हमारे कहने से यदि वह कुछ कम हो जाय तो आपको हमारा शुक्रिया अदा करना चाहिए बजाय इस बात के कि आप हमें यह शिक्षा दें। इसके अतिरिक्त मैं बजट पर एकाध बात और कहना चाहूँगा।

(घंटी)

श्री अध्यक्ष—टाइम का खयाल रखें।

श्री वेदपाल त्यागी—मैं दो तीन मिनिट में ही खत्म कर दूंगा। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना को मैंने देखा तो लेबर डिपार्टमेंट और कोऑपरेटिव का मुझे पता लगा कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना को क्रियान्वित करने का आपका प्रोग्राम है वह अगर आपने कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट को ठीक नहीं किया है तो आप उसको पूर्णतया पूरा नहीं कर सकेंगे। इसमें, इन योजनाओं में सबसे बड़ा भाग कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट का है, लेकिन आपने इस डिपार्टमेंट को एक अखाड़ा बना दिया है उन लोगों

[श्री वेदपाल त्यागी]

के लिये जिनको कि आप पेट्रोनाइज करना चाहते हैं। एक आदमी को रखा और फिर उसको निकाल दूसरे को रखा, तीसरे को रखा और उसको निकाला फिर चौथे को रखा। यह एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें टेक्निकल नालेज की बहुत आवश्यकता है। हम देखते हैं यू० पी० या पंजाब में कि जिस किसी आदमी को चाहे वह आई. ए. एस. या यू. पी. सरविस का हो उसको मुकर्रर कर दिया जाता है तो वह चलता रहता है और उसको वहीं पर तरक्की दी जाती है लेकिन यहां पर यह कहा जाता है कि वह आई. ए. एस. की जगह है दूसरे को रखेंगे। कभी यह कहा जाता है कि आर. ए. एस. की जगह है इसलिये आई. ए. एस. को नहीं रखेंगे। यह एक अखाड़ा बना रखा है कि जिनको पेट्रोनाइज करना चाहते हैं इस डिपार्टमेंट में भेज देते हैं जो कि इस डिपार्टमेंट की टेक्निकेलिटीज को नहीं जानते हैं। अभी जो इसका अध्यक्ष नियत किया गया है वह एक साल के बाद रिटायर हो जावेगा इस तरह के लोगों को आप रखकर फायदा उठाना चाहते हैं तो गलत है। मैं निवेदन करूंगा कि इसको अखाड़ा नहीं बनाया जाय, उन लोगों का, जिन लोगों को आप पेट्रोनाइज करना चाहते हैं। इसलिये ऐसे व्यक्ति रखें जो यहां के काम को कर सकें और इस डिपार्टमेंट में कुछ कर सकें। मैं निवेदन करूंगा कि उस डिपार्टमेंट की जानकारी रखने वाले बहुत कम लोग हैं। यह डिपार्टमेंट एक टेक्निकल डिपार्टमेन्ट सा है। यह एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट नहीं है। इसमें टेक्निकल नालेज की आवश्यकता है। लेकिन उसकी जानकारी रखने वाले बहुत कम लोग हैं। इसलिये इस डिपार्टमेंट को इम्प्रूव किया जाय अगर वास्तव में हम किसी तरह से इस योजना को सफल बनाना चाहते हैं।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी—मि० स्पीकर सर।

राजा श्री मानसिंह—अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष—श्री विश्वम्भरनाथ जोशी।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी—Mr. Speaker, Sir.

श्री अध्यक्ष—Brevity is the soul of wit.

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी—I wish to make a few observations on the annual financial statement made in the House by the hon'ble Finance Minister a few days ago.

एक माननीय सदस्य—Hindi, Hindi. Speech in Hindi wanted.

श्री अध्यक्ष—The hon'ble members has a right to speak in English.

एक माननीय सदस्य—For whom he should speak in English ?

श्री अध्यक्ष—For all those who are concerned. Let us welcome the speech in English.

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी—Hon'ble the Finance Minister has in the very second paragraph of the statement said that the country's goal is the attainment of a socialistic pattern of Society and it has been accepted that the objective of our economic and social policy should be the attainment of this goal.

So far I have no quarrel with him. We, Sir, who are here on behalf of various political parties are here to implement the policies of our respective parties and those on whom the burden of running the government falls are expected to implement the economic policy of the party to which they belong. It is no secret that the Congress Government has accepted to carry out and to implement the economic policies laid down by the Congress Organization and the All India Congress Committee.

The essence of socialism is the removal of disparities of income. Very recently the Rajasthan Government has announced the revision of pay scales. It would have been much better had that revision been announced on the floor of the House but some how or the other this was not done. A provision is sought to be made in this budget which we are required now to pass for the implementation of that revision of pay scales and in being required to pass this budget we are called upon to set the seal of our approval on the pay scales recently annonnced by the Government. These pay scales, as amply demonstrated by a number of examples given in details yesterday by hon'ble members of the treasury benches as well as members of the opposition, tend to further widen the gap which is already a wide one existing between the salaries of various cadres of government employees. It is no secret, Sir, when I state that the announcement of the pay scales has aroused a great deal of dis-illusionment, bitterness, frustration and deep resentment amongst the low paid staff of the Government which were expecting some sort of substantial relief by way of a wage increase. Sir, the tragedy of this action has been further hightened by the unfortunate fact that my hon'ble friend the Finance Minister happens to be a gentleman who was at one time associated with the Trade Union Movement, who used to be regarded as a labour worker, a labour Leader. Naturally therefore, the employees were entitled to expect from him some sort of substantial relief, entitled to expect from him that atleast some attempt will be made to reward them for the very hard and loyal services which they are rendering. But a very substantial increase in salaries is said to have been given to those who are enjoying good salaries already. I have no grievance against making any increase in the salaries of those who are having good scales of pay but my only sub-

[श्री विश्वम्भरनाथ जोशी]

mission is that the man who has not enough to feed, to educate, whose children are dying of pneumonia because he cannot afford to purchase penicillin, the man who cannot send his children to college or school because he has no money to pay fees it is he, Sir, who is entitled to expect some sort of relief. We have also in mind, Sir, that ultimately it is these low paid staff, it is these poor people, these low wage earners on whom the burden of every Five Year Plan falls and who are in fact the back bone of an economy. If they are neglected, I have to say that it is bound to create a widespread resentment in the society. It is no secret, Sir, that the Finance Minister has aroused an all round resentment, dis-satisfaction, and dis-illusionment. He has failed in every respect but he has succeeded in one respect. He has succeeded in bidding good bye to socialism, good bye to Gandhism good bye to Avadi and good bye to Amritsar. We are here on behalf of a political party which has accepted the socialistic pattern of society and we should not be dis-loyal to our election pledges and the congress manifesto. This budget has further widened the gulf of disparity of incomes. This budget is grossly against this policy. This budget is a negation of this policy and therefore if we are expected to support this budget, I am sorry to say that hon'ble Finance Minister is expecting us to do a thing which we are not prepared to do and unless the Government is prepared to announce that they are prepared to make a very substantial adjustment in the wage increasements that they have announced, I think it would be very difficult for the conscience of a Congressman to support this budget. It is a total negation of the economic policy as laid down by the All India Congress Committee at Avadi and Amritsar.

One important thing more, Sir. We are having increased allotment from the Central Government in respect of Five Year Plan, in respect of development schemes but the pity is that we are unable to utilize properly within the time limit the amount allotted to us. A sum of Rs. Thirty one crores has been allotted to us in the First Five Year Plan. Now we learn that about Rs. four crores are to lapse because the government machinery could not make necessary plans in time. They could not implement the schemes on account of the inefficiency of the government machinery. The State will now have to lose a sum of Rs. four crores. We could not utilize this amount in time. Still in para 42 of the statement the hon'ble Finance Minister has chosen to express satisfaction over the performance of the government machinery and he has in a way congratulated them. I have only to say that this satisfaction is entirely unjustified. When we have not been able to utilize Rs. thirty one crores during the first five year plan

[श्री विश्वम्भरनाथ जोशी]

period, how can we say that we would be able to utilize a far greater allotment of Rs. one hundred one crores wich is being made to Rajasthan within the same period of five years. I am very apprehensive that this time too the amount would lapse as a result of the inability of the government machinery unless steps are taken in the meanwhile to remedy the state of affairs.

Now, Sir, coming to the working of the various departments of the Government I have few more observations to make in respect of the Public works Department. I am constrained to observe that such things as community projects; roads, etc., are now the subject matter of politics. Road alighments are changed on account of political considerations. As for instance there is the case of Baswa Road. This road, Sir, during the past three years has undergone many changes on account of allignments. The State Exchequer has had to incur a wasteful expenditure of about Rs. 60,000/-on account of very frequent, unwarranted and unjustifiable allignments, made in defience of public opinion inspite of the numerous representation of the local public and my representations to the minister-in-charge of that portfolio.

Regarding agriculture, Sir, I have to say that the working of the department is more academic and demonstrative in nature. When the Government is not able to run on economic lines the divisional state managed grass farms, dairy farms and agricultural farms, how it can at all set an example for the poor farmer who has not got resources which are at the disposal of the state and the experience and know how which a Government can command in modern days. So when the Government working with highly paid officers and with all its material resources, are not able to run its own farms on economic lines, we are setting a very poor example before the farmers of the State. The Agriculture Department, therefore, needs an over-hauling.

Coming to the Education Department I have to state that atleast eight or nine years have elapsed since we got independence of the country and it was agreed that the education policy of the nation requires a very thorough and drastic revision. It was stated that the previous education policy was chosen to create an army of clerks and indeed it was a fact. Education must be harmonized with needs of the society and since the needs of the society and since the needs of an independent nation are different from a dependent nation, the education policy in our contry needs to under go a radical change. Education is a provincial subject and if we are waiting for the lead by the Centre, it would be waiting in vain. The Central

[श्री विश्वम्भरनाथ जोशी]

Government knows that the change in the educational policy must come from the provincial government. As we all know in the field of education we are still continuing along the old path. I have to submit that the mere chnage of text books does not mean any change of educational policy. The system of examinations is very defective and it also requires a radical change. As regards vocational education I have views of my own which I wish to express. Of-course it was necessary to give a vocational bias to the education because the education should help people to earn a decent living. It should also be able to create respectable citizens who are prepared to serve the country. Keeping in view the cultural and artistic traditions of this country if we think that merely by giving a technical or vocational training, we shall be improving things and we shall be doing all that is needed, it will not be proper. India, Sir, has been a country which has always bosted about its philosophers, its scientists and its thinkers. If, therefore, instead of producing philosophers, scientists and thinkers our, educational system aims only at producing carpenters and blacksmiths, I think, it may not be a desirable change. It will also not bring any progress in the country. Therefore, my submission is that the literal aspect of education should very attentively be kept in view and not neglected for the sake of giving a vocational bent to the education. Further, unfortunately, although there has been a quantitative improvement in the field of education in as much as we have been able to open a number of primary schools, raise middle schools to higher secondary standard and open a number of intermediate colleges but there has been a qualitative deterioration which is very deplorable because it is the quality which matters. The reasons for the qualitative deterioration are administrative. The personnel of the Education Department is very defective in as much as a teacher is appointed irrespective of the fact whether or not he possesses the qualifications which are necessary for a teacher. Holding of a degree is not in any way the real qualifcation of a teacher. A large number of the teachers regard the teaching profession as a stepping stone to better their own careers. They are always engaged in private studies. They want to pass the examinations and therefore neglect the studies of their students. The result is that they go away as soon as they are able to leave this department and join better careers with the result that the condition of the department goes from bad to worse. I think the hon'ble Minister for Education should have a thorough knowledge of the department and he should be conversant with the present state of affairs but

[श्री विश्वम्भरनाथ जोशी]

unfortunately during the last five years there has not been any improvement in the state of affairs in the Education Deptt.

Coming to the Police, Sir, I am constrained to observe that this particular department happens to be one which is least affected by the change, vast changes brought about in this country after the coming of indepenence. The Government has require that police Sub-Inspectors should keep a board in front of their police station reading, "May I serve you", or, "May I help you". Now the kind of help that is given to the villagers. Let me tell you, is that the police is always eager to extert the maximum amount of money. They say that torture is prohibited by law. But let me tell you that it is still practised, it is still in vogue. The amount of recoveries is very poor and the treatment is most undesirable and objectionable. The villagers are ignored, mal-treated and not attended to. There are a large number of cases in which reports of cognizable offences are not entered. Then at the prosecution stage, I may say, that a very large percentage of police cases are dismissed in courts because invariably the probable prosecution witnesses are won over by the accused and instead of serving the cause of prosecution the police officers are more eager to serve the cause of the defence. Moreover, the police is not at all working under the control of the magistracy. Lower magistracy has no power of supervision over the work of the policemen who are expected to carry out the instructions, serve summons and warrants of their courts and therefore the administration of criminal justice is also in a very bad state of affairs because the police is not at all obedient to serve the magistracy.

As regards the efficiency of the police I have to say that thay have not been provided with the modern methods of investigation and modern know how has not been imparted to the police personnel and they are left without any method at all because they have been prohibited to use third degree methods and first degree methods are not known to them. The result is that confusion is prevalent in the police department.

Sir, I shall be failing in my duty towards my own constituency as well as many other constituencies if I do not bring about the partial manner in which some of the development schemes are carried out. All the years of the First Five Year Plan have passed and not a single National Extension Block or Community Development Area has been allotted to my particular sub-division viz, Dausa Sub-Division which has four Tehsils. The Govern-

[श्री विश्वम्भरनाथ जोशी]

ment has also converted 25 high schools into multi-purpose high schools but not a single school has been chosen for being converted out of twelve high schools in my particular sub-division. These are only illustrative examples which could be multiplied adinfinitum. Even in the matter of development schemes in which field we are expected to be above the feelings of group loyalties and party loyalties, we have not been able to rise to the occasion and here too particular selected areas are favoured in the matter of allotment of community development blocks and N. E. S Blocks and a great deal of harm is being done. I am constrained to observe that there is an utter and gross favouratism in the matter of development work, in the matter of N.E.S. blocks as well as gross examples of undue interference in the construction of roads and the political considerations influence the changes in the road alighments.

I wish to raise this point before the Central Government, the States Ministry which has a constitutional duty of superintendence over part B States, the Planning Commission itself.........

श्री अध्यक्ष—You are administering a threat to the House.

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी—I am only giving notice of my intention on the floor of this House.

श्री अध्यक्ष—I think you are coming to a close by these observations.

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी—Yes Sir. I am coming to a close.

Coming to local development works, Sir, I have to say that the amount ear-marked is grossly inadequate. This is one sphere in which we are having double the work of the amount spent because if there is an allotment of Rs. 100/- for work in a particular village, that amount will be spent only when the village contributes an equivalent amount and therefore we have having double the work. There is no scope of wastage and corruption and the money being utilized by the accredited representatives of the people and also the district officer who is directly responsible for the programme of construction, if the Government had been able to allot more and sudstantial amounts under this head, that would have been in the way of rendering a very useful service to the province. But where very large

[श्री विश्वम्भरनाथ जोशी]

grants are being made available at other places for local development works which are very necessary and very useful part of government activity, a very poor amount has been allotted and the various district development committees are just left to do, what they can out of the amount that would be placed at their disposal. I understand that a sum of Rs. eleven lacs had been asked for Jaipur District for the ensuing year. But now they say that the total for the whole of Rajasthan is Rs. thirteen lacs. So obviously it would not be possible to allot Rs. eleven lacs to one district viz. Jaipur district. I wish that the grant under this head be enhanced considerably.

Secondly I have to say that we......

श्री अध्यक्ष—It is yet secondly going on and not the ' last '.

श्री विश्वम्भर नाथ जोशी—However, Sir, I have to state that we talk much about village people, about meeting their difficulties, perhaps also sympathize with them, when we are reminded that the soul of India resides in villages. At the same time the grant made for the village panchayats which must be strengthened financially and in every other respect because if the villages are to be self governing units which are able to carry on their own affairs, then I have to say that the grant of Rs. thirteen lacs for about three thousand panchayats of Rajasthan is grossly inadequate and desires to be enhanced. Moreover, Sir,

श्री अध्यक्ष—You keep something for others also.

श्री विश्वम्भर नाथ जोशी—In the matter of government advertisements the same tale of favouritism and red tapism could be repeated. Government advertisement regarded as a price for the persons who are prepared to sing the songs of those who for the time being compose the ministry. Those papers which flatter and which are prepared to sing the songs of those who are in power, are given money from the public exchequer. The merits of those respective papers are ignored weeklies with hardly any circulation. hardly any standing are given government advertisements to the tune of thousands whereas old, established and large circulation papers are totally ignored. Why this discrimination ? Simply because they are not prepared to sing the songs of those who happen to compose the ministry.

[श्री विश्वम्भरनाथ जोशी]

I have a lot to say, Sir, but in view of the paucity of time I wish to conclude by saying that atleast as a true congressman I have not been able to find in the budget any step towards the socialistic pattern of society.

श्री मुक्तिलाल मोदी—माननीय अध्यक्ष, मैं कई दफा खड़ा हो चुका हूं बोलने के लिये।

श्री अध्यक्ष—आपको कई दफा बुलाया, लेकिन आप नहीं थे।

श्री मुक्तिलाल मोदी—पचास आदमी बाहर बैठे थे।

श्री अध्यक्ष—Order please !

श्री मुक्तिलाल मोदी—इस बात का फैसला कर दीजिये।

श्री अध्यक्ष—Order please !

(शोर गुल एवं घन्टी)

श्री मुक्ति लाल मोदी—माननीय अध्यक्ष,....

श्री अध्यक्ष—Order please !

(घन्टी)

Have patience, धीरज रखिये।

श्री मुक्तिलाल मोदी—कल भी ११॥ बजे था।

श्री अध्यक्ष—८॥ बजे से १ बजे तक बैठते हैं, उनको टाइम मिलता है। बीच में आते हैं, जाते हैं; उनको नहीं मिलता।

श्री मुक्तिललाल मोदी—बीच में आता जाता........

श्री अध्यक्ष—Yes, Raja shri Man Singh

राजा श्री मानसिंह—During the last year and most probably...

श्री अध्यक्ष—Honble member will please Concentrate on the mike so that the reporters may be able to catch.

राजा श्री मानसिंह—(अश्रव्य)....My statement, Sir, is not entirely evasive.

Since the merger of the former Bharatpur State in the former Matsya and later in Rajasthan there has been no industrial improvement, there has been no improvement in the Power House, there has been no implementation of Water works scheme although these have been provided in the fromer State Budgets. and vague promises have been made by our leaders but there has been no proper maintenance of roads, no proper Management of irrigatien works, no inprovement in education, no proper functioning of the Bharatpur Municipal Board, no proper building for the college, no sufficient funds have been provided for development schemes and as compared to other areas there are no city improvement schemes. Besides no proper distribution of good seeds from the Agriculture Department to farmers, no proper veterinary facilities, no improvement in the hospital which could easily be raised to 'A' class hospital and no proper supervision of back ward class welfare schemes have been made. There are so many things, Sir, which I would tell you, that have not taken place in Bharatpur. However. Sir, after mentioning a few itemes fifteen in number to be enact I hope the Government would do its best to rectify this policy. We have been told, Sir, that this Budget will be a deficit budget to a tune of Rs. 1,70,00,000. I do not quite agree with these figures. If you look to the Budget under head 'famine' you will kindly see that although we provided in the budget a sum of Rs. twenty lacs approximately, the actual expenditure usually exceeds fourty lacs rupees. If this happens to be the case this year, this budget will have the deficit of more than rupees two crocres.

Similarly, the Budget presented before the House last year showed a deficit of a few lacs but the figure given in the Budget speech clearly shows that the last year's budget fell short by Rs. two and a half crores, if a Budget is to be put before this House, I do feel, Sir, that a correct figure should be placed before this House irrespective of the fact whether the budget is a deficit budget or not.

Since the population of Rajasthan is more than two third agricultirist, I will bring forward certain suggestions for the consideration of the Government. To decrease the deficit the Rajasthan Governmeet has ordered an increase in irrigation rates throughout the province.

[राजा श्री मानसिंह]

This order was issued on the 10th January, 1956. The order reads, Sir, :—

"His Highness the Rajpramukh has been pleased to order that the following irrigation rates will be charged on irrigatien done from irrigation work which have been constructed after Ist January 1952 :—

Wheat Rs. 10/- per acre.

Gram...Rs. 7/- per acre.

Barley...Rs. 8/- per acre.

Sugarcane...Rs. 22/- per year.

Vegetables...Rs 12/-per year.

Gardens...Rs. 12/-per year.

All other crops...Rs. 7/- per year.

Innundation irrigation, if subsequent water is given, should be raised by Rs- 4/- for all crops".

I admit that there should be certain increase in taxes and irrigation rates. But there must be some idea behind this increase. The cost of food production in Rajasthan, as compared to other areas, is very high. Our farms, since customs duties have been abolished, can not compete with the farmers of other provinces. The cost of essential commodities is more in Rajasthan than in the neighbouring States. I therefore feel that atleast irrigation rates for new and old works should be less than those of the neighbouring States, I am sure, Sir, the House will join me in requesting the Government to reduce these rates.

I feel that the Agriculture Department should distribute good seeds to the farms in the whole of Rajasthan in order to improve the agricultural conditions. This will benefit our farmers. We are here being told that the number of major irrigation schemes is going up and there will be great demand of seeds. If the Agriculture Department distributes seed of a good variety to its farmers, it will benefit the farmers as well as to the whole of the province.

I suggest, Sir, that the Rajasthan Government should have an agricultural work-shop in the State for the manufacture of tools and implements for mass-distribution amongst farmers to be designed by the agri-

[राजा श्री मानसिंह]

culturel department. I suggest that the key village schemes for imroving the cattle breed should be started in right earnest throughout the whole of province in all Districts. At present we have contemplated this scheme only in 10 districts. Then there is the question of poultry farms. We are informed in the budget that at present the Rajasthan Government spends Rs. 18,860 on a poultry farm near Jaipur. This is not very fair, nor we exactly know what work is being done there. I will suggest that more poultry farms should be opened in the State. There should be a scheme to open a poultry farm at least in every division so that the farmers intrested in poultry farming may benefit there from. Then the question comes, Sir, of plant protection. The measures at present being taken are neither satisfactory nor adeuate. In my district, namely, Bharatpur, this year we have had mass destructions of crops by aphids, known in Hindi as chain. I am very sorry to inform the House that no action whatsoever was taken by the Department although lacs and crores are allotted for the benefit of the farmers.

Then I should like to make a suggestion, Sir, that in community projects and N. E. S. blocks, the main development works are either agricultural or educational. I will suggest that the Head of these blocks should be from the appropriate Departments, agricultural or educational, and not from revenue departments. I will suggest, Sir, that the Technical Departments should have technical heads of Departments. It is impossible to imagine that a Technical Department can function properly without a technical head, and that is true of the Agriculture Department as well. The pay grades of our technical dpeartments should not be less than the executive departments. They should be more liberal. The real progress of this State depends on technical men and unless we liberalise their pay scales I cannot hope that technical men will be drawn towards the improvement of the State.

There has been a big demand for taccavi loans. I would suggest, Sir, that the demand is more toward the construction of wells and the Government should grant more for constuction of wells rather than for purposes of purchase of agricultural machinery, and especially in view of the fact, with which I do not agree, that ceilings will be coming into force shortly.

Then again the former Matsya is agriculturally a very important

[राजा श्री मानसिंह]

area of Rajasthan. I am sorry to point out that there is no Government agricultural farm in that area. I would suggest to the Government that they should start agricultural farm some where in the former Matsya.

Lastly, Sir, I have been listening to the debate here and I have come to the conclusion that there is a disease which I call 'ority'. This disease seems to hit various sections of the house. Regarding Udaipur we get it in the form of 'priority' amongst services, there is talk of 'seniority'. While others are being pushed back into 'juniority'. A member of the house has unfortunately been shouting that jats have overwhelmed Rajasthan. Regarding this, I feel it my duty to say a few words. I do not want to critisize the Government in any way because I feel that whatever is being done is quite fair. But I should like to point out that it is wrong to say that jats overwhelmed Rajasthan. Amongst the 29 M. Ps. there is one jat M. P. out of 160 members of this house there are 15 jats in number. out of the 13 member of our Cabinet there are 2 jats.

(हंसी)

Out of all the Head of departments there is on jat Head of the department. There are two Assistant Directors who are jats and when the question of third promotion comes up they too will most probably be by passed. In the Police Department there is no senior officer except one S. P. There are two Collectors. There is no jat Secretary to the Government. There is no jat member of the Revenue Board. In the public Service Commission there are no jats. This is the position of jats in Rajasthan. I want to know how it can be said that jats have overwhelmed Rajastan. Sir, the disease of 'ority' effect the hon'nle member also. He has it in form of 'inferiority'.

(हंसी)

(श्री हिम्मतसिंह अटरू, सभापति, पदासीन)

श्री टीकाराम पालीवाल—अध्यक्ष महोदय, पिछले दो दिनों से बजट पर काफी विचार प्रकट किये गये। किसी भी राज्य के बजट पर चर्चा करते समय सदन के सदस्यों को अवसर मिलता है, बजट से प्रकट होने वाली सरकारी रीति नीति के बारे में अपने विचार प्रकट करने का और साथ ही शासन के सम्बन्ध में भी आम तौर से।

[श्री टीकाराम पालीवाल]

जहां तक नीति का प्रश्न है क्योंकि हमारी सरकार कांग्रेस दल की सरकार है, इसलिए उसकी नीति अपनी कोई स्वतन्त्र या भिन्न नीति नहीं हो सकती, उस आम नीति से जो समस्त देश भर में कांग्रेस ने अपनाई है केन्द्र में अथवा और दूसरे राज्यों में । मुख्य नीति कांग्रेस की घोषित नीति है वह नीति हो सकती है और वह असल नीति यही है । जिन उद्देश्यों और सिद्धान्तों को सामने रखकर कांग्रेस ने शुरु से अपने देश का शासन सम्भाला वही सिद्धान्त और वही उद्देश्य देश के प्रत्येक कार्य में जहां भी कांग्रेसी सरकारें हैं और आज देश के प्रत्येक हिस्से में कांग्रेस की सरकारें हैं उन सबकी वही नीति है, वही उद्देश्य हैं, वे ही लक्ष्य हैं और उन्हीं लक्ष्यों की ओर अपनी वफादारी रखते हैं और और उन्हीं को सामने रखकर काम करने का प्रयत्न करते हैं। यह देश की असल नीति है ।

फिर भिन्न भिन्न राज्यों की सरकारों के लेखे-जोखे के अलावा नीति की आलोचना के लिये उस पर विचार प्रकट करने के लिये चीज क्या रह जावेगी ? असल में नीति की घोषणा दूसरी चीज है और किसी सिद्धान्त को मानना, किसी उद्देश्य को किसी लक्ष्य को सामने रखना एक बात है और उस पर उसके अनुसार आचरण करना और चलना और उसकी प्राप्ति के लिये सतत् प्रयत्न करना यह कुछ भिन्न चीज पड़ती है कई बार और वह भिन्नता आती है व्यक्तियों के आधार पर जो किसी खास समय किसी खास क्षेत्र में जिम्मेदार होते हैं, उन नतीजों और उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिये।

जैसा मैंने निवेदन किया जहां भी कांग्रेसी सरकारें हैं वे सब उन्हीं मुख्य नतीजों और सिद्धान्तों को अपनाये हुए हैं । लेकिन जनता अथवा और दूसरे लोग या सदन के सदस्य उन नीतियों को परखेंगे, कसौटी पर कसेंगे सरकार के कामों से, उसके व्यवहार से और यह कोई नई बात हमारे यहां है ऐसा नहीं है । संसार भर में ये ही चीजें हैं ।

नीति की घोषणाएं होती हैं संसार में, और बड़े सुन्दर शब्दों में होती है । हम जानते रूस और अमेरिका दोनों ही की घोषित नीति है संसार की शांति के लिये काम करना, लेकिन वास्तव में किस हद तक संसार की शांति के लिये वे काम कर रहे हैं यह हैं रूस और अमेरिका दोनों ही की घोषित नीति है संसार की शान्ति के लिए वे काम कर रहे हैं यह हम जानते हैं । दुर्भाग्य से दोनों ही एक दूसरे की घोषित नीति में विश्वास नहीं करते और दोनों ही कहते हैं ; अमेरिका कहता है, घोषणा करता है शान्ति की नीति की पर तैयारी कर रहा है लड़ाई की । और यही दूसरी तरफ से भी कहा जाता है, और दोनों तरफ से सही कहा जाता है क्योंकि दोनों तरफ से घोषणा होती हैं नीति की पर वास्तव में काम उनके उस नीति की विपरीत दिशा में किया जा रहा है । मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि संसार की सभी सरकारों पर यह चीज लागू होती है । पर मैं यह कहना चाहता हूं कि असल नीति केवल घोषणा पर से ही मान ली जावे, ऐसी बात नहीं है । उसको देखना होगा , कार्यों के आधार पर ।

हमारे यहां पर भी यद्यपि कांग्रेस का वही उद्देश्य रहा पर अब ज्यादा साफ शब्दों में

[श्री टीकाराम पालीवाल]

सोशलिस्टिक पैटर्न लाने का उद्देश्य सामने रक्खा है और उस लक्ष्य को सामने रखकर ही केन्द्रीय सरकार भी और दूसरी राज्य सरकारें भी अपनी शासन व्यवस्था को चलाना चाहती हैं।

(श्री अध्यक्ष पुनः पदासीन)

हमारे यहां भी हमारी सरकार ने इस नीति को स्वीकार किया। अब देखना यह है कि जिस नीति को स्वीकार किया है उसमें हम किस हद तक सफल हो रहे हैं। सफलता दूर रही, हम किस हद तक उस दिशा में चल रहे हैं, हमारे कदम और हमारे काम हमें उस दिशा में किस हद तक ले जा रहे हैं। पिछले दो दिनों से कई बातों को लेकर यह कहा गया कि हमारे सोशलिस्टिक पैटर्न के बारे में हम बातें ही बातें करते हैं, काम कुछ कम करते हैं असल में। वह एक बहुत बड़ा काम है, बहुत बडा उद्देश्य है और हमारा महान् लक्ष्य है। देश की सारी समाज व्यवस्था को बदलने की बात है, सारी अर्थ रचना को एक नये रूप के देने की बात है और वह इतना बड़ा काम है कि उसके बारे में भिन्न भिन्न सरकारें बड़े रूप से अलग अलग दिशाओं में नहीं जा सकतीं। आज देश में कांग्रेस दल का शासन है, केन्द्रीय सरकार कांग्रेस की है और भिन्न भिन्न राज्यों की जो सरकारें हैं उनको भी उसी नीति को मूल रूप में अनुसरण करना ही पड़ता है, करना ही होगा, जो नहीं करेंगी केन्द्रीय सरकार की मुख्य नीति के अनुसार जो लोग प्रकट में नहीं चल पायेंगे वे निश्चित रूप से केन्द्रीय सरकार का समर्थन नहीं प्राप्त कर सकते और वे कांग्रेस के नाम पर सरकार भी नहीं चला सकते। इसलिये बडी अर्थ व्यवस्था की बातें हों; जैसे ऐग्रेरियन लॉज की बात है। भूमि सम्बन्धी कानून बनाने की व्यवस्था बदलने की बात है जो मूलतः मूल सिद्धान्त हैं उनको करीब करीब देश के सभी राज्यों में एक प्रकार से किया गया है। देश के हरेक राज्य में भूमि सम्बन्धी कानून करीब करीब एक सिद्धान्त पर एक दिशा में बनाये गये हैं। इसमें कोई राजस्थान अलग नहीं रह सकता। दूसरी ओर जो अर्थ सम्बन्धी नीति है इन्डस्ट्रियल नीति है, औद्योगीकरण की अथवा विकास कार्य करने की जो नीति हैं इनमें भी यह नहीं हो सकता कि केन्द्रीय सरकार एक दिशा को इंगित करे और राज्य सरकारें या सरकार दूसरी दिशा में चलने लगें। राज्य सरकारों को भी उसी दिशा में चलना ही होगा।

फिर हमारे यहां देखने की बात क्या रह जाती है। केन्द्र से इन बड़ी बड़ी बातों में पथ-प्रदर्शन मिलता है, इन बड़े बड़े मामलों में मार्ग दर्शन मिलता है और मार्ग दर्शन भी ऐसा कि जिसके अनुसार चलना ही होगा। जब यह स्थिति है तो फिर अपने यहां देखने, सुनने और चर्चा करने की क्या बात रह जाती है। पर बात रह जावेगी यह कि हम उन चीजों को किस हद तक और किस स्पिरिट में कार्यान्वित कर रहे हैं। जितना करना अनिवार्य है वह तो है ही, पर इसके अलावा जो कुछ हमारे यहां करने की चीजें हैं वे हम किस हद तक कर रहे हैं यह देखना है।

पे स्केल के बारे में मैं कहूं कि यह बहुत बडा अंग नहीं है सोशलिस्टिक पैटर्न को लाने

[श्री टीकाराम पालीवाल]

का। वह दूसरी चीजें हैं बड़ी। भूमि सम्बन्धी कानून बनाना है, औद्योगीकरण के लिये बड़ी नीतियों का पालन करना है, खनिज पदार्थों का राष्ट्रीयकरण करना है; ये बड़ी चीजें हैं उनमें कोई बहुत बड़ी भिन्नता रह नहीं सकती केन्द्रीय सरकार की नीति से। लेकिन जो स्थानीय राज्य सरकारों के हाथ की बात है, जो काम उनको करने हैं, जहां उनका डिस्क्रिशन काम में आता है वह काम किस प्रकार से किया जाता है इस चीज को देखना, इसकी जांच करना, इसका ध्यान रखना, यह मेरा ख्याल है, हमारे इस सदन का काम है जिससे हम अन्दाज लगा सकें कि हमारे साथी उस मूल नीति में कितनी दिलचस्पी से और कितनी आस्था से चल रहे हैं।

अभी पे स्केल्स के बारे में बहुत बातें हुई हैं। बहुत दिनों के बाद यह नई श्रृंखला बनी। जहां तक वेतन वृद्धि का संबंध है कोई भी यह नहीं चाहता है कि राज्य के कर्मचारियों को, राज्य के अधिकारियों को वेतन कम मिले या उनका वेतन नहीं बढ़ाया जाय। हम सभी चाहते हैं कि हमारे राज्य के कर्मचारियों, हमारे राज्य के अधिकारियों, और कर्मचारियों की ही क्यों, दूसरे श्रमजीवी या किसानों की सभी की आमदनी बढ़े, और सब को जितना अधिक से अधिक दे सकें वह दें। देखना यह है कि किस समय और किस अनुपात से दिया जाय। प्रश्न इस बात का है। नीति सम्बन्धी बात वहां आती है जहां यह देखना होता है कि प्रायोरिटी किस चीज़ को दी जाय। जब आलोचना यह की जाती है कि स्केल्स ऐसे बनाये जायं जो सोशलिस्टिक पेटर्न की बात करते हैं, उनको चिन्ता नहीं रही; ऐसा मालूम होता है। इन पे स्केल्स को बनाते हुए, तब उसमें तथ्य मालूम पड़ता है। इसलिए नहीं कि जिनको दिया गया है उनको नहीं दिया जाना चाहिए, बल्कि इसलिए कि जिनको पहले दिया जाना चाहिए था और जितना दिया जाना चाहिए था वह पहले और उतना नहीं दिया गया है, यह निश्चित बात है। इसके डिटेल्स में जाने में कोई चीज़ रुचिकर नहीं होगी। इसलिए नहीं होगी कि मेरा भी यह मानना है कि पे स्केल्स किसी खास सिद्धान्त पर नहीं बनाये गये हैं। रेशनेलाइजेशन ऑफ पे स्केल्स के नाम से इसको रेफर किया गया है। मेरी ऐसी फीलिंग (feeling) होती है कि यदि इसको रेशनेलाइजेशन कहा जा सकता है तो रेशनेलाइजेशन शब्द की परिभाषा को बदलना पड़ेगा, निश्चित रूप से बदलना पड़ेगा। मैं यह भी नहीं कहना चाहता हूँ कि जिनको ज्यादा मिला है उनसे मेरा कोई द्वेष या कोई बात हो। ऐसी बात नहीं है। हम चाहते हैं कि सबको ज्यादा मिले और ज्यादा मिलने से ही, ज्यादा तनख्वाह दे देने से ही सोशलिस्टिक पेटर्न ऑफ सोसाइटी नहीं बना सकते हैं। आमदनी सारे देश की ज्यादा बढ़ती है आम तौर से तब भी सौशलिस्टिक पेटर्न ऑफ सोसाइटी नहीं बनती है। अमेरिका की मिसाल हमारे सामने है। वह बहुत धनाड्य देश है। वहां के कर्मचारियों को बहुत ऊंची तनख्वाहें मिलती हैं, क्योंकि वहां के सारे लोगों की आमदनी खूब अच्छी है। तब भी वह एक सौशलिस्टिक कन्ट्री नहीं है। समाजवादी व्यवस्था वहां पर नहीं है। इसलिए नहीं है कि धनाड्य होने पर भी वहां पर धन की असमानता है और काफी हद तक असमानता है। यदि उनका गरीब से गरीब आदमी ७०० रु० या ८०० रु० कमाने वाला है तो बड़े से बड़ा आदमी लाखों रुपये कमाने वाला है, करोड़ों रुपये कमाने वाला है। यद्यपि जो निम्न श्रेणी के, नीचे से नीचे के आर्थिक स्तर पर खड़े होने वाले आदमी हैं वे अपनी आवश्यक-

[श्री टीकाराम पालीवाल]

ताओं को भली भांति पूरा कर लेते हैं इतनी आमदनी उनको मिल जाती हैं तब भी वहां असमानता इतनी बड़ी हैं। नीचे के स्तर पर खड़ा होने वाला आदमी और ऊंची से ऊंची आय वाले आदमी में असमानता इतनी बड़ी है उनके अपने माप दंड के अनुसार भी उस असमानता के कारण उसको सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी नहीं कहा जा सकता है। वह एक कैपिटलिस्टक सोसाइटी तो निश्चित रूप से है। इसलिए सोशलिस्टिक और कैपिटलिस्टिक सोसाइटी के अन्तर में यह नहीं है कि हमने कुछ लोगों की आमदनी बढ़ा दी। यह इतनी मूल्य की चीज नही है जितने मूल्य की चीज यह है कि हम आमदनी, आय, के सामाजिक स्तर में लोगों में जो बहुत बड़ा अन्तर है बड़े और छोटे का, ऊंचे और नीचे का, ज्यादा और कम के पजेशन का उस अन्तर को कम करते चले जायं। मैं नहीं कहता कि वह एक स्ट्रोक (Stroke) में एक साथ हो सकता है। वह कभी भी नहीं हुआ है और अगर हुआ होगा तो बहुत एक बल के कारण और एक भयंकर क्रान्ति के कारण हुआ होगा, जैसा कि रूस में हुआ है और जिसको हम चाहते नहीं। तो वह एक दिन में होने वाला नहीं है, लेकिन यह तो कम से कम हमें निश्चय होना चाहिए कि हमारा जो एक एक कदम उठ रहा है, चाहे धीरे से उठ रहा है, चाहे वह कदम लम्बा नहीं है, लेकिन एक एक कदम हमारा उस असमानता को कम करने की ओर उठता है, उसको बढ़ाने की ओर नहीं उठता है। इन पे स्केल्स में निश्चित रूप से जैसा कि कल मेरे एक दो साथियों ने बताया वह असमानता बढ़ी है। फिर प्रश्न यह होता है कि यह भी हो सकता है कि कई दफा जो अनिवार्य चीज़ हो जाती है, तो करना पड़ता हैं। मुख्य उद्देश्य तो वही है हमारे सामने फिर भी किसी इमरजेन्सी के कारण कभी कोई ऐसा काम करना पड़ता है जिससे कि वह मेन पिक्चर में फिट हुआ नहीं दिखाई दे फिलहाल थोड़े समय के लिए। मैं मानता हूं कि मेरी यह धारणा है कि जो कुछ बताया गया है वह ऐसा नहीं था कि अनिवार्य था, इसी समय करना था। उससे पहले ज्यादा आवश्यक था छोटी तनख्वाह के लोगों की तनख्वाहें बढ़ाना और उसके बाद दोनों की अगर कर सकते हैं तो जो बड़े लोग हैं उनकी तनख्वाहें बढ़ाते। उनको बढ़ाने के साथ साथ यदि हमारे पास इतनी गुंजाइश होती तो छोटे लोगों की भी तनख्वाहें बढ़ाते। उस अनुपात की बराबरी की मैं नहीं कह रहा हूँ। अनुपात से मेरा मतलब परसेन्टेज से नहीं है कि ५ परसेन्ट उनका बढ़ाओ तो ५ परसेन्ट इनका बढ़ाओ। उससे मतलब मेरा नहीं है। परसेन्टज से काम नहीं चलता है। बहुत थोड़ी तनख्वाह है उनको कहीं ज्यादा परसेन्टज से इन्क्रीमेन्ट देना लाजमी होगा और जिनकी तनख्वाहें कम हैं उनको कम परसेन्टेज से इन्क्रीमेन्ट देने से काम चल सकता है। यह सिद्धान्त इसमें नहीं रखा गया है। क्यों नहीं रखा गया? बहुत आवश्यक होते हुए भी उस चीज़ को क्यों नहीं रखा गया? यह समझ में नहीं आता। ऐसा सुना है कि व्यक्तिगत कन्सीडरेशन भी रहा है, और लगता भी ऐसा है कि जो चीज़ स्पष्टतः गलत हैं; डिक्लेयर्ड पोलिसी (declared policy) के खिलाफ पड़ती है, जो करना बहुत ज्यादा आवश्यक नहीं थी, आज जिसको किये बिना काम चल रहा था और चल सकता था वह चीज की गई है, तो निश्चित रूप से समझा जा सकता है कि एक्स्ट्रानुअस कन्सीडरेशन्स रहे हैं। मैं यह नहीं कहता हूं कि जिन लोगों को यह लाभ पहुँचा है इन पे स्केल्स से वे सभी ऐसे सौभाग्यशाली हैं कि जिनके व्यक्तिगत कन्सीडरेशन के लिये ये किये गये होंगे। यह नहीं है कि सभी ऐसे हैं। कुछ व्यक्तिगत कन्सीडरेशन्स के कारण वह

[श्री टीकाराम पालीवाल]

एक जनरल सी चीज बन जाती है, और फिर जैसा कि लोग कहते हैं गांव में कि गेहूँ के साथ बथुए को भी पानी लग जाता है ।

एक माननीय सदस्य—गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है ।

श्री टीकाराम पालीवाल—गेहूँ के साथ घुन वाली दूसरी चीज है । वह इसके विपरीत है । यहां गेहूँ के साथ बथुए को पानी लग जाता है यानी गेहूँ को पानी से सींचना होता है तो उसके साथ बथुआ जो है उसको भी पानी मिल जाता है । ऐसा कहीं जरूर रहा होगा । लेकिन यह साफ प्रकट है कि वह हमारी नीति के अनुकुल नहीं है ।

फिर और चीजें है जिनके बारे में बार बार प्रश्न उठाया जाता है । जब हम सोशलिस्टिक संस्था की बात करते हैं, कांग्रेस के उद्देश्य और सिद्धान्तों की बात करते है तो हमारे सामने निश्चित रास्ता रहता है । जिस चीज को लेकर कांग्रेस ने देश का शासन संभाला है और जिन सिद्धान्तों को लेकर कांग्रेस ने विदेशी शासन को खत्म किया है; विदेशी शासन को ही खत्म नहीं किया बल्कि स्वदेशी राजाओं को भी खत्म किया । विदेशी शासन को तो हमने इसलिये खत्म किया कि वह विदेशी था चाहे वह कितना ही अच्छा था लेकिन स्वाभिमान पर उससे चोट पड़ती थी और स्वाभिमान के विरूद्ध पड़ता था, इसलिये उसको हमने खत्म किया लेकिन हमने देशी राजाओं के राज्य को भी खत्म किया । इसलिये किया कि हम एक निश्पक्षता के साथ शासन को देश में स्थापित करना चाहते थे । हम ऐसे शासन की स्थापना करना चाहते थे जिसमें करपशन न हो, और हो तो उसको कम से कम, न्यूनतम कर दिया जाय । ऐसा शासन जिसमें पक्षपात न बढ़े; क्षेत्रीय भावनाओं, जातिगत भावनाओं का जोर न हो, खुद परस्ती और दोस्ती के आधार पर शासकीय कार्यवाही न की जाय; इस प्रकार का शासन हम लाना चाहते थे । और राजाओं के खिलाफ यह शिकायत थी हम लोगों की और वह सही थी । आज भी मैं यह मानता हूं कि बहुत अंश में, सभी तो नहीं; लेकिन बहुत अंश में सही था कि राजाओं के शासन में करपशन खूब रहता था ।........

श्री जसवन्तसिंह—आजकल चल रहा है उससे भी ज्यादा ?

श्री टीकाराम पालीवाल—(जारी) करप्शन भी रहता था लेकिन पक्षपात तो काफी था, यह नहीं कि सभी राजाओं के शासन में पक्षपात का बोलबाला था । ऐसी भी रियासतें थीं और राजस्थान में थीं जिनके शासन को प्रगतिशील शासन आम तौर से कहा जाता है । यह नहीं कि उन में करप्शन नहीं रहा हो, आम तौर से जिसे कहें कि शासन करेप्ट है उस तरह का नहीं था । इस प्रान्त में हमारे राजाओं का शासन था लेकिन वह भी अच्छा कहलाने वाला शासन था । उनमें भी पक्षपात, नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म और कुनबा परस्ती ज्यादा थी । कोई एक दिशा में ज्यादा था तो कोई दूसरी दिशा मे ज्यादा था । और इन सब चीजों से छुट्टी पाने के लिये कांग्रेस ने तय किया था कि

[श्री टीकाराम पालीवाल]

इन राजाओं को खत्म करके प्रजातंत्र राज्य बनाया जाय। जिन राजाओं को खत्म किया उनके यहां कई प्रकार की वेलफेअर एक्टिविटीज नहीं होती थीं, ऐसी बात नहीं है। हम जिस तरह से वेलफेअर एक्टिविटीज़ में आज एन्गेज्ड (engaged) हैं उसी तरह से वे भी वेलफेअर एक्टिविटीज करते थे। सब नहीं करते थे लेकिन फिर भी करते थे। ऐसा भी था कि कई राजा आमदनी का काफी हिस्सा वेलफेअर एक्टिविटीज में लगाते थे। सडकें बनाने में, बांध बनाने में रुपये लगाते थे, शिक्षा पर काफी खर्च करते थे, चिकित्सा पर खर्च करते थे। वे ही सारी एक्टिविटीज थी जिनमें आज हमारी सरकार काम करती है जिनका श्रेय उनको मिलना चाहिये लेकिन वह श्रेय ऐसा है जो पिछली कई सरकारों को मिल सकता है लेकिन उनके बावजूद भी उन सरकारों को बदलना जरूरी समझा गया। ये खर्चा वे सरकारें उतना नहीं कर पाती थीं जितना आज हमारी सरकार कर पाती है। उसका कारण स्पष्ट है कि उनके पास इतनी आमदनी नहीं थी और केन्द्र से इतना सहारा नहीं था, केन्द्र की इतनी सहायता नहीं थी। आज हमको केन्द्र से बराबर सहायता मिलती है और इसलिये हमारे बजट में बड़े उत्साहप्रद आंकड़े हमको दिखाई देते हैं जिनके लिये हम गर्व करते हैं, कि हम काफी खर्च करते हैं। करोड़ों रुपये हम शिक्षा पर खर्च कर रहे है और दूसरे डेवलपमेन्ट वर्क्स में भी खर्च कर रहे हैं; वेलफेअर एक्टिविटीज़ पर हम काफी खर्च कर रहे हैं, यह बहुत संतोष की बात है, गर्व की बात नहीं हैं; लेकिन कोई अनोखी बात भी नहीं हैं क्यों कि अपनी शक्ति के अनुसार पहले के राजाओं की सरकारें भी कई राज्यों में उनकी शक्ति के अनुसार खर्च करती थी और क्योंकि हमको केन्द्र की सहायता काफी मिल रही है इसलिये हम भी खर्च कर रहे हैं। यह संतोष की बात है अच्छी बात है लेकिन अनोखी बात नहीं है।

मूल चीज जो आती है शासन के निष्पक्ष सिद्धान्त और जो लक्ष्य सामने रखे हैं सोशलिस्टिक संस्था के उस लक्ष्य की ओर चलने का और इन दिशाओं में हम किस हद तक कामयाब हुए हैं। हमारा प्रत्येक कार्य इस दिशा की ओर हम को ले जा रहा है या नहीं और यदि ले जा रहा है तो कितनी तेजी से ले जा रहा है या उल्टा पीछे ढकेल रहा है? इन चीजों को देखना होगा और जब हम उन चीजों को देखते हैं अध्यक्ष महोदय, तो हमें निराशा होती है, अभी विरोधी दल के नेता ने बीच में इन्टरप्ट करके कहा था जब कि मैं यह कह रह था........

कु० श्री जसवन्तसिंह—मेरी रनिंग कमेन्ट्री थी।

श्री टीकाराम पालीवाल (जारी) : जब में यह कह रहा था कि पुराने शासकों में करप्शन था सब में न सही, लेकिन बहुतों में करप्शन था तो बीच ही में उन्होंने कहा था, "इससे ज्यादा तो नहीं" ठीक है, इस प्रकार से आप का कहना क्यों कि उस वक्त इतना अवसर नहीं था। आज हमारे पास खर्चा करने को ज्यादा है तो उस में से ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं (हीअर हीअर) लेकिन मैं आप को यकीन दिलाना चाहता हूँ कि मैं लाइट मूड में यह नहीं कह रहा हूं और न यह ताली बजाने की बात ही है। इसकी जिम्मेदारी जितनी मेरे साथियों की है जो आज सरकार चला रहे है

[श्री टीकाराम पालीवाल]

उससे कम जिम्मेदारी सदन के प्रत्येक व्यक्ति की भी नहीं है और मैं समझता हूँ कि इसके लिये जितने आप जिम्मेदार हैं उतना ही मैं भी हूँ और जितना मैं हूँ उतने ही आप भी जिम्मेदार हैं व प्रत्येक सदस्य है। इसलिये कि पहले राजाओं के जमाने में जो राज्य चलाते थे, वे चलाते थे, उनके भाई बेटे और जागीरदार, सहयोगी। शायद उन्होंने भी अपनी एक प्रणाली बना रखी थी। उन्होंने भी अपने समर्थकों का एक दल अपने इर्द गिर्द, चारों ओर कर रखा था कई प्रकार से। कइयों को बड़ी बड़ी नौकरियां मिलती थीं और कइयों को बड़ी २ जागीरें और भूमि मिलती थी और कइयों को नकद जागीर देकर इस प्रकार के समर्थकों का एक दल बनाया था और उनके सहारे से उनकी मदद से वे अपना शासन चलाते थे। जहां जनता की बात आती है, हमारी आम तौर से जनता उस समय भी शासन के प्रति उतनी ही उदासीन थी जितनी आज है। अब भी कुछ २ जागरूकता की बात है। लेकिन जनता की जागरूकता ऐसी नहीं है कि वह शासन के प्रत्येक कार्य को देख सके, जांच सके, निर्णय कर सके और प्रभावित कर सके। ऐसी जनता आज भी नहीं है। देश के दूसरे भागों में है या नहीं, इस के बारे में सब जगह के लिये मैं नहीं कह सकता। हमारे देश के भिन्न भिन्न भागों में जागृति एक ही समय में नहीं आई, आगे पीछे आई और इसलिये जनता की जगरूकता, राजनैतिक जागरूकता, नैतिक जागरूकता; यह भी सब जगह बराबर नहीं की। राजस्थान के बारे में निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि हमारे यहां की आम जनता में जागृति हुई है लेकिन इस बात की हुई कि यहां सड़कें बनवानी चाहिये, यहां अस्पताल होना चाहिये, यहां स्कूल खुलने चाहिये, यहां बांध बनने चाहिये, कुए बनाने चाहिये। इस बात की जागृति हुई है कि क्या क्या चीजें उनके यहां होनी चाहिये। चाहे ये चीजें इनके यहां करदी जावें, बाद में शासन शुद्ध तरीके से चले या करप्ट तरीके से चले, कर्मचारी या अधिकारी कितने कर्त्तव्यपरायणता से कार्य कर रहे हैं या बीच में ही गोलमाल हो रहा है, इससे उनको कोई ज्यादा मतलब नहीं है।

यह निश्चित बात है कि जो कोई भी पब्लिक में काम कर दिखाएगा उसको यह चीज मिल जावेगी। उनको इस बात की चिन्ता नहीं है कि आप उस पर कितना खर्चा कर रहे हैं उनके क्षेत्र में कुए खुद जावें, उससे उनको संतोष होगा। कुए खुदाने में ५ हजार रुपये लगने चाहिये उसकी जगह आपने १२ हजार लगाया या १० हजार लगाया, उसकी उनको कोई चिन्ता नहीं है। १२ हजार रुपया लग कर भी कुए बनवा दिए तो उनके लिये यह बहुत बड़ी बात होगी और वह उतनी ही होगी कि अगर वह मेरे कहने से बनवा दिए तो वे मुझे धन्यवाद देंगे और चीफ मिनिस्टर के आदेश से बने हैं तो वे उनको धन्यवाद देंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि जिसके दृष्टिकोण से बनते हैं वे उनको धन्यवाद देंगे और वफादारी का परिचय भी देंगे और देते हैं। तो यह जागरूकता उन लोगों से, आम जनता से नहीं की जा सकती, उसकी आशा की जानी चाहिये। हमारे उन साथियों से जो इस कार्य को कार्यान्वित कर रहे हैं और जब हम यह देखें कि यह चीज गोलमाल तरीके से चल रही है तो यह ठीक नहीं कि आप मेरे पर तालियें पीटें और न मेरे कहने पर तालियां पीटें और न यह ताली बजाने की चीज है। हम लोगों की आत्मा जागृत हैं, हम लोग चुने हुए हैं और हम लोग एक लाख में से चुन कर आए हैं। एक लाख व्यक्तियों ने हमें चुनकर भेजा है। हम उन लोगों में से हैं

[श्री टीकाराम पालीवाल]

जिसे लाखों में से एक कहा जाता है, इम लोगों का सौभाग्य है कि हमको यह सौभाग्य प्राप्त है कि वह लाखों में से एक हैं, और जो लोग यहां पर बैठे हुए हैं उन सबको यह सौभाग्य प्राप्त है। इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति यहां पर बैठे हुए हैं। लाखों में से एक व्यक्ति की आत्मा इतनी जागृत है जो यह तोल सके कि जो काम हम कर रहे हैं या जो काम यहां पर हो रहा है इस सदन के समर्थन से, इस सदन की ताकत से वह काम सचमुच ऐसा है जो हमें इस लक्ष्य की ओर ले जा रहा है। क्या वह सोशियल पेटर्न की ओर ले जाने वाला है। जो शासन में निष्पक्षता लाने वाला है, अगर इस प्रकार तरीका चल रहा है तो हम बधाई के पात्र हैं और अगर नहीं है तो हम भर्त्सना के पात्र हैं। चाहे हम लोग मन में संतोष मान लें कि हम लोग चुनाव में जीतते हैं इसलिये जनता हमें चाहती है। मैं यह कहूँगा कि चुनावों में जीतना बिल्कुल दूसरी बात है। हमने कई उपचुनाव लड़े और जीते। शायद सभी उपचुनाव हमने जीते हैं लेकिन यह एक स्थिति के प्रति, वास्तविकता के प्रति आंखें बन्द करना होगा। यदि हम यह मान लें कि पब्लिक यह समझती है कि हमारे सारे काम न्याय की दृष्टि से हो रहे हैं और पब्लिक यह समझ कर हमें यहां पर भेज रही है, यह बात गलत होगी। मैं यह नहीं कहूँगा कि सारी पब्लिक ही बिना सोचे वोट देती है। सोच समझ कर वोट देने वाले लोग इन्टेलिजेन्शिया बहुत थोड़े होते हैं। बहुत से लोग सत्ता के पीछे या कांग्रेस के नाम के पीछे चलते हैं। हमने देखा, मुख्य मंत्री जी ने कहा था शायद राजप्रमुख के भाषण के अवसर पर कहा था कि यह कहा जाता है कि पब्लिक में असंतोष है लेकिन फिर भी चुनाव तो सब जीत रहे हैं, इससे हमको प्रसन्नता है। लेकिन मैं यह निवेदन करूंगा कि इसका अर्थ यह नहीं होता कि हम चुनाव जीतते हैं इसलिए जो कुछ हम कर रहे हैं और उसे समझदार लोग ठीक मान रहे हैं और चुनावों का जीतना ही उनके लिये इस बात का प्रतीक है कि जनता जो कुछ वे कर रहे हैं उसको ठीक मानती है। पब्लिक का बहुत बड़ा भाग इन चीजों को समझ ही नहीं सकता। बहुत से लोग तो ऐसे हैं कि उनके यहां थोड़ा काम हो गया वह बहुत काफी है और वे लोग शक्ति के पीछे चलते हैं। इसका परिणाम हमने पिछले जनरल इलेक्शन में देखा है। पिछले जनरल इलेक्शन में ओपोजीशन की संख्या हमसे सिर्फ दो कम थी, वे लोग इसलिये चुनावों में नहीं आए कि उनके शासन से पब्लिक अप्रसन्न थी। ऐसी बात नहीं थी। आप मुझे इसके लिये माफ करेंगे कि जो लोग पहले ओपोजीशन की बैंचेज़ पर बैठते थे और अब इधर बैठते हैं उस समय ओपोजिशन की की संख्या हम से दो कम थी लेकिन वे इतनी बड़ी संख्या में जीत कर आये इसका कारण यह नहीं था कि जब सत्ता उनके हाथ में रही उस समय लोगों को उन्होंने बहुत सुख और सुविधाएं दीं। लेकिन वे इसलिये जीत कर आए कि छोटी मोटी सत्ता उस समय भी उनके हाथ में थी और इसी भावना से वे लोग जीत कर काफी बडी संख्या में यहां पर आये थे। करीब करीब बराबर की संख्या थी, सिर्फ दो की कमी थी। वह इस बात का प्रतीक है कि हमारी जनता ने केवल सिद्धान्त पर वोट नहीं दिये थे। उस वक्त पब्लिक सत्ता के पीछे, व्यक्तिगत प्रभाव और संबन्ध के पीछे बह गई थी। आज भी चार सालों में सारी पब्लिक बदल नहीं गई है। जिस समय ये लोग आये थे उस समय भी हमने यही कहा था कि ये लोग इसलिये नहीं जीत कर आए हैं कि उन्होंने जनता के साथ अच्छा व्यवहार किया जिस समय उनके हाथ में सत्ता थी। सत्ता के दबाव

[श्री टीकाराम पालीवाल]

और प्रभाव से ये लोग जीते थे । आज हमारे शासन संबन्धी कार्य दूसरों की कसौटी पर सही नहीं निकलते हैं, समझदारों की कसौटी पर सही नहीं निकलते हैं, वे भी यह कह सकते हैं कि आप चुनाव जीत रहे हैं वह सत्ता के बल पर और दूसरे बल पर । चुनावों मेंजीतना यह हमारे लिये बहुत बड़े संतोष की बात नहीं है । देखना यह होगा कि हमारे शासन चलाने का तरीका अपने आप से ठीक हो सकता है लेकिन समझदार लोगों की निगाह में सही है या नहीं और इन कामों से किस नीति का संकेत हमें मिलता है । माननीय अध्यक्ष महोदय, यह खेद की बात है कि ऐसे कुछ काम हुए हैं जिनसे ऐसा लगता है कि जिन सिद्धान्तों पर हमारा शासन चलना चाहिये नहीं चलता है । मैं जब यह कहता हूं कि जिन सिद्धान्तों पर चलना चाहिये नहीं चलता है, उससे मेरा मतलब यह नहीं कि मैं उनसे इतनी बडी आशा करता हूं कि शासन के प्रत्येक कार्य बडे से बडे अधिकारी से लेकर छोटे पटवारी और कांस्टेबल तक सब लोग एक श्रेणी के नैतिक स्तर पर आ सकते हैं । मैं कभी इस प्रकार के अव्यवहारिक बात की आशा नहीं करता लेकिन यह तो आशा करनी चाहिये कि हाइएस्ट लेवल और हाइयर लेवल पर तो सचाई और ईमानदारी की स्थिति रहेगी । यह तो मानना चाहिये और वह लोगों में प्रकट होगी और जो काम होगा वह ऐसा होगा जिससे लोगों को शंका करने का अवसर नहीं रहेगा । यह तो प्रकट होना चाहिए । जब यह होता है तब नीचे के स्तर पर जाकर उसका अच्छा प्रभाव पड़ सकता है । यदि यह नहीं होता है तो नीचे के स्तर पर उसका प्रभाव नहीं पडता है ।

इस प्रकार की बहुत चीजें सुनने को मिलती हैं, उनसे ऐसा विश्वास पैदा नहीं होता बल्कि शंका होने लगती है कि दिन व दिन मामला सुधरने के बजाय दिन व दिन बिगड़ता जा रहा है । अच्छे जिम्मेदार और बडे अधिकारी कहिये, कइयों के बारे में आम धारणा है कि ईमानदार है, अच्छा अफसर है उनको यह कहते हुए सुना जाय कि इससे तो किसी बनिये की ही नौकरी कर लेते तो अच्छा था, हमें ड्राफ्टिंग करना पडता है । तो इसमें किस चीज़ का संकेत मिलता है ? ऐसे कई उदाहरण है ।

बहुतसी चीजें सुनने में आती हैं, बहुतसी चीजें अखबारों में आती हैं और उनमें से कई ऐसी चीजें हैं जिनका कोई जबाब नहीं है । वैसे जबाब हर एक चीज़ का दिया जा सकता है लेकिन माकूल जबाब नहीं है । मेरी इच्छा नहीं थी कि किसी इन्डीविजुअल आइटम को रेफर किया जाय लेकिन शायद फिर यह कहा जाय कि जनरल बातें कह डाली वास्तव में ऐसी चीज़ नहीं हैं । मैं मानता हूं कि केवल जनरल बातें कहने से काम नहीं चलता लेकिन सारी बातों को लाकर रखना भी मुमकिन नहीं है और उचित भी नहीं है । मिसाल के तौर पर एक दो चीजें कही जा सकती हैं । एक चीज़ का उल्लेख तो इसी सदन के माननीय सदस्य श्री वेदपालजी त्यागी ने किया था । वह है नाथद्वारा का मामला ।

नाथद्वारा को राजस्थान में एक बहुत बडी धार्मिक संस्था के रूप में माना जाता है । मुझे भी उस सम्बन्ध में डील करना पडा । सन् ५१-५२ में वहां की समस्या सरकार के सामने आई । वहां के महाराज के सम्बन्ध में मैं कुछ कहना नहीं चाहता, यहां पर सब लोग जानते है और मेरे साथी और हमारे मित्र मुख्य मंत्री हमसे भी ज्यादा जानते हैं, जिस प्रकार से और जैसा उनका

[श्री टीकाराम पालीवाल]

रहन सहन है। बहर हाल यह सही है कि उनके अनुयायियों में से, उस मूर्ति के परम भक्तों में से बहुत से जिम्मेदार लोगों ने जो अपनी इन्टीग्रिटी और अपनी सामाजिक स्तर की अच्छाइयों के लिए निर्विवाद रूप से प्रतिष्ठित लोग कहें जा सकते हैं, गएय मान्य लोग कहे जा सकते हैं, काफी बडी तादाद में लोगों ने यह महसूस किया कि वहां का प्रबन्ध महाराज के हाथ से ले लेना चाहिए और उन्होंने स्वयं आपस में मिल कर तय किया और उस वक्त को सरकार के सामने रिप्रेजेन्टेशन भी किया गया। एक प्रबन्ध समिति बनायी गई। वह प्रबन्ध समिति उस सम्प्रदाय की इन्टीग्रिटी के हिसाब से, उच्च से उच्च प्रतिष्ठा के हिसाब से उच्च से उच्च समिति बनी। महाराज का मासिक व्यय नियत कर दिया गया। वह सम्भवतः दो हजार रुपये के आस पास है। सारा प्रबन्ध उस समिति के हाथ में आगया। प्रबन्ध भी और सम्पत्ति भी। सदन के सब माननीय सदस्यों को मालूम नहीं होगा यह कि वहां बहुत बडी सम्पत्ति है। करीब एक करोड़ के जेवरात हैं .. ६० लाख के होंगे या ८० लाख के होंगे, कुछ लाख में कमो बेशी हो सकती है। तो इस तरह से करीब करीब १ करोड़ के जेवरात हैं। यह एक बडी मूर्ति हैं और छोटी मूर्ति है जिनको नवनीत प्रियाजी कहा जाता है, वह अलग है। दो के सिवाय और हो तो मुझे नहीं मालूम है। इनको ही जनता था। तो प्रबन्ध समिति ने सारा काम अपने हाथ में ले लिया। वहां के महाराज ने जनता के असंतोष को देख कर, अपने अनुयायियों को दृढ़ता को देखकर कि यह गोलमाल नहीं चलने दिया जायगा इस बात पर अपने अनुयायियों की दृढ़ता को देखकर और उस समय की सरकार के रुख को देख कर कि सरकार भी इस प्रकार का गोलमाल चलने देना पसन्द नहीं करती हैं उन्होंने अपने आप उस समिति के पक्ष में एक पावर ऑफ एटोरनी भी लिख दी और वह समिति सक्षम समिति बन कर काम चलाने लगी। काम काफी दिनों तक चलता रहा, अच्छे ढंग से चलता रहा और समिति के कई महानुभाव जो मुझ से मिले और उन्होंने और दरख्वास्तें भी पहुंचा चुकी थीं उनसे स्थिति दिग्दर्शन में आयी, उन्होंने अपने पास से नया रुपया लाकर के इधर उधर से प्रबन्ध करके समिति को चलाना शुरू किया, जो अपव्यय हो रहा था उस पर अंकुश लगाने का प्रयत्न किया और जो संचित रकम थी जनता को उसका भी प्रबन्ध किया। फिर अचानक सुनने को मिला कि पुरानी समिति के स्थान पर एक नई समिति का संगठन हुआ है और उस पुरानी समिति के जो गणमान्य प्रतिष्ठित व्यक्ति थे उनमें से अधिकांश व्यक्ति गायब थे। एक दो रहे हों। नई समिति बनी। महाराज, जिनको तिलकियात जी महाराज कहते हैं, ने अपने उन अनुयाइयों का और उस वक्त की सरकार का रुख देख कर जो चुपचाप से पावर ऑफ एटोरनी लिख कर उस समिति को दे दी थी उसको समिति ने केन्सल कर दिया और दुबारा पॉवर रिज्यूम करली। मिसाल है कि एक दफा भाग्य के अनुकूल हवा नहीं होती है तो जो है वही चला जाता है और जब दूसरी दफा भाग्य पल्टा खाता है तो वह मिल जाता है। इस तरह से उन्होंने अपने दुबारा पावर्स ले लिये। हवा उनके अनुकूल बहने लगी। इस तरह से नई समिति का गठन हुआ। पुरानी समिति के जो प्रतिष्ठित लोग थे उनको भी अचानक मालुम पड़ा, ऐसा मुझे मालुम हुआ है। मेरे माननीय साथी जयनारायणजी व्यास से एक दो सदस्य जो उस पहले की समिति में थे, जो उस समिति के सक्रिय सदस्य थे, उन्होंने एक दो बातें उनको बताई थी और उन्होंने

[श्री टीकाराम पालीवाल]

बताया कि नई जो समिति बनी है, नई समिति के हाथ में प्रबन्ध है उसमें अधिकांश लोग ऐसे रख लिए गए हैं जो उन महाराज को खुले हाथ देना चाहते थे, खुले हाथ देनें से मैं मानता हूं कि वे जैसा चाहें वैसे आमदनी का उपयोग करें और जो पहले की सम्पत्ति रखी हुई थी एक करोड़ के करीब उस पर भी पूरा अधिकार उनको दे दिया जाय। ऐसे लोगों की समिति बनी । उसमें ज्यादा भक्त लोगों में से होंगे। मैं यह नहीं कहता कि वे ऐसे होंगे, वे ऐसे लोग बताये जाते हैं कि जो महाराज को जैसा चाहे उस तरह से सम्पत्ति का उपयोग करने के लिए छुट्टी देना चाहते हैं। इस तरह की प्रबन्ध समिति बनी। महाराज का खर्चा पहले से बढ़ा दिया गया और महाराज का अधिकार मान लिया गया। इस प्रकार की व्यवस्था है। डिटेल्स तो मेरे पास नहीं हैं। सुनी सुनाई है, उनके द्वारा जो कि इस से पूर्व समिति के प्रतिष्ठित सदस्य या जानकार लोग जैसे कि श्री जयनारायणजी व्यास हैं। यह नई समिति की व्यवस्था पुराने लोगों को अचानक मालूम हुई और उन्होंने कहा कि जिस तरह से बिगड़ी हुई अवस्था से निकाल कर सुव्यवस्था पर लाना चाहते थे उस किये कराये पर पानी फिर गया और जो संचित निधि है उसको भी खतरा है।

इसलिये उन्होंने बड़े अधिकार पूर्ण स्थानों पर इनकी सूचना दी और अपना विरोध प्रकट किया उसी के फलस्वरूप वहां के कई व्यक्तियों ने जिन्होंने इस बात को अधिकार पूर्ण स्थानों पर पहुँचाया उनको मालूम हुआ, मुख्य मन्त्री महोदय को पूछा गया, यह क्या गोलमाल है। अगर मेरी यह सूचना सही है तो मुख्य मन्त्री महोदय ने उत्तर दिया वे पूछ कर बतलायेंगे अपने किसी साथी से। मैंने जब यह सुना मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि मुख्य मन्त्री इस प्रकार उत्तर देते हैं मैं अपने साथी से पूछ कर बतला सकता हूँ खास तौर से उस जगह के बारे में जहां से वे आते हैं और नाथद्वारा के बारे में। मैं मानता हूं कि मैं जब मुख्यमन्त्री था जिन साथियों के हाथ में ऐसे काम होते थे वे बिना मेरी जानकारी के नहीं करते थे, व्यास जी की केबीनेट में कोई भी काम उनकी अनुमति के बिना साथी नहीं करते थे। केवल अनुमति और सहमति ही नहीं, कई बार मैंने और व्यासजी ने अपनी ओर से चलाकर सुझाव दिए हैं और उनको केरीआउट किया हमारे साथियों ने। ऐसी दशा में मेरे लिए यह मानना कि यह उनकी जानकारी के बिना हो गया है। संभव नहीं है। आखिर हुआ क्या इस सारे कांड की जांच हुई, क्या जो परिवर्तन वे करना चाहते थे हुआ उस परिवर्तन के क्या इम्पलीकेशन्स है जांच के बाद, फिर वही पुराना प्रबन्ध रखा गया। जो नई चीज होने जा रही थी उसको रोका गया, उसको रोकना जरूरी समझा गया और वह चीज रुकी। इस अदला बदली का औरकोई उद्देश्य नहीं था। केवल मुख्य मन्त्री पर वैष्णव लोगों का प्रभाव पड़ा और उनके कहने के लिहाज से परिवर्तन कर दिया गया केवल कुछ लोगों के लिहाज से। लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, मुख्य मन्त्री भी बैठे हैं वे इस चीज को ज्यादा साफ करेंगे जो पहले ही हो जाना चाहिये था क्योंकि यह विषय जनता में बहुत बड़ी चर्चा का रहा है। इस बारे में कोई अधिकार पूर्ण विज्ञप्ति भी नहीं निकाली गई अब तक तो इस बात को साफ कर दिया जाना चाहिये था। अगर किसी का प्रभाव भी उन पर था तो मैं उनसे कहूँगा कि आखिर यह तो निर्विवाद है कि वैष्णव लोगों में भी कुछ लोग ऐसे थे जो कि महाराज को इस एक

[श्री टीकाराम पालीवाल]

करोड़ की सम्पत्ति खुले अधिकार देना नहीं चाहते थे और जो इस व्यवस्था को कड़ाई के साथ पालन करवाना चाहते थे । आखिर यह तो मानेंगे मुख्य मन्त्री, वैष्णवों में भी दो राय के लोग जरूर थे। जब दो राय के लोग थे तो यह राय क्यों पसन्द आई जिसमें महाराज को छूट मिले; वह चाहे जैसे उस सम्पत्ति का प्रयोग करें जो प्रबन्ध कड़ा करने की बजाय शिथिल करना चाहते थे वही राय क्यों पसन्द आई, यह एक आश्चर्य की बात है । ऐसी चीजों से ही नीति के दर्शन होते हैं कि हम किस रास्ते पर चल रहे हैं । और भी एक दो बातें सुनी जाती हैं सब चीजों को सुनना एक चीज है और उनको मानना दूसरी बात है हो सकता है उनमें किसी हदतक वास्तविकता भी हो जहां दूसरी बात है उनके लिये चर्चा करना ठीक नहीं ।

एक और दूसरी चीज अखबारों में आई, लेकिन उसका स्पष्टीकरण नहीं आया, वह मामला इतना बडा तो नहीं है किन्तु ट्रेन्ड तो बतलाता है । नीति की दृष्टि से वह महत्वपूर्ण माना जा सकता है । वह था एक कांड जमीन का । कोटा में एक जमीन थी किन्हीं जागीरदार या चारण की; मुझे मालूम नहीं इस सदन में इससे पहले इस पर चर्चा हुई या नहीं........

एक माननीय सदस्य—मामूली सी हो कर रह गई, लेकिन उसका जवाब नहीं आया ।

श्री टीकाराम पालीवाल—मैं यह चाहता हूँ कि निश्चित चीजें सामने आनी चाहिये, खास तौर से उस हालत में जब कि उनसे हाइएस्ट लेवल के लोग कन्सर्न्ड हों तो तथ्य सामने आने चाहिये । कोटा की जमीन के बारे में बतलाया जाता है कि जब कोटा गवर्नमेन्ट ने उस जमीन को एक्वायर करने का आदेश दिया तो उसमें दो आने प्रति गज हिसाब से कम्पेनसेशन देने का तय किय और बाद में उन जागीरदार महोदय ने चार आने गज के हिसाब से क्लेम किया बतलाते हैं । चार आने गज का क्लेम उन जागीरदार महोदय ने किया यह कहा जाता है । यह चार आने गज की बात मैंने स्वयं तो कागज में नहीं देखी, मेरे साथी ने कागजों से देखी है और मैं उन्हीं के कहने के आधार पर कहता हूँ । कागज देखने से, पत्रावली देखने से यह साफ प्रकट होता है कि उस चार आने गज का जो कम्पेनसेशन मांगा गया उस समय किसी स्टेज पर पुराना राजस्थान बन गया, तब दुबारा वह कागज कलैक्टर को उस पर अवार्ड देने के लिये भेजा गया कि इस पर कलेक्टर का अवार्ड होना चाहिये । तो कलेक्टर के पास जब वे कागजात पहुँचे तो कलेक्टर ने उस जमीन का जिस जमीन का कोटा गवर्नमेन्ट ने दो आना कम्पेनसेशन देने का तय किया और जिसके लिये जागीरदार महोदय स्वयं चार आना मांगते थे, कलैक्टर ने उस पर सवा दो रुपये का अवार्ड दिया । यही फाइल पर बताया जाता है । यह कैसे हुआ ? कोई भी अधिकारी के द्वारा इस प्रकार चीजें करना मुझे असंभव मालूम होता है । अभी जैसा कि मेरे साथी बतला रहे हैं उस फाइल पर नीचे से फोरजरी हुई । जो एप्लीकेशन चार आने गज के लिये दी गई थी उस चार आने की पाई को तो ज्यों का त्यों रखा; उसके आगे दो और बढ़ा दिया गया । अर्थात उस एप्लीकेशन में चार आने की जगह सवा दो रुपया कर दिया गया । उस एप्लीकेशन को

[श्री टीकाराम पालीवाल]

देखने से ऐसा बताया जाता है बाकी हिस्सा एप्लीकेशन का और लैंगवेज में कोई तब्दीली नहीं लेकिन जो दो का अङ्क किया गया वह निश्चित रूप से अलग अलग मालूम पड़ रहा है। फिर बाद में फाइल पर नोटिंग हुआ है उस पर किसी समय अंग्रेजी में हुआ बतलाया जाता है और अंग्रेजी में 'फोर आनाज पर यार्ड' नोटिस हुआ है। फिर किसी स्टेज पर उसको काटकर फोर अनाज तो यों का यों रखा गया पर यार्ड शब्द काटकर पर फुट किया गया है यह कटा हुआ बतलाया जाता है। इस चीज को देखा है जिसने वे इस नतीजे पर पहुँचे हैं निश्चित रूप से बाद में गोलमाल हुआ है। बाद में किसी के इशारे पर यह काट छांट हुई यह मैं नहीं कह सकता। यह हुआ इसलिये उन्होंने यह निर्णय किया कि सवा दो रुपये का जो कलेक्टर का अवार्ड है वह दे दिया जाय और जैसी सिफारिस की गई है वह मन्जूर कर ली जाय जब कि कोटा इम्प्रवमेन्ट ट्रस्ट मना कर रहा है इस रेट पर वह जमीन नहीं ले सकता उस पर यह हुआ कि यदि इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट सवा दो रुपया दे दे तो सरकार उस ट्रस्ट को रुपया देने को तैयार है। उस सिफारिश को मानने से मना कर दिया और फिर ऐसा समय आया और वह किस्सा खत्म हो गया लेकिन उसके बाद यह सुना गया मिनिस्टीरियल लैवल पर वह मामला चला है। अगर इसमें कुछ गलत हो तो आइ एम ओपन टू करेक्शन; मिनिस्टीरियल लैवल पर इस बीच को फिर दुबारा उठाया गया और सवा दो रुपये गज के हिसाब से कम्पेनसेशन देने का आर्डर कर दिया।

श्री भैरूसिंह—Ministerial level means class fourth level....?

श्री पालीवाल—I mean cabinet lavel.

केबीनेट लैवल पर यह आर्डर्स हो गये कि सवा दो रुपये के हिसाब से दे दिया जाय। यह बात जहां दो आने की थी वहां सवा दो रुपया होना दीखने में तो कोई बड़ी बात मालूम नहीं होती। जितनी जमीन बताई जाती है दो आने गज के हिसाब से करीब १३ हजार रुपया होता है। चार आने गज के हिसाब से २६, २७ हजार रुपया करीब होता है, और सवा दो रुपये के हिसाब से ढाई लाख रुपया बनता है।

तो कोटा गवर्नमेंन्ट ने १३ हजार जिस चीज का तय किया और जैसा कि खुद ने २६ हजार मागे उसको सवा दो लाख ढाई लाख देने की बात तय की जावे तो यह बात क्यों हो गई ?

श्री अवनीकुमार मुकर्जी—क्या इस रुपये पर ब्याज भी दिया गया है ?

श्री टीका राम पालीवाल—सिर्फ यही नहीं बल्कि ब्याज भी दिया जाना चाहिये, यह भी ऑर्डर हुआ।

(हियर हियर एवं करतल ध्वनि)

[श्री टीकाराम पालीवाल]

इसके बारे में बहुत ज्यादा शोर नहीं करें। यह शोर करने की बात नहीं है। व्याज को मिलाकर तीन लाख की बात हुई। यह चीज अखबारों में भी आई और बहुत दिन पहले आई। मुझे याद नहीं, पर कहा यह गया कि इस सदन में भी चर्चा हुई। पर इसका कोई भी स्पष्टीकरण अधिकृत रूप से नहीं किया गया। गोलमाल बातें कही गईं। टाला जाय, यह बात दूसरी है। इससे सन्तोष नहीं होता इन्टेलीजैन्ट लोगों को कम से कम। गांवों में जाकर लोगों को किसी तरह से समझा दो, यह दूसरी बात है।

फिर यह भी सुना कि यह उड़ते उड़ते खबर ऊपर पहुँची और जब अधिकार पूर्ण स्थान पर पहुँची यह चीज तो कागजों को वहां मंगाया गया और उन्हें देखा गया तो वहां से यह आर्डर हुआ कि यह तीन लाख ढाई लाख रुपया नहीं दिया जा सकता। जो पहला निश्चय है गवर्नमेंट का वह ठीक है, अगर वह व्यक्ति कोर्ट में चाराजोई करना चाहे तो करे।

आखिर इस प्रकार की महत्वपूर्ण बातों में यह तो फैक्ट है ही न कि जो निर्णय ढाई लाख का किया गया उसको सही नहीं माना गया। इसमें दो रायें हैं क्या ? पर प्रश्न रह जाता है कि इतना गलत निर्णय क्यों किया गया ? क्या चीज थी इसके पीछे ! जिस अफसर ने उसे सवा दो रुपये का अवार्ड दिया, मुझे निश्चित तो नहीं मालूम यह किस अफसर ने किया लेकिन नाम जिस अफसर के लिये लिया जाता है उसको मैं भी जानता हूं और मेरी भी धारणा है और जैसी कि और लोगों की भी धारणा है उस अफसर के बारे में कि उस अफसर की इन्टेग्रिटी को कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते। उन अफसरों को जिनको करप्ट अफसर गिना जाता है उन करप्ट अफसरों की गणना में उस अफसर की गणना नहीं की जा सकती। कमजोर अफसरों में उसकी गणना जरुर की जाती है पर करप्टों में नहीं। तो फिर इससे और कुछ चीज सामने आई जोकि (अश्रव्य) इम्प्रेसेज टैकटिक्स हो सकती है। और वे इम्प्रेसेज और भी ज्यादा स्ट्रांग उस वक्त हो जाती हैं जब यह मालूम होता है कि उस निर्णय को जिसको एक मिनिस्टर पहले नामन्जूर कर चुका तो यह सही नहीं हुआ है। जिसके बारे में एक मिनिस्टर ने पोइन्ट आउट किया कि यह फोर्जरी हुई है, उसको बदल कर फिर दुबारा उस कलेक्टर के निर्णय के अनुसार निर्णय केबिनेट लेवल पर होता है और उस निर्णय को बदल देने के बाद भी उस अफसर से कोई पूछ ताछ नहीं की जाती कि तुमने ऐसा क्यों किया, किस आधार पर किया ? काट छांट की बात छोड दीजिये मान लीजिये कि फोर्जरी नहीं है। चार आना गज नहीं मांगा, दो आना गज ही मांगा था फिर भी क्या यह रीजन को अपील करतो है; जिसको थोडी सी भी बुद्धि है उसकी बुद्धि को अपील करती है। एक सवा दो रुपया गज का कम्पेन्सेशन मांगता है जिसको कि दो आना कम्पेन्सेशन देना ठीक समझा गया था और फिर सवा दो रुपया मांगता है और कलक्टर भी सवा दो का पूरे का पूरा ही अवार्ड देता है, दो रुपया भी करना उचित नहीं समझा तो यह क्या बात रीजन को अपील करती है। क्या उस कलक्टर ने उसमें अपना डिस्क्रेशन इस्तैमाल किया ! उसका क्या बेसिस था ! ऐसी कोई चीज नहीं मालूम पडती। इससे साफ पता लगता है कि इनएविटेबली उसको इम्प्रैस किया

[श्री टीकाराम पालीवाल]

गया। उसने अपनी मरजी से नहीं किया। उससे यह काम करवाया गया। किसने करवाया होगा, यह अन्दाज लगाया जा सकता है।

कु० श्री **जसवन्तसिंह**—हम तो अन्दाज नहीं लगा सकते।

श्री **हिम्मत सिंह**—मैं अन्दाज लगा सकता हूँ।

श्री **टीकाराम पालीवाल**—इन चीजों का कोई स्पष्टीकरण आना चाहिये, निश्चित स्पष्टीकरण आना चाहिये।

श्री **मोहन लाल सुखाड़िया**—कहीं आपकी मिनिस्ट्री में सैंक्शन होना साबित नहीं हो जावे।

श्री **टीकाराम पालीवाल**—हो सकता है। मेरी मिनिस्ट्री में सारे ही मिनिस्टरों के कामों की जानकारी मुझे हो, यह मैं कह भी नहीं सकता। पर मेरे दोस्तों को याद होगा कि जो बात मेरे ध्यान में आई और जो ठीक नहीं थी उनको मैंने बराबर रोका। यह मोहाना बीड दिया जा रहा था तीन लाख में। मैंने उसको दिये जाने से रोका और कई काम हुए जिनको मैंने रोका। सांगानेर का मोहनबीड खड़ा है आज भी जिसको जाकर कोई भी देखना चाहे तो देख ले। कम से कम तीन लाख की लकड़ी पडी है। कुछ दोस्तों को दिया था मेरे रेवेन्यू मिनिस्टर ने पर मैंने इन्कार किया।

(करतल ध्वनि)

और मेरी मिनिस्ट्री की बातें और बतलाता हूँ।

श्री **मोहनलाल सुखाड़िया**—यह आपने ही देने के लिये कहा था, मैं आपको याद दिला दूं।

श्री **टीकाराम पालीवाल**—गलत कहते हैं आप। आपने ही एप्रोच किया था। यह बात सत्य से उतनी ही दूर है कि जितनी अमावस्या की रात्रि में दोपहर के सूर्य का उगना।

(करतल ध्वनि)

और बताऊं।

श्री **कुम्भाराम आर्य**—सवाई माधोपुर का बीड किसने दिया था? अभी लकड़ियां बिक रहीं हैं बाजार में।

श्री **टीकाराम पालीवाल**—वह भी मैं कहने वाला था।

१. श्री हिम्मतसिंह अटरू—अध्यक्ष महोदय, हद हो गई यह तो।

श्री टीकाराम पालीवाल—मेरी मिनिस्टरी में ही नहीं, फाइनेन्स मिनिस्टर था तब की बात बताऊं। मैंने कई बातों पर अंकुश लगाया, जहां तक बना अंकुश लगाया। एक सदस्य ने कल कम्प्रेसर की बात की कि कितने ही के कम्प्रेसर आ गये। मेरे सामने यह चीज आई और वह कम्प्रेसर की चीज बाकायदा मेरे सामने आने के पहले में यह अफवाह सुन रहा था कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेन्ट में जब कि में फाइनेन्स मिनिस्टर था, तब की बात कहता हूं, १०-१५ लाख की मशीनरी खरीद रहा है और इसमें माथुर साहब के भाई इन्टरेस्टेड हैं। [हियर हियर]

श्री गोपीलाल यादव— मेरी समझ में नहीं आता ....

श्री टीकाराम पालीवाल—You do not want to allow me ?

(कुछ विराम के अनन्तर)

I am serious

श्री गोपीलाल यादव.... आपकी क्लेक्टिव रेस्पोन्सिबिलिटी है। We will believe you as well as them.

श्री टीकाराम पालीवाल.... मैं तो कहता हूं मैं इसमें शामिल हूं।

श्री गोपीलाल यादव .... यह इस वक्त होना भी नहीं चाहिये। इस

(हंसी एवं करतल ध्वनि)

श्री टीकाराम पालीवाल.... में स्पष्ट करना चाहता हूं कि....

श्री घीसीसिंह .... हमको तो पता नहीं चल रहा है कि यह क्या हो रह हैं, दोनों तरफ से हमको तो बातें सुनने को मिल ही रही हैं।

(हंसी एवं करतल ध्वनि)

श्री अध्यक्ष.... Order please ! order please !! The hon'ble member will have the right to speak. He should not be interrupted in the middle and I take it that the House will allow him to have his say.

श्री गोपीलाल यादव—वे कुछ कहेंगे, आप कुछ कहेंगे। इससे फायदा क्या होगा ?

श्री टीकाराम पालीवाल—आप सच्चाई से क्यों डरते हैं, आनी चाहिये सारी बातें सच्चाई हैं अगर तो।

श्री गोपीलाल यादव.... डरता नहीं हूं टाईम वेस्ट होता है।

श्री टीकाराम पालीवाल.... It is not wasting time and no body except the chair has a right to say whether I am wasting the time or not. what is it? जिन कम्प्रेसरों के बारे में मैं कह रहा था दस लाख की बात हो सकती हैं, पन्द्रह हो सकते हैं, मुझे एग्जेक्ट फिगर याद नहीं। पर मैं यह बताना चाहता हूं कि मुझसे जहां तक हुआ मैंने ये चीजें रोकने की कोशिश कीं। यह गलत है कि मैंने किसी की सिफारिश की। वैसे मैं रोक नहीं पाता। पर एट दी इलेवन्थ आवर मुझे मालूम हुई और मैंने उसी समय कलक्टर को टेलीफोन किया; कल जंगल का कब्जा दिया जाने वाला है! मैंने कलक्टर को फोन करके उसे रोका और यह कहा उसे रोको, इस मामले को दुबारा तय करना है और मैंने अपने फोरेस्ट मिनिस्टर श्री यादव जी को कहा कि तुम जाकर देखो कि वह चीज देने लायक है क्या? उन्होंने रिपोर्ट की कि यह चीज कभी नहीं देने की है।

श्री अमृतलाल यादव.... किस बारे में?

श्री टीकाराम पालीवाल.... मोहाना बीड की बात है।

श्री भैरूसिंह....(१६) कुकस के बीड़ के बारे में भी बताने की कृपा करें।

श्री टीकाराम पालीवाल.... कुकस के बीड को रोका गया जब कि मेरे हाथ में अधिकार नहीं था।

श्री अध्यक्ष— There will be no interruption.

श्री टीकाराम पालीवाल....(जारी) तो उस समय वह १० लाख के कम्प्रेशर्स का मामला मेरे सामने आया जिसकी शायद कल चर्चा हुई है। मेरे सामने भी वह चीज़ रखी गई। एग्रीकलचर डिपार्टमेन्ट में कुए खुदवाने के लिये कुछ कम्प्रेशर्स की जरूरत है इसलिये एक कम्प्रेशर नहीं बल्कि कई कम्प्रेशर्स खरीदने में, जिनकी १० लाख कीमत होती थी; तो जो चीज मैं सुन रहा था वह याद आई जब कि फायल मेरे सामने आई और मुझे शक हुआ कि इसमें गड़बड़ जरूर है इसलिये इसमें मैंने ज्यादा गहराई से देखा वर्ना मुमकिन है कि कन्करेन्स के लिये फाइनेन्स में आता है तो जो डिपार्टमेन्ट की बजेटेड रकम है उस पर कन्करेन्स दे दी जाती है मामूली तौर पर, और उसकी स्वीकृति देनी चाहिये। गहराई से देखने पर मैंने यह देखा कि टेन्डर्स लोगों के लिये, और कई लोगों के टेन्डर्स आये। कुछ ऐसे लोगों के टेन्डर्स थे जिनके कम्प्रेशर्स आलरेडी बाजार में चल रहे थे,

[श्री टीकाराम पालीवाल]

काम दे रहे थे, और एक टेन्डर ऐसे किसी कम्प्रेशर्स का था, उसका नाम याद नहीं है, जो बिल्कुल नया था, हिन्दुस्तान में नया था, अनटाइड चीज थी जिसके बारे में यह नहीं कहा जा सकता है कि यहां को कन्डीशन्स में वह सफल हो सकेगा या नहीं। मुझे आश्चर्य हुआ यह देख कर कि जो रिकमन्डेशन्स आई थी उसमें आधे से अधिक आर्डर एक कम्प्रेशर के लिए था, जो कि अनटाइड था, जिसके बारे में शक था कि वह कामयाब होगा या नहीं। बाकी एक दो आइटम्स दूसरों के लिए थे। स्पष्ट हो गया था इसलिए ज्यादा विवाद में न पड़ कर मैं यह सिफारिश की, उसे एग्री नहीं किया कि गवर्नमेंट आफ इंडिया के स्टोर्स परचेज डिपार्टमेंट से हमको वह मशीनरीं खरीदनी चाहिए। मेरी इस शिफारिस के दो करण थे। सब से पहला तो यह कि गवर्नमेंट आफ इडिया को जो मैन मेन्युफेक्चरर्स हैं वह अपनी चीजों को खास तौर से कन्सेशन रेट्स पर देते हैं। गवर्नमेंट के लिए एक अलग रेट होती है और पब्लिक के लिए अलग रेट होती है। गवर्नमेंट रेट एक कन्सेशनल रेट होती है। तो मेरा उद्देश्य यह था कि हमको कन्सेशनल रेट्स का फायदा मिल जायगा तथा दूसरा कारण यह था कि गवर्नमेंट आफ इडिया के स्टोर्स परचेज डिपार्टमेंट के जरिये खरीदेंगे तो यह भी मालूम हो जायगा कि कौनसी चीज हिन्दुस्तान की हालत जो है उसके उपयुक्त होगी। यह रिकमन्डेशन मैंने की थी। उस मेन रिकमन्डेशन को दोस्त मना नहीं कर सकते थे। तो वह फाइल लेकर मेरे पास आये और कहने लगे कि यह माथुर के भाई का आर्डर है, इसको करना चाहिए लेकिन आई डिडनॉट एग्री विद हिम। (हंसी) और मैं समझता था कि वह चीज खत्म हो गई लेकिन कल सुनने से मालूम हुआ है कि कम्प्रेशर्स खरीदे गये हैं। मैं देखता हूं कि मेरे गवर्नमेंट में नहीं रहने के बाद वह चीज हो गई। तो मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रकार की चीजों से विश्वास तो पैदा नहीं हो सकता। आप उप चुनाव चाहे जीत लें, यह दूसरी बात है उपचुनाव तो आप और दूसरे कारण से भी जीत सकते हैं, लेकिन विश्वास पैदा नहीं हो सकता। मैं, अध्यक्ष महोदय, ये चीजें ऐसी थीं, जिनकी चर्चा नहीं करना चाहता था लेकिन गलत तरीके से चीजों को डिफेन्ड करते जांय तो ठीक नहीं है।

श्री रामनिवास मिर्धा.... वे कम्प्रेशर्स गवर्नमेंट आफ इन्डिया से खरीदे गये हैं।

श्री पालीवाल.... तो मैं समझता हूं कि मैंने निवेदन किया था जिनके बारे में अगर वह कम्प्रेशर्स गवर्नमेंट आफ इंडिया से खरीदे गये, तो अच्छा हुआ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया.... माथुर के भाई से नहीं खरीदे गये।

श्री पालीवाल.... उस वक्त तो खरीदे जा रहे थे। अगर नहीं रोके जाते तो खरीदे जाते।

श्री सुखाड़िया.... उसका जवाब तो मैं कल दूंगा।

श्री पालीवाल.... बाजार में जो चलने वाले कम्प्रेशर्स हैं उनमें कमीशन कम मिलता है। नये में कमीशन की पर्सेन्टेज बहुत बड़ी होती है।

श्री जसवन्तसिंह— कांग्रेस की इतनी सेवा करते हैं बेचारे। अगर हुआ है तो क्या हो गया ?

श्री टीकाराम पालीवाल—(जारी) I will not mind spending more for something which is worth while than spending any thing on a worthless thing.

इस प्रकार से मैं आपसे कहता हूँ कि नीति प्रकट होती है हमारे कामों से और कल भी चर्चा हुई और शायद आज भी किसी ने चर्चा की एक टेक्स्ट बुक के बारे में, उसका सीधा सम्बन्ध है, इधर के मुख्य सचेतक से। एक साल से अधिक होगया। एक साल होगया करीब करीब और उसके बारे में जो तथ्य हैं उन तथ्यों के लिए कोई बहुत बड़ी एन्क्वायरी की जरूरत नहीं है। सीधा सादा तथ्य है और वह यह है कि किसी खास बैक ग्राउन्ड के पीछे मैंने अपने साथी जो मेरे साथ एजूकेशन मिनिस्टर थे उनको मैंने यह सलाह दी थी कि टेक्स्ट बुक के सिलेक्शन के लिए जो मशीनरी सिलेक्ट करें उसमें इस बात का ध्यान रखें कि उसके पहले साल में जिस प्रकार का गोलमाल हुआ था वह नहीं हो पाये जिससे कि कांग्रेस गवर्नमेंट बदनाम हुई थी। इसलिए मैंने उनको काशन किया कि अब की दफा ऐसी मशीनरी डिवाइस करें कि जिससे व गोलमाल न हो पाये, और उन्होंने बड़ी वफादारी के साथ, सचाई के साथ जितनी कोशिश कर सकते थे ऐसी मशीनरी डिवाइस की और वह मशीनरी यह थी कि आथर्स को यह कहा गया था कि वह डिपार्टमेंट में अपनी किताबें भेज दें और और डिपार्टमेंट को यह इन्स्ट्रक्शन्स थे कि वह ऑथर या पब्लिशर जिस किसी की तरफ से आई है उनके ऊपर का जो टाइटल पेज है उसको अलग निकाल कर रखें, और हरेक किताब को एक सीक्रेट नम्बर दिया जाय। वह नम्बर सीक्रेट रहने वाला था। यह आर्डर मेरी सलाह से शिक्षा मन्त्री ने दिया था उस वक्त। रिव्युअर्स व एक्जामिनर्स वगैरह थे उनके नाम सीक्रेट रखने की कोशिश की गई। किसी को उनका नाम मालूम नहीं पड़ा, लेकिन यह सारा प्रबन्ध किया गया। नम्बर एलाट किये जायं वह सीक्रेट रहें। रिव्युअर्स के नाम सीक्रेट रहे। यह सीक्रेसी हमने जितनी होनी चाहिए रखने की कोशिश की। मेरे बावजूद और मेरे एजूकेशन मिनिस्टर के बावजूद भी कुछ लोगों ने उन नम्बर्स को जान लिया और रिव्युअर्स के नाम भी जान लिये, और एक क्लार्क भी गिरफतार हुआ था सेक्रेटेरियेट का। उसके पश्चात का पता नहीं कि क्या क्या मसाला मिला। यह सीक्रेट लीक करने के सिलसिले में मुझे मालूम हुआ कि एक गिरफतारी हुई। उसका क्या हुआ बाद में मालूम नहीं मैं गवर्नमेंट में नहीं था इसलिए मालूम नहीं। लेकिन बाद में जो पत्र माथुर साहब का यहां पेश किया गया वह उनके ही हैन्ड राइटिंग से उनका ही साइन किया हुआ था, इसलिए मानने के अलावा दूसरा चारा नहीं है। उन्होंने साफ तौर से सिफारिश करी थी एक किताब के बारे में जिसके ऊपर की नम्बर लिखा हुआ था कि अमुक नम्बर की किताब का ध्यान रखेंगे। ऐसी सिफारिश की थी एक पब्लिक सरवेन्ट को, डाईरेक्टर को। उसका एक्स्प्लेनेशन यह दिया जाता है कि वह लेटर कभी उनके पास पहुँचा ही नहीं, और माननीय मुख्य मंत्रीजी ने भी इस एक्स्प्लेनेशन को काफी समझ लिया और अगर सिफारिश कर दी तो इननोसेन्स सी चीज मानली और उसकी एन्क्वायरी करने में एक साल लग; गया जब मैं कहना नहीं चाहता था, उस समय मैंने कहना ठीक

[श्री टीकाराम पालीवाल]

नहीं समझा, और मुख्य मंत्रीजी को ही इसकी सूचना दी, लेकिन आज इसलिए कहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्रीजी उस पर सो गये। मैंने सूचना दी थी कि यह कहना कि यह लेटर डाइरेक्टर के पास नहीं पहुंचा गलत है, क्योंकि डाइरेक्टर ने वह लेटर मुझको दिखाया था (हियर, हियर) और किन सरकमस्टानसैज में देखा था वह भी बता दिये (कु० श्री जसवन्तसिंहजी के हंसने पर) कुंवर साहब........

कुँ० श्री जसवंतसिंह—I am sorry.

श्री टीकाराम पालीवाल—I am not saying anything for any body's pleasure. I am saying because I feel & if somebody derives plasure out of it, I resent it.

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—All right.

श्री टीकाराम पालीवाल—किन्हीं खास परिस्थिति में वह लेटर मुझे दिखाया था और वह परिस्थिति यह थी कि उनको पहले जैसा कि उन्होंने आकर बतलाया था एक एजीटेटेड मूड में मेरे पास आये थे जब कि मैं गवर्नमेंट में नहीं था। यह शायद जून या अप्रेल थी जब कि मैं गवर्नमेंट में नहीं था; तो वह मेरे पास आये थे, जून या जुलाई के आसपास। बहुत एजिटेटेड मूड में मेरे पास आये और कहने लगे कि मुझे आश्वासन दिया था कि तुमको एक्सटेन्शन दिया जायगा लेकिन अब एक दम मुझे रिटायर करने का ओर्डर भेज दिया जिससे मैं छुट्टी भी नहीं ले सका। पहले पता चलता तो छुट्टी तो अवेल कर लेता, अब मुझे वे रिटायर कर रहे हैं और देखिये इस प्रकार से मेरे से काम लेते रहे है इसके बावजूद भी हमारे साथ इस तरह का दुर्व्यवहार किया जाता है। इस तरह से काम लेते रहने के संबंध में यह चिट्ठी दिखाई थी। उन्होंने यह नहीं किया कि इस प्रकार का मैंने काम किया या नहीं किया और मुझे भी पूछने की जरूरत नहीं थी लेकिन मुझे वह लेटर दिखाया था। यह सूचना मैने मुख्य मंत्रीजी को दी एक लेटर के द्वारा और मुख्य मंत्रीजी ने मेरे पास जवाब भेजा, एक लेटर लिखकर भेज दिया और उसमें यह लिखा कि मैंने डाइरेक्टर साहब के पास एक लेटर भेजा था उसके जवाब में जो लेटर उनके पास से आया है उसकी प्रतिलिपि भेज रहा हूं। आपने उनसे पूछा बताया कि ऐसा लेटर आप के पास पहुँचा या नहीं। यह पूछने की जरूरत क्यों पड़ी? उस के जवाब में उन्होंने यह लिखा कि यह लेटर मुझे नहीं मिला। प्रत्येक सदस्य आज जिसके पास न्याय की दृष्टि है उनसे मैं पूछता हूँ कि क्या ऐसी परिस्थिति में डाइरेक्टर यह बात जाहिर करेगा क्या जब कि सिलेक्शन न्यायपूर्वक करना चाहिये और उससे सिफारिश की जाती है कि तुम इस पुस्तक में रियायत करो और वह कर डाले तो क्या वह स्वीकार करेगा कि मैंने ऐसा किया है। ऐसी हालत में क्या उसका जवाब संतोषप्रद हो सकता है। और उसके बाद में मुख्य मंत्रीजी चुप बैठे रहे। इसके बाद में क्या उन्होंने कोई इन्क्वायरी की है या सिर्फ यही लेटर एडमिट करके ही बैठ गये?

[श्री टीकाराम पालीवाल]

किताब सिलेक्ट की गई। इसका फर्स्ट नंबर नहीं आता है, दूसरा नंबर आता है। पर्टिकुलरली यह चीज देखने की है कि इसको स्वीकार किया गया। एक और किताब थी जिसको रिव्यूअर्स ने फर्स्ट नंबर दिया था और उसको फर्स्ट नंबर से स्वीकार किया गया लेकिन फिर उसको ब्लेक लिस्ट कर दिया गया क्यों कि उसके पब्लिशर ने सीक्रेट नंबर मालूम करने की कोशिश की। जिस किताब को रिव्यूअर्स ने फर्स्ट रखा उसको ब्लेक लिस्ट किया गया इसलिये कि उसके पब्लिशर ने नंबर मालूम करने की कोशिश की या मालूम कर लिया होगा, इसलिये उसे ब्लेक लिस्ट किया गया और इसलिये कि इस किताब को दूसरा नंबर दिया गया था, सिफारिश के आधार पर इसलिये वह फर्स्ट हो गई। ज्यादा से ज्यादा आप कहेंगे कि सिफारिश के आधार पर नहीं लेकिन उसका सेकन्ड नंबर ही था। सेकन्ड नंबर तक आने में सिफारिश ने काम नहीं किया यह कहेंगे, लेकिन मैं फिर पूछता हूँ कि इसका क्या जवाब है कि एक किताब का नंबर मालूम करने के अपराध में ब्लेक लिस्ट किया गया और दूसरी किताब नंबर मालूम करने के आधार पर फर्स्ट हो गई और वह फर्स्ट आज तक मौजूद है। आप यह कह सकते है कि सिफारिश की बात नहीं मालूम थी जब कि उसे फर्स्ट किया गया। लेकिन मालूम पड़ने के बाद आपने क्या किया ? क्या उसे ब्लेक लिस्ट किया या किताब को रिमूव किया केरिकुलम से ?

माथुर साहब का कहना है कि सीक्रेट नंबर मैंने नहीं मालूम किये, गणपत माथुर ने मालूम किया होगा। लेकिन गणपत माथुर की पहुँच नहीं हो सकती कि वह गुप्त नंबर मालूम करलें। इस तरह की पहुँच माथुर साहब की ही हो सकती है। मान लीजिये कि उन्होंने नहीं मालूम किया, गणपत माथुर ने किया लेकिन फिर गणपत माथुर के खिलाफ कुछ एक्शन लिया गया क्या ? ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में पॉवर दी गई है कि जो गवर्नमेन्ट के सीक्रेट्स मालूम करे उसे सजा दी जा सकती है। जब इस किताब के बारे में मालूम हो गया, मान लीजिये सिफारिश नहीं चली, डाइरेक्टर ने सिफारिश के आधार पर फर्स्ट नहीं किया तब भी यह तो मालूम हो गया कि इस ओथर को सीक्रेट नंबर मालूम हो गया है; तो उस ओथर की किताब को क्यों नहीं रिमूव किया गया ? वाट इज इट ? गोलमाल जवाब का क्या अर्थ है। क्या ईमानदारी के साथ जवाब दिया जा सकता है कि हम निष्पक्ष रूप से बिना भेदभाव के इस चीज को चला रहे हैं ? कुछ चीजें ऐसी होती हैं जहां बस नहीं चलता, लेकिन बस चलता है वहां भी नही चलाया जा रहा है। मैं निवेदन करता हूँ कि इसके बाद होने वाली चीज भी सामने नहीं आती, उसको एक साल हो गया है।

दूसरी परंपरा की बात करते हैं। पार्लियामेन्ट में एक केस ऐसा हुआ था उसकी नेचर ऑन आल फोर्स वही नहीं थी। यदि हाई कोर्ट की तरह नजीर ढूंढना चाहें ओन आल फोर्स तो ऐसी नजीर नहीं मिल सकती क्योंकि इस प्रकार के केसेज कभी कभी ही हुआ करते हैं।........

श्री मोहनलाल सुखाडिया—मुझे इन्टरपशन के लिये माफ करें, माननीय अध्यक्ष। इस बहस के बाद आपके और मेरे विचारने की बात की जरूरत नहीं रहेगी और न कुछ कहने की

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

आवश्यकता प्रतीत होगी। वेदपालजी के कहने के बाद सोच रहे थे, We are going into the merits of the case.

श्री वेदपाल त्यागी—प्रतीक्षा की भी हद होती है।

श्री मोहनलाल सुखाडिया—मैं ऐतराज नहीं करता, लेकिन फिर हम दोनों को विचार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

श्री अध्यक्ष—When the Leader stands, he should not be interrupted.

श्री टीकाराम पालीवाल—मैं यह निवेदन कर रहा था कि ओरडिनेरी क्रिमिनल केसेज में नजीर ओन आल फोर्स मिल सकती है इसलिये कि जन साधारण में साधारण आदमी एक से जुर्म करते रहते हैं और वे केसेज इनवेरिएबली कोर्ट्स में पहुँचते रहते हैं इसलिये बहुत से केसेज एक प्रकार के निकल जाते हैं। लेकिन किसी विधान सभा के सदस्य इस प्रकार की कार्यवाही करते हों, ऐसे केसेज कम होते हैं। इसलिये ओन आल फोर्स ऐसी नजीर नहीं मिल सकती। हां, सिद्धान्त एक से आप को मिल जायेंगे। यह चीज आपको मुद्गल केस में मिल जायगी जिसमें श्री मुद्गल को पार्लियामेन्ट से एक्सपेल किया गया और हमारे नेता श्री जवाहरलालजी नेहरू के कहने पर किया गया। पार्लियामेन्टरी परंपरा है कि सदन के नेता ऐसे मामलों में इनिशियेटिव लें, ऐसे मामलों में उनके द्वारा प्रोटेक्टिव व्यू नहीं लिया जाता है। दूसरे देशों में भी ऐसा ही हुआ है। जिन देशों में ऐसी चीजें आई हैं वहां पर सदन के नेता ने इनिशियेटिव लेकर इन्क्वारी कराई है और उन सदस्यों के खिलाफ एक्शन लिया गया है और कई जगह तो सदस्यों ने खुद ने अपनी हालत देखकर स्थान छोड़ दिया है। ऐसी परंपरा है। आप क्या परंपरा की बात करेंगे? ये हमारी परंपराएं हैं और इन चीजों के होते हुए भी आश्चर्य होता है जब कभी कभी इतनी स्पष्ट चीज को जानते हुए भी कुछ लोग सुनते होंगे जो स्वयं इससे सीधे संबंधित नहीं है उन लोगों को भी थोडी बेचैनी हो रही है। वह बेचैनी क्यों हो रही है, समझ में नहीं आया। वह बेचैनी वैसी ही मालूम होती है जब हम राजाओं के शासन काल में उनके शासन की आलोचना करते थे तब उनके जो भृत्य हुआ करते थे वे राजाओं से भी ज्यादा नाराज होते थे क्योंकि उनसे वे सम्बन्धित थे, उन पर डिपेन्डेन्ट थे। वे उनसे भी ज्यादा नाराज मालूम होते थे। वह नाराजगी इस सदन के सदस्यों के लिये नहीं है। इस सदन के सदस्य खुले दिमाग से बात सोचें और क्लीयर निर्णय दें और गाइडेंस दें कि किस प्रकार काम करना चाहिये। लेकिन यदि हम केवल अपने बहुमत के जोर पर जो मूल सिद्धान्त है शासन का जिसको लेकर हमने कांग्रेस में रहकर इतने वर्षों तक लडाई लडी और देश के सामने बडा नक्शा पेश किया। इन चीजों के बल पर, केवल अपने बहुमत के बलपर चलते रहे तो मैं, माननीय अध्यक्ष से यह निवेदन करूंगा कि यह बड़ी खतरनाक स्थिति होगी, खतरनाक इस माने में कहता हूँ कि जो स्थिति आज राजस्थान में करप्शन की, इन्टेन्सिटी के हिसाब से, पक्षपात के हिसाब से पब्लिक में जो थिंकिंग

[श्री टीकाराम पालीवाल]

पार्टी है उनमें जो शासन के प्रति एक प्रकार की अप्रतिष्ठा की भावना आ गई है उसको देखते हुए यह कहा जा सकता है कि अच्छे से अच्छे ऑफीसर को यह मालूम नहीं कि उसकी स्थिति क्या है, यदि वह बड़े बड़े अधिकारियों के इशारे पर नहीं चले। यदि वह अपनी आत्मा के अनुसार किसी चीज को सही समझ कर करें और दूसरों के इशारों पर नहीं चले तो तुम्हारी क्या दशा होती है? अगर यह हालत हो जाती हैं तो Sense of insecurity discontentment किया जा रहा है। अगर ऐसी ही स्थिति वेस्टर्न देशों में हो जो देश राजस्थान के बराबर स्वतन्त्र हों तो वहां की स्थिति ऐसी हालत में क्या हो जावेगी जब कि वहां के विधान सभा के सदस्यों में इस प्रकार का असंतोष हो और सर्विसेज में इतना डिसकन्टेन्टमेंट हो; तो मैं यह कहूँगा कि शासन को पलटने की नौबत आ जाती है। अगर वैधानिक रास्तों से पलटा जा सकता है तो ठीक, अन्यथा बाई फोर्स कई जगह शासन पलट दिया गया है। इजिप्ट देश में यही हुआ। वहां पर एक गुट का शासन हो गया था, वहां की विधान सभा भी एक मत की सी हो गई और उसकी चलती नहीं थी। वहां का शासन पलट गया। मैं मानता हूँ कि जब तक कांग्रेस की सार्वभौम सत्ता देश में छाई हुई है यहां पर इस प्रकार की नौबत नहीं आ सकती, जब तक उसके प्रति देश सेवा का अस्तित्व है यह स्थिति नहीं आ सकती है लेकिन असंतोष लोगों में है, यह कोई अच्छे लक्षणों की ओर संकेत नहीं है।

श्री अध्यक्ष—It is a proper time to give replies.

श्री गोपीलाल यादव—माननीय अध्यक्ष, बजट पर दो रोज से बहस चल रही है। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि जो बातें अपोजिशन के लोग कहा करते थे और जब मैं भी अपोजिशन में था, कहा करता था, आज कांग्रेस बैंचों पर बैठने वाला हर एक आदमी बोल रहा है और इसके लिये मैं हाउस के नेता को बधाई देता हूँ। मैं पहले शिकायत किया करता था वह यह कि कांग्रेस के सदस्यों को व्हिप लगाना पड़ता था और उनके मुंह पर ताला लगा दिया जाता था लेकिन आज उन्होंने इतनी स्वतन्त्रता दे दी है कि उनकी बेंच पर बैठने वाले जो चाहे बोल सकते हैं।

("हिअर हिअर" की आवाज)

इसके अलावा बजट पर भाषण करने से पहले एक पॉइन्ट ओन दी पॉइन्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन के रूप में यह कह देना चाहता हूं। मेरे मित्र पालीवाल जी ने नाराजी प्रगट करते हुए कहा जब मैंने बीच में कहा। उन्होंने कहा कि कई लोग राजाओं के भक्तों की तरह नाराज होते हैं लेकिन मैं उनको यह बता देना चाहता हूं कि वे एक घण्टा और ४५ मिनट बोले। मैंने कोई इन्ट्रप्ट नहीं किया इन्ट्रप्ट जब किया जब वे ऐसी बात कह रहे थे जिसको कि मैं आज कल केबिनेट की परम्पराओं के खिलाफ मानता हूँ। केबिननेट के चीफ मिनिस्टर के नाते उनका यह फर्ज होता है कि उनके साथियों पर जो इलजाम लगाये जाते हैं अगर उसकी कोई चर्चा करें और बतावें कि वे चोर हैं तो उनको

[श्री गोपीलाल यादव]

कहना चाहिये कि मैं चोर हूँ। यह चीज गलत कही थी और जब मैंने कहा तो वे नाराज हो गये।

श्री टीकाराम पालीवाल—मैंने उन साथियों को, जो गड़बड़ कर रहे थे, रोका।

श्री गोपीलाल यादव—मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि जहां तक बजट का सम्बन्ध है इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि पिछले ५ बजट जो हाउस के सामने पेश हुए हैं इन पांचों बजटों में निश्चय ही यह बजट सबसे अच्छा बजट है। उन पांचों बजटों से इसमें जनकल्यानकारी कार्यों पर ज्यादा खर्च किया गया है। इसकी सबसे बड़ी कसर है तो यह है कि यह समाजवादी व्यवस्था की तरफ ले जाने वाला बजट नहीं है और इसी कारण से हर एक आदमी ने इसको कोसा है और कोस रहा है और मैं भी कोसूंगा लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं हो सकती कि यह बजट पिछले ४ सालों के बजटों से कहीं अच्छा है।

अब रह गई समाजवादी व्यवस्था की बात। मैं इस बात को मानता हूँ कि हम कहते कुछ हैं और करते कुछ और हैं। यही मेरा इल्जाम जब मैं अपोजिशन में था, था। अपोजिशन में तो सच बोलते थे, झूठ नहीं बोलते थे। मैं बता देना चाहता हूँ कि एक रोज मेरे मित्र, कौन बोले यह याद नहीं, बोले कि, हाउस के नेता बोले कि कम्युनिस्टों की सरकार होने वाली है। मैंने उस समय यही कहा था कि हरगिज नहीं होगी, जब तक हम लोग जिन्दा हैं कम्युनिस्टों की सरकार हरगिज नहीं हो सकती। आज हमारा ध्येय है सोशियल पेटर्न। हमने उसको डिक्लेअर किया चाहे हम उस पर अमल करें या नहीं करें। हमको सोश्यल कहे कि सेन्टर का पेटर्न कर दो तो हम वह पेटर्न कर दें।

(हियर हियर)

मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ इस बात के लिये कि सोशियल पेटर्न हमने डिक्लेअर कर दिया चाहे हम उस पर अमल करें या न करें।

श्री वेदपाल त्यागी—चाहे आप उस पर अमल करें या नहीं करें, लेकिन डिक्लेअर तो कर ही दें।

श्री गोपीलाल यादव—मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि हमको हर एक चीज को देखना है। मेरे मित्र पालीवालजी ने कहा कि जितने अच्छे काम हुए हैं वे सारे सेन्टर की नीति के हैं। तो राजस्थान सरकार ने अच्छे काम किये उसका श्रेय भी सेन्टर को दिया और कोई काम आप को पसन्द नहीं आया उसको हम कहते हैं कि हमारी सरकार ने किया और उसमें सेन्टर को बचाते हैं। मैं यह मान कर चलता हूँ, पे स्केल में भी सेन्टर का हाथ है और सेन्टर से पूछ कर यह किया गया है।

एक माननीय सदस्य—आपको यह कैसे मालूम हुआ कि इसमें सेन्टर का हाथ है ?

श्री गोपीलाल यादव—कोई गवर्नमेन्ट इतना बड़ा काम सेन्टर को पूछे बगैर नहीं कर सकती है। इसलिये अगर इसमें कोई कमी है तो मेरी तरह हिम्मत हो तो कहिये कि असली कमी और गलती राजस्थान के मंत्रीमंडल की नहीं असली कमी है हमारे सेन्टर की और जब तक आप सेन्टर से इस कमी को दूर नहीं करेंगे, तब तक सोशियलिस्ट पेटर्न कायम नहीं हो सकता। क्या इसके लिये सेन्टर ने कोई कदम उठाया, क्या उन्होंने मिनिस्टरों की तनख्वाह कम की या चपरासियों की तनख्वाह बढ़ाई या दूसरी कोई इस प्रकार की चीज हुई ! जब दूसरों में नहीं हुई तो ये भी सेन्टर के ताबे होते हुए कैसे कर सकते हैं ! मैं तो कर सकता हूँ लेकिन उनकी हिम्मत नहीं होती कि वे कुछ करें। इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि जहां तक सोशलिस्टिक पेटर्न का सम्बन्ध है, कोरे नारे हैं, जिस प्रकार रूस में कम्युनिस्टों का नारा है। आज ४० साल में रूस में कम्युनिज्म नहीं हुआ है। दुनिया को बहकाने के लिए नारे चल रहे हैं इसी तरह से आप इतमिनान रखिये कि यह भी एक नारा है और इसको अमली रूप लेने में बहुत समय लगेगा और अगर कायम हुआ तो स्टेटिजम कायम होगा न कि समाजवाद; स्टेटवाद बन जावेगा, समाजवाद बनने वाला नहीं है, यह आप विश्वास रखिये।

तो यह बजट के अन्दर कमी है और बजट के ऊपर सबसे बड़ा अटेक (attack) इसलिये हो रहा है कि कांग्रेस ने समाजवादी व्यवस्था का नारा लगाया और अमल नहीं किया। किस वजह से हम अपने वित्त मंत्री पर और गवर्नमेंट पर इल्जाम लगायें कि समाजवाद का नारा लगाते हो, देश का कुछ नहीं कर रहे हो, कांग्रेस की नीति के खिलाफ चलते हो ? कांग्रेस की नीति के खिलाफ कैसे चलने दिया जा सकता है, चलना भी चाहे तो फौरन ऊपर से हुक्म होगा कि हटो। (हंसी हीयर, हीयर)

कांग्रेस की नीति के खिलाफ कोई नहीं चल रहा है। हां, एक चीज़ जरूर है जो हाउस के नेता से और वित्त मंत्री से कहूँगा कि उन्होंने जो पे स्केल्स बनायी हैं उन पर फिर जरूर विचार करना चाहिए और सबसे ज्यादा विचार करना चाहिए। अगर सेन्टर भी उनके मार्ग में बाधा डाले तब भी उन पे स्केल्स को इस तरह से रिवाइज करिये कि छोटे आदमियों की तनख्वाहें ज्यादा बढ़ें और बड़े आदमियों की कम। दो चीजें ये स्पष्ट करनी चाहिये, नहीं करेंगे तो काम चलने वाला नहीं। आपने ग्रेड तो बना दिया और जिस आदमी को यह ग्रेड दे रहे हैं उसकी २८ साल की सर्विस है, ८० से लेकर २०० तक की ग्रेड है, पांच साल और ज्यादा से ज्यादा सर्विस करेगा, अगर उससे पहले ही ३० साल में रिटायर हो जाता है और पांच रुपया तरक्की मिलती है हर साल तो १२० पर रिटायर होगा। उसके साथ तो अन्याय ही हुआ जब कि एक नये आदमी को भी वही मिल जाता है जिसने इतने वर्ष तक राजाओं की सर्विस की, अब दस साल से आपकी कर रहा है उसको तो कोई फायदा नहीं हुआ। जिस व्यक्ति ने काफी लम्बा समय सर्विस में बिताया, राजाओं की सर्विस में बिताया आपकी सर्विस में बिताया, आप उसको फायदा क्यों नहीं देना चाहते, नये आने वाले को क्यों इस तरह से देना चाहते हैं ? आप इस

[श्री गोपीलाल यादव]

पर गम्भीरतापूर्वक विचार करें। हमने मत्स्य के समय इस प्रश्न पर विचार किया था और हमने यह तय किया था कि हर तीन साल की सर्विस पर एक इन्क्रीमेन्ट दे दिया जाय। एक आदमी की बीस साल की सर्विस है उसको ७ इन्क्रीमेन्ट दिया जाय, और जिस की २८ साल की सर्विस है उसको ९ इन्क्रीमेन्ट्स दे दिये जांय। अगर आप यह नहीं करने जा रहे हैं तो यह निश्चित रूप से बता देना चाहता हूं कि उन गरीब लोगों के साथ जिनकी २८ साल या तीस साल की सर्विस हो चुकी है, जो रिटायर होने वाले हैं दो चार साल से उनके साथ बड़ा अन्याय होगा। इसके लिए कहीं से रुपया पैदा करना पड़े, आप कर सकते हैं, करना चाहिए और नहीं कर सकें तो आप मुझे बतायें मैं कर सकूंगा।

(विरोधी पक्ष द्वारा हीयर, हीयर)

दूसरी चीज़ बजट के सम्बन्ध में कहना चाहता हूँ वह यह है कि जहां यह बजट पिछले साल के बजट से प्रगतिशील है वहां मैं यह शिकायत करूंगा कि किसानों का बोझ कम नहीं हुआ है। हम इस बात की कोशिश करें कि ऐसे टाइम में जिनके पास अनइकोनोमिक होल्डिंग हो उनकी गवर्नमेंट मदद करे। वह बोझ उतना ही है। एक चीज़ फिर निवेदन करना चाहता हूँ कि खास तौर पर विचार करेंगे कि ५२-५३ में कानून बनाया कि १ अप्रेल सन् १९५२ के बाद या ५३ के बाद जो सेटलमेंट होगा उस सेटलमेंट की रेट होगी वह १।६ ग्रोस प्रोड्यूस होगी और पहले १।४ है। अब आप यह देखिए कि जहां एक दिन का संबंध है या दो दिन का सम्बन्ध है वहां किसान किस तरह उस बोझ को बर्दाश्त करते हैं। सेटलमेंट तीस साल रहने वाला है। यह कर दिया गया कि जहां ३० मार्च को सेटलमेंट ३० साल रहने वाला है यह कर दिया गया कि जहां ३० मार्च को सेटलमेंट हुआ वहां तो १।४ के हिसाब से किसान रेन्ट रेट देगा और जहां एक अप्रेल से हुआ है वहां वह १।६ से देगा। मैं यह कहता हूँ कि १।६ १।४ का २।३ होता है और आपको कानून बनाकर तय कर देना चाहिए कि जो सेटलमेंट ३० मार्च को हुआ था उसकी रेन्ट रेट १।४ रखी थी, उसके बजाय २।३ होगा और यह निश्चित कर देनी चाहिए। अगर नहीं करते हैं तो इन किसानों के साथ अन्याय है, कोई जस्टिस नहीं है कि १।४ पर जो रेन्ट कायम हुआ उसको चालू रखें और किसानों से पैसा लें।

इसके साथ मैं एक चीज़ पर अपने मित्र वित्त मंत्रीजी को बधाई दूं कि उन्होंने २५० से कम तनख्वाह पाने वाले कर्मचारियों के बच्चों की पढ़ाई की फीस माफ कर दी है। इससे भी मुझे डिस्क्रिमिनेशन मालूम होता है जैसा कि राजाओं के जमाने में हुआ करता था कि उनके बच्चे पढ़ सकेंगे, उनके ही बच्चे नौकर हो सकेंगे जो कि ऊंचे ओहदे पर हैं, उनके ही बच्चों को नौकरी मिल सकेगी कि जो रेल्वे में है। इस सिद्धांत को फैलाये कि २५० से कम किसी भी व्यक्ति की आमदनी है, चाहे वह किसान हो, चाहे, वह मजदूर हो, चाहे वह दुकानदार हो उनके बच्चों की फीस माफ करेंगे। जब आप यह नहीं कर रहे तो मैं यह कहूँगा कि सब के साथ एकसा व्यवहार नहीं कर रहे हैं और यह आपको करना पड़ेगा।

[श्री गोपीलाल यादव]

मैं एक चीज सदन को निवेदन करना चाहता हूँ जिस पर सदन में कई दफा चर्चा होती है और वह है एक बीमारी जिसको लोग कास्टिजम कहते हैं और पंचायत का नाम लेकर और दूसरी चीजों का नाम लेकर उस कास्टइज्म का जिक्र चलाते हैं। मैं आपकी आज्ञा से दो तीन मिनिट में बता देना चाहता हूँ कि यह कास्टिजम दर असल है क्या और क्यों होव्वा बनाया जा रहा है ? असली चीज जिसे कास्टिजम कहते है वह जान पहिचान है और एक दूसरे का विश्वास और संपर्क। एक आदमी देहात में रहने वाला है, अड़ौसी पड़ौसी सब को जानता है वे उसको राय देंगे न कि मुझे और आस पास के लोग एक ही जाति के है तो उन पर जातिवाद का इल्जाम लगाना अन्याय है। किसी पंचायत क्षेत्र से पं० नेहरू को खड़ा कर दीजिये और आप खड़े हो जाइये, वहां सारे के सारे जाट हैं, अहीर है, राजपूत हैं, और आपके मुकाबले में राजपूत हैं, जाट हैं, अहीर हैं, तो अहीर, अहीर को और राजपूत, राजपूत को और जाट, जाट को वोट नहीं देंगे किन्तु वोट देंगे पं० नेहरू को क्योंकि सब उनको जानते हैं। उनके दिमाग में जातपात की बात नहीं। आज जिस स्टेन्डर्ड के लोगों को वे वोट देते हैं,वे उनकी समस्याओं को ज्यादा जानते हैं,उनके वोट देने से उसमें जान पहिचान, विश्वास और पर्सनल चीजों का सवाल है न कि जातिवाद का। क्या आप पं० नेहरु पर भी जातिवाद का इल्जाम लगावेंगे। जितने आदमी उनकी सरकार में हैं उनमें से अधिकांश काश्मीरी, इलाहबादी या जो उनके सरकल के हैं। मैं तो नहीं। उसका कारण है यह है कि मुझे वे नहीं जानते। मेनन को जानते हैं, आर० के० नेहरू को जानते हैं, उन्होंने उनको चीन भेज दिया, मुझे भी जानते तो रशिया Russia भेज देते।

(हंसी)

तो सवाल यह है कि जाति पांति का सवाल नहीं, योग्यता का सवाल है, पं० नेहरू से जान पहिचान का सवाल है। जाति का नारा लगा कर जान पहिचान की चीजों का देश के अन्दर जातिवाद कौन फैलावे। हमारे देश के अन्दर जातिवाद की कभी नहीं है और न थी। अब लोगों को डर पैदा हो रहा है और जातिवाद का नारा लगाते हैं। जहां तक जातिवाद का सवाल है मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि मैं जब मेरे इलाके से खड़ा हुआ तो चालीस पचास हजार वोटरों में से एक हजार भी मेरी जाति के नहीं थे। मुझे कहा कि अहीरों के वोट से खड़े हो मैंने कहा कि जिस दिन जाति के वोट पर खड़ा हो जाऊंगा राजनीति को छोड़ दूंगा। राजपूतों और गुजरों ने वोट देने से इंकार किया। किसानों का वोट होना चाहिये जातिपांति का नहीं। अगर आदमी उनकी समस्याओं को नहीं समझते हैं, ऐसे आदमी असेम्बली में आकर बैठ जाते हैं, लगान लगे १।६, १।४ तो उनके लिये कोई आवाज नहीं है; तो निश्चित रूप से उनके रिप्रेजेन्टिटिव्ज नहीं है। उनकी समस्याओं को समझे और बीच में रहे। किसानों को यह समझा दिया कि मेजोरिटी लोग हमारी समस्याओं को हमारे बोझ को नहीं समझते और टैक्स का बोझ लगाते हैं। किसान होगा तो, किसान को भेजेगा।

आज जो जातिवाद का नारा लगाया जा रहा है यह एक महज भ्रम है। यह इसलिये

Page No.81

[श्री गोपीलाल यादव]

कि यह नारा लगाया जायगा तो जातिवाद के नारे से घबरा कर वे चुप बैठ जायेंगे और शासन वैसा चलता आ रहा है चलता रहेगा। मैं यह मानता हूं कि जातिवाद का नारा इतना झूठा और खतरनाक है जिसको नहीं लगाना चाहिये, वरना देश की एकता में बड़ा नुकसान हो जायगा।

श्री अध्यक्ष—There are some fourty members more who are willing to speak according to the list given by the congress whip.

श्री मानसिंह महार—माननीय अध्यक्ष, मैं ऐसा समझता हूँ बोलने का पूरा अधिकार होना चाहिये और समय मिलना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—(श्री गोपीलाल यादव से आपको और कितना समय लगेगा।)

श्री गोपीलाल यादव—आधा घण्टा और लूंगा।

श्री मोहनलाल सुखाडिया—अध्यक्ष महोदय, जबकि इतने सदस्य बोलना चाहते हैं और बोलने का अधिकार सब को है तो आज शाम को और मीट कर लिया जाय, कल सुबह जबाव हो जायगा। एक रोज कम होगा तो डिमान्ड्स फोर ग्रान्टस के समय हम एक्सेस सीटिंग कर लेंगे।

श्री गोपीलाल यादव—अध्यक्ष महोदय, इसके लिये भी समाजवादी व्यवस्था कर दी जाय। जितने भी बोलने वाले हैं सबके साथ एक सा व्यवहार होना चाहिये।

श्री माननीय अध्यक्ष—We adjourn to this evening at 4.

(विधान सभा की १२.४५ मध्यान्ह पर संध्या के ४ बजे तक के लिये स्थगित हुई)

विधान सभा भवन,
जयपुर,
दिनांक- १४ मार्च, १९५६

मनसाराम पुरोहित
सचिव,
राजस्थान विधान सभा।

Page No.82

परिशिष्ट १

(कृपया प्रश्न संख्या ७५ का उत्तर देखिये)

क्र० सं०	नाम		नं० रैंक	योग्यता	अर्सा सर्विस वर्षों में
१	दौलतसिंह	एच. सी.	७४२	मेट्रिक	साड़े पांच
२	धनपतसिंह	,, ,,		इन्टर	ढाई
३	भंवरलाल		२६८	मेट्रिक	लगभग दो
४	मोहम्मद रशीद	एल. सी.	७७	,,	सवा दो
५	लक्ष्मणसिंह	एच. सी.	१२०३	,,	
६	रामस्वरूप	,, ,,	५६६	,,	पांच
७	भंवरलाल	,, ,,	६६५	,, फेल	सवा १०
८	योग्यनारायणसिंह	,, ,,	७१	,,	५
९	भैंरोसिंह	,, ,,	१२२४. :१३७:	,,	साडे ६
१०	खुशालचन्द	,, ,,	७४४	,,	साड़े ३
११	पैतूराम	,, ,,	६६५		
१२	नैकीराम	,, ,,	३६७		
१३	अब्दुल रजाक	,, ,,	४६६. १४८०	मिडिल	१३
१४	निरन्जनसिंह	,, ,,	४२१	,,	२
१५	भंवरसिंह	,, ,,	४४७	मेट्रिक	साढ़े ४
१६	ओंकारनाथ	,, ,,	५११	मिडिल	१०
१७	भंवरलाल	,, ,,	४३२	मेट्रिक	१०
१८	जसवन्तसिंह	का०	२४७	मिडिल	२६
१९	बहादुरसिंह	का०	६२५	मेट्रिक	ढाई
२०	अखैराम	का०	५६७		
२१	मुरलीधर	का०	१६४		

Page No.83

क्रम संख्या	नाम		न० रैंक	योग्यता	अर्सा सर्विस वर्षों में
२२	रघुवीर	एच. सी.	१५		साढ़े ८
२३	कृष्णलाल	बी. जे		बी. ए.	ढाई
२४	नन्दलाल	एच. सी.	४८	मेट्रिक तक	१३
२५	भूपसिंह	,, ,,	२६	मेट्रिक	७
२६	रामस्वरूप	,, ,,	५३	मेट्रिक	साढ़े ४
२७	मोहब्बतसिंह	,, ,,	५५	,,	
२८	इन्द्रसिंह	,, ,,	४६		७
२६	गिरधारीसिंह	,, ,,	३१	मिडिल, रतन	१२
३०	साधूसिंह	,, ,,	३४	मेट्रिक फेल	साढ़े ७
३१	पृथ्वीराजसिंह	,, ,,	४४	मेट्रिक	१५
३२	सद्दीराम	,, ,,	६०	मिडिल	१३
३३	गंगासिंह	,, ,,	३४७	मेट्रिक	६
३४	सूरज प्रकाश	,, ,,	५८	,,	
३५	आत्मासिंह	एल. सी	२७६	,,	५. ३. अ० ४.
३६	गिरदावरसिंह	,, ,,	३४५		
३७	सीतारामसिंह	एच. सी.	६६६		१०
३८	अब्दुल कदम खां	बी. जे.	१५६७	मिडिल	६
३६	समशैल गनी	एच. सी.	१८१५		
४०	निर्भयसिंह	,, ,,	१०१		
४१	मदनलाल	बी. जे.	१८६६		
४२	इस्तयाक अली	एच. सी.	६५८		
४३	भैरूसिंह	बी. जे.	६५६	मेट्रिक	६
४४	दुर्गासिंह राव	एच. सी.	८६३	इन्टर	ढाई
४५	वंशीलाल	,, ,,	२२१	एल. एल.बी.	
				प्रथम वर्ष एम. बी.	ढाई
४६	रामानन्द	,, ,,	६११	मेट्रिक	ढाई
४७	जालिमसिंह	,, ,,	१०७२	इन्टर	१. ५. ५०. ५ साल

क्रम संख्या	नाम		नं० रैंक	योग्यता	अर्सा सर्विस बर्सों में
४८	रामचन्द्र	,, ,,	४१६	बी. ए.	साढ़े ३
४६	जसवन्तसिंह	,, ,,	१६५८		
५०	मिर्जामोहम्मद इकबालवे	एल. सी.	३६५	मेट्रिक	साढ़े तीन साल
५१	हरिसिंह पावर	एच. सी.	१५१६	,,	३ साल
५२	मंगलसिंह शर्मा	एल. सी.	१७०१	,,	३ साल
५३	जसवन्तसिंह	,, ,,	६६६	आचार्य	साढ़े पांच साल
५४	रतनसिंह	बी. जे.			१६ साल
५५	छगनलाल	एच. सी.	१८४६		१५ साल
५६	सत्यनारायण	,, ,,	६००	नोनमेट्रिक	ढाई साल
५७	मांगीलाल जैन	,, ,,		मेट्रिक	४ साल
५८	मदनलाल शर्मा	,, ,,	८४२	मिडिल	३
५६	हरिसिंह	,, ,,	२०६		
६०	रामचन्द्र शर्मा	,, ,,	८६२		
६१	राममूर्ती शर्मा	,, ,,	८३८	इन्टर	३ साल
६२	राज मोहम्मद	,, ,,	५११	मेट्रिक	ढाई साल
६३	गम्भीरसिंह	,, ,,	४३५	,,	तीन साल
६४	सोहनलाल	एल. सी.	२३१	,,	४ साल
६५	भंवरलाल	एच. सी.	६३	,,	५
६६	जसवंतसिंह	,, ,,	६०८	,,	२
६७	अम्बासहाय	,, ,,	२६	इन्टर फेल	३
६८	रामनारायण शुक्ला	,, ,,	३१७	इन्टर तक	सवा २
६६	मांगीलाल	,, ,,	७८		१२
७०	रामस्वरूप शर्मा	एल. सी.	५४१	मेट्रिक	सवा २
७१	चंद्रप्रकाश	एच. सी.	८६१	,,	३
७२	दुलेसिंह	एस. आई		मेट्रिक तक	साढ़े ३
७३	विक्रमसिंह लोढ़ा	बी. जे.	५३	मेट्रिक तक	साढ़े ६
७४	अमीनउल्ला	एच. सी.	२४८	मेट्रिक	साढ़े ३

क्रम संख्या	नाम		नं० रैंक	योग्यता	अर्सा सर्विस वर्षों में
७५	वीरेंद्रसिंह	बी. जे.	१५४६		साढ़े ८
७६	रामसिंह	,, ,,		मेट्रिक तक	१० साल
७७	चतुरसिंह	एच. सी.	१५१५	ला क्लास	१६
७८	चोथमल शर्मा	,, ,,	७५६		
७९	श्याम मनोहर शर्मा	,, ,,	५३२		१३
८०	विजयनारायण शर्मा	,, ,,	३६३		८ वर्ष
८१	नंदकिशोर	,, ,,	७१७	मिडिल	१०
८२	मोहम्मद मुल्तान	,, ,,	४५७		साढ़े ७
८३	प्रकाश लाल	,, ,,	३	मेट्रिक	साढ़े ६
८४	नंदसिंह	,, ,,	८५३	मेट्रिक	सवा ४ साल
८५	अब्दुल करीम		२०८	इंटर तक	
८६	मुल्तानसिंह	एल. एन. के.	६६६	मेट्रिक	साढ़े ५
८७	रामरतन शर्मा	,, ,, ,,	१३७२	,,	साढ़े ३
८८	श्यामस्वरूप	,, ,, ,,	६६३	,,	साढ़े ३
८९	रामकल्याण नागर	,, ,, ,,	१०२७	,,	साढ़े ३
९०	सय्यद जफर हुसैन	एफ. सी.	१५४०	इंटर	३
९१	प्रभूलाल वर्मा	एच. सी.	१५५२	मेट्रिक	२
९२	किशनसिंह रावत	एफ. सी.	४३७	,,	ढाई साल
९३	शंकर मोहम्मद	,, ,,	२७६	,,	ढाई साल
९४	जगदीश प्रसाद शर्मा	,, ,,	१५७	,,	सवा दो
९५	मोहनलाल	,, ,,	१८२	,,	२ साल
९६	जगन्नाथ प्रसाद	,, ,,	५५	,,	सवा दो
९७	अब्दुल करीम	,, ,,	९४३	,,	ढाई साल
९८	मोहनलाल	,, ,,	१६३६	,,	२ साल
९९	त्रिलोकीचंद	एच. सी.	७२	,,	३ साल
१००	शराफत अली	बी. जे.	१५	मिडिल हिंदी	साढ़े १४
१०१	रघुवीरसिंह	एच. सी.	४२३	मेट्रिक	

Page No.86

क्रम संख्या	नाम		नं० रैंक	योग्यता	अर्सा सर्विस वर्षों मे
१०२	घनश्यामलाल	,, ,,	४४२	मेट्रिक	साढे तीन साल
१०३	जगदीश चंद	,, ,,	१५१	,,	५ साल
१०४	दाताराम	,, ,,	३६७	,,	
१०५	फतहचंद	बी. जे.		,,	७
१०६	श्री० गोपाल	एल. एन.	१४६	,,	ढाई साल
१०७	घनश्यामलाल	एफ. सी.	२६५	,,	२ साल
१०८	रामसिंह	एच. सी.	५४	,,	४ साल
१०९	मदनलाल	बी. जे.	४६	,,	१० साल
११०	वनसिंह	एल. सी.	१३४१	,,	२, ३, ४
१११	जयराम	एच. सी.	-५२	इंटर	साढ़े चार
११२	टीकमसिंह	,, ,,	४२	बी.ए. प्रथम वर्ष	५
११३	मोतीलाल सोलंकी	,, ,,	७७४	बी. ए.	६
११४	घनश्याम	बी. जे.		मेट्रिक	
११५	लक्ष्मणसिंह	एच. सी.		मेट्रिक	२
११६	चिमनाराम	,, ,,	४४५	मिडिल	१५ साल
११७	गूनेंद्र	,, ,,	४११	मेट्रिक फेल	९ साल
११८	खेमसिंह	,, ,,	१६०		१५ साल
११९	नरपतसिंह	,, ,,	१४२	इंटर तक	३ साल
१२०	अबुसिंह	,, ,,	१६५	मेट्रिक	६ साल
१२१	मानसिंह	,, ,,	१८८	मेट्रिक फेल	१५ साल
१२२	डूंगरसिंह	,, ,,	२०३	मेट्रिक	१२ साल
१२३	थानसिंह	,, ,,	४	,,	४
१२४	पदमसिंह	,, ,,	१६६	,,	४
१२५	त्रिभुवनलाल	,, ,,	२०	मिडल तक	
१२६	पुनमचंद	,, ,,	४२४	मेट्रिक	२
१२७	पुनराजसिंह	एल. सी.	६२८	,,	ढाई साल
१२८	मोतीसिंह	,, ,,		,,	२ साल

Page No.87

क्रम संख्या	नाम		नं० रैंक	योग्यता	अर्सा सर्विस वर्षों में
१२६	खमानसिंह	एफ. सी.	६	आठवीं क्लास तक	१५ साल
१३०	युक्तोकरण	एच. सी.	६०	बी. ए.	३ वर्ष
१३१	टीकाराम	,, ,,	५४३	इंटर	२
१३२	प्रभूराम	,, ,,	६२६	मेट्रिक	४
१३३	इब्राहीम खां	बी. जे.			१५
१३४	अब्दुल अली	एच. सी.	४८		८ साल
२३५	शिवकरण	,, ,,	६१	मिडिल	११ साल
१३६	मोतीलाल	,, ,,	५८	नवी क्लास	
१३७	देवीसिंह	एच० सी०	३		
१३८	भोपालसिंह	,, ,,			१३ साल
१३९	इब्राहीम खां	,, ,,	५६	६क्लास तक	१२
१४०	पीरसिंह	,, ,,		मैट्रिक	३ साल
१४१	करीम खां	एल. सी.	२३४		४ साल
१४२	जीवसिंह	एच. सी.	५५	मिडिल तक	१५ साल
१४३	कालूराम	,, ,,	७४	इन्टर	५ साल
१४४	चंचलमल लोढा	,, ,,	२७०	मैट्रिक	२ साल
१४५	हरिसिंह	,, ,,	२१५	,,	२ साल
१४६	भगवान दास विसा	,, ,,	११	,,	५ साल
१४७	वित्तल दास धाभाइ	,, ,,	११७८	,,	५. ३. ४.
१४८	एन. एन. दीवान	,, ,,	६१५	,,	५ साल
१४९	अमरसिंह	का.	२६७	,,	साड़े ३
१५०	चेरसिंह	एच. सी.	३६		साड़े १४ साल
१५१	मदनसिंह	,, ,,	७		१२ साल
१५२	हरगोविन्दसिंह	वी. जे.	३८	मैट्रिक तक	५ साल
१५३	शिवदान	एच. सी.	८५	मिडिल	
१५४	रामस्वरूप शर्मा	,, ,,	८६	मैट्रिक	
१५५	सिंमाहन	,, ,,	६९	,,	६ साल

Page No.88

क्रम संख्या	नाम	नं० रैंक		योग्यता	अर्सा सर्विस वर्षों में
१५६	नानूराम	,, ,,	५७	,,	६ साल
१५७	शमसाद अली	का.	४०५	,,	१० साल
१५८	हजारीलाल	एच. सी.	१६	मैट्रिक तक	१२ साल
१५९	मुसद्दीलाल	,, ,,	२५७	मैट्रिक	७ साल
१६०	श्रवणलाल	एल. सी.	५९०	,,	
१६१	दीनदयाल शर्मा	एच. सी.	३२२	,,	७ साल
१६२	मोहम्मद शरीफ	एल. सी	५५६	,,	ढाई साल
१६३	विश्वनाथ	एच. सी.	२२६	,,	६ साल
१६४	जगदीश प्रसाद	,, ,,	५११	,,	६ साल
१६५	अमृतलाल	एच. सी.	४१२	,,	
१६६	रामजीलाल	बी. जे.	५०७	,,	९ साल
१६७	रामचरण	एच. सी.	५८८	,,	८ साल
१६८	भंवरसिंह	एच. सी.	३०४	,,	८ साल
१६९	भवानीसिंह	,, ,,	५६३		८ साल
१७०	भवानीसिंह	,, ,,	४७५	इन्टर	९ साल
१७१	गंगासहाय शर्मा	,, ,,	४०९	मैट्रिक	८ वर्ष
१७२	रघुवीरसिंह	,, ,,	४८६	मैट्रिक फेल	
१७३	बाबूलाल	,, ,,	७०८		१५ साल
१७४	लायकसिंह	,, ,,	६४०	मैट्रिक	५ साल
१७५	जीवनदास	,, ,,	४	,,	
१७६	कन्हैयालाल	,, ,,	३८९	मैट्रिक तक	१५ साल
१७७	मोतीसिंह	का.	६४६	मैट्रिक	५ साल
१७८	रामेश्वर चन्द्र	का.	८१७	,,	३ साल
१७९	गोरीशंकर	का.	४०३	इन्टर	
१८०	निरन्जनसिंह	एच. सी.	६०३	मैट्रिक	७ साल
१८१	महेशचन्द्र दुबे	,, ,,	१६५	इन्टर	३ साल
१८२	बलवानसिंह	,, ,,	१५१	मैट्रिक	३ साल

Page No.89

क्रम संख्या	नाम	नं० रैंक	योग्यता	अर्सा सर्विस वर्षों में
१८३	रघुनन्दन लाल	,, ,, १२६	,,	१३ साल
१८४	रामदयाल शर्मा	,, ,, ८७	,,	८ साल
१८५	नाथसिंह	बी. जे,	इन्टर	५ साल
१८६	फूलचन्द	एच. सी. ४५६		१२ साल
१८७	करणसिंह	,, ,, ५४८	बी. ए.	११ साल
१८८	हजारीलाल	का. ४८७	मैट्रिक	५ साल
१८९	रामशरण	एच. सी. ३६	,,	७ साल
१९०	महावीर प्रसाद	,, ,, २१३	,,	४ साल
१९१	रामसिंह	,, ,, १८	,,	२ साल
१९२	किशोरीलाल	,, ,, ६३	,,	१३ साल
१९३	करतारसिंह	,, ,, १६	,,	१० साल
१९४	रुद्रभानसिंह	,, ,, २९५	,,	९ साल
१९५	बाबूलाल	,, ,, ७२	,,	७ साल
१९६	मानिकलाल	,, ,, २०२	बी. ए.	सवा दो सात
१९७	केदार नाथ	,, ,, ९३	मैट्रिक	८ साल
१९८	बिद्याराम	बी. जे.	,,	९ साल
१९९	बिशम्भर नाथ	एच. सी. २४८	,,	७ साल
२००	नारायन दास	एल. सी. ५८	,,	२ साल
१०१	सांवतसिंह	बी. जे	,,	६ साल
२०२	शिवदत्त शर्मा	एच. सी. १०९७	,,	१२ साल
२०३	चांद शेखर	बी. जे. १२२०	,,	७ साल
२०४	मंगलचन्द	एच. सी. १२९	,,	४ साल
२०५	वीरबाबू	एल. सी. २७०५	,,	७ साल
२०६	लक्ष्मणसिंह	बी. जे. १०६१	बी. ए.	८ साल
२०७	भारतदास भूषण	एच. सी. १००५	मैट्रिक	६ साल
२०८	उदयसिंह	,, ,, ११०८	,,	साडे ५ साल

क्रम संख्या	नाम	नं० रैंक		योग्यता	अर्सा सर्विस वर्षों में
२०९	रामचन्द्र यादव	,, ,,	१०३१	,,	४ साल
२१०	उम्मेद सिंह	एल. सी.	१६३३	मैट्रिक	५ साल
२११	नारायणलाल	का.	२२०६	,,	३ साल
२१२	शेरसिंह	एस. सी.	१००४		१० साल
२१३	महावीरप्रसाद	,, ,,	२३३३	,,	
२१४	माधोप्रसाद शर्मा	,, ,,	१२४९	इन्टर	सवा दो साल
२१५	गुलाबसिंह	एच. सी.	११८६	मैट्रिक	५ साल
२१६	ओमप्रकाश वेदी	वी. जे.	१०७३	इन्टर	
२१७	श्रीनिवास	एस. सी.	१०५७	मैट्रिक तक	४ साल
२१८	प्रभुदयाल	,, ,,	५३	वर्नाक्युलर मिडिल	७ साल
२१९	हर प्रसाद	,, ,,	१०५१	संस्कृत प्रथमा	१३ साल
२२०	मुरलीधर शर्मा	,, ,,	११७३	मैट्रिक	७ साल
२२१	रिचपाल सिंह	वी. जे.	१०८६	इन्टर	३ साल
२२२	महेशचन्द्र	एस. सी.	११७५	वी.ए.	३ साल
२२३	पूर्णमल	एच. सी	५	मैट्रिक फेल	६
२२४	शैतानसिंह	,, ,,	४५१	मैट्रिक	८
२२५	रिधसिंह	,, ,,	५६	,,	६
२२६	मोहम्मद अली खां	,, ,,	३८		
२२७	पूर्णचन्द	,, ,,	२१६	इन्टर	२
२२८	निरन्जन लाल शर्मा	,, ,,	१८	मैट्रिक पास	५
२२९	फैज मोहम्मद	,, ,,	३६२	मैट्रिक	४
२३०	किशनसिंह	वी. जे.	४०		७
२३१	रघुवीरसिंह	वी. जे.	५२	मैट्रिक बी. ए. ओनर्स	२
२३२	वल्लभ नारायण	एच. सी.	२३	मैट्रिक तक	१४
२३३	सालग्राम	,, ,,	६९	मिडिल	७
२३४	नारायणसिंह	,, ,,	३९	मैट्रिक	३
२३५	ब्रह्मदत्त	,, ,,	११२	इन्टर	३

क्रम संख्या	नाम	नं० रैक	योग्यता	अर्सा सर्विस वर्षों में
२३६	महेन्द्र सिंह	,, ,, ५३	मैट्रिक	ढाई
२३७	रमेशचन्द्र शर्मा	एल. सी. ५२८		४
२३८	राम कल्याण सोनी	,, ,, ६६६		सवा दो साल
२३९	गोविन्द लाल	,, ,, ५१४	,,	सवा दो
२४०	ताराचन्द	का. ७६३	बी.ए.एल.एल.बी.	साढ़े ६ साल
१४१	शक्तिदान	आ.एस.आ.	बी.ए.	६ साल
२४२	शम्भूसिंह	एच. सी.	इन्टर	सवा ३ साल
२४३	रंजूमल	,, ,,	,,	
२४४	टेकचन्द	,, ,,	मैट्रिक	५ साल
२४५	घनश्यामलाल	,, ,, ७०	इन्टर	६ साल
२४६	खेमचन्द	,, ,,	,,	४ साल
२४७	भैरूसिंह	,, ,,	बी. ए.	२
२४८	विश्वनाथ	,, ,,	मैट्रिक	४ साल
२४९	मदनलाल व्यास	,, ,,	बी. ए.	ढाई साल
२५०	वंशीधर	,, ,,	मैट्रिक	८ साल
२५१	मांगीलाल	,, ,,	मिडिल	११ साल
२५२	रमेशचन्द्र	एल. सी. २५३४	मैट्रिक	३ साल
२५३	प्रेमकुमार	,, ,,	,,	५ साल
२५४	नरेन्द्रकुमार	,, ,,	इन्टर	ढाई साल
२५५	गनपतसिंह	एच. सी	इन्टर	साढ़े ३ साल
२५६	हरिसिंह	एल. सी.	मैट्रिक	साढ़े ३ साल
२५७	बलवीरसिंह	एल. सी.		२ साल
२५८	पुरुषोत्तम दास	एच. सी.	,,	५ साल
२५९	मदनलाल	,, ,, ७		
२६०	श्री उमाशंकर	,, ,, ६		
२६१	भवानीशंकर	बी. जे. ६	इन्टर	५ साल
२६२	निरन्जनलाल सेनी	एच. सी	मैट्रिक	५ साल
२६३	परभातीलाल	एच. सी.	,,	४ साल
२६४	फतैहलाल	एच. सी.	इन्टर	
२६५	प्रकाशसिंह	बी.जे,		
२६६	हरिकृष्ण शर्मा	एल. सी २५४६	मैट्रिक	साढ़े ३ साल

परिशिष्ट २

(कृपया प्रश्न संख्या ८८ का उत्तर देखिये)

SATEMENT SHOWING THE EXPENDITURE ON VARIOUS KIND OF IRRIGATION WORKS OF FIRST FIVE YEAR PLAN, TAKEN UP BY IRRIGATION DEPARTMENT.

S. No.	District.	Expenditure (Rs. Lacs)			Total.
		Plan works.	Scarcity area works.	Minor Works	
1.	Udaipur	19.15	36.77	47.66	103.58
2.	Chittor.	44.01	26.86	7.62	38.49
3.	Bhilwara.	52.51	46-26	11.88	110'65
4.	Dungarpur.	1.86	3.96	8.40	14.22
5.	Banswara	8.12	1.80	7.22	17.14
6.	Pali	127.54	..	1.06	128.60
7.	Sirohi	3.77	8.98	5.67	18.42
8.	Jodhpur.	3.17	–	–	3.17
9.	Jalore.	0.13	–	–	0.13
10.	Jaipur,	35.10	–	14.62	49.72
11.	Tonk.	3.45	13 20	18.95	35.60
12.	Sawai Madhopur.	46.55	–	5.27	51.82
13.	Kotah.	2.84	14.62	5.37	22.83
14.	Bundi	42.50	13.50	7.83	63.83
15.	Jhalawar.	0.46	8.28	0.65	9.39
16.	Alwar.	2.17	–	14.42	16.59
17.	Bharatpur.	67.71	–	12.83	80.64
	Total:—	421.14	174.23	169.45	764.82

परिशिष्ट ३

तारांकित प्रश्नोत्तर जो सम्बन्धित प्रश्नकर्ताओं की अनुपस्थिति के कारण सदन की मेज पर रखे गए तथा जिनके प्रकाशित करने की सम्बन्धित मंत्री महोदयों की अनुमति हैं।

प्रश्न

८० (२१। एच. एम.) **श्री महाराज केसरीसिंह, एम. एम. ए. डिविजन नम्बर ७४**—क्या गृह मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) बूंदी कलेक्टरी में कितनी टोपी-दार बन्दूकों के लाइसेन्स के लिए दरख्वास्तें पेश हुई, और कब?

(ख) क्या इनको लाइसेन्स दिये जा चुके हैं?

(ग) क्या कारण है कि फीस जमा हुए बाद भी लोगों को अभी तक लाईसेन्स नहीं दिये गये हैं?

उत्तर

क. बून्दी कलेक्टरी में ता० २२. १. ५४ से ता० ६. २. ५४ तक ३००० आवेदन पत्र टोपीदार बन्दूकों के लाईसेन्स देने के लिये पेश हुए।

ख. जी नहीं। टोपीदार बन्दूकों के लिये लासेन्स नहीं दिये जाते।

ग. इन आवेदन-पत्रों के साथ फीस जमा हो चुकी है। टोपीदार बन्दूकों के लाईसेन्स नहीं दिये जाते, केवल उनको रजिस्टर ही किया जाता है जो निःशुल्क होता है। बतौर फीस के जमा हुई रकम वापस लौटाने की कार्यवाही दर पेश है।

प्रश्न

87. (26 A.T.M.) Sri Maharaj Keshri Singh, M. L. A. (Div. No. 75) Will the Agriculture Minister be pleased to state:—

(a) How many experimental agricultural farms are there in Rajasthan?

(b) What is the yearly expenditure in each of these farms?

(c) What profit does each of them give yearly to the Government?

(d) How much seed is yearly distributed by different farms to the villagers.

उत्तर

निम्नलिखित चार फार्मों पर खास तौर से एक्सपेरीमेन्ट होते हैं:

१. श्री गंगानगर २. मन्डोर

३. दुर्गापुरा ४. बस्सी

ख.	नाम फार्म	खर्चा
	श्री गंगानगर	४२, ६१८ रु०
	मन्डोर	२५, ४५३ रु०
	दुर्गापुरा	१८, ६२६ रु०
	बस्सी	२४, १०२ रु०

ग. एक्सपेरीमेन्टल फार्म होने के कारण लाभ का सवाल नहीं उठता है:

घ.	१. रायसिंह नगर	५०० मन
	२. पदमपुर	५०० मन
	३. करनपुर	५०० मन
	४. जैतसर	५०० मन
	५. बून्दी	५० मन
	६. सवाईमाधोपुर	५० मन
	७. पड़सोली	३००० मन
	८. सादड़ी	१५० मन
	९. त्रिलाडा	१५० मन
	१०. दोनडी	१५० मन
	११. बांसावडा	५० मन
	१२. टोंक	५० मन
	योग	५६५० मन

प्रश्न

६१ (२६ । एम. एल. एम.) श्री केसरीसिंह, एम. एल. ए., डिवीजन

नम्बर ७५:—क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(क) ग्राम पीपल्या तहसील नैनवा जिला बूंदी में अलग ग्राम पंचायत कायम होने का आदेश कब हुआ ?

(ख) क्या वहां पंचायत कायम हो गई है ?

उत्तर

(क) दिनांक २०–१०–५४ को स्थापित करने की स्वीकृति दी गई थी। परन्तु नई पंचायत के अधिकतर गावों के लोगों ने तलवास पंचायत से निकलने में ऐतराज किया। तलवास पंचायत की कुल जन संख्या ३७२५ है पीपल्या पंचायत बनाने से तलवास की १९४५ और पीपल्या की १७८० रह जाती है। इतनी कम जन संख्या की पंचायतों का खर्चा नहीं चल सकता। इसके अतिरिक्त ६.३.५५ को बूंदी जिले की पंचायतों के सरपंचों व पंचों का सम्मेलन हुआ था। उसमें यह प्रस्ताव पास किया था कि बूंदी जिले की कुछ पंचायतों के क्षेत्रों के टुकड़े कर अलग छोटी छोटी पंचायतें बनाई गई हैं जो उनकी उन्नति में बाधक हैं। यह पंचायतें ६ वर्ष से सफलता पूर्वक काम कर रही हैं इसलिये इनके टुकड़े न किये जांय। इसलिये इनके चुनाव नहीं करवाये गये।

(ख) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट-४

(कृपया प्रश्न संख्या ६२ का उत्तर देखिये)

Name of Project		Estimated cost (in lacs)	Annual Irrigation (in acres)
		UDAIPUR DIVISION	
1. Banas		480	225000
2. Khari feeder		20	8000
3. Jakham		117	53000
4. Mahi		195	70000
5. Berach (Vallabh Nagar)		32	14000
6. Berach (Bar-Gaon)		45	20000
7. Wakan		46.5	26500
8 Bandora		32.6	1720
9 Rudari		1.03	550
10 Parsoli		0.71	830
11 Pick up weir Banswara	No. 1	0.06	110
12 „ „ „ „	No. 2	0.16	270
13 „ „ „ „	No. 3	0.26	138
15 Dhaku Pick Up Weir		0.28	222
15 Singhpur Pick Up Weir		0.14	195
16 Wacheria pick Up Weir		0.53	1200
17 Bheru Ji Bajwar		3.63	370
18 Bholi ka Khera		9.89	1041
19 Lunda		2.98	380
20 Brahmani River		2.50	1600
21 Bankia		4.23	2425
22 Chandar Bhaga		10.0	7000
		KOTAH DIVISION	
1 Manohar Thana		95	50000

Name of project.	Estimated cost (Rs. in lacs)	Annual Irrigation (in acres)
2 Sawan Bhadon	11	10000
3 Alnia	12.5	11000
	JAIPUR DIVISION.	
1. Kantri	10.00	24000
2. Deopura	5.00	27000
3. Khirkhari	1.5	900
4. Akora.	1.2	600
5. Baretha.	2.0	1000
6. Bhagwantgarh tank	1.5	1000
7. Mui Bandh	1.5	1000
8. Lania	6.0	5000
9. Karnawal.	1.5	1000
10. Thund River.	7.5	4000
11. Mohari	1.5	1000
12. Hazai wala bawan Bala Bund.	2.5	2000
13. Namod gaon	2.5	1500
14. Bharoti Bund.	5.0	2000
15. Sodra.	10.0	6000
16. Dai Nadi.	10.0	8000
17. Kaleg Sagar	3.00	1500
18. Dai Nadi.	5.00	3000
19. Dolat Sagar.	2.5	1500
20. Ajagra.	2.5	1200
21. Agra feeder.	10.0	30000
22. Ranipur	5.5	4000
23. Papara Bund.	1.2	800
24. Buchhera	2.0	1500
25. Sabi.	2.5	46000
26. Bharatpur feeder.	20	50000

Name of project.	Estimated cost (Rs, in lacs)	Annual Irrigation (in acres)
	JODHPUR DIVISION.	
1. West Banas	28	14500
2. Sukli	18	8000
3. Bandi	26	8000
4. Khari Storage.	30	13500
5. Sagi	9.88	9400
6. Dehpura.	5.50	2700
7. Ramsin.	2.60	1800
8. Wirari.	3.62	2230
9. Withan	2.57	1650
10. Raipur luni	10.00	10000
11. Bhandar River	7.40	7400
12. Batrak River	6.00	6000
13. Gajnaik Bnnd	2.70	2700
14. Bhankri Bund	0.64	640
15. Kantalia.	2.74	2740
16. Saran.	0.62	620
17. Sirili	1.42	1420
	BIKANER DIVISION.	
Nill for the present.		

राजस्थान विधान सभा

बारहवीं बैठक, बुधवार, दिनांक १४ मार्च, सन् १९५६ ई०

(सायंकालीन बैठक)

विधान सभा की बैठक सभा भवन, जयपुर, में सायंकाल ४ बजकर १० मिनट पर प्रारम्भ हुई।

(श्री नरोत्तमलाल जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

आय-व्ययक भाषण पर सामान्य वाद-विवाद (पूर्व क्रम से)

श्री गोपीलाल यादव—माननीय अध्यक्ष, मैं सुबह बजट पर बोलते हुए जातिवाद के संबंध में कुछ कह रहा था। उस वक्त एक चीज़ मुझे और याद आई कि जिस वक्त भारतवर्ष के दो टुकड़े हुए, उसका पार्टीशन हुआ तो कांग्रेस के ऊपर एक इल्जाम लगाया गया कि उन्होंने कम्युनलिज्म के नीचे अपना सिर झुकाया और कम्युनलिज्म के बेसिस पर भारत के टुकड़े किये। उस वक्त पंडित नेहरू ने, मुझे याद है, कहा था कि जो लोग यह कहते हैं कि कम्युनलिज्म के बेसिस पर भारत के टुकड़े किये गये हैं, वे गलत हैं। हमारा बेसिस टेरीटोरियल था और जिस इलाके के लोग हमारे साथ नहीं रहना चाहते थे तो हम इनसे कह दें कि तुम जाओ। तो जो हम लोगों को प्योरली कम्युनल चीज़ नजर आती थी तो एक सही नुक्ते निगाह से देखें और कहीं कम्युनलिज्म को इस्तेमाल करके क्यों जहर बढ़ाया जाय। यह एक टेरीटोरियल बेसिस पर हुआ है, चाहे वहां किसी कौम के आदमी बसे हुए हों वह हिन्दुस्तान के साथ नहीं रहें तो जाओ। इसी तरह से मैं बतला रहा था कि हमें हर एक चीज़ का आपस में विश्वास और जान पहिचान पर इस चीज को लेना चाहिए। मैं एक चीज़ की याद दिलाता हूं कि कांग्रेस प्रेसीडेन्ट श्री ढेबर से मेरी बातचीत हुई थी तो मेरे मुंह से ये शब्द निकल गये कि एक आदमी जीत गया और एक आदमी हार गया तो आज जो जीत जाय उसके साथ सब को रहना चाहिये। ढेबर साहब ने कहा कि जीतने और हारने की परिभाषा है? वह मेरी परिभाषा नहीं है। हम तो यह समझते हैं कि किसको ज्यादा लोगों का विश्वास प्राप्त है। जीता भी हो लेकिन ज्यादा लोगों का विश्वास प्राप्त किस को है? तो मैं सिर्फ यह निवेदन करना चाहता हूँ कि ज्यादा लोगों का विश्वास प्राप्त किसको है इस तरह से हमें हरेक चीज को देखना चाहिये और न तो जातिवाद का नारा लगाना चाहिए न और कोई मोटिव्ज इम्प्यूट करने चाहिए।

माननीय अध्यक्ष, एक दूसरी चीज जिस पर कि इस सदन में बहुत चर्चा हुई है वह है भ्रष्टाचार। मैं उन आदमियों में से हूं जो निश्चित यह मानते हैं, कि भ्रष्टाचार दिन ब दिन कम

[श्री गोपीलाल यादव]

होता जा रहा है। मैंने लोगों से बहुत बातें की इस भ्रष्टाचार के संबंध में, और दिन रात जहां कहीं भी मुझे आदमी मिलते हैं वे भ्रष्टाचार की असलियत मुझे बताते रहते हैं कि यह बीमारी क्या है ? एक वकील मुकद्दमे में हार जाता है तो अपनी कमजोरी को छुपाने के लिये अपने मवक्किल से कहता है कि देखिये वहां रिश्वत पहुँच गई इसलिए मुकद्दमा हार गये और कहीं कोई रिश्वत नहीं है। दूसरी चीज ऐसी है कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनका रोजगार ही इस तरह के काम का है। वे कहते हैं कि पैसा देओ और हम अफसर के पास पहुँचा देंगे। वह उसके पास पहुंचाते नहीं हैं लेकिन अपनी जेब में रख लेते हैं। मुकद्दमा जीत गये तो कह देते हैं कि हाकिम को दे दिया और हार गये तो उसे वापिस दे देते हैं १०, २० रूपये खा पी कर ऐसे लोग जो एन्टी सोशल एलीमेंन्टस anti-social elements हैं वह इस देश में मौजूद हैं। उनके कुकृत्यों से भ्रष्टाचार नजर आता है, वह बड़ा हुआ दिखाई देता है। वास्तव में ईमानदारी से देखेंगे तो हरेक जगह नजर आयेगा कि भ्रष्टाचार कम हो रहा है। अफसरान अपने काम को ईमानदारी और देशभक्ति से कर रहे हैं और उनके अन्दर यह चीज नहीं है कि वे लूट रहे हैं, बेइमानी कर रहे हैं या इर्रेस्पान्सिबिल आदमियों की तरह से काम कर रहे हों।

अब एक चीज हमारे सामने आई है कि कांग्रेस गवर्नमेन्ट कमजोर है यदि कमजोर है तो उसका कारण क्या है ? मैं निवेदन करूंगा कि गवर्नमेंन्ट में यदि कोई कमजोरी होती है और उसके कारण कहीं भ्रष्टाचार नजर आता है तो उसकी जिम्मेवरी कांग्रेस बैंचों पर बैठने वाले कांग्रेस के मेम्बरों की है जो कि कांग्रेस—मैन होते हुए भी कांग्रेस सरकार का साथ नहीं देते। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कोई भी गवर्नमेन्ट तब तक मजबूत नहीं हो सकती जब तक कि एक एक आदमी उसका मेम्बर अपनी वफादारी उसके प्रति न रखे और उसके लिए जीने और मरने को तैयार न हो। आज आप एक चीज़ देखेंगे कि अगर गवर्नमेन्ट से यह रोष है, किसी भी गवर्नमेंट से, जिस वक्त शास्त्री गवर्नमेंट थी और उनके खिलाफ लोग अविश्वास का प्रस्ताव ला रहे थे तो मैं कह रहा था कि आप यह गलती कर रहे हैं, जिस वक्त व्यास जी की गवर्नमेन्ट में अविश्वास का प्रस्ताव ला रहे थे उस वक्त भी मैं कह रहा था कि यह चीज़ गलत है, उसके बाद सुखाड़ियाजी की गवर्नमेंट बनी और उसको लोग सहयोग नहीं देने लगे या नहीं दे रहे हैं तो यह चीज भी गलत है। हमारी ड्यूटी और फर्ज है कि हम गवर्नमेंट को मजबूत बनायें, और गवर्नमेंट की पार्टी का एक एक आदमी इस तरह से देखेगा कि हम उसे मदद न दें तो निश्चित कमजोरी आयेगी। अगर कहीं कोई कमजोरी है तो उसकी जिम्मेदारी उन आदमियों पर ज्यादा है जो कि पूरी वफादारी से कांग्रेस के मेम्बर होते हुए भी गवर्नमेंट की मदद नहीं करते हैं।

माननीय अध्यक्ष, इस सदन में दो व्यक्तियों पर अक्सर चर्चा होती रहती है; उनमें एक हैं चौधरी कुम्भाराम और दूसरे हैं श्री मथुरासाद माथुर। मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि जब कभी कुम्भारामजी का जिक्र आता है तो मैं महसूस करता हूं कि हरेक सेशन में एक

Page No.101

[श्री गोपीलाल यादव]

ही आदमी पर दिन रात हमला करना मुनासिब है क्या ? क्या वह वास्तव में एक बुरा आदमी है ? मैं उनकी सारी हिस्ट्री देखने लगता हूँ तो कांग्रेस ने सन् ५१ में उनको टिकट नहीं दिया । टिकट नहीं देने के बाद भी वे कामयाब हो गये और कामयाब होने के बाद यह किन लोगों की जिम्मेदारी थी कि जो व्यक्ति कांग्रेस से नामज़द होता है उसे हराकर यहां पर आये तो उन्हें कांग्रेस में शामिल किया । उन्होंने एक डिसिप्लिन को तोड़ा । उनको बुरा मानते थे तो बचपन से उनमें यह तमाम बुराइयां होंगी । जो लोग उस वक्त सदन के नेता थे, जो लोग पार्टी के लीडर थे उनकी यह जिम्मेदारी थी कि उनको कांग्रेस से निकाल कर बाहर करते तो वह यहां अपोजिशन में आकर बैठते और उस वक्त अपोजिशन की गवर्नमेंट बनती क्योंकि दो ही आदमियों का फर्क था, लेकिन उस वक्त कुम्भारामजी की बुराई हटाई गई क्योंकि उनकी मदद की, हम लोगों को जरूरत थी । उसके बाद कुम्भारामजी को मिनिस्ट्री में नहीं लिया तो एक इलेक्शन आया और उसमें हमें कुम्भारामजी की मदद की आवश्कता हुई, उन्होंने मदद की, उनके साथियों की मदद की आवश्यकता हुई तो सेन्टर पर दबाव डालकर तो एक अवांछनीय आदमी को जिसको आज हम सब बहुत बुरा कहते हैं मिनिस्ट्री में लिया गया । मैं कहता हूं कि उस वक्त कहां चली गई थी उनकी सारी बुराइयां और उनके सारे दोष ? उनको मिनिस्ट्री में लिया गया, फिर आपस में अनबन हो गई तो आज हम कहते हैं कि वह आदमी चोर है, डाकू है, वह आदमी बलवन्तसिंह है, पता नहीं कि क्या क्या है ? मैं कहता हूँ कि यह कहां कि इन्सानियत है कि हम अपने एक साथी के साथ अन्याय करते हैं कि जिसने अपना तमाम जीवन कांग्रेस के लिए दिया । जिसके बाबत मैंने कांग्रेस दुश्मनों से पूछा तो उन्होंने कहा कि वैसे आदमी निहायत ईमानदार है । आदमी में कोई दोष नहीं है अगर थोड़ा बहुत है तो इतना ही है कि बुरे से बुरे आदमी जो हैं वे इनके दोस्त हैं । वे अपने दोस्तों को अलग निकालने की कोशिश नहीं करते हैं । उनको कांग्रेस से निकालते नहीं हैं । इस तरह से आज एक आदमी उनके खिलाफ एक इल्जाम लगाने को तैयार है तो फिर हर वक्त जब कि हम २४ घन्टे साथ रहें, जब कि उनको मिनिस्ट्री में लिया गया जो कि हर वक्त बुराई करता रहा । अगर कोई बुराई है तो अब भी आप सेन्टर में गये और जाकर बोले और उनसे मिनिस्ट्री से इस्तीफा दिलवाया, यही सारी चीजें की उस आदमी के साथ जिसे हमने मतलब के लिए कांग्रेस में लिया, मिनिस्ट्री में लिया ।

इसके बाद दूसरी चीज़ आती है मथुरादासजी माथुर के सम्बन्ध में । इस सम्बन्ध में मैं ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा क्योंकि हाउस के नेता इस सम्बन्ध में विचार कर रहे हैं और वे लोगों के सामने रखेंगे, लेकिन आज एक बात जो मुझे बुरी महसूस हुई उसके सम्बन्ध में कहना चाहता हूं । मेरे मित्र पालीवालजी ने एक बात सदन के सामने रखी और वह यह थी कि पिछले जो डाइरेक्टर महोदय थे वे उनसे मिले और उन्होंने वह चिट्ठी उनको दिखाई और दिखाकर यह कहा कि देखिये साहब पहिले तो ऐसे ऐसे काम करवाते थे अब हमको वे एक्सटेंशन नहीं देते । मेरी समझ में नहीं आया सबसे पहले कि डाइरेक्टर महोदय की यह हिम्मत

[श्री गोपीलाल यादव]

कैसे पड़ी कि अपने खुद के काले कारनामों का पालीवालजी के सामने जिक्र करें जो कि चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। उनको, डाइरेक्टर को, यह समझ होनी चाहिए कि एक आदमी के सामने जो कि चीफ मिनिस्टर रह चुका है और आगे भी चीफ मिनिस्टर रह सकता है यह रखूं कि मैं दूसरों के कहने पर ऐसे ऐसे बुरे काम करता रहा हूं और आज वे मुझे एक्सटेंशन देने को तैयार नहीं हैं। क्या कोई ऐसा आदमी ऐसी बात कहने की कोशिश कर सकता है और ऐसे आदमी से कह सकता है जो कि निहायत ईमानदार आदमी माना जाता है ? और ऐसे आदमी से कहना जो निहायत ईमानदार माना जाय, मैं निवेदन करता हूं कि इस तरह की बात जब पालीवालजी कह रहे थे तो मुझे ताज्जुब हो रहा था कि वे कह क्या रहे हैं ? सोच समझ कर क्यों नहीं कहते ? यदि किसी ने उनको इस तरह की बात कही है तो वह उनके सामने हां नहीं करेगा चाहे कितनी ही खराब इन्फरमेशन हो वे कहेंगे कि मैंने तो पालीवालजी से यह बात नहीं कही और दूसरे कहेंगे कि कही तो नतीजा क्या होगा ? जांच करेंगे तो भी कैसे करेंगे ? मैं कहूँगा कि पालीवालजी का यह कर्तव्य था कि जिस समय एक्स डाइरेक्टर ऑफ एज्युकेशन ने उनसे यह बात कही तो उनको चाहिए था कि चीफ मिनिस्टर को वह बात कहते कि यह चीज मेरे सामने आई है इसकी जांच की जाय। उस समय तो उन्होंने वह बात नहीं कही। लेकिन जब आपस में रंजिश हो जाय तो ईमानदार आदमी भी सही बात कहता है तो उनको शक होता है तो हमारे अन्दर यह चीज पैदा हो रही है, केबिनेट के सीक्रेट आउट किये जा रहे हैं। कितना ही लोगों पर इल्जाम लगाते रहें, यह उचित नहीं है। इतना कहने के बाद मैं दो तीन और बातों के बारे में निवेदन करना चाहता हूं।

सबसे पहली चीज यह है कि जिसके बारे में मैं यह कहूंगा कि हाउस के नेता ध्यान दें कि फाइनेन्स डिपार्टमेंट का जो रेडटेपिज्म है उसको कम करने की अवश्य कोशिश की जाय। तमाम डिपार्टमेन्ट्स के लोग, हैड ऑफ डिपार्टमेंट्स यह शिकायत करते हैं कि जितना वे काम करना चाहते हैं द्वितीय पंच वर्षीय योजना के सिलसिले में, डेवलपमेंट के बारे में, पी० डब्ल्यू० डी०, कलेक्टर वगैरा जो काम करना चाहते हैं उनका काम ढंग से, ठीक समय पर फाइनेन्स डिपार्टमेंट के रेड टेपिज्म के कारण नहीं कर सकते। दूसरी चीज यह है कि इमरजेन्सी पावर्स कलेक्टर वगैरा को ज्यादा मिलनी चाहिये। आग वगैरा लगती है तो आप के कलेक्टर वगैरा के पास उनके लिये पूरा फंड होना चाहिये कि आवश्यकता पड़ने पर वे इमीडियेट रिलीफ भेज सकें। यह नहीं हो कि कागज आगे भेजा है मंजूरी आने पर सुनवाई होगी। जब तक आप यह नहीं करेंगे तब तक न तो आप का काम ठीक ढंग से चलेगा और न लोगों की तकलीफ दूर होगी चाहे कितना ही अच्छा बजट बनावें ? जब तक नीचे के अधिकारियों के अधिकार नहीं बढ़ावेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। इसके अलावा कलेक्टर ने प्रपोजल भेजा कि इस काम के लिये ५००० रु० खर्च होंगे इसलिये ५००० की मंजूरी दी जाय। लेकिन फाइनेन्स डिपार्टमेंट कहता है कि ३ हजार से काम चल जायगा। कुर्सी पर बैठे हुए उनको क्या पता कि ३००० से काम चलेगा या ५००० से ? अभी नागरे में पानी नहीं था वहां ३ हजार की मंजूरी थी लेकिन पानी की व्यवस्था करने में १२०००) रु० खर्च हुए। ३०००) रु० मंजूर

[श्री गोपीलाल यादव]

किये उससे कैसे खर्च चलता ? वही ऑफिसर जो ओन स्पोट है वही जानता है कि कितना खर्चा लगेगा और कैसे काम चलेगा ?

माननीय अध्यक्ष, एक चीज जिस के संबंध में निवेदन करना चाहता हूँ वह है रिहेबिलिटेशन के संबंध में। डिस्प्लेस्ड परसन्स है उनमें कई तरह के लोग हैं। कुछ वे शरणार्थी हैं जो पाकिस्तान से आये हैं। कुछ वे मेव लोग हैं जो डिस्प्लेस्ड हुए और उनके सम्बन्ध में राजप्रमुख के भाषण पर भी चर्चा हुई और एक सदस्य ने गवर्नमेंट पर इल्जाम लगाया। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि यह पेचीदा समस्या है इसको ठीक ढंग से हल करना चाहिये वरना नतीजा इसका भयंकर हो सकता है। इसमें तीन कम्युनिटीज़ हैं। एक तो शरणार्थी जो पाकिस्तान बनने पर वहां से भाग कर आये। दूसरे है मेव्ज जो डिस्प्लेस्ड हुए पाकिस्तान भागे और वहां से लौट कर वापिस आये। तीसरे हैं लोकल हिन्दू काश्तकार। इन सब में सबसे ज्यादा मुसीबत लोकल हिन्दू काश्तकारों की है। लोकल हिन्दू काश्तकारों से आम तौर से जमीन मेवों को बसाने के लिये छीन ली गई थी। इस पर शोर हुआ तो यह तय हुआ कि जो लोग सब टिनेन्टस थे उनको बसाया जायगा उनको जमीन दी जाय। जब गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया तो शोर हुआ कि उनकी जमीन छीनी जारही है और उन पर अत्याचार हो रहा है वह नहीं होना चाहिये। मैं निवेदन करूंगा कि इसके लिये एक कमेटी अवश्य बनाई जाय। जहां पाकिस्तान से हिन्दू आये हैं या आरहे हैं वहां मेव भी पाकिस्तान से वापिस आरहे हैं पहले जब गिनती की गई तो उनकी तादाद ३८००० थी और आज पाकिस्तान से वापिस आने पर उनकी संख्या ७० हजार हो गई। इतनी ही नहीं बल्कि एक दो साल में उनकी संख्या २ लाख होगी। जितने भी मुसलमान और मेव वहां गये हैं सबे पाकिस्तान की इकोनामिक पोलिसी से तंग आकर वापिस आयेंगे। जब तक आप कमेटी नहीं बनायेंगे तब तक वह मसला हल नहीं होगा। पाकिस्तान से आनेवालों की खबर कौन देगा। आप इसका पूरा इन्तजाम नहीं कर सकेंगे और सारा इकोनोमिक ढांचा बिगड़ जायगा।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं। एक मौका है और कहा भी है कि स्ट्राइक वेन आइरन इज होट 'Strike when iron is hot.' आज कहा जाता है, कि सारा हिन्दुस्तान एक है। प्रोविन्शियेलिज्म की ओर ध्यान नहीं देना चाहिये। जिस समय राजाओं का जमाना था। यमुना का सारा पानी पंजाब और यू० पी० को दिया जाता था। लेकिन अब तो एकता का सवाल है। अब तो कम से कम एक नहर राजस्थान के लिये निकाली जानी चाहिये। आप देश की एकता का ध्यान रखिये और राजस्थान को पानी देने में इन्कार मत करिये।

श्री नाथूराम मिर्धा—माननीय अध्यक्ष महोदय, बजट के सिलसिले में लगातार तीन दिनों से इस सदन में चर्चा चल रही है। इस सदन के बहुत से माननीय सदस्यों ने जो इस ओर बैठने वाले हैं और जो उस ओर बैठने वाले है वाद विवाद में हिस्सा लिया है। अध्यक्ष महोदय, मुझे इस सदन में इस बार करीब करीब सभी महत्वपूर्ण बोलने वाले माननीय सदस्यों की बहस सुनने का मौका मिला है। मैं अपने दिमाग में, जब उनके भाषणों को सुन रहा था, कई तरह की प्रतिक्रियां चल रहीं

[श्री नाथूराम मिर्धा]

अनुभव कर रहा था । बहुत से माननीय सदस्यों ने जो कि सरकारी बैंचों की तरफ बैठते हैं इस तरह से बोल रहे थे जैसे उस तरफ बैठने वाले माननीय सदस्य बोलते हैं। माननीय अध्यक्ष, जब यह बहस और जब यह तरीका काफी तेजी पर पहुंच गया तो मुझे भी राजस्थान के एक किसान नुमायदे की हैसियत से कुछ बातें कहनी पड़ रही हैं। मै थोड़ी चर्चा इस बजट पर करना चाहता हूं । यह वादविवाद पिछले कुछ दिनों से इस सदन में, इस बजट के सिलसिले में चल रहा है, वह क्यों पैदा हुआ ? इसका क्या कारण है ? बहुत से माननीय सदस्यों ने जिन्होंने इस बहस में हिस्सा लिया है उनमें से करीब करीब चार पांच को इन बैंचों पर बैठने का मौका मिला है ।

एक माननीय सदस्य—आपको भी मौका मिला है।

श्री नाथूराम मिर्धा (जारी)—मैं भी उनमें से एक हूँ और आज इस बैंच पर नहीं बैठा हूँ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं इस सरकार का, जो कुर्सी पर बैठी है उसके अच्छे समर्थकों में से एक समर्थक हूँ । और मैं जो लोग इन कुर्सियों पर जब भी बैठे हैं उनका भी समर्थक था । उनके लिये भी किसी तरह गैर जिम्मेदारी की बात किसी समय नहीं कही । चर्चाएं चली हैं । मैने कहने वाली बात को कहने के मौके पर कही है । जहां इन बातों को लाना चाहिये वहां लाया हूँ । पार्टी की बैठक में कही है । कांग्रेस की जो मीटिंगें हुई हैं, चाहे डी० सी० सी० की या पी० सी० सी० की हुई हैं वहां मैंने कहने वाली बातें कही है और जहां कहने की आवश्यकता थी वहीं कहीं हैं । इस सदन में आज तक इस तरह से बात नहीं की । इसमें थोड़ी बातें मुझे साफ करनी जरूरी हैं । माननीय अध्यक्ष, इस राजस्थान में दो तीन सरकारें बनी और बदली हैं । समय समय पर सरकारें बनी उनमें से दो को मैं महत्वपूर्ण मानता हूं । वे इस तरीके से जब आज हमारे एक माननीय मुख्य मंत्री बोल रहे थे उनका भी मैं सहयोगी रहा और उनके साथ भी इमानदारी सेकाम किया है और आज भी मैं यह आशा नहीं करता था कि वे माननीय सदस्य इस तरह से बहस सदन में करेंगे, जिस तरह की आज सदन में की । एक दूसरे चीफ मिनिस्टर की पहले इस राजप्रमुख के भाषण पर वाद विवाद चला तब उनकी भी बहस सुनने का मुझे मौका मिला । उनका भी मैं सहयोगी रहा । जोधपुर में भी मैं उनका सहयोगी रहा । मैं उनके काम करने के तरीके को शुरू से जानता हूं । उन्होंने २५, २६ साल से कांग्रेस में काम किया है । उन्होंने आजादी की लड़ाई में अच्छा भाग लिया । उसके बाद में माननीय अध्यक्ष, वे इस राजस्थान सरकार के चीफ मिनिस्टर भी रहे और उनके साथ भी मैं काम नहीं कर पाया परन्तु उन्होंने कहा कि मेरे साथ में रह कह काम करो परन्तु कुछ बातें ऐसी थी इसलिये मुझे इस्तीफा देना पड़ा । मैने दिया । इसके बाद में भी उनके लिये वही सद्भावना और प्रेम आज भी मौजूद है जो पहले था । परन्तु माननीय अध्यक्ष, आपस में कई तरह की बातें कर सकते हैं, वे आपस में बैठकर कर सकते हैं । हमारी पार्टी में बहस हो सकती है लेकिन ये बातें आज सदन में क्यों की जा रही है । अध्यक्ष महोदय, इसमें से बहुत से साथी थे कुछ भूल चन्द महीने पहले कर चुके थे और उस भूल के कारण उनको ऐसा महसूस होने लगा कि हम शायद इस कांग्रेस के बैंचों पर ज्यादा दिन बैठ पावेंगे या नहीं । ६ नवम्बर को पहले एक तरह का वातावरण

[श्री नाथूराम मिर्धा]

बना था और हमारे उस समय के चीफ मिनिस्टर यह नहीं चाहते थे कि ५ हजार से नीचे की जागीरें रिज्यूम की जावें। उन्होंने पार्टी में इस बात को कहा बहुत से लोगों का यह मत थाँ कि अब इस समय में एक पैसे की जागीर भी नहीं रह सकती। इस पर आपस में मतभेद हुआ। जो लोग किसानों के नुमायन्दे हैं उन्होंने यह मत दिया कि एक पैसे की जागीर भी कायम नहीं रह सकती। आपको जागीरों को रिज्यूम करना होगा। इस पर काफी मतभेद पैदा हुआ और इस मतभेद की वजह उनको

श्री भैंरूसिंह—(१६) सदन में बजट पर बहस हो रही है या पार्टी की बातें यहां पर कही जा रही हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा—उस समय ५ हजार की जागीरों को रिज्यूम नहीं करने के सम्बन्ध में और करने के सम्बन्ध में डिफरेन्स ऑफ ओपीनियन की नौबत यहां तक पहुँची कि वे चीफ मिनिस्टर रह सकेंगे या नहीं, इसका मौका पार्टी को मिला और पार्टी ने फैसला किया और उसके फलस्वरूप आज इस सदन के नेता जो हैं वह चीफ मिनिस्टर और नेता चुने गये और इस फैसले के बाद में कई ऐसी बात हुई। कुछ उधर बैंठने वाले साथियों को इसलिये इधर लिया गया कि बैलेन्स में जो कमी पड़ रही है उसको कम किया जाय और अपना पॉवर कायम रख सकें तो अच्छा हो। यह इतिहास इस राजस्थान का पिछले कुछ महीनों में रहा है। माननीय अध्यक्ष, इस वातावरण में जब मैं आज इस सरकार की ओर से पेश हुए बजट का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूँ, मैं यह कहना चाहता हूं, कि मैने इस बजट को अपनी आंखों से देखा है और मैं समझ कर यह कहता हूं कि सरकार में बैठे हुए और काम करने वाले माननीय सदस्यों ने जो बजट पेश किया है उसका मैं समर्थन करता हूं। उनकी नीति राजस्थान के दबे हुए लोगों को ऊंचा उठाने के लिये, राजस्थान के गिरे हुए किसानों को ठीक तरह से ऊंचा ओहदा दिलाने के लिये प्रयत्नशील है। इस लिये मैं सरकार का समर्थन करता हूँ। मैने उन लोगों का समर्थन जब तक किया जब तक यकीन था कि वे इस मामले में ध्यान दे रहे हैं और दबे हुए तबके को आगे लाना चाहते हैं। मै उनका सहयोगी रहा और उनकी मदद सहयोगी रह कर की और उसके बाद में सदन में, केबिनेट में बैठा तब की और केबिनेट में नहीं बैठा और बाहर रहा तब की। लेकिन जब उनका फैसला ६ नवम्बर को हो गया तो बहुत से साथियों की जिनकी उस जगह बैठने की आदत पड़ गई थी उनको नाराजगी हुई। वे खुले आम इस तरह की बात करते हैं जिस तरह की विरोधी दल के साथी भी नहीं करते। माननीय अध्यक्ष, मुझे इस बजट के सिलसिले में कुछ बता देना आवश्यक होगी।

कल एक माननीय सदस्य खड़े हुए और कहने लगे कि जिस समय मै उपमंत्री था मैं अपने इलाके में दौरे पर गया और वहां पर उस समय पडियारा की डकैती के सिलसिले में लोगों ने मुझे कहा कि यह डकैती चोर और डाकुओं से किसी ने मिल कर कराई है, मैंने उनकी बात नहीं मानी। उनको यह नहीं मानना उस समय जरूरी था।

श्री चंदनमलवेद—मैंने यह कहा था कि यह गलत है ।

श्री नाथूराम मिर्धा—(जारी) लेकिन उनको यह अच्छी तरह मालूम है कि उनके प्रयत्नों के फलस्वरूप ही वे उस कुर्सी पर बैठे थे । जब वह हाथ उनके नीचे से निकला तो वह कुर्सी भी हट गई । इसलिये मैं यह कहूँगा कि आज जब वहां पर वे दौरे में जाते तो जो आपको बात वहां गलत नजर आती थी आज बिल्कुल सही नजर आए । आज यहां तक कहा जाता है कि बलवन्तसिंह है, जो व्यक्ति कल तक आपको कुर्सी पर बिठाने के लिये जिम्मेवार था आज वही बलवन्तसिंह डाकू बन गया । इस कुर्सी पर बैठ कर हम इस प्रकार की बातें करें तो यह शोभा की बात नहीं रहती हैं । माननीय अध्यक्ष, बहुत से चीफ मिनिस्टरों को जब यहां से हटना पड़ा, शायद नहीं कहता कि आगे और भी मामला ठीक बन सकता हो, वैसे उछल उछल कर कहा जा रहा है कि जनता में बहुत असंतोष है, कांग्रेस में भ्रष्टाचार को देख कर बड़े मामले खराब हो रहे हैं । बहुत बातें कही जा रही हैं । बड़ी बड़ी बातें कही जा रही हैं जैसे उनके राज्य में तो कोई शान्ति की गंगा बह रही थी और अब इस समय राज्य में दिन दहाड़े गजब हो रहा है । इस प्रकार की बातें कहना सदन में ठीक नहीं है । आज जब वे अपने समाज में जो दबे हुए लोग हैं, जो गिरे हुए लोग हैं, जिन्होंने सदियों से बुरे दिन देखे हैं, उनके लोगों को भी नुमायन्दगी करने का मौका मिलता है । हो सकता है कि उन लोगों में इतनी अक्ल नहीं हो जितनी की आप लोगों में है जो बहुत दिनों से अक्लमन्द रहे हैं ।

परन्तु माननीय अध्यक्ष महोदय, लोगों में, जैसा उन्होंने खुद ने स्वीकार किया जागृति है, डरते डरते स्वीकार किया है, जागृति उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए इसलिए चुनाव जीतने से क्राइटेरियन मान ले सब ठीक है, कांग्रेस इसीलिए जीती है, कुछ लोगों में जागृति है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा कि लोगों में पांच वर्षों में चेतना फैली है । कुछ माननीय सदस्य जो बहुत दिनों तक इन कुर्सियों पर बैठे थे उनको डर है कि शायद आ सकें या न आ सकें।

श्री चन्दनमलवैद—आपकी कोई गारन्टी है ? -

श्री नाथूराम मिर्धा—(अपना भाषण जारी रखते हुए) : आपसे ज्यादा गारन्टी है ।

इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, इस तरह कटु आलोचना करना उनकी बातों को डिस्क्लोज करना जो कि केबिनेट में बैठे साथियों के विचार विमर्श में होती हैं, मुझे भी कई बातें मालूम हैं, मैं उन बातों को कह कर इस प्रकार की ट्रेडीशन नहीं डालना चाहता कि उन बातों को सदन में रखूं, माननीय सदस्यों के सामने उन बातों को पेश करूं यह किसी अच्छे आदमी का काम नहीं है । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे साथियों में कई प्रकार की चर्चाएं हो सकती हैं उनमें कईयों के विचार सही हो सकते हैं, कुछ काम सही हो सकते हैं, सबको मिलाजुलाकर तमाम की जोइन्ट रेस्पोन्सिबिलटी है उस जोइन्ट रेस्पोन्सिबिलटी को एक्जीक्यूट करना है । जब एक माननीय मित्र कह रहे थे कि रोकने की कोशिश की । नहीं मानते हैं तो आपको चुपचाप छोड़ कर हट जाना चाहिए था और नहीं माने तो इस कुर्सी पर नहीं बैठे रहना चाहिए था, नहीं मानते हैं तो हट जाओ ।

[श्री नाथूराम मिर्धा]

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने कुछ मुद्दों पर जो बजट की बहस के सिलसिले में उठाये गये थे अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं। उस रो में बैठने वाले जोधपुर से आने वाले एक माननीय साथी ने और सरदारशहर से आने वाले माननीय साथी ने इस बजट की आलोचना करते समय यह कहा कि इस सरकार ने चुपचाप ८४ लाख की आमदनी जो कि पेज १३ बजट पर दी गई है, ऊपर से तो कहा की टेक्स नहीं लगाना चाहते लेकिन यह ८४ लाख की आमदनी का टेक्स लोगों पर सरका दिया।

माननीय अध्यक्ष महोदय हमें इस सदन में बैठने से पहले सदन में बजट की पोथियां दी गई है उनको आंखों से देखें, पढ़ें और समझने कोशिश करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो करीब ८४ लाख रुपये का आंक इस बजट में नयी आमदनी के रूप में दिखाया गया है उसका ब्योरा बजट के एक्सप्लेनेटरी मेमोरेन्डम में ठीक तरह से समझाया गया है। यह जो दो लाख रुपये की बढ़ोतरी, आमदनी स्टाम्प्स ड्युटी में बढ़ायी गई है उसके लिए एक्सप्लेनेटरी मेमोरेन्डम को देखने से साफ मालूम हो जायगा कि यह टेक्स के बढाने से नहीं होगी। कुछ आने वाले वर्ष में ज्यादा बिक्री की उम्मीद मानते है या पिछले साल के जो रिवाइज्ड एस्टीमेट्स है वहां आने वाले साल में ६३ लाख का एस्टीमेट लगाया गया गया है। लगातार पिछले दो तीन साल से २, ३ लाख की बढोतरी हुई है और आने वाले साल में भी तीन लाख की बढोतरी की आशा है। यह आशा करना पिछले दो तीन साल के आंकड़ों के देखने से गैरवजिब नहीं है। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कोई दीगर टेक्स का सवाल नहीं है।

श्री चन्दनमल वैद—भाषण में एडीशनल टेक्सेज का सवाल कहां था?

श्री नाथूराम मिर्धा—यह कहा गया था कि ८४ लाख की आमदनी दिखाई गई है वह किस मद से होगी? सदन के मेम्बर आसानी के लिए या जो इन बजट के पोथों को नहीं देखते उन लोगों की अक्ल को समझाने के लिए यह कहा गया है।

श्री चन्दनमल वैद—पैरा ७७।

(घंटी)

श्री अध्यक्ष—The language should not be too personal and sarcastic

श्री नाथूराम मिर्धा—माननीय अध्यक्ष महोदय, बीच में सवाल उठता है तो जरूर सारकास्टिक बात कहने का मौका आ जाता है।

(हंसी)

श्री अध्यक्ष—I have given the hon'ble member the possession of the floor.

श्री चन्दनमल वैद—पैरा ७७........

श्री अध्यक्ष—Order Please ?

(घंटी)

श्री नाथूराम मिर्धा—दस लाख की आमदनी जो बढ़ोतरी के रूप में बतायी गई है वह भी अगर साफ तौर से देखे तो पता चलेगा कि एक्सप्लेनेशन में दिया गया है वह यह है कि—

"The actuals during 1953-54 and 1954-55 amounted to Rs.32, 87, 678 and Rs. 35, 74, 656 respectively. For the current year the estimate was framed at Rs. 36 lacs. On the basis of actual flow of receipts during the first nine months of the current year it is expected that the receipts during 1955-56 may go upto Rs. 39 lacs and this figure has been adopted for the Revised Estimate for 1955-56. Taking into account likely increase in the number of vehicles and increase in rates the forecast for the next year has been placed at Rs. 50 lacs."

तो माननीय अध्यक्ष महोदय, कुछ रेट्स के रेशनेलाइजेशन से कुछ इन्क्रीज इन व्हिकल्स की वजह से हमने आने वाले साल में ५० लाख का अन्दाज लगाया है। इसी तरह इरीगेशन रेन्ट्स का एक्सप्लेनेशन इस बजट के एक्सप्लेनेटरी मेमोरेन्डम के पेज ३० और पेज २९ पर दिया हुआ है और उसमें यह बताया गया है कि इरीगेशन की जो रेट्स हैं उनको रेशनेलाइज करेंगे, की है, अब भी कर दी है। रेशनेलाइजेशन हो चुका है। वह रेशनेलाइजेशन करना किसानों के हित में जरूरी था। जहां नये वर्क्स चल रहे है, या खत्म हो गये है, नये नोमिनल रेट्स थे। रेट्स लगाई गई थी उन इरीगेशन रेट्स को संकलन करना जरूरी था और उनका संकलन किया गया।

(घंटी)

जो रेशनेलाइज्ड और इन्क्रीज्ड इरीगेशन हुआ है उस इन्क्रीज्ड नेशनेलाइजेशन की वजह से माननीय अध्यक्ष महोदय, यह आमदनी ३९ लाख के करीब बढ़ी है। इन सारों का एक्सप्लेनेशन हमारे इस मेमोरेन्डम में मौजूद है और माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत से जिम्मेदार साथियों का यह कहना कि जनता पर टेक्स नहीं बढने देंगे अगर जनता पर टेक्स बढाया गया तो जनता रिवोल्ट कर देगी। माननीय अध्यक्ष, जब हम इन पांच साल में जनता के कई फायदे के काम कर पाये और आगे आने वाले पांच वर्षों में काम करने हैं इस बजट के आंकड़ों को देखें तो इरीगेशन के आंकडो में, मेडीकल के आंकडो में लगातार बढोतरी हुई है। एजुकेशन में आये साल ३० लाख का खर्चा बढा है, ज्यादा स्कूल खोलते है, बच्चों को पढ़ाना है ज्यादा फायदे के काम करने हैं, किन्तु एक पैसा नहीं देना चाहते, रेशनेलाइजेशन का सवाल उठता है तो हम भी आवाज

[श्री नाथूराम मिर्धा]

लगायें कि एक पैसा नहीं देंगे तो ये जनता के फायदे के काम कैसे होंगे? हमको तरक्की करने के लिए कुछ पैसा लोगों की जेबों से निकालना पड़ेगा और उस पैसे को काम में लगाना पड़ेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, गये पांच सालों में कार्य जो किये गये हैं जो जनता की भलाई के लिये किये गये हैं, पंचवर्षीय योजना में कार्य हुए हैं वे बजट की शुरूआत में दिये गये हैं। कुछ अनपढ़ लोगों के दिमाग में भी लाया जा सकता है, नक्शे दिये गये हैं।

श्री अध्यक्ष—Don't show these to me.

(हंसी)

श्री नाथूराम मिर्धा—माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके जरिये कुछ साथियों को दिखाना चाहता हूं जिनको कुछ अपने दिलों के उद्गार निकालने है, उन्होंने लम्बी पोथी को देखा नहीं, उनके लिए नक्शे और चार्ट बिना पढ़े लिखे लोगों के लिए दिये हैं उनको भी नजर से उटा कर देख लेते तो पांच सालों में किन किन मदों पर खास तौर पर गये साल में खर्च हुए हैं।

अध्यक्ष महोदय, अगर माननीय सदस्य जो नकशे पहले पेज पर दिये हुए हैं वे भी देख लेते तो इस बजट को समझने में कोई दिक्कत नहीं होती। पहले पेज पर जो सर्किल दिये हुए हैं उनमें बताया गया है कहां से तो पैसा आयगा और कहां पैसा जायगा। अगर वे शुरू के पेज को देख लेते तो वे इस परिणाम पर पहुँचते कि पिछले साल डेढ़ साल में प्लानिंग का बहुत ज्यादा काम हुआ है इस सरकार के चार्ज संभालने के बाद ही जो पहला काम किया गया वह था, प्लानिंग डिपार्टमेन्ट का निर्माण। इसका डिपार्टमेन्ट नया खोला गया इसी वजह से बहुत से नकशे जो पहले पेज पर हैं जिसके अन्दर छोटे छोटे खम्भे हैं आखिरी वर्ष के अन्दर आप देखेंगे वे खम्भे काफी बढ़ गये। कुछ मदों के अन्दर खम्भे जरूर छोटे रहे हैं वह इसलिये कि पिछले तीन चार वर्षों में उनकी तरफ कम ध्यान दिया गया जैसे बिजली का महकमा। उसमें ऐसा था कि मशीनें जैसी चीजें हमें मिल नहीं पाई थी, अगर शुरू से इसके लिये कोशिश की जाती तो जल्दी से इस बारे में छानबीन करके जल्दी से टेन्डर्स इनवाइट करते तो इस संबन्ध में भी हम उतने ही आगे बढ़ गये होते जितने कि अन्य क्षेत्रों में राजस्थान के कई हिस्सों में जो कुछ काम उस समय करने थे, उस समय आपस में ज्यादा गड़बड़ थी इसलिये इतना समय नहीं मिल सका कि इस काम को टीक तरह से कर लिया जाता। इस सरकार के इन कुर्सियों पर आने के बाद जिसको केवल एक साल, सवा साल का पीरियड मिला था उसमें इन्होंने जितना भी रुपया ज्यादा से ज्यादा सहूलियत देने के लिये खर्च किया जाना आवश्यक था खर्च किया गया। उसके बावजूद भी कई सदस्य यह कह सकते हैं कि साल के आखिरी वक्त में जिस प्रकार गवर्नमेंन्ट डिपार्टमेन्टस खर्च करते हैं उसी प्रकार प्लान के आखिरी वक्त में खर्च किया जा रहा है अत: जितना अच्छा उपयोग इसका होना चाहिये था उतना अच्छा उपयोग नहीं हो रहा है और एक दो ऐसी बातें भी कहीं गई कि नये नये टैक्स लगाये जा रहे हैं जो जनता बरदाश्त नहीं कर सकती अगर किसी भी प्रकार के टैक्स नहीं लगाते हैं तो फिर आप पंच वर्षीय योजना का काम **कैसे**

[श्री नाथूराम मिर्धा]

चलाना चाहते हैं ? हमारे प्लानिंग डिपार्टमेन्ट ने रात दिन प्रयत्न करके इस बात को ध्यान में रखते हुए कि पिछलेपांच वर्षों में कम प्रयत्न के कारण कम रकम जनता के हित के लिये प्राप्त कर सके, आने वाले पांच वर्षों में हम ज्यादा रकम प्राप्त कर सके, और इस ओर प्रयत्न किया और हम ज्यादा रकम दूसरी पंच वर्षीय योजना के लिये प्राप्त करने में भी सफल हो सके। प्लानिंग डिपार्टमेन्ट के एस्टेब्लिश होते ही उस विभाग ने रात दिन काम किया और उन्होंने इसमें बहुत मेहनत की, कि किस प्रकार की योजनायें हम बनायें ताकि हम अपने प्रान्त को आगे ले जासकें, उसी के प्रयत्न के फलस्वरूप हमें एक अरब रुपये के करीब द्वितीय पंच वर्षीय योजना में खर्च करने को मिला।

कई माननीय सदस्यों ने इस सम्बन्ध में कुछ कहने सुनने के बजाय अपने अरमान निकालना ज्यादा अच्छा समझा। माननीय अध्यक्ष, जनता को यह बताना उनके लिये आवश्यक था कि आगामी पंच वर्षीय योजना में हम क्या क्या करने जा रहे हैं ? लेकिन इन चीजों को न बताकर अपने दिल के गुबारों को निकालना जरूरी समझा।

मैं आपके सामने कुछ ऐसी बातें जो दूसरे साथियों ने रखी थी; उन पर कुछ कहना चाहूंगा।

(घंटी)

श्री अध्यक्ष—Try to finish by 5.

श्री नाथूराम मिर्धा—(जारी) अध्यक्ष महोदय मैं पांच बजे तक खत्म कर दूंगा पांच, दस मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा। तो अध्यक्ष महोदय, जो आप सरकारी बेन्चों पर बैठे हुए माननीय साथी हैं मैं उन लोगों का समर्थन इसलिये कर रहा हूं कि इन लोगों ने हमारे राजस्थान के दबे हुए लोगों को आगे लेजाने के लिये और उनकी बहतरी के लिये बहुत काम किया है। और ज्यादा कार्य आयन्दा सालों में उनके द्वारा होने की आशा है लोगों के हित में काम करने की उम्मीद है और इन्हीं कारणों से मैं इनका समर्थन करता हूँ और आशा करता हूँ कि सब लोग मेरे इस कथन पर ध्यान देकर इसका समर्थन करेंगे।

माननीय, अध्यक्ष, हमने बराबर उन लोगों को समर्थन दिया जो इनसे पहले सरकार का कार्य करते थे हमने उस समय किसी प्रकार की भी नाराजगी इन स्थानों पर बैठने वालों के प्रति व्यक्त नहीं की। आने वाली पंच वर्षीय योजना में हमें बहुत कुछ काम करना है। यह हमारी पहली पंचवर्षीय योजना का अन्तिम वर्ष है इसके लिये गांवों और इलाकों में हमें बहुत काम करना है। जिन लोगों को कुआ खुदवाने के लिये और और कोई तकलीफ हो उनको हल करवायें यह हम लोगों को महसूस करना चाहिये क्योंकि हम जनता के नुमायन्दे हैं हमें उन लोगों के बीच काम करना है। हमारे बहुत से साथी जो खुद इस बात को जानते हैं और मानते हैं और वे काम करने के वक्त में काम न करें सिर्फ आलोचना करने के लिये आलोचना करें तो मैं समझता हूँ कि हम इस सदन के

[श्री नाथूराम मिर्धा]

समय का उपयोग नहीं कर रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि इस सदन में और भी बोलने वाले साथी हैं और माननीय अध्यक्ष की भी यह इच्छा है कि मैं जल्दी ही खत्म कर दूं।

श्री अध्यक्ष— ....If the hon'ble member could contribute Something I am ready to extend the time.

श्री नाथूराम मिर्धा—अध्यक्ष महोदय, कन्ट्रीब्यूट करने के लिये मैं तैयार हूँ किन्तु कन्ट्रीब्यूशन करने का लोग मौका देते ही नहीं। मैं आज सब आंकड़े तैयार करके लाया हूँ। जो कुछ माननीय सदस्यों ने बातें कही हैं उनकी अगर सफाई न की जाय तो बहुत से लोगों को गलत फहमी रह सकती है इसलिये गलतफहमी को साफ करना जरूरी होता है।

श्री भैंरूसिंह (१६)—मिनिस्टर साहब अगर ठीक से जवाब नहीं देते हैं तो गलत फहमी जरूर रहेगी।

श्री नाथूराम मिर्धा—अध्यक्ष महोदय, कुछ हमारे माननीय सदस्य के हमारे सदन के, मुख्य सचेतक के बारे में शुरू से एक मामले को लेकर रगड़े ही जा रहे हैं। जिस समय की यह बात है उस समय मैं भी इस केबिनेट में एज्यूकेशन मिनिस्टर था। उस समय मुख्य मंत्री जी ने मुझे खास तौर पर हिदायत दी थी कि टेक्स्ट बुक्स (Text Books) के बारे में ध्यान रखा जाय, इसमें किसी प्रकार की गड़बड़ न होने पाये। मैं जब तक इस विभाग में रहा मेरा हमेशा यही उद्देश्य रहा कि और मैं हमेशा यही महसूस करता रहा कि इस कार्य को जितना भी पवित्रता से किया जाय उतना हीं अच्छा है। और मैं हमेशा इस बात के प्रयत्न में रहा। बुक्स के सिकरेट नम्बर जो आउट हुए उसके कारण उस समय एक अहलकार को सजा भी मिली और वह जेल भी गया। और इसी सिलसिले में उनमें से एक नम्बर किसी तरह इनके पास भी पहुंच गया और उस पर उन्होंने पत्र लिखा....

श्री अध्यक्ष—Better not say about these things.

श्री नाथूराम मिर्धा—(जारी रखते हुए) इस सम्बन्ध में जांच पड़ताल चल रही है उसके बाद जो कुछ भी नतीजा होगा वह सदन के सामने आ जायगा। इसलिये मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि थोड़े दिन और इनको इन्तजार करने दिया जाय तो ज्यादती नहीं होगी। यह जबरदस्ती इस मामले को रगड़ा जा रहा है यह ठीक नहीं है। एक दूसरी बात....

श्री अध्यक्ष—This word is very harsh for the chief whip.

श्री नाथूराम मिर्धा—अध्यक्ष महोदय, चीफ व्हिप को रगड़ने की बात नहीं कह रहा हूं। इसी सिलसिले में कई साहबानों ने यह भी कहा कि ट्रेक्टर्स दिये गये आदि आदि इसके लिये मैं सदन

[श्री नाथूराम मिर्धा]

के नेता महोदय से यह कहूँगा इस सम्बन्ध में वे साफ तौर से प्रकाश डालें मुझे भी इस बारे में जानकारी है। जिस तरह जानकारी, इस सदन में कलर देकर रखते हैं और किसी को बदनाम करने का प्रयास करते हैं, यह ठीक नहीं है। कई लोग अखबारों में छपी खबरों का उल्लेख करके यहां सदन में कहते हैं कई अफवाहों के आधार पर बोल देते हैं यहां तक की अफवाहों के आधार पर भी हाई कमांड को बड़े बड़े पत्र रगड़े जाते हैं, बड़े बड़े खरड़े भेजे जाते हैं। आज हमारा ज्यादा समय इसी काम में लग जाता है, जहां हमें आने वाले वर्षों में काम करने के लिये जनता को तैयार करना है वहां हमारी सरकार का समय इन कामों से ज्यादा लग जाता है। अफवाहें तो रोज ही पचासों सुनते रहे हैं। यहां भी कई तरह की अफवाहें चलती हैं लेकिन केवल अफवाहों को आधार लेकर किसी बात को कह देना ठीक नहीं है और उन माननीय सदस्य के लिये जो मुख्य मंत्री रह चुके हैं, फाइनेन्स मिनिस्टर रह चुके हैं, सार्वजनिक निर्माण मंत्री रह चुके हैं उनके द्वारा इस प्रकार की बातें कहना ठीक नहीं है। माननीय सदस्यों ने और जो भी विशेष मुद्दे उठाये हैं उस पर हमारे मुख्य मंत्री प्रकाश डालेंगे। जिस समय उनकी बातें गलत साबित होती है तो वे माननीय सदस्य मुंह लटकाये सुनते रहते हैं असलियत क्या है। इन शब्दों के साथ ज्यादा समय सदन का न लेता हुआ अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री मानसिंह मह्मार—माननीय अध्यक्ष, आज सदन में कुछ वातावरण ऐसा गरमा-गरम होगया है और मैं तो यह मानता हूँ कि कई माननीय मित्र वास्तविकता से दूर होने लग गये हैं। मैं वापिस सदन को बजट पर लाने की कोशिश करूंगा।

श्री अध्यक्ष महोदय, सब से पहली बात जो मैं सदन में निवेदन करूंगा वह यह है जिस रोज वित्त मंत्री महोदय ने अपना बजट भाषण हम लोगों को पढ़कर सुनाया तो उस समय अधिक माननीय सदस्यों को नींद आने लग गई थी उस समय उनको यह महसूस हो रहा था कि राजस्थान की प्रगति और चाहे किसी तरफ न हुई हो किंतु प्रतिवर्ष यह बजट स्पीच वित्त मंत्री की तोंद की तरह बढ़ती ही जा रही है। सब से बड़ी बात यह है कि यह बजट स्पीच बहुत लम्बी होगई इससे लोगों को बोरिंग होने लगा। इसलिए आयन्दा आने वाले वित्त मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि अगर सदन में इस प्रकार की बातें हों तो उन्हें चाहिए कि शुरू से ही वे अपनी स्पीच शोर्ट और स्वीट डिलीवर करेंगे। उनका कन्ट्राडिक्शन नहीं होगा।

इसके बाद में सदन के सामने एक तथ्य ऐसा रखना चाहता हूँ जिसके बारे में मेरा ख्याल है कि सदन के इस तरफ या उस तरफ बैठने वाले सभी सदस्यों के दो मत नहीं हो सकते। मैं पिछले वर्ष से देखता आया हूं यह कहने से पहले मैं स्पष्ट कर दूं मैं गुटबाजी में, पार्टीबाजी में विलीव नहीं करता हूं। मैं शुरु से आखिर तक जो भी मेरे लपेटे में आया सब को एक साथ ही लपेट लेता हूं। जब श्री पालीवालजी की सरकार बनी उसको ले लीजिये, व्यासजी की सरकार बनी उसको ले लीजिये और आज हमारे मुख्य मंत्री श्री सुखाड़िया जी को ले लिजिये उस लपेटे से जिसका कि मैं जिक्र करूंगा बचने की कोई गुंजाइश नहीं। वह लपेटा यह है कि आप लोग शहरों

[श्री मानसिंह महार

के लिये अधिक कर रहे हैं और हम ग्रामीणों के लिये बहुत कम कर रहे हैं। सब से बडी जो मेरी शिकायत है वह यह है कि आप अपना रवैया बदलिये आप उस प्रिन्सीपिल को अपनाइये जिससे शहर के साथ जो पक्षपात हो रहा है वह मिट जाय। हमको बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि हम गांवों में अगर पानी पीने के लिये कुआं खुदवाते हैं तो सरकार को ले लिजिये, जल बोर्ड को ले लिजिये, सब यही कहते हैं कि आधा रुपया तुम गांव वाले लगाओ तभी तुम लोगों को पीने का पानी मुहैया हो सकता है। इसी सिलसिले में मैं यह भी निवेदन करूंगा और भी कोई काम होता है मैं मेडिकल और हैल्थ मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि हमारे इलाके में दूर दूर तक दवाइयों के लिये साधन उपलब्ध नहीं। जनता दवाइयों के अभाव में मरी जा रही है। जब हम इस प्रकार की मांगे करते है तो हमें कहा जाता है कि आप मकान बनवा दीजिये फिर कहीं दवाखाना और औषधालय खोलने की बात सोची जा सकती है। आप किसी विभाग में चले जाइये हरेक में यही जवाब मिलेगा बिना कुछ आपके खर्च किये हम कुछ खर्च नहीं कर सकते।

शहरों का हाल ले लेजिये उदयपुर में 'ए' क्लास होसपीटल बन गया, बीकानेर में वेटरनरी कालेज खुल गया, जयपुर कालेज में एडीशन हुआ क्या आपने जयपुर, उदयपुर और बीकानेर की जनता से भी यह कहा क्या तुम लोग भी इसमें श्रमदान या सम्पत्तिदान करो किसी ने नहीं कहा। शहरों में जो कुछ भी काम होते हैं वहां न श्रम दान होता है न सम्पति दान। आज भी हम देखते हैं शहरों के लिये हीं ज्यादा बजट रखा गया है शहरों में वाटर सप्लाई के लिये और गांवों में वाटर सप्लाई के लिये पैसा रखने में कितना भेद रखा गया है बजट देखने से मालूम पड़ जायगा। अरबन वाटर सप्लाई के लिये ४० लाख और रुरल वाटरसप्लाई के लिये भी ४० लाख यह आंकडों से मैं यह निवेदन करूंगा अरबन वाटर सप्लाई जो होगी उसमें श्रमदान द्वारा एक पैसा भी नही आयेगा यह फैक्ट है अध्यक्ष महोदय। रूरल वाटर सप्लाई के लिये हमारे लोग चाहें कुछ भी कहें उसमें आधा हिस्सा या वन थर्ड जब गांव वालों द्वारा दिया जायगा तभी यह काम हो सकेगा। यह ग्रामीणों के साथ सरासर अन्याय है।

मैं सदन में एक जो नई बीमारी पैदा हुई वह भी बताना चाहता हूँ। वह बीमारी यह कि आजकल शिक्षा विभाग में भी यह बीमारी फैल गई है हमारे इलाके में हाई स्कूल नहीं मिडिल स्कूल नहीं। मैं मेरी कोन्स्टीट्यूएन्सी के लिये निवेदन कर दूं जमवा-रामगढ़ तहसील में जहां ६८ हजार वोटर्स थे यह वह तहसील है जो जयपुर शहर को पानी देती है। उस तहसील में हाई स्कूल तक नहीं। इस संबन्ध में शिक्षा मंत्री और डाइरेक्टर ऑफ एज्यूकेशन से जब निवेदन किया जाता है कि इतनी बडी तहसील है कम से कम हाई स्कूल की व्यवस्था तो कीजिये तो पहले यह जवाब मिलता है कि आप बिल्डिंग का इन्तजाम कीजिये। उसके बाद में जब हमने जमवारामगढ और अचरोल में भवन दिये जब कि वहां की जनता ने दो हाई स्कूल बिल्डिंग का इन्तजाम किया इस प्रकार इन्तजाम करने के बाद भी जब निवेदन किया गया तो जबाब मिला दस हजार रूपये का और इन्तजाम कीजिये यह दुर्भाग्य की बात है अध्यक्ष महोदय, वाकई में जो गरीब इलाका है क्या वहां की जनता

[श्री मानसिंह महार

दस हजार रुपया दे सकती है इतनी मोटी रकम वहां की ग्रामीण जनता नहीं दे सकती क्योंकि वहां पर पूंजीवादी इतने नहीं पहुँचे हैं अगर पहुँच जाते तो क्या वे वहां हाई स्कूल की शिक्षा पाने से वंचित रह जाते। यह आज हमारे ग्रामीण लोगों की हालत हैं। आपने जो रवैया गांव वालों के साथ अख्त्यार किया यह हम गांव वालों के साथ अन्याय है. इसको आपको बदलना पडेगा वरना अध्यक्ष महोदय, में यह कहूंगा कांग्रेस गवनमेंन्ट हो, और किसी संस्था की सरकार हो चाहे उसमें नाथूरामजी मिर्धा के सपोर्ट के मुख्य मंत्री हों अगर उनको वापिस इलेक्शन में आना है तो गांव वालों के लिए भी में यह चाहता हूँ इस बजट के अन्दर वही बातें निश्चित की जायें जो वाजिब हों।

(घंटी)

श्री मानसिंह महार—जब आपने मुझे टाइम दिया तो अब दूसरी बात कहूंगा।

श्री अध्यक्ष—पांच मिनिट और।

श्री मानसिंह महार—साहब इसमें भी ५ मिनिट (हंसी) देंगे तो यह अन्याय ही होगा और तो मैं क्या अर्ज करूं।

माननीय अध्यक्षजी, अब मैं चन्द बातें भूस्वामी आन्दोलन और मेरे कुछ साथी जो इन कुर्सियों पर आकर बैठे हैं उनके बारे में निवेदन करूंगा। भूस्वामी आन्दोलन के बारे में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो कुछ जवाब दिया वह बड़ा ही विकसित सा जवाब था इसमें कोई संदेह नहीं है। फेस वेल्यू (face value) पर अगर उसे देखा जाय तो यह मानना पड़ेगा कि इसके अलावा सरकार के पास कोई चारा नहीं था। जहां सरकार यह चाहती थी कि कोई समझौता किया जाय तो वह किस तरह का हो जैसा कि अकालियों के साथ में पंजाब में हुआ है। उस तरह की बात समझ कर चलेंगें तो मैं समझता हूँ कि समझौता होना कोई मुश्किल बात नहीं है। तो मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रकार सरकार ने जो ५, ६ महीने पहले उन्ही भूस्वामियों से समझौता किया था। उस समय तो आज से भी ज्यादा ऊटपटांग उनकी मागें थीं। उस प्रस्ताव में सबसे पहिली मांग यह थी कि सुखाड़ियाजी गद्दी छोड़ दो। उस वक्त तो यह मांग होते हुऐ भी हमारी सरकार ने कोई समझौता किया था वह ब्लेक व व्हाइट आया चाहे न हो। तो मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि समझौता करने की कोशिश करें और समझौता करने के मूड में जरूर आना चाहिए। सरकार को यह शोभा नहीं देता। एक भले आदमी ने कहा कि अब हम कैसे करें। इसलिए यह मेरा निवेदन है अध्यक्ष महोदय; सरकार को।

दूसरी चीज जो मैं कहूंगा वह यह है कि भूस्वामियों को लोग अगर गलत रास्ते पर ले जाते हैं तो आप उसकी बुनियाद पर जायें कि लोग कैसे ले जाते हैं ? एक आदमी गलत रास्ते पर चला जायेगे, दो चले जायेगे, १०,२० चले जायेगें। अगर आप समझते है उनको गलत बातें कहते तो आप उनको विज्ञप्ति के द्वारा समझाने की कोशिश कीजिये। वर्तमान महासभा नेता

[श्री मानसिंह महार]

आपकी है उस से बुलेटीन निकलवाइये, उनसे समझवाइये। उनसे समझवाने से बहुत कुछ हो सकेगा मैं यह मानकर चलता हूं। यह भी नहीं कर सकते हैं तो एक सुझाव और देता हूं कि आप अपने विभाग में विभाग पर फिर कहुँगा तो मंत्रीजी कुछ नाराज होंगे, लेकिन मुझे कहना पड़ता है जैसे फोड़ा होता हैं उसका आपरेशन किया जाता है वैसे ही अपने यहां आपरेशन का तरीका अपनाये। वह तरीका यह है कि कुछ लोगों को आपके प्रति इतना असंतोष क्यों है? यद्यपि समझौता हुआ नहीं था अब क्यों इतने भड़क पड़े? तो मैं कहता हूँ कि जागीर डिपार्टमेंट में जाकर देखिये तो वहां मेवाड़ी ही मेवाड़ी भरे हुए हैं राजस्थान में और कोई लोग ऐसे नहीं हैं, जयपुर में नहीं है जोधपुर में नहीं है, बीकानेर में नहीं हैं कि और कोई भी इधर उधर का लगा दिया जावे।

एक माननीय सदस्य—नाम बता दीजिये।

श्री मानसिंह महार—वहां के नाम भी बता सकता हूँ। मैं इस तरह की बातें कहता हूं। लेकिन थोड़ा सा अर्ज कर देता हूँ किसी भी तरह से लोभ करके नाम नहीं लूंगा। बड़े आफिसर होते हैं उनके लिए क्या निवेदन करूं। यह जरूर है कि मेरा जो कम्पेन्सेशन का केस है उसमें आज यह कहने की वजह से बहुत रोड़े अटकेंगे। उसमें अननेसेसरी डिले होगी। यह भी मान कर चलता हूं फिर भी हिम्मत करता हूं भूस्वामियों की जो वाजिब मांगें हैं उनको हमारे माननीय मुख्य मन्त्रीजी तक पहुंचाना मैं अपना परम कर्त्तव्य समझता हूं। मैं चाहता हूं कि किसी तरह से समझौता हो जाय। इसलिए निवेदन करूंगा कि जागीर डिपार्टमेंट में मेवाड़ी ही मेवाड़ी हो रहे हैं। हम जाते है तो जरा अफसोस होता हैं कि वहां महाराणा प्रताप ही, प्रताप दिखते हैं तो जयपुर वाले तो डर कर भाग जाते हैं। इसलिए यह कहता हूं कि उसमें सबका सम्मिश्रण करके उसको थोड़ा कास्मोपोलिटन बना दें तो बड़ी महरबानी हो। वहां की एक घटना का निवेदन कर दूं कि एक जयपुर के जागीरदार थे उनका सेटिलमेंट नहीं हुआ था। उनका रिजम्पशन की लिस्ट में नाम आगया। वह मेरे पास आये मेरे पास अमुमन जागीरदार लोग आते नहीं हैं क्यों कि वे यह जानते हैं कि यह जायगा तो काम बिगड़ेगा, फिर भी वे आगये। वह बोले मेरा सेटिलमेंट नहीं हुआ और मुझे रिजूम कर दिया गया है जो कि कानून नहीं है। मैं तो चाहता हूं कि कि मेरी जागीर को रिजूम हुए डेढ़, दो साल होगये तो औरों की जल्दी से जल्दी रिजूम हो लेकिन उनके साथ अन्याय हुआ और वह आये हैं तो चलो जागीर कमिश्नर सहाब से मिल लें। उनसे मिला और कहा कि इनका सेटिलमेंट नहीं हुआ है और यह नकल हुकुम भी लाये हैं कि इनका सेटिलमेंट नहीं हुआ इसलिए इनको आपके नोटिफिकेशन के बाहर रखना चाहिए। तो उनसे जवाब मिलता है कि जो सरकार से द्वेष रखते हैं उनको हम छोड़ नहीं सकते। सरकार से कोई द्वेष नहीं रख सकता। सरकार प्रत्येक व्यक्ति की है। सरकार किसी व्यक्ति की नहीं है। सरकार जागीर कमिश्नर की नहीं है। सरकार हम सबों की हैं। एक एक आदमी के पसीने और खून से बनी हुई, हमारी सरकार है। (हंसी)। यह कह देना कि ऐसे लोगो की है, गलत है। तो मैं यह कह रहा हूं कि जैसा पालीवाल जी ने फरमाया था कि १६० लखपतियों की है तो ऐसा सरकार को महसूस करना चाहिए कि १६० में ऐसे मिलेंगे कि जो जागीरदारों का

[श्री मानसिंह महार]

कुछ न कुछ पक्ष लेते होंगे । इसलिए सरकार के लिए लाजमी हो जाता है जि उनकी तरफ ध्यान देवें, और ऐसी कोई ग्रास इन्जस्टिस होती हो तो अवश्य ध्यान दें ।

तीसरी बात जो निवेदन कर रहा था, वह आलोचना कहूंगा रगड़ाई तो मैं अपनी जबान से नहीं कहूंगा वहतो मिर्धा साहब को हीं अच्छा लगेगा । इन्होंने फरमाया था कि यह जो जागीरदार इस तरफ आकर बैठे हैं वे व्यासजी को उस कुर्सी पर बनाये रखना चाहते थे । अध्यक्ष महोदय, दावे के साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस रोज व्यासजी में नो कॉन्फीडेन्स का प्रस्ताव पास हुआ उसमें यदि सभी जागीदार व्यासजी को वोट देते तो व्यासजी कभी नहीं हारते ।' पहला मेरा दावा यह हैं । दूसरा एक और दावा यह है कि आज जितने भी जागीरदार बैठे हैं उनमें २, ३ की मैं नहीं कह सकता; माननीय अध्यक्ष महोदय, मगर जो रिमेन्डर हैं वह तो इन्हीं के समर्थक हैं । यह उनकी क्रेडिट पर मैं कहता हूँ कि नाथूरामजी मिर्धा के जो वाक्य हैं ठीक नहीं हैं । तीन, चार आदमियों को छोड़कर और लोग सब जो हैं वे 'बड़े हुकम' के समर्थक हैं । यह बिल्कुल गलत है कि सब जागीरदार लोग व्यासजी को कुर्सी पर टिकाये रखने के लिये आये ।

एक माननीय सदस्य—आपने भी तो समर्थन किया है ।

श्री मानसिंह महार—मैं तो अपने को अभी कच्ची कौड़ी में ही समझता हूं समर्थन का सवाल ही नहीं आता है । भगवान ने मुझे आलोचना से बचाया है । एक. दो साल से मैं एडमीशन की कोशिश कर रहा हूं । जागीरदारों को साथ में ले जाते हुए उनकी नीची टॉट करके दुबकाया जाय लेकिन मैं खरी कहे बिना नहीं रहूँगा । नाथूरामजी की परवाह करके कहने से शायद उनकी समझ में आगे आजाय, क्योंकि उन्होंने गलती की है । तो माननीय मुख्य मंत्रीजी से आशा करूंगा कि अपने जबाब में इसका क्लेरिफिकेशन देगें । और मैं निवेदन करूंगा कि जैसा कि फरमाया गया कि इधर वाले जागीरदार सारे युनेनीमसली व्यासजी को सपोर्ट करते तो वह लीडर नहीं चुने जाते । यह निश्चित चीज है, तो यह कह देना गलत है । जागीरदारों पर आप कीचड़ उछालें तो हमें दुःख नहीं है । हम कीचड़ प्रूफ हैं । लेकिन यह दुर्दशा है कि आप लोग आपस में कीचड़ उछालते हैं । हमें तो बीस वर्ष हो गये आपके टारगेट बने । हम तो कीचड़ प्रूफ हैं । फिर भी यह कह देना उन लोगों के साथ, अभी भी मैं एडमिट नहीं हुआ हूँ, एक जुल्म है । मैं यह मानकर चलता हूँ कि आज श्री खेतसिंहजी आपकी केबीनेट में बैठे हुए हैं फिर भी यह बात तथ्यहीन हो जाती है । लेकिन आपकी जब मैंने यहां बातें सुनी तो मेरे कानों के कीड़े झड़ गये । मैं सही निवेदन करता हूं कि किसी सदन के सदस्य से और स्वयं माननीय मुख्य मंत्रीजी से यह आशा नहीं करता था कि वह ऐसी बात कह सकते हैं । कोई भी आदमी यह नहीं कह सकता कि आज राजस्थान में भ्रष्टाचार कम हुआ है । यह तो एक बात है और मैं-यह मानकर चलता हूं कि हमारा मोरेल स्टेन्डर्ड कितना गिर गया है कि भ्रष्टाचार कम करना मुश्किल बात है । यह कहना कि भ्रष्टाचार में कमी हुई, बुराई पर पर्दा डालना है ।........

श्री भैरूंसिंह—किसने कहा ?

Page No.117

श्री मानसिंह महार—मेरे आगे जो माननीय सदस्य बैठे हैं उन्होंने कहा। उन्होंने यह फरमाया कि भ्रष्टाचार कम हो गया है। यह बात बिल्कुल गलत है। जैसा एक साथी ने फरमाया था, मुझे याद नहीं है कि किसने फरमाया था, कि राजाओं के समय में खाने के लिये पैसा ज्यादा नहीं था और अब पैसा ज्यादा आया है इसलिये भ्रष्टाचार बढ़ गया है मैं यह भी मानता हूँ कि भ्रष्टाचार बढ़ा है। मैं किसी सदस्य पर आक्षेप के लिये नहीं कहना चाहता। लेकिन जिस माननीय सदस्य ने यह बात कही कि भ्रष्टाचार कम हुआ है वे पहले इधर बैठते थे और अब वे उधर विराजे हैं। उस दिन से आज तक ट्रान्सपोर्ट ओथोरिटी के यहां के यहां के मुकद्दमों में जो मुख्त्यारनामे पेश होते हैं उनमें तीन वर्षों में उनके कितनें मुख्त्यारनामें पेश हुए थे और आर. टी. ओ. के यहां और उधर बैठने के बाद में कितने पेश हुए हैं। इसका पता लगाने से आपको पता लगेगा कि कितनी वृद्धि हुई है। मैं कह नहीं सकता कि भ्रष्टाचार दूर हुआ है या नजदीक आता है। जो इसके नजदीक जाते है वे ही देख सकते हैं। हम तो यह जानते हैं कि सरकार को देखना चाहिये कि भ्रष्टाचार बढ़ा है या कम हुआ है इस पर विचार करना चाहिये।........

श्री गोपीलाल यादव—सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है।

श्री मानसिंह महार—आपको हरा ही हरा दिखता है। मैं जो चाहता था वही हुआ। जो आदमी भ्रष्टाचारी है उसको भ्रष्टाचार ही नजर आता है।........

श्री गोपीलाल यादव—मैं चेलेन्ज करता हूं कि आर. टी. ओ. के यहां जिसने भ्रष्टाचार किया है उसको प्रूफ करें। इस तरह की शरारत की बातें करते हैं।

(घंटी)

श्री गोपीलाल यादव—इस तरह की बातें मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। बेईमानी की हद है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री)—अध्यक्ष महोदय, इस तरह की चर्चा सदन में न चले तो ज्यादा अच्छा हो।

श्री गोपीलाल यादव—कम से कम बेईमान आदमी इसको बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन मुझ सा आदमी जो जिन्दगीभर ईमानदार रहा है उसको बेईमान आदमी की बेईमानी की बातें बर्दाश्त नही हो सकती। वे साबित करें कि किस किस वकालातनामें में और कहां भ्रष्टाचार किया है।

श्री घोसीसिंह—यह भी बताऊं क्या, कि जो मत्स्य में किया है ?

श्री गोपीलाल यादव—यहां की और मत्स्य की भी।

श्री अध्यक्ष—फिनिश करिये।

Page No.118

श्री मानसिंह महार—अध्यक्ष महोदय, दूसरों को इतना समय दिया है तो थोडा तो मुझे और दीजिये यह मेरा आखिरी भाषण है। मुझ से जो नाराज हो गये हैं उनको राजी भी तो करने दीजिये। मैं किसी को नाराज नहीं चाहता। सब को खुश करके कहना चाहता हूँ चाहे सच हो चाहे झूठ हो, मैं नहीं समझता कि इतने नाराज होने की क्या जरूरत थी। उन्होंने ही कहा था कि श्रावण के अंधे को हरा ही हरा दिखता है। मैं किसी पर आरोप नहीं करता। आर. टी. ओ. से लिस्ट मंगाकर देखी जाय तो पता चल जायगा।........

श्री गोपीलाल यादव—आज ही मंगाकर देखें।

श्री मानसिंह महार—यह तो मुख्य मंत्रीजी का काम है। मुझको प्रिविलेजेज कमेटी में भेज दें तो मैं वहां भी बयान दे दूंगा।

अब आज मुझे और जो बातें कहनी है वे कई बार दोहराई गई हैं बजट के मौके पर और राजप्रमुख के अभिभाषण के समय भी दोहराई गई हैं, सर्विसेज की जो बात है। उनके ग्रेड्स वगैरा दिये गये हैं उनसे सर्विसेज में बड़ा असंतोष है। सर्विसेज वाले यह समझते हैं कि हमारे साथ अन्याय किया गया है। आपने जो कुछ कर दिया वह तो हो गया। अब थोड़ा बहुत हेर फेर कर दीजिये जैसा आर. ए. एस. वाले कहते कि उनके साथ अन्याय हुआ। मास्टर लोग कहते हैं कि हमारी तनख्वाएं पहले ही कम थी और अब भी कुछ नहीं दिया गया। फोर्थ क्लास सर्विसेज के लिए तो आप एक प्रिंसिपल ही बना लीजिये, १०, २० लाख रुपये खर्च हो जांय तो कोई परवाह मत कीजिये। आप यह तय कर दीजिये कि राजस्थान के छोटे कर्मचारियों को ५० रु० मासिक से कम किसी को नहीं मिलेंगे। आप इतना तो कर दीजिये ताकि हम सोशलिस्ट पेटर्न की ओर चल सकें। मैं यह नहीं कहता कि सोशलिस्टिक पेटर्न भुलावे की बात है। मैं नहीं मानता कि पंडित जवाहरलालजी नेहरू के स्लोगन्स भुलावे के लिए चल रहे हैं। मैं इसको भुलावा नहीं कह सकता। राजस्थान और मत्स्य के पुराने मंत्री कह सकते हैं कि नेहरूजी इस में भुलावा देते हैं लेकिन मैं नहीं मानता। मैं सही तरीके से सोशलिस्टिक पेटर्न की ओर बढ़ते देख रहा हूँ।

एक मुद्दे की बात और कहना चाहता हूं। हमारे जयपुर में जो जू (Zoo) है उसके बारे में एक और निवेदन है। इस जू (Zoo) में आजकल बद इन्तजामी चरम सीमा तक पहुँच चुकी है। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं हर समय वहां जाता रहता हूँ, मैं वहां का रेगुलर विजीटर हूँ। मैं जानवरों में इन्ट्रेस्टेड हूं। जब वहां जाता हूँ तो नाक पकड़ कर जाता हूँ लेकिन जाता जरूर हूँ। वहां सफाई का नाम नहीं है। बहुत बदबू आती है। मैंने इसकी जड़ ढूंढना चाहा तो उसमें क्या देखता हूं कि, मुझे कहना नहीं चाहिये लेकिन स्पष्ट कहूँगा कि हमारे मंत्री महोदय हैं इस विभाग के उनके कृपा पात्र के लड़के को वहां पर अपोइन्ट कर दिया है। इसके बारे में मुझे भी किसी तरह से मालूम हो गया। मुझे कहना तो नहीं चाहिए क्यों कि उनके और मेरे सम्बन्ध में फर्क आयगा। लेकिन वे उनके कृपा पात्र हैं। उनको अपोइन्ट करने के बाद उनको, राजस्थान सरकार का आदेश होते हुए भी कि सरकारी नौकरी बिना इजाजत कोई इम्तहान नहीं दे सकता, उन्होंने लखनऊ जाकर इम्तहान दिया। अब भी वे इम्तहान देने जायेंगे। अब यदि यह भाषण सुनकर वे

[श्री मानसिंह महार]

अपना इरादा बदलदें तो दूसरी बात हैं। यदि सरकार यह कहे कि उन्होंने एल. एल. बी. का इम्तहान नहीं दिया तो मैं साबित करूंगा युनिवर्सिटी के रिकार्ड से फिर आप उन्हें सजा दीजिये। यह फेक्ट है! जयपुर के जू (Zoo) की जो दयनीय दशा हो रही हैं उसको सुधारने के लिए आपको कदम उठाना चाहिए और टेम्पोरेरी आदमियों को वहां लगाकर इसकी दुर्दशा कर रहे हैं यह सरासर गलत चीजें हैं।

अब जैसी अध्यक्ष महोदय की आज्ञा। मुझे कहना तो बहुत था लेकिन अभी समय नहीं हो तो कट मोशन के समय बोलकर निवेदन करूंगा। मैंने एक दो बातें जो कहीं हैं उनमें यदि सत्य हो तो उसके अनुसार काम करना चाहिए। किसी के नाराज होने की गुंजायश नहीं है।

श्री भैरूंसिंह (डि. नं० १६)—अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्रीजी ने राजस्थान का सन् ५६–५७ का आय व्यय का लेखा इस सदन में प्रस्तुत किया और उसके बाद से ही इस संबंध में अधिकांश सदन के माननीय सदस्यों ने वाद-विवाद किया। माननीय अध्यक्ष, किसी भी सरकार का किसी भी वर्ष का यदि कोई बजट प्रस्तुत होता है तो उससे यह बात स्पष्ट मालूम होती है कि हमारे राज्य में इस वर्ष में कितनी आमदनी होगी और कितना खर्च होगा और यदि खर्चा ज्यादा होता है और आमदनी कम होती है तो वैसी स्थिति में जो घाटा रहता हैं उसकी पूर्ति हम किस प्रकार करेंगे।

माननीय फाइनेन्स मिनिस्टर ने भी इस परम्परा को निभाकर इस बात की चेष्टा की कि राजस्थान के बजट में भी एक तरफ आय बताई जावे और दूसरी तरफ खर्चा बताया जावे और खर्चा ज्यादा है इसलिये जितना घाटा है, घाटा बताया जावे और इसका फैसला किस तरह से होगा, इसे सदन में बताया जावे। लेकिन अफसोस है कि न मालुम किस भय से या चालाकी से या कारीगरी से घाटे को किस तरह से पूरा किया जावेगा इस बात को छुपाया गया। कल सदन में जब इस बात की चर्चा हुई थी कि राजस्थान में ८४ लाख रुपयों के अतिरिक्त टैक्स की योजना बनी है। उस समय मैं यह समझता था कि सरकारी बेंचों की ओर से बोलने वाले सबसे अच्छी तरह से इस बात का स्पष्टिकरण करेंगे कि ८४ लाख का टैक्स किस प्रकार से लगेगा लेकिन अभी एक भाषण को सुन कर मुझे खेद ही नहीं बल्कि इस बात पर इतना ज्यादा रंज होता है कि सरकार पर किस प्रकार विश्वास किया जा सकता है। सरकार की तरफ से और बजट स्पीच में यह लिखने के बाद भी ८४लाख के टैक्सेस सरकार लगा रही है एक माननीय सदस्य यह कहते हैं कि मेमोरेन्डम को नहीं देखा है। उन्होने आंकडे बताये और एस्टीमेट में से कुछ स्टेटमेंट और नक्शा हैं उसकी ओर ध्यान आकर्षित करने की चेष्टा की। अगर वे स्टेटमेंट और नक्शे की ओर नहीं जाते और बजट के स्पीच को ही पढ़ लेते तो आपको जो शंका है वह दूर हो जाती।

माननीय अध्यक्ष, फाइनेन्स मिनिस्टर ने अपने स्पीच में स्पष्ट बताया है:

"Adding to the normal receipts, Rs. 176.70 lakhs on account of aid from the Government of India during 1956-57, in respect of development

[श्री भैरूसिंह]

schemes inculded in the Second Five Year Plan and Rs. 84 lakhs (and something) to be raised as a result of additional taxation measures on revenue account, the aggregate of Receipts Estimate works up to Rs. 2498.96 lakhs".

मुझे समझ में नहीं आया कि इन्होने इस प्रकार कहने की कुचेष्टा किस प्रकार कि केवे आंकडे और गोल मोल नक्शा बना कर सदन को मुगालते में डाल सकेंगे। सिर्फ उनके लिये इतना ही कहना और संकेत सदन के लिये काफी होता फाइनेन्स मिनिस्टर की तरफ से ८४लाख रुपयों का टैक्स राजस्थान सरकार इम्पोज करने वाली है लेकिन उनको इससे संतोष नहीं हुआ। उन्होने यहां आय और व्यय के आंकडे देते हुए १ करोड ७० लाख का घाटा बताया। वहां उन्होने यह भी कहा कि घाटा कम होगा क्योंकि डेवलपमेंट के वर्क के लिये अभी तक उनको पूर्ण रुप से कितना खर्च करना होगा उसका संकेत नहीं मिल सका है। जब आपको स्पष्ट रुप से मालुम नहीं हुआ है तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि घाटे में कमी होगी। इसके अलावा एक बात और कही गई कि आगे चल कर गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया से हमें मदद मिलने वाली है, वह इन्क्रीज होने वाली है और इससे घाटे में कमी आ सकती है। मैं यह कहूंगा कि कोई बजट बने लेकिन जब तक सरकार को अपने हिसाब का पूरा ज्ञान नहीं है तो बजट किस प्रकार बनेगा और बनाया गया इसमें संदेह होता है।

मैं यह निवेदन करूंगा कि द्वितीय पंच वर्षीय योजना में ४८ सो करोड रुपया सारे भारत वर्ष में खर्च होगा और उसमें राजस्थान में भी उसके हिस्से का एक करोड रुपया उसको मिल सकेगा।

श्री दामोदरलाल व्यास—एक करोड़ रुपया नहीं एक अरब रुपया उसके हिस्से में आवेगा।

श्री भैरूसिंह—ठीक है। एक अरब रुपया। अब टैक्स की बात कही। ८४ लाख का टैक्स इसके बाद में लगने वाला है, लगावें। अध्यक्ष महोदय, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो टैक्स लगाने की जिम्मेदारी होती है उस हिसाब से ८ करोड़ रुपयों को टैक्सों के रूप में ४ या ५ सालों में इकट्ठा करना होगा। इसके लिये किसी तरह इन्कार नहीं कर सकती हैं। यदि उसको इस साल नहीं लगाया गया तो अगले साल लगाना होगा जो उससे ज्यादा होगा और दो तीन साल तक नहीं लगाया तो इसका बोझा जनता पर बहुत पड़ जावेगा और क्या कोई यह उम्मीद कर सकता है कि ८ करोड़ रुपया एक साथ टैक्स के रूप में लगाकर इकट्ठा किया जाए। यह असंभव सी बात है। इसलिये सरकार को द्वितीय पंच वर्षीय योजना से सही खर्चे की सही योजना बनाती है और उसके अन्तर्गत ८४ लाख का टैक्स और अगर १ करोड़ ७० लाख की पूर्ति नहीं होती है तो और टैक्स लगाना होगा। सरकार को टैक्स लगाने की बात को पूर्ण रूप से स्वीकार करनी चाहिये और जो कुछ भी इसमें संकोच हो उसको दूर करना चाहिये। आज पब्लिक के सारे

[श्री भैंरूसिंह]

व्यापार का दारोमदार बजट पर निर्भर है। बजट में घाटा रहा इसलिये टैक्स लगाना पड़ेगा, मगर किस पर टैक्स लगेगा किस प्रकार टैक्स लगाये जावेंगे कितने टैक्स लगेंगे और किस प्रकार लगे हुये टैक्सों में रद्दोबदल होगा इस प्रकार का कोई ज्ञान सदन को नहीं कराया, अगर आप बताते तो हम अपनी जिम्मेदारी को निभाते और उस समय कुछ कहते। लेकिन ऐसा नहीं करके आप पब्लिक को धोका देना चाहते हैं। आप टैक्स बढ़ा देंगे और आर्डीनेन्स स्वीकार करा लेंगे। जो सब्ज्यूल्ड है उसमें कुछ आर्टीकल को बढ़ा देंगे। वसूल सारा का सारा टैक्स हो जावेगा और सदन में ६ महीनों के बाद जब सदन की बैठक होती है यह कहा जाता है कि ६ महीने इन टैक्सों को देते हुये आपको हो गये हैं, सरकार का काम है, पैसे बटोरना। मगर मैं यह कहूंगा कि इस प्रकार से लोगों से पैसे बटोरना, लोगों के कलेजे को निकालना है।

अभी सदन में बलवन्तसिंह की बात कही गई, मैं यह कहूँगा कि बलवन्तसिंह लोगों से रुपया पैसा छीनता है और वह पुराने टाइप का बलवन्तसिंह है आजकल दुनियां में मोडर्न टाइप के बलवन्तसिंह हैं हमें उनसे बचना चाहिये और उनसे बचने का हमें पूरा प्रयत्न करना चाहिये।

इसके अलावा मैं यह कहना चाहता हूँ कि हमारे पर टैक्स लगाये जाते हैं लेकिन बजट में इस बात का भी संकेत नही होता की किस चीज पर यह टैक्स लगाये जावेंगे और किस प्रकार से लोग उसको अदा कर सकेंगे। क्या कारण है कि सरकार ने जो अपना बजट पेश किया उसमें इसका साफ तौर से कोई जिक्र नहीं किया और इस बात की तरफ कोई संकेत नहीं किया कि किस प्रकार यह टैक्स लगेंगे।

बजट में हम सोशल्सिटक पेटर्न की बात कर रहे हैं। इस सम्बन्ध में हमारे भरतपुर से आने वाले माननीय मित्र ने बताया कि यह सोश्यलिस्टक पेटर्न का हमारा स्लोगन है अगर यह एक प्रकार से स्लोगन है तो इसके लिये कोई कहने की बात नहीं। मैं समझता हूं कि यह अकेले उन्हीं का कहना है कि यह केवल नारा है बाकी सदस्य कोई इस बात को नहीं कहता कि यह केवल नारा है इसलिये इस पर विश्वास नहीं हो सकता कि यह समाजवाद का नारा है। कहा यह जाता है कि हम इस ओर प्रगति कर रहे हैं और आगे बढ़ने की चेष्टा करते हैं और की है। वैसे तो सोचना पड़ेगा कि समाजवाद के लक्ष्य को सामने रख कर सरकार ने जो लोगों की तनख्वाह बढ़ाई है उसमें समाजवाद के नक्शे को सामने रखा है या नहीं। मैं यह कहूँगा कि आज कोई भी माननीय सदस्य जब बाहर जाते हैं और छोटे कर्मचारी से बात करेंगे या उनके प्रतिनिधि से बात करेंगे और छोटे छोटे लोगों से मिलेंगे तो आपको मालूम होगा कि सरकार ने बड़े कर्मचारियों की तनख्वाह ज्यादा बढ़ाई है और छोटे कर्मचारियों की तनख्वाह बिल्कुल कम। जहां १ प्रतिशत छोटे कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ाई है तो दूसरी तरफ बड़े कर्मचारियों की ३० प्रतिशत बढ़ाई है। मैं समझता हुँ कि यह समाजवाद की तरफ बढ़ने का कोई विशेष जरिया नहीं हो सकता। इस संबंध में ज्यादा बातें नहीं कह कर स्कूल के

[श्री भैंरूसिंह]

मास्टरों के बारे में जो तनख्वाह अपनाई गई है, उसके बारे में विशेष रूप से सदन का ध्यान आकर्षित करूंगा।

अनट्रेंड मेट्रिकुलेट मास्टरों की तनख्वाह ५०-४-७० से ५०-४-७०-५-८० दूसरी तरफ जितने कम्पाउन्डर जिनकी योग्यता उतनी ही है उनकी तनख्वाह आपने इस प्रकार रखी है:— ६०-४-८०-५-१२०। उसने भी ट्रेनिंग पाई है इसके कम्पाउन्डरने भी ट्रेनिंग पाई है। इसके अलावा कम्पाउंडर के लिये यह भी जरूरी नहीं कि वह मेट्रिक हो यदि वह कम्पाउंडर है तो उसकी तनख्वाह १२० तक होगी। ट्रेंड मेट्रिकुलेट की तनख्वाह ८० पर रुक जावेगी उधर अनट्रेंड ६०-४-६०-५-१०० और एल. डी. सी. के ग्रेड ६०-४-८०-५-१००-५-१३०।

माननीय अध्यक्ष, यह देखना पड़ेगा कि जब दोनों एक ही प्रकार की क्वालिफिकेशन्स के आदमी हैं, किसी गवर्नमेंन्ट सर्विस में लेते हैं तो सोचना पड़ेगा कि जब दोनों की ड्यूटीज एकसा हैं, दोनों की क्वालिफिकेशन्स एकसा है, एक्सपीरियन्स एकसा है तो वैसी हालत में एक के साथ न्याय करें और दूसरे के साथ अन्याय करें यह कैसे वाजिब हो सकता है। जितने भी ट्रेन्ड मेट्रिक हैं और ट्रेन्ड इन्टर हैं उनमें आपको विशेष प्रकार की चीज मिलेगी। ट्रेन्ड मेट्रिक है ७०. ४. ८०. १३० उसी तरह से जो ट्रेन्ड इन्टर है उसकी ग्रेड है ७०. ४. ६०. ५. १४०। मुझे निवेदन करना यह है, कि यदि कोई ट्रेन्ड मेट्रिक ७० पा रहा है तो उसको ग्रेड मिलेगी ७०. ४. ८० ५ १३० और ट्रेन्ड इन्टर को क्या मिलेगा वहां चार रुपये के हिसाब से इन्क्रीमेन्ट ८० तक और उसके बाद ५) के हिसाब से, तो एक बढ़ेगा १३० तक और दूसरा १४० तक।

आगे देखिये, मेट्रिकुलेटस में दो केटेगरीज आती है। एक हैं ट्रेन्ड मेट्रिकुलेट और दूसरा हैं अनट्रेन्ड मेट्रिकुलेट। एक ट्रेन्ड मेट्रिकुलेट की तनख्वाह है ७०. ४. ६०. ५. १३० और दूसरा जो अनट्रेन्ड मेट्रिकुलेट है उसकी है ७०- ५. ६०. ५. १३०। जो व्यक्ति अनट्रेन्ड मेट्रिकुलेट है उसको पांच रुपया इन्क्रीमेन्ट मिलेगा जब कि जो ट्रेन्ड मेट्रिकुलेट है उसको चार रुपया मिलेगा। जो ज्यादा क्वालिफाइड है उसको तो कम मिलेगा और जो कम क्वालिफाइड है उसको उससे कम मिलेगा। इस प्रकार के इन्क्रीमेन्टस इस सरकार के लिए कभी शोभाजनक नहीं हो सकते।

यह इतना ही नहीं माननीय अध्यक्ष, राजस्थान में कई ऐसे स्कूलों के टीचर्स हैं जिनका फिक्सेशन नहींहुआ है उनका क्या हाल होगा। किसी को बीस रुपया मिलता है किसी को तीस रुपया मिलता है। राजस्थान में ड्रिल मास्टरों के नाम से सरकारी स्कूलों में एक एक ड्रिल मास्टर है। जयपुर में उन ड्रिल मास्टरों को २५ रुपया माहवार मिलता है। एक तरफ तो आप उनके समकक्ष मास्टरों की ग्रेडस बढ़ाते हैं और दूसरी तरफ उनकी नहीं बढ़ाते है और उनका फिक्सेशन भी नहीं करते हैं तो उनको वे ही २५)मिलेंगे। सरकार ने कहा कि केवल तनख्वाहे बढ़ा देने से अच्छी अर्थ व्यवस्था कायम नहीं हो सकती है उन्होने कहा कि २५० से कम तनख्वाह पाने वाले कर्मचारियों के बच्चे डिग्री कालेजों तक बिना फीस के पढ़ते रहेंगे, और इस तरह से हमने उनको एक सहूलियत दी है। माननीय अध्यक्ष,

[श्री भैरूसिंह]

जिन दिनों स्कूलों में एडमिशन्स होते हैं, स्कूलों के सामने आप खड़े होकर देखिये कि लडकों की एडमिशन के लिए कितनी बाढ़ आती है, उनको एडमिशन्स नहीं मिलते और जब उनको एडमिशन्स नहीं मिलते है तो उनको मजबूर होकर प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन लेना पड़ता है अर जब उनको प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन लेना पड़ता है तो वे प्राइवेट स्कूल सरकार की इस आज्ञा को नहीं मानेंगे और प्राइवेट स्कूल्स जिस तरह से दूसरों से फीस लेते हैं उसी तरह से उनसे भी फीस वसूल करेंगे। उनके सामने कोई उनके लिए रियायत नहीं है कि सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के बच्चों की पढ़ाई के लिए उनको फीस से मुक्त कर दिया है। मैं समझता हूं जो इस प्रकार की रियायत दी गई वह केवल नाम मात्र की रियायत है। इसमें यह लिखा है कि २५० से नीचे तनख्वाह पाने वाले नोन गजेटेड कर्मचारियों के बच्चों से जो कालेज में पड़ते हैं उनसे फीस नहीं ली जावेगी। माननीय अध्यक्ष, यह समझ में नहीं आया कि यहां भी गजेटेड और नोन गजेटेड इस प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन क्यों रखा गया है? २५० से नीचे तनख्वाह पाने वाले कर्मचारियों के बच्चों के लिए किसी प्रकार की रियायत करना है तो यह फिर नोन गजटेड और गजटेड का फन्दा क्यों रखा है? होना तो यह चाहिये था कि चाहे गजेटेड हो या नोन गजेटेड हो जो २५० से नीचे की तनख्वाह पाने वाले सरकारी कर्मचारियों के बच्चे है वे फीस से मुक्त किये जाते है। इस प्रकार की रियायत देनी चाहिए थी।

कुछ माननीय सदस्यों ने संकेत किया था कि तनख्वाहों के घटाने बढ़ाने में बड़ी अनियमिततायें की गई हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं भी निवेदन करना चाहूंगा और खास कर आर. ए. एस. ऑफिसर्स के बारे में। श्रीमन् राजप्रमुख के अभिभाषण पर जिस समय जमुआ-रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने इन बातों पर विचार प्रकट करते हुए सरकार का ध्यान दिलाया था कि इनमें जितने भी प्रोमोशन्स हुए हैं उनमें राजपूत ऑफिसर्स के साथ ज्यादती हुई है। मैं उस बात पर नहीं जाउंगा कि राजपूत ऑफिसर्स के साथ ज्यादती हुई है। मैं उस बात पर नहीं जाऊंगा कि राजपूत आफिसर्स के साथ ज्यादती हुई हैं, लेकिन मैं तो यह निवेदन करूंगा कि यदि किसी भी ऑफिसर के साथ चाहे वह राजपूत हो, चाहे और कोई हो, उसके साथ ज्यादती हुई है तो वह राजस्थान सरकार के लिए शोभा की बात नहीं है। राजस्थान के आर. ए. एस. ऑफिसर्स को सिनियोरिटी की लिस्ट के हिसाब से ५३ नम्बर तक तो प्रोमोशन दे दिया उसके आगे ५३ पर रन्जीतसिंहजी हैं उनको अच्छी ग्रेड मिल गई अपनी जगह पर काम कर रहे हैं। उसके बाद नम्बर ५४ पर जो है श्री ओंकारसिंह उनको प्रोमोशन नहीं मिला। नम्बर ५५ पर श्री मथुरानाथ पंचोली हैं उनको प्रोमोशन मिल गया, हिम्मतसिंह गलुन्डिया को प्रोमोशन मिल गया, हजारी लाल मेहता को प्रोमोशन मिल गया, और उसके बाद आते हैं सौभाग्यसिंह उनको प्रोमोशन नहीं मिला। उसके बाद सुरेन्द्रनाथ को प्रोमोशन मिल गया, मगनलाल नेनावटी को प्रोमोशन मिल गया, धरनीधर मोहिल्ल को प्रोमोशन मिल गया, मूलसिंह किशनपुरी आई. ए. एस. में चले गये। दो तीन रह गये हैं, अब्दुल जलील, रामसिंह सेकिंड, इनको प्रोमोशन नहीं मिला। ६८ नम्बर को छोड़ कर सारे नम्बर को सरपास करते हुए बनेसिंह धाबाई को प्रोमोशन मिल गया। शरफअली को छोड़ दिया, जीवनसिंह को छोड़ दिया, टी.के.बी. कुरुप को छोड़ दिया और माननीय उपाध्यक्ष, सुरेन्द्रसिंह, कन्हैयालाल जो ७७

[श्री भैरूसिंह]

नम्बर पर हैं १५ आदमियों को छोड़ कर उनको प्रोमोशन मिल गया। इसमें सरकार ने चाल क्या खेली है यह बताने के लिए कि किसी के साथ अन्याय नहीं हुआ है ? जो अन्याय हुआ है उसकी पुष्टि करने के लिए जो चाल खेली है वह यह है कि आर. ए. एस. ऑफिसर्स की ग्रेड को बढ़ा दिया। इसमें दो केटेगरीज़ हैं एक तो ५०० तक थीं और दूसरी ७०० तक। जिनको प्रोमोशन्स दे दिये गये और जिनको नहीं दिये गये उसको छिपाने के लिये एक चाल खेली, जिन लोगों के हकों को मार दिया गया था, उसको छिपाने के लिए चाल खेली वह चाल खेली, यह कि जो गलत कार्यवाही की गई है उस पर पर्दा डाल दिया जाय और उन्होंने बीच की ग्रेड को उठा करके २५० से ७५० तक उनकी ग्रेड कर दिया। इसका मतलब यह हुआ कि जो ५०० तक पहुंचने वाले थे अब ७५० तक पहुँचेंगे लेकिन जिनका हक मार दिया गया सो तो मार ही दिया गया, सुपरसीड कर दिया सो तो कर ही दिया। जिनको प्रोमोशन्स देने थे दे दिये, ५०० रुपये से आगे जिनकी ग्रेड करनी थी सो कर दी। उन्होंने सोचा कि आर. ए. एस. ऑफिसर्स में इस प्रकार का अन्याय होने से, उनके हकों को मारने से एक बबेला हो सकता है, असंतोष का कारण हो सकता है, परिस्थितियां ऐसी बन सकती हैं, उनको डिग्रेड कर देने से, इसलिए अच्छा यह हो कि इस बीच के झमेले को हटा दिया जाय और २५० से ७५० कर दिया जाय, फिर आगे जैसे जैसे होगा प्रोमोशन मिलता जावेगा। कुछ व्यक्तियों को, कुछ मर्जीदानों को पांच सौ से स्टार्ट करके उस पांच सौ के झमेले को वापिस ले लिया। उनके हकों को मार ही दिया। जिन लोगों के हकों को मारा गया उनके हकों को न मारा जाय।

माननीय उपाध्यक्ष, आर. ए. एस. के साथ साथ और लोगों की तनख्वाहें बढ़ायी हैं डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स की भी बढ़ायी हैं। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स को ७५०) की की है लेकिन यदि उसी डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट मेडिकल एन्ड हेल्थ ऑफिसर है तो उसकी तनख्वाह उससे ज्यादा है, अगर कोई डिस्ट्रिक्ट इन्जीनियर है तो उसकी तनख्वाह उससे ज्यादा है। इस तरह से डिस्ट्रिक्ट के एक ही तरह के ऑफिसर्स में डिस्ट्रिमिनेशन हैं। इस प्रकार कदम से उनमें बड़ा भारी असंतोष है। मुझे यह जानकारी प्राप्त हुई है कि आर. ए. एस. ऑफिसर्स ने परसों ही एक मिटिंग की कि सरकार के पास एक प्रस्ताव भेजें। सरकार को संकेत करें कि उनके साथ अन्याय हुआ है। चाहे मुख्य मंत्री कहते रहें कि ऑफिसर्स का सरकार के प्रति विश्वास है, सरकार के इशारे पर चलते हैं, लेकिन आर. ए. एस. ऑफिसर्स जिनके साथ अन्याय हुआ है वे एक विकट स्थिति पैदा कर देंगे और उन्होंने तय भी कर लिया है।

मैं समझता हूँ कि उनका रोष प्रकट न हो उसके पहले ही सचेत होकर गवर्नमेन्ट मशीनरी के असन्तोष को दूर करे। मैं समझता हूँ कि यह सरकार के लिए उचित चीज होगी।

इन दोनों चीजों को लेकर जो इन्क्रीमेन्ट्स हुए हैं उससे लोग असन्तुष्ट हैं। मैं आपसे कहता हूँ आप बंगाल बिहार और मध्यभारत आदि के आंकडे मत देखो। आंकडे देखना है तो

[श्री भैरूसिंह]

वहां के लोगों की आमदनी के दूसरे सोर्सेज को भी देखो। वहां आम लोगों की आमदनी हमारे यहां के लोगों की औसत आमदनी से अधिक है तो ऐसी स्थिति में अगर इसको तनख्वाह का आधार बनावें तो ज्यादा ठीक होगा। अब सीलिंग कमेटी आपने बनाई। अधिकृत रूप से तो नहीं कह सकता पर जो ड्राफ्ट मैंने देखा है और उससे जो जानकारी मिली है उस जानकारी के आधार पर कह सकता हूं कि आपने १२ सौ रुपया की नैट इन्कम एक काश्तकार की रक्खी है। उधर खादी ग्रामद्योग बोर्ड ने सिफारिश की है द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कि प्रत्येक व्यक्ति की आमदनी तीन हजार से ज्यादा होनी चाहिये।

एक तरफ सीलिंग कमेटी की रिपोर्ट है १२ सौ रुपया रखने की और दूसरी तरफ खादी ग्रामोद्योग बोर्ड कहता है तीन हजार से कम नहीं होनी चाहिये। यह खादी ग्रामोद्योग बोर्ड केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्य है। इसके साथ हमारी राजस्थान सरकार ३० रुपया की तनख्वाह देकर अध्यापकों को और चपरासियों को या फोर्थक्लास सर्विस वालों जो कि ३६० रुपया सालाना आमदनी होती है घमण्ड करती है कि हम सामाजवाद की ओर आगे बढ रहे हैं। यह समाजवाद नहीं है दैन्यतावाद है। यह उनको गरीबी के खड्डे में ढकेलने की योजना है। बड़े बड़े ऐश आराम करते रहें और गरीब मरता रहे यह व्यवस्था की जा रही है राजस्थान सरकार द्वारा। इतना ही नहीं टैक्स लगाते हैं एक तरफ और दूसरी तरफ अपना जो बकाया पड़ा है उसकी वसूली का कोई प्रबन्ध नहीं। मेरा अन्दाज है वह बकाया है ५ करोड़ २५ लाख रुपयों की, हम टैक्स लगाते हैं १ करोड़ और ७० लाख के लिए। यह हम घाटा बताते हैं। ८४ लाख का टैक्सेशन करते हैं। पर सरकार इस तरफ ध्यान नहीं देती कि लोगों का बकाया कितना है। मेरी जानकारी के अनुसार मैं सदन को सूचना देना चाहता हूं कि आज के दिन तक ५ करोड़ २५ लाख की बकाया लोगों में बाकी है राजस्थान सरकार की। यह बकाया ज्यादा ही हो सकती है, कम नहीं। अगर जरूरत हुई तो विस्तृत आंकड़े मैं सदन में प्रस्तुत करने को तैयार हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, इस बकाया में खास तौर से इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट, इन्डस्ट्री औरज सप्लाई की बकाया मुख्य है। इनके अलग अलग खर्चे जो लोगों में से बकाया है आज भी वसूल नहीं किये जा रहे हैं।

राजाओं के लिये कहा जा रहा है कि बिजली और पानी का जितना उनमें ड्यू है। पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी कह रही है कि इनसे यह रकम वसूल की जाय। उसने दो साल पहले अपनी रिपोर्ट में यह मांग की कि उनको कितनी छूट है इसका निर्णय किया जाकर बाकी की वसूली की जाय और यह भी निर्णय किया जाय कि वसूली हो सकती है या नहीं। यह निर्णय सरकार को करना है और यह निर्णय हो जावे तो तुरन्त वसूली की जाय। पर वसूली करने की उनकी हिम्मत नहीं। यह निर्णय आज तक सरकार नहीं कर पाई है। इसका नतीजा यह हुआ कि वह वसूली और वह बकाया बढ़ता रहा और आज भी बढ़ता जा रहा है पानी के ड्यूज भी इसी तरह बकाया पड़े हैं पहले के, उनका कोई निर्णय नहीं किया जा रहा है और आगे भी बकाया धीरे धीरे बढ़ रही है।

मैं निवेदन करूंगा कि अगर राजाओं के बारे में, म्यूनिसपैलिटियों के बारे में, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर सप्लाई के बारे में जो स्थिति है वह अगर सरकार को सुधारनी है और उनको सुधारने में, सरकार अगर कमजोरी महसूस करती है तो ये बिजली पानी के महकमे और दूसरे छोटे मोटे उद्योग

[श्री भैरूसिंह]

धन्ने म्यूनिसिपलटियों को संभला दे सरकार। ये सीधे जयपुर, जोधपुर की म्यूनिसिपलिटियों को दे दे, बड़े बड़े शहरों में म्यूनिसिपलटियों का बोझा भी इससे हलका होगा और आपकी यह बकाया भी वे वसूल कर लेंगे जल्दी से जल्दी। फिर आप देखिये कि बकाया कैसे नहीं वसूल होती है। प्राइवेट पार्टियां भी जल्दी से जल्दी सारी की सारी बकाया देती हैं कि नहीं। अगर नहीं देती है तो उनके वाटर और इलेक्ट्रिसिटी के सारे कनेक्शन काट देंगे। पर आप में इतनी हिम्मत नहीं। इसलिये निवेदन करूंगा आप अपने सारे हक म्यूनिसिपलटी को दो।

जिससे क्या होगा ? आक्ट्राय ड्यूटी इम्पोज कर रहे हैं जनता की अवाज के खिलाफ। आपको अधिकार नहीं है कि आप इम्पोज करें। मेरा यह कहना है कि पहले म्यूनिसिपैलिटियों का चुनाव कराइये और फिर वे चुने हुए जनताके प्रतिनिधि ही इस बात को तय करें कि आक्ट्राय लगाना जरूरी है या नहीं। फिर जितने भी म्यूनिसिपैलिटीज के आमदनी के सोर्सेज हैं वे भी उनको पहले दिये जावें। इसके बाद में अगर उचित समझें कि इस जगह टैक्स लगाना वाजिब है तो आक्ट्राय ड्यूटी इम्पोज की जाय। प्रजातंत्र में आप डिक्टेटरशिप चलाना चाहते हैं तो यह उचित नहीं होगा। जनता की इच्छा के खिलाफ आपको टैक्स इम्पोज करने का अधिकार नहीं यह अधिकार तो जनता की चुनी हुई म्यूनिसिपैलिटियों को ही होना चाहिए। पर सरकार जबरदस्ती करने पर तुली हुई है। कल के दिन से ही सरकार जयपुर, जोधपुर में यह ड्यूटी लगावेगी। पर मेरा निवेदन है कि सरकार इस पर गम्भीरता से सोचे। धन तेरस को जिस तरह से पोस्टपोन किया था उस तरह से फिर पोस्टपोन करने की नौबत न आ जाय। सरकार अपनी जिद्द पर अड़ी हुई है। और इस बारे में सरकार नाजियों का सा रूप अख्तियार करती जा रही है। अगर आंदोलन चला तो मुझे डर है कि कहीं इस सरकार को नाजियों के टेकटिक्स न अपनाने पड़े। आप इस तरह से अपनी भूलों से बचने के लिए नाजी नहीं कहलाये जावें इससे बचने के लिए जरा ठंडे दिमाग से सोचें और यह अधिकार म्यूनिसिपैलिटी को सौंप दें, यह काम म्यूनिसिपलिटियों का है। आप इसमें इन्टरफीयरेन्स जबरदस्ती न करें तो मैं समझता हूं कि यह ज्यादा उचित होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने कम्यूनिटी प्रोजेक्ट सेन्टर, राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड की की योजना बनाई। इसके बाद में राजप्रमुख ने अपने भाषण में बताया कि राजस्थान में २१ राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड हैं और १५ कम्यूनिटी प्रोजेक्ट सेन्टर्स हैं। इस विरोधी दल में जितने सदस्य बैठे हैं उनमें दो के अलावा मैं यह जानना चाहता हूँ कि किसकी कान्स्टीट्यूएन्सी में इन २१ राष्ट्रीय विस्तार खण्डों में से कोई खण्ड खुला है ? मैं कहता हूं कि सब की तरफ से ना का उत्तर मिलेगा। इसका साफ मतलब है कि हम अपोजीशन वालों को सरकार किसी तरह से क्रश करना चाहती है और किसी तरह से उनकी कान्स्टीट्यूएन्सी में काम न हो जावे इसकी तैयारी करनी है। और इसी का यह कारण है कि आज जितने भी विरोधी दल के सदस्य हैं अपनी अपनी कान्स्टीट्यूएन्सी में जब वे जाते हैं तो उनको वहां की जनता यह उलाहना देती है कि आप

[श्री भैंरूसिंह]

सरकार का विरोध मत करो, नहीं तो हमारे यहां, कोई हमारे फायदे का काम नहीं होने वाला है। जैसा कल दौसा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था उसी तरह से मैं स्वयं कहता हूं कि मेरे क्षेत्र में भी जब मैं जाता हूँ तो लोग वहां के यही उलाहना देते हैं कि सरकार का विरोध मत करो। विरोध करते हो इसलिये तुम्हारी कान्स्टीट्यूएन्सी में काम नहीं होता। सरकार भी इससे यह चाहती है कि या तो विरोध करना छोड़ो या फिर कम्यूनिटी प्रोजेक्ट के या और डवलपमेंट के कामों की उम्मीद न करो। मैं अपने क्षेत्र के लोगों को तसल्ली भी दिलाता हूं कि आप तसल्ली रक्खो, काम हो रहा है, आपके यहां भी होगा, पानी का प्रबन्ध हो रहा है। सरकार ने जल बोर्ड के नाम से एक संस्था बनाई है। गांवों की सेवा होरही है रुपया पैसा खर्च होरहा है। पर वे कहते हैं कि गांवों में खर्च नहीं होता। बल्कि वह रुपया खर्च होता है कांग्रेस पार्टी का अपना प्रचार करने में। सरकार ने इसमें दो करोड़ की योजना रक्खी है। पानी की व्यवस्था के लिये दो करोड़ खर्च होगा उनमें से चालीस लाख रुपया इस वर्ष खर्च किया जावेगा और किस मशीनरी के द्वारा? वाटर बोर्ड के द्वारा। उस बोर्ड पर हमारी यह सरकार अभिमान करती है कि वह न्याय से काम करता है। वे व्यक्ति न्यायप्रिय हैं, दलगत राजनीति से सर्वथा दूर हैं अगर ईश्वर का अवतार या ईश्वर भी कहा जावे तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। पर मैं बताऊं वे कितने न्याय प्रिय हैं, और दलगत राजनीति से कितने दूर हैं और ईश्वर कहां तक हैं, कैसे ईश्वर हैं। उनके कारनामों को देखते हुए यही कहा जा सकता है कि वे न्याय करना तो दूर रहा, बल्कि कांग्रेस पार्टी का प्रचार करने के लिये हैं। मैं लिस्ट बताऊं उनकी। जितने भी जल बोर्ड के सेक्रेटरी नियुक्त किये गये हैं इन १७ में से एक भी ऐसा नहीं है जो गैर कांग्रेसी हो और कांग्रेसी में भी सक्रिय कांग्रेसी न हों। यदि लिस्ट देखना चाहें तो मैं वह लिस्ट भी उपाध्यक्ष महोदय पढ़कर सुना देता हूँ। सब कट्टर कांग्रेसी हैं। आप अगर पूछना चाहें तो उनके सक्रिय कार्यकर्ता का लिस्ट का नम्बर भी मेरे पास है कि किस किस नम्बर पर उनकी सक्रिय सदस्यता कांग्रेस के रजिस्टर में दर्ज है।

श्री ओमदत्तजी शास्त्री	जयपुर
शिवराम	
रत्नपाल	
परसराम चौधरी	
चन्द्रदत्त पुरोहित	
पूरणलाल शर्मा	
इन्द्रदत्त	
धूलजी भाई भावसार	
शंकरलाल	
लीलाधर व्यास	

[श्री भैंरूसिंह]

देवदत्तशर्मा

कन्हैयालाल

मूलचन्द

ब्रह्मदत्त शर्मा

भवानीदत्त

प्रभुलाल

भंवरलाल भदादा भीलवाड़ा

ये १७ डिस्ट्रिक्ट और १७ सेक्रेटरी हैं जिनके पास जलबोर्ड का लाखों रुपया रहता है, जल बोर्ड की जीपें और उसका सारा सामान रहता है वे गावों में जाते हैं और अपने ढंग से कांग्रेस का प्रचार करते हैं और रुपया देते हैं। मेरे क्षेत्र में भी मैं बताऊं उपाध्यक्ष महोदय, वे लोग आये। रुपया बांटने के लिए सेक्रेटरी साहब पहुँचे मेरे हल्के में। लोगों को कहा कि तुम्हारे यहां कुए नहीं हैं, तुम भैरोंसिंह के पास दरख्वास्त क्यों देते हो, उसको दरख्वास्त दी है तो क्या होता है। आप हमारे पास आया करो, हमें दरख्वास्त दो, हम देते हैं रुपया। इस पर मेरी तौहीन करने के लिए अपना प्रोटेक्शन देने की बात कहते हुए उनको कहा जाता है कि लाओ अभी तुम मुझे दरख्वास्त लिखकर दो, मैं अभी रुपया देता हूँ तुम्हें। सात सौ रुपये की दरख्वास्त ली उन्होंने और दे दिये रुपये जैसे अपनी जेब से देते हों।

फिर इन जिला जल बोर्डों की जीपों का मोटरों का उपयोग पंचायतों के चुनावों में होता है। बदकिस्मती है हमारी कि हम चिल्लाते हैं इसके लिए पर कोई सुनने का सवाल नहीं। अभी सुबह जो बातें देखी सुनीं उससे मुझे तो और विश्वास हो गया कि सरकार को इस सरकार को चाहे जितना कहो सुनो यह किसी की सुनने वाली नहीं है। सेक्रेटरी को अपोइन्ट करने के बाद भी अगर सरकार सन्तोष लेती तो मेरी कान्स्टीट्यूएन्सी पर विशेष असर नहीं पड़ता। पर वह सरकार एक कदम और आगे बढ़ी। सोशल वर्कर के नाम पर ६०) रुपया माहवार पर एक नियुक्ति की गई। मेरी कान्स्टीट्यूएन्सी में खुशकिस्मती से इस पोस्ट पर नियुक्त हुई है लाधूरामजी जोशी की, जो कि सीकर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी हैं। ६० रुपया माहवार पर जलबोर्ड का मुलाजिम रखकर जल का प्रबन्ध करने के लिए ये मनोनीत किये गये। अब सीकर जिला-कांग्रेस कमेटी के प्रेसीडेन्ट जल बोर्ड की मोटरें लेकर और रुपया लेकर गांव गांव में जाते हैं बांटने के लिये। तो इससे यह व्यक्त होता है कि यह जल बोर्ड सरकार का नहीं, कांग्रेस का ही है एक तरह से। मैं समझता हूँ कि अगर आप सारी जल की समस्या को दूर करना चाहते हैं तो इसको दूर करने में आज जो आपने प्राइवेट मशीनरी एडोप्ट कर रक्खी है उसको हटाकर सरकारी मशीनरी आप लगाएं। तहसीलदार और पंचायतों के आदमियों को यह काम आप सौंपें। अगर गवर्नमेंट को अपनी ही मशीनरी में विश्वास नहीं है तो उनको बरखास्त कर दीजिये। पर यह कहना कि दूसरे सेठ इसका प्रबन्ध कर

[श्री भैंरूसिंह]

रहे हैं, सरकार का विशेष खर्च नहीं हो रहा है यह बात जंचने वाली नहीं है। आपको जंचती होगी तो जंचे पर किसी न्यायप्रिय व्यक्ति को यह बात जंचने वाली नहीं है।

इस बात का भी इसमें संकेत मिलता है कि जितने भी सोशल वैलफेयर के सेन्टर बनाये हैं आपने और इन सेन्टरों के जितने भी काम होते हैं सारे कांग्रेस के सदस्यों के निर्वाचन क्षेत्रों में होते हैं। ये सारे उनके निर्वाचन क्षेत्रों में खोले हैं और इनके साथ जो कन्वीनर मनोनीत किये गये हैं वे भी आप सुनेंगे तो दंग रहेंगे। वे भी सारे के सारे कांग्रेसी हैं और उनको १८२५ हजार रुपये खर्च करने की सुविधा दी है। वह लिस्ट पढ़ने लायक है। मैं पढ़कर सुनाता हूं उसे, माननीय उपाध्यक्षजी:—

प्रोजेक्ट है	कन्वीनर हैं
१—गांधी विद्यामन्दिर, सरदार शहर	श्रीमती लक्ष्मीदेवी शर्मा, इनका सम्बन्ध श्री गौरीशंकर आचार्यजी से है।
२—महिला मण्डल, अलवर	श्रीमती कलावती देवी शर्मा, ये वहां की एक प्रसिद्ध कांग्रेस कार्यकर्ती हैं।
३— महिला मण्डल उदयपुर	श्रीमती मोहिनी देवी, ये हमारे मुख्यमन्त्री महोदय की एक अति कृपापात्रों में से हैं, कांग्रेस की कार्यकर्त्री हैं।
४— जयपुर प्रोजेक्ट	श्रीमती शीला गोयल, ये कांग्रेस की कार्यकर्त्री हैं।
५— महिला उत्थान समिति, झूंझनूं	श्रीमती किशोरी देवी, पत्नी श्री हरलालसिंहजी एम. एल. ए.
६— किशन बोर्डिंग हाउस, छोटी खाटू, नागौर	श्रीमती विमला चौधरी, पत्नी श्री मोतीलालजी चौधरी, एम. एल. ए.
७— ग्रामोत्थान विद्यापीठ, सांगरिया	श्रीमती सावित्री देवी, ये भी वहां की एक कांग्रेस कार्यकर्त्री हैं।
८— आर्य कन्या भरतपुर	श्रीमती अनार देवी, ये मास्टर आदित्येन्द्रजी की पत्नी हैं।
९— महिला उद्योगशाला, बूंदी	श्रीमती पुष्पा माथुर, मानिकलालजी के भतीजे श्री........

श्री ब्रजसुन्दर—नो, नो। यह गलत है।

श्री भैरूसिंह (१६)—मैं ठीक कह रहा हूं, आप जांच कर लें। श्री मानिकलालजी के भतीजे नहीं, मानिकलालजी के भानजे श्री भगवतस्वरूप या सूरजनारायणजी नाम में गलती हो तो आप करेक्ट कर लीजिये, की पत्नी।

१०–महिला आश्रम, भीलवाड़ा श्रीमती स्नेहलता देवी, श्री मानिकलालजी की सुपुत्री।

मैं निवेदन करता हूँ कि इन दसों सेन्टरों में सब जगह काम खराब होता होगा। यह मेरी मान्यता है। जयपुर में मैंने देखा शीला गोयल काम करती हैं। अगर इसी तरह से काम करते हैं तो ठीक है। फिर अपनी आंखों से देखा खाटू, अलवर, उदयपुर और झूंझनूं के क्षेत्र को तो हमेशा देखता हूं। उनमें जिस प्रकार की लीलाएं होती हैं वे कोई शोभा की चीजें नहीं कही जा सकतीं।

तो इस तरह से जो रुपया जनता की गाढ़ी कमाई का टैक्सों के रूप में सरकार वसूल करती है दुरुपयोग होता है तो जनता को सोचना पड़ता है। आप टैक्स लगावें पैसा इकठा करें पर यह भी देखें कि उसका दुरुपयोग न हो। इस टैक्स से राजनैतिक दलों का प्रचार न हो। अगर यह नहीं देखेंगे तो जनता को सोचना होगा कि ये टैक्स क्यों ऐसी सरकार को दिये जायें। तो जनता का लाभ भी हो ऐसा प्रबन्ध आपको करना होगा।

माननीय उपाध्यक्षजी, अभी सदन में ला और आर्डर के बारे में जिक्र आया। बलवन्तसिंह के बारे में और जवानसिंह के बारे में भी जिक्र आया। मैं बलवन्तसिंह जवानसिंह का जिक्र नहीं करता। उनकी बात करने से लोगों की मनोवृत्ति भी ऐसी ही होती है। पर मैं एक नई चीज की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, समय रहते हमें इससे सावधान हो जाना चाहिये कि इस राजस्थान में जवानसिंह और बलवन्तसिंह ही नहीं अब तो पुतलियां भी पैदा होने लग गई है और पुतली का मैं दृष्टान्त आपके सामने उपस्थित करता हूँ।

एक हाई कोर्ट में रिट पेश हुई है। वह रिट पेश हुई है रामसहाय आदि की तरफ से। वहां एक हलफनामा पेश किया गया उस रिट पिटीशन में ही। वह मैं अर्ज कर दूं। १४ मार्च, ५५ को सिरसी पंचायत का चुनाव हुआ। एक व्यक्ति सरपंच के लिये खड़ा हुआ। रिटर्निंग अफसर ने कहा कि तुम इस गांव के नहीं हो, उम्मीदवार खड़े नहीं हो सकते। तो उन्होंने कहा ठीक है पर यह साबित करने के लिए मुझे क्या करना चाहिये यह आप बता दें। उसने कहा कि गांव के सौ पचास आदमियों के दस्तखत करा कर लाओ कि आप यहीं के रहने वाले हैं तो मैं मानूंगा। ऐसी दरख्वास्त रिटर्निंग अफसर को दे दी गई और इलेक्शन हुआ और वह सरपंच चुना गया। अब इसके खिलाफ पिटीशन होती है और वह इस बिना पर होती है कि उस गांव का वाशिन्दा नहीं है। अब इसके सबूत के लिये आवश्यक है कि जिन व्यक्तियों ने दस्तखत किये थे उनसे कहलवाया जावे कि उन्होंने इस प्रकार के दस्तखत नहीं किये। उन दस्तखत करने वालों में बदकिस्मत से एक कम्पाउन्डर भी आ गया। वह वहां ५ साल से नौकर हैं जैसे वेतन लेने पर दस्तखत किये वैसे ही दस्तखत उस पर कर दिये। अब आगे का किस्सा हलफनामे में आया हुआ है। उपाध्यक्ष महोदय उसे मैं पढ़कर सुना देता हूँ

[श्री भैंरूसिंह]

यह कि १३।२।५६ को सायंकाल करीब साढ़े चार बजे जब कि मैं विनायका जा रहा था प्रभुनारायण हनुमान नैनूं किराये की मोटर लेकर मेरे पास पहुँचे और मुझे मोटर में बिठाकर जयपुर बड़े अस्पताल में श्रीमती कमला देवी बेनीवाल के पास ले आये श्रीमती कमला देवी बेनीवाल ने, उपमंत्राणी ने, मुझको आदेश दिया कि मैं हाई कोर्ट के समक्ष यह बयान करूं कि १४।३।५५ को मैंने किसी प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किये। यदि वह जैसा कहती हैं वैसा बयान किया तो वह मुझको नौकरी में पुख्ता कर देगी और मेरी औरत जो तपेदिक से बीमार है उसका इलाज करा देगी। मेरे साथ रामसहाय खाती, रामसहाय मीणा, व रामसहाय मास्टर को भी श्री प्रभु नारायण व गनेशलाल श्रीमती कमला देवी के पास ले गये थे। मैंने श्रीमती बेनीवाल से झूठा बयान देने से इन्कार कर दिया। तो मुझे को रात्रि को श्रीमती कमला देवी बेनीवाल के बंगले सी स्कीम में रक्खा गया। सिपाही जो पहरे पर तैनात थे उन्होंने मुझे व अन्य लोगों को बंगले से बाहर जाने से इन्कार कर दिया। अगले दिन मुझे प्रभुनारायण व गनेशलाल हाईकोर्ट में ले आये और वहां बिठाये रक्खा। एक अंग्रेजी में छपे कागज पर यह कह कर दस्तखत कराये गये कि यह दस्तखत मेरी नौकरी पुख्ता करने के लिये ही है!

(घंटी)

मैं इतना संकेत करते हुए निवेदन करूंगा कि जो लोग बलवंतसिंह और जीवनसिंह की बातें करते हैं वे ये बातें करना छोड़ दें, नहीं तो उल्टा असर पड़ेगा।

इतना कहने के बाद एक बात की ओर फिर सदन का ध्यान मैं आकर्षित करने की चेष्टा करूंगा वह है भूस्वामी आन्दोलन के बारे में। मैं उसके मैरिट्स डीमेरिट्स पर नहीं जाता। मैं यह भी नहीं कहता कि मांग उचित है या अनुचित है। पर एक बात मानकर चलता हूँ कि इस कान्स्टीट्युशन के मातहत हरेक व्यक्ति को अपने विचार प्रकट करने का हक है तो यह हक भूस्वामी संघ वालों को भी है अपने विचार व्यक्त करने का, फिर उनके विचारों से कोई सहमत हो या न हो यह अलग बात है।। चाहे वे जागीरें रखने की बात करते हों, गलत बातें कहते हों पर अधिकार तो है उनको अपने ये विचार भी व्यक्त करने का। वह मांग करते हैं अगर सरकार उसको मन्जूर नहीं करती है तो वे आन्दोलन भी कर सकते हैं जनता को अपने पक्ष में करने का वे भी हक रखते हैं। उनको अधिकार है। यह सरकार को सोचना पड़ेगा। सत्ता का दुरुपयोग उनके अधिकारों के छीनने में नहीं किया जा सकता। अगर करती है तो यह सरकार नाजी सरकार ही नहीं है उससे भी कहीं बुरी सरकार है जिसने बरबर्ता पूर्वक लाठीचार्ज किया है जोधपुर में। तीन फरवरी को जोधपुर में यह लाठी चार्ज हुआ मैंने स्वयं देखा जिन पर लाठियों के घाव थे। वह जगह भी मैंने देखी। सरकार कहती है वे पुलिस वालों पर हमला करने वाले थे।

वे कहते हैं कि हड़ताल कराने वाले थे। कलक्टर का आफिस एक किनारे रहता है, एक किनारे। कमिश्नर का कार्यालय रहता है। उनसे दूर भूस्वामी आन्दोलन करने वाले थे। वे पीटे गये

[श्री भैरूसिंह]

पूछने को जाते हैं तो कहा जाता है कि सरकार को उलटने की सारी बातें कहते हैं । वे सब कुछ गलत थे, लेकिन हमारा यह हक नहीं था कि हम बर्बर्ता से उन पर लाठियां चलाकर १०-२० को लाठियों से पीटकर किसी का हाथ तोड़ दिया किसी का क्या तोड दिया यदि जांच करते हैं तो पता लगेगा कि एक आदमी के तो पुलिस के सिपाही की लाठी से दांत टूट गये उनमें से दो दांत तो मेरे पास पड़े हैं, और बाकी के दांतों का पता नहीं । यह कहा जाता है कि हम गोलियां चलाते नहीं, लेकिन लाठियां गोलियों से ज्यादा खराब हैं जो कि आदमी को बिल्कुल बेकार करके कमाने खाने के काम के अयोग्य कर देती है । सरकार लाठी चार्ज नहीं करती तो उन्हे भय था कि वे दरवाजे तोड़ देते । यदि कोई ऐसा अन्याय का काम करते हैं, या अन्याय पर उतारू हो जाते हैं तो इसकी आवश्यकता होती, लेकिन निरपराध के लिए नहीं । निरपराध जहां खड़े हैं वहां लाठी चार्ज नहीं कर सकते हैं । दांता हाउस में उनको रोक दिया और कईयों को लाठी से पटक कर पीटा गया और जंगल में लेजाकर छोड़ दिया और ऐसे गांव में जाकर छोड़ दिया कि जहां राजपूतों के दुश्मन रहते थे ताकि वह वहां खाना और रोटी नहीं पा सके और आकर अपने अफसर को सलाम बोल दिया कि ३० मील पर छोड़ दिया । सरकार की जिम्मेदारी है कि जो सरकार के खिलाफ आन्दोलन चलाते हैं उनको सरकार समझाने की कोशिश करे।

दूसरी चीज जो हुई हैं उनकी ओर देखेंगे तो साधारण राजपूत की हालत क्या है । साधारण राजपूत नहीं चाहता हैं कि जागीरें रहें । लेकिन उनकी सारी उचित मांगों को दबाने के लिये सरकार यह कहती है कि यह एक षड़यन्त्र है, जागीरें के नाम पर भूस्वामीयों या राजपूतों का नहीं है बल्कि ऐसे लोगों का है जिनका लक्ष्य राजनैतिक है, तो वह भ्रम में हैं । राजपूतों की वास्तविक ग्रीवेन्सेज को राजपूतों को रिहेबिलिटेट करके पूरा करें । आपने कितने लोगों को धन्धा दिया । ६० हजार लोग हैं जो कि ५ वर्ष से राजस्थान में जितनी रियासतें मिली हैं उनके बेकार हो गये हैं । उन लोगों को आपने कितना धन्धा दिया हैं । जागीरों को रिज्यूम करने के बाद जो उनके १५ हजार मुलाजिम थे, जागीर के एम्प्लाईज थे वह बेकार हो गये हैं । आपने उनमें से कितनों को धन्धा दिया ? जागीर एम्प्लाईज की १८०० की पेन्शन की एप्लीकेशन पड़ी हुई हैं तो उनमें से १८०० में से कितने लोगों को आपने पेन्शनें दी हैं, और कितने बाकी हैं उन्हें क्या दिया । वे सारे के सारे बेकार है । यह कहा जाता हैं कि भूस्वामी जागीरें मांग रहे हैं और जागीरों के नाम पर भूस्वामियों को दबाने की चेष्टा है, राजपूतों की वाजिब मांगों पर भी इस तरह से पानी फेर देने की बात ठीक नहीं होगी । मैं समझता हूं कि यदि आप इस प्रकार की चेष्टा करेंगे तो मैं आपको सूचित कर दूं कि सरकार अपनी रोटी का सवाल करने वाले भूखों के आन्दोलन को नहीं दबा सकेगी । राजपूतों की आर्थिक समस्या है । उसमें राजनैतिक समस्या लवलेश भी नहीं है । राजपूत नहीं चाहते हैं कि जागीरें रहें । राजपूतों को जागीरों के नाम पर सरकार दबाना चाहती है तो वह राजपूतों की हितैषी नहीं है । यदि सरकार उससे फायदा उठाना चाहती है तो वह जनता की हितैषी नहीं है । इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए मैं मुख्य मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि हम दुबारा जागीरें नहीं चाहते हैं । जागीरों के अलावा भी और कई काम करने हैं समझौता भी कर सकें ऐसी बातें करनी हैं । मैं सिर्फ पांच मिनट और चाहूंगा । (समय समाप्ति सूचक घंटी)

[श्री भैरूसिंह]

मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि शिक्षा विभाग के बारे में मुझे निवेदन करना है। राजस्थान के शिक्षा विभाग के बारे में इस सदन में कई बार चर्चा हुई है........

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—उपाध्यक्ष महोदय, आपकी ओर से जब ८ बजे डिबेट समाप्त करने का निर्णय किया है तो मैं समझता हूं कि उसका ख्याल करते हुए समय का संचालन किया जाय।

श्री भैरु सिंह—मैं ५ मिनट में समाप्त कर दूंगा।

माननीय उपाध्यक्ष, आज कल एक प्रवृत्ति चल रही है कि राजस्थान के जितने अधिकारी हैं उन अधिकारियों को मौका न दिया जाकर और बाहर से अधिकारी बुलाये जाय...

श्री उपाध्यक्ष—आप कटमोशन पर बोल लें।

श्री भैरुसिंह—मैं ५ मिनट और बोलूंगा।

वे अधिकारी राजस्थान के अधिकारियों से अधिक योग्य हैं, यह भी इस बात की दलील नहीं है कि, जो राजस्थान के अधिकारी हैं उन अधिकारियों का शोषण करना चाहिये। लेकिन उन अधिकारियों से हम हमारी मर्जी के अनुसार काम नहीं करा सकते। हमारे कामों में बाधा पहुंचती है उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि यहां के चीफ इन्जीनियर जो थे इलेक्ट्रिक एन्ड मैकेनिकल डिपार्टमेन्ट के श्री बशीर अहमद थे, उन श्री बशीर अहमद का रेकार्ड देखें तो इस बात का विश्वास होगा कि जिस डिपार्टमेन्ट में ईमानदार से ईमानदार आदमी भी भ्रष्ट हो सकता है उस डिपार्टमेन्ट में शुरू से लेकर आखिर तक जो आदमी ईमानदार रहा, जो आदमी काबिल रहा, जो शुरू में उसने उस डिपार्टमेन्ट का सारा काम किया, जोधपुर के इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेन्ट में जो भ्रष्टाचार था उसको रोकने की कोशिश की; उस व्यक्ति को यहां पर इन्जीनियर बनाया जाय, लेकिन उसमें एक कमी थी वह यह कि टेलीफोन पर की गई सिफारिशों को वह नहीं मानने वाला था, अपनी कलम से कोई गलत काम नहीं करने वाला था। सरकार ने जांच की, उनके बजाय बाहर से बुलाकर एक मीरचन्दानी साहब को लगाया गया, यह कह कर कि राजस्थान में कोई योग्य आदमी नहीं हैं उस योग्यता में जिससे कि बशीर अहमद साहब काम करते थे कितना अन्तर पड़ रहा है। तो इतने से अर्से में कितने घोटाले हुए हैं। उसी प्रकार आजकल हम समाचार पत्रों में सुनते हैं कि डायरेक्टर आफ एजूकेशन को हटाया जा रहा है? क्यों हटाया जा रहा है? इसलिये कि उनका सिलेक्शन आई. ए. एस- में हो गया है, उनकी क्वालिफिकेशन बढ़ी है। लेकिन राजनैतिक कारण और राजनैतिक नहीं कहें तो, माननीय उपाध्यक्ष जी, यह कहें कि आपसी दलबन्दी के कारण उन डाइरेक्टर साहब को वहां से हटाया जा रहा है। अगर उनको इस तरह से हटाते हैं तो जनता में बदनामी का डर है। उनको हटाने की कोशिश की लेकिन हटा नही सके, लेकिन अब आई. ए. एस में उनका सिलेक्शन हो गया इसलिये उनको हटा दिया। जब तक ऐसा मौका नहीं आया तो रुपये का

[श्री भैरूंसिंह]

सदुपयोग करने वाली हमारी सरकार ने दो डिप्टी डाइरेक्टर बनाये, एक बना दिया एडीशनल डाइरेक्टर और दूसरा बना दिया प्लानिंग डाइरेक्टर। (समय समाप्ति सूचक घंटी) इसके अलावा जो चीफ डाइरेक्टर थे वे अलग इन्सपेक्शन करते रहे। यदि कोई स्कूल का इन्सपेक्शन होता है और उसमें कोई गड़बड़ मालूम होती है तो डाइरेक्टर को सूचना नहीं दी जायगी, जब कि उसके मातहत एडीशनल डाइरेक्टर है उनको लिखा जाता है कि आप सूचना दें। मैं समझता हूँ कि सर्विसेज में वैमनस्यता से काम लेंगे तो वह वैमनस्यता नहीं चल सकती।

इसी प्रकार फोरेस्ट में किया गया है। बाहर से चीफ कंजरवेटर एक रिटायर्ड व्यक्ति को यहां लाया गया जो कि राजस्थान की परिस्थितियों से वाकिफ नहीं है, जो यहां की जलवायु से वाकिफ नहीं है। यहां की मिट्टी और आबहवा से वाकिफ नहीं है, जो कि राजस्थान के जंगल से वाकिफ नहीं है, उसको राजस्थान के जंगलों का प्रबन्ध करने के लिए रखा गया है और जो राजस्थान से परिचित हैं उन लोगों को प्रमोशन नहीं दिया जाय, केवल इस बात को लेकर कि उनके पास टेकनिकल ट्रेनिंग नहीं है। वे हाईली क्वालिफाइड नहीं हैं। मैं समझता हूं कि हाईली क्वालीफाइड से एक्सपीरियन्स ज्यादा काउन्ट करता हैं। प्रेक्टीकल एक्सपीरियन्स इस बात में ज्यादा काम करता है, केवल डिग्री को ही आधार मानते हैं तो वह न्याय संगत नहीं होगा। ज्यादा डिटेल में तो मैं इस महकमे पर कट मोशन के समय जिक्र करूंगा। लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि चीफ कन्जरवेटर नये होने के कारण राजस्थान की परिस्थिति से वाकिफ नहीं होने के कारण जंगलों में किस प्रकार का प्रबन्ध हो रहा है उसका विश्लेषण मैं कटौती प्रस्ताव पर कहूँगा।

इतना कह कर मैं निवेदन करूंगा कि माननीय वित्त मन्त्री ने अपने बजट भाषण में जो टेक्सेज लगाने की योजना बनाई है उसके ऊपर फिर गम्भीरता से सोचें और सोचने के बाद यदि वह आवश्यक नहीं समझते तो जनता को स्पष्ट रूप से कहें। अगर उनको टेक्स लगाना है तो जनता की स्वीकृति प्राप्त करें। जनता की स्वीकृति प्राप्त करना उचित है टेक्स लगाने के लिए। यदि इस प्रकार से काम किये गये तब बहुत मुमकिन है कि मेजोरिटी के आधार पर आज वे जनता की आवाज की अवहेलना कर सकते हैं, लेकिन वह दिन दूर नहीं जबकि जैसा कि पालीवाल जी ने कहा था कि कन्स्टीट्यूशनली नहीं तो अनकन्स्टीट्यूशनली जनता उनको हटाने के लिए तैयार हो जायगी। वह प्रयास चल रहा है। यदि कन्स्टीट्यूशनल मेथड से कुछ हो गया तो ठीक वर्ना वह तरीका तैयार है और तरीके की आपको प्रतीक्षा करनी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष—बोलने वाले सदस्य बहुत हैं और अब तक जो बोलने की इजाजत दी गई वह जितनी देर तक उन्होंने बोलना चाहा उतनी देर तक बोलने की इजाजत उनको दी गई। अब समय थोड़ा रह गया है और सब लोग नहीं बोल सकते इसलिए उनको कट मोशन्स पर बोलना चाहिए और जो बोलने वाले हैं वे काफी तादाद में हैं इसलिये वे अपना समय थोड़ा थोड़ा करके और लोगों को भी बोलने का मौका दें।

श्री मुक्तिलाल मोदी—अब मैं बोलूं साहब। मैं ३ दिन पहले से कोशिश कर रहा हूँ।

श्री उपाध्यक्ष—यदि पांच पांच मिनिट लेंगे तो भी काफी रहेगा।

श्री जवानसिंह—आपका फैसला क्या रहा ?

श्री उपाध्यक्ष—श्री मुक्तिलाल मोदी बोलेंगे।

श्री मुक्तिलाल मोदी—माननीय उपाध्यक्ष जी, राजस्थान का बजट ५६,५७ का पेश हुआ हैं। इस बजट में २६ करोड़ ६८ लाख रुपयों का खर्चा बताया है उसमें, से जो ८४ लाख रुपये जनता से टेक्स के रूप में लेने का बताया। यह टेक्स जनता के ऊपर पड़ेगा, चाहे सेल्स टेक्स के रूप में हो चाहे और किसी रूप में हो। यदि सरकार इस टेक्स को न लगाकर अपनी आंखें खोलती और यहां पर उद्योग धंधों को बढ़ाती तो ८४ लाख रुपया ही नहीं बल्कि २ करोड़ रुपयों की आज सरकार को इन्कम होती। लेकिन इस बजट में उद्योग के लिए सरकार ने केवल १८ लाख रुपये रखे हैं। इनसे राजस्थान में कुछ भी नहीं हो पाता। १८ लाख रुपये जो उद्योग धन्धों की तरक्की पर लगाने का जो विचार है उससे क्या सरकार बेकारी दूर कर सकती है। दूसरी चीजों पर खर्च करने से बेकारी दूर होना मुश्किल है। जिन उद्योगों को तीन साल से सेन्ट्रल गवर्नमेंट तरक्की दे रही है उसके अनुसार पहले साल और इस साल भी काफी कहा कि राजस्थान सरकार इन उद्योगों को आगे बढ़ावे। राजस्थान का क्षेत्रफल के लिहाज से हिन्दुस्तान में दूसरा नम्बर है। लेकिन राजस्थान सरकार दूसरी सरकारों की बनिस्पत जितनी पीछे हटी है उतनी ही दूसरी सरकारें आगे बढ़ी हैं। उद्योग के बारे में राजस्थान सरकार क्या कर रही है और क्या नहीं कर रही है यह मैं बताना चाहता हूँ।

फर्टिलाइजर के कारखाने के बारे में राजस्थान सरकार की तरफ से एसेम्बली में बयान दिया गया था कि हम सेन्टर से कोशिश करेंगे कि फर्टिलाइजर का कारखाना राजस्थान में खोला जाय। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ये सिंदरी फेक्ट्री में ५० करोड़ रुपये सेन्टर के खर्च हुए हैं। उस फेक्ट्री के लिए १८०० टन सीमेन्ट राजस्थान से जाती है। जिप्सम का राजस्थान में दूसरा नम्बर आता है। जिप्सम का जितना उद्योग इस समय यहां चल रहा है उससे कहीं १०० गुना ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। केवल १ वर्ग मील के एरिया से काम चल रहा है। एक ही नहीं तीन सिंदरी जैसी फेक्ट्रीज यहां चल सकती हैं।

दूसरी बात यह है कि आज राजस्थान सरकार यदि कोई स्टील का कारखाना खोलना चाहे तो उसके लिये कम से कम २० लाख टन आयर्नओर राजस्थान में डिपोजिट है लेकिन राजस्थान सरकार की तरफ से कोई प्रयत्न नहीं किया जाता। राजस्थान में जो आयर्नओर का डिपोजिट है वह बहुत ही अच्छा है। उसके लिये सेन्ट्रल सरकार हमारे लिये क्या कर रही है, क्या सुविधा दे रही है, इसका कुछ भी पता नहीं है। इससे जनता का कितना लाभ हो सकता है, यह सोचने की बात है। इससे काफी बेकारी दूर हो सकती है। इसके बारे में मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। सेन्टर के

[श्री मुक्तिलाल मोदी]

मिनिस्टर साहब ने यह कहा है कि राजस्थान सरकार की तरफ से फ्रेट माफ करने के लिये एक भी पत्र नहीं आया है।....

श्री वृज सुन्दर शर्मा—आपने भी इसके लिये दरख्वास्त दी है क्या ?

श्री मुक्तिलाल मोदी—मैंने कोशिश करके फ्रेट माफ करवाया है और में कहने-सुनने में नहीं आता, करने में विश्वास करता हूँ।

आज बीकानेर की तरफ भी उद्योग धंधों में कोई प्रगति करने की ओर ध्यान नहीं दिया गया। वहां पर चाइना क्ले काफी मिलती है उससे बहुत अच्छा पोटरी का कारखाना खुल सकता है। इससे भी काफी लोगों को फायदा हो सकता है। इसी तरह से सवाईमाधोपुर में भी कई तरह की चीजें मिलती हैं।। ६ वर्ष बाद भी चान्स नहीं आया है। दुबारा एप्लीकेशन मांगी जानी चाहिये। इसमें ५०,००० रु० सालाना की इन्कम हो सकती है। आज सरकार इन चीजों की ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। सरकार इन चीजों की ओर से क्यों आंखें बंद किये बैठी है. इसका पता नहीं चल रहा है।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

मैं तो बहुत थोड़ा बोला हूं, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष—औरों को भी मौका देना है।

श्री मुक्तिलाल मोदी—और लोग तो और तरह की बातें करते हैं, मुझे थोड़ा समय और दिया जाय।

ऐसी हालत में सरकार को सर्वे करने के लिये मैंने पहले साल के बजट के समय भी कहा था कि राजस्थान में उद्योगों का सर्वे करना चाहिये। लेकिन आज तक सर्वे करने के लिये इस सरकार ने एक पैसा भी मंजूर नहीं किया है। इसके लिये बिल्कुल प्रयत्न नहीं किया है। राजस्थान में पैट्रोल, जिप्सम, शीशा, तांबा आदि की खानें हैं और वे खानें हैं जिनके लिये सरकार कुछ भी नहीं कर रही है। आज सोडियम सल्फेट का बहुत बड़ा कारखाना सांभर में खुल सकता है। कास्टिक सोड़ा मिल सकता है। इस बारे में ५० पेज की एक रिपोर्ट श्री यादराम चतुर्वेदी की देखी है जिसमें बताया गया है कि कास्टिक सोड़ा और सोडियम सल्फेट के कारखाने खोले जा सकते हैं। इसके लिये ६ लाख रुपये के टेन्डर सेठ गंगेलेला ने दिये थे कहा था, हम देने को तैयार हैं। ऐसी हालत में भी सरकार ने उद्योग की तरक्की के लिये कुछ नहीं किया सरकार उद्योग की तरक्की नहीं चाहती है, ऐसा मालूम होता है। सरकार तो जनता पर टैक्स लगाना चाहती है। इस टैक्स का नतीजा क्या होगा उधर बैठने वालों को तो उससे जरूर फायदा

[श्री मुक्तिलाल मोदी]

होगा। मैं भी उधर बैठने वालों में से एक था लेकिन मैंने उधर बैठना छोड़ दिया और इधर आ गया, इसका क्या कारण है ? इसका कारण यह है कि उधर वाले जनता की भलाई के लिये कुछ भी नहीं करना चाहते। इधर बैठने वाले एक शख्स थे वे उधर चले गये, आज क्या हो गये ? कोई इस तरह से चल सकते हैं लेकिन मैं नहीं चल सकता। वे जैसा करते हैं वैसा मैं नहीं कर सकता। जो पहली सरकार गड़बड़िया करती थीं उसका पाप फूटा और जो पाप करेगा वह जरूर फूटेगा। मैं इस सरकार से भी कहता हूं कि यदि ऐसे काम करेंगे तो यह सरकार भी ज्यादा दिन नहीं चलने वाली है क्योंकि यह जनता पर ज्यादा टैक्स लगाती है।

श्री उपाध्यक्ष—आप दूसरी बात कहें।

श्री मुक्तिलाल मोदी—मुझे ५ मिनट और दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष—आपको बोलते हुये १० मिनट हो गये हैं। सब को बोलना है। मैं आपको दो मिनट और देता हूँ।

श्री मुक्तिलाल मोदी (जारी)—जो बिजली के बारे में बिजली घर की जो इन्क्वायरी थी उसके अन्दर तीन महिने पहले श्री रानावात जो रेवेन्यू बोर्ड में थे उन्होंने इन्क्वायरी करके लिखा कि ३॥ लाख रुपया की गड़बड़ है। लेकिन आज उनके लिखने के बावजूद भी उस पर सरकार ने क्या, किया वह माननीय चीफ मिनिस्टर से मैं यह निवेदन करूंगा कि वे लोगों को बतावें कि हम लोगों ने ३॥ लाख की रिपोर्ट देने पर इन्क्वायरी करके उन लोगों को क्या सजा दी है। अगर इतना बड़ा आदमी जो रेवेन्यू बोर्ड का चेअरमैन है इस प्रकार की रिपोर्ट करता है और कोई एक्शन नहीं लिया जाता है तो यह कोई अच्छी बात नहीं है।

दूसरी बात यह है कि पहले जिस फेक्ट्री को दो आना पर युनिट बिजली मिलती थी उस स्पिनिंग मिल को आज डेढ़ आना प्रति युनिट मिलती है। किसी से कम और किसी से ज्यादा पैसा लिया जाता है। इसके लिये एकाउन्टेन्ट जनरल यह कह रहा है कि दो आनों से डेढ आना क्यों किया गया ? मेरे दोस्त माननीय मिनिस्टर साहब जब बोल रहे थे उन्होंने बताया मुझ को अच्छी तरह मालूम है कि ६ लाख रुपयों में तय हुआ था। अगर ऐसा है तो १॥ रुपया पहले बाकी रहा था। इस तरह से ३ साल में तो सारा रुपया ही पूरा हो जावेगा।

(घंटी)

मैं पांच मिनट में समाप्त कर दूंगा।

(श्री अध्यक्ष पुनः पदासीन)

तो आज ऐसी हालत पाई जाती है कि सरकार की यह नीति रही है कि वह पूंजीपतियों को प्रोत्साहन दे। इसके अलावा आज छोटे लोगों को तनख्वाह पूरी तरह से नहीं बढ़ाई गई है।

[श्री मुक्तिलाल मोदी]

जब तक उन लोगों की पूरी तनख्वाह नहीं बढ़ेगी राजस्थान सरकार में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है, मेरे को मालूम है कि आज कितना भ्रष्टाचार फैल रहा है और वह मिटने वाला नहीं है। मैं यह कहूँगा कि भ्रष्टाचारी की आप वकालत करते हैं और इससे और ज्यादा भ्रष्टाचार फैलता है। माननीय अध्यक्ष, इतना कह कर मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ।

श्री मोटाराम—माननीय अध्यक्ष, बजट पर भाषण हुआ, उसका समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं और खास समस्या हमारे क्षेत्र की है उसको बताने के लिए खड़ा हुआ हूं। हमारा बाडमेर डिस्ट्रिक्ट रेगिस्तान कहलाता है। इस वर्ष में वहां पर ज्यादा वर्षा होने से अकाल है मगर वहां के कलेक्टर सहाब ने जो रिपोर्ट दी है राजस्व मंत्रीजी को मैं यह बता देना चाहता हूँ कि उसमें उसने हमारे यहां का नाम नहीं दिया है। मैं नहीं समझता कि उन्होंने किस आधार पर ऐसा किया है। बाद में जब हम लोगों को मालूम हुआ तो हमने सरकार को प्रार्थनापत्र दिये कि हमारे यहां भयंकर अकाल है और कलेक्टर ने यह कैसे लिख कर नहीं दिया, यह बात हमारे समझ में नहीं आई। हमारी सरकार के कर्मचारी हैं वे किस तरह से पक्षपात करते हैं वह सूचना गवर्नमेंट के पास जरूर है। इसलिए मैं यह कहूंगा कि उस पर कुछ न कुछ अवश्य विचार करना चाहिये क्योंकि हमारी आर्थिक हालत को सुधारने के लिए यह एक समस्या है। इसलिये मेरा यह कहना है कि जब अकाल होता है तो उस समय कुछ न कुछ रेमिशन मिलना चाहिए और बजट में यह नारा लगाया जा रहा है कि काल पड़ेगा, लोगों को मदद देंगे। इसके लिये हमारे बजट में कोई आंकड़े नहीं। हम विरोध नहीं कर रहे हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि कुछ न कुछ हमको रिलीफ अवश्य मिलना चाहिए।

हमारी सरकार ने जो जो रियायतें इसके लिए दी हैं वह किस आधार पर मिल रही हैं और किन किन को मिल रही हैं, यह बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ। हम लोग राजस्थान में तीन लाख आदमी हैं और हम लोग इतने पिछड़े हुए हैं कि इसमें शिक्षा की कमी है। आज ३ लाख में से एक आदमी सरकार ने लिया है क्योंकि हमारी सरकार में बहुत पक्षपात है और हमारे पास कोई ऐसी जागीर नहीं कि हम आगे बढ़ सकें। मैं सारे नेताओं को जानकारी करवाना चाहता हूँ कि ३ लाख में से एक अमीन लिया गया है और उसको गांवमें रखा गया है। इसका कारण यह है कि हमारे पास कोई सिफारिश नहीं है। हम पटेल हैं। हमारे नेता ने यह बात गांव में आकर बताई और कहा कि हम कल्याणकारी राज्य बना रहे हैं। आप कल्याणकारी राज्य की बात कह रहे हैं। मैं यह कहूँगा कि जिस प्रकार ३ लाख के पीछे एक आदमी नौकर लिया गया उस प्रकार किसी भी मुल्क में नहीं हुआ होगा। इसलिए मैं यह निवेदन और प्रार्थना करूंगा कि मुख्य मंत्रीजी और जो भी राज्य के चलाने वाले हैं कुछ न कुछ राज्य तो हमें भी दें और आगे बढ़ने देने का प्रबन्ध करें और आगे बढ़ने पर कोई प्रतिबन्ध न करें।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि पंचवर्षीय योजना बनाई है। मेरा यह निवेदन है कि हम रेगिस्तान के इलाके में रहने वाले हैं। पाकिस्तान में आते जाते थे लेकिन पाकिस्तान बनने

[श्री मोटाराम]

के बाद वहां आने जाने के रास्ते बन्द होगये। हम लोग मजदूर आदमी हैं, मजदूरी करने वाले हैं। हमारे यहां पानी की बहुत तकलीफ रहती है। एक या डेढ़ लाख रुपया से बेरा खुदवा दिया था लेकिन ४। ५ फीट नीचे पानी निकलता है। अगर इसको पूरा करा दिया जावे या पानी का प्रबन्ध कर दिया जावे तो हमारे गरीब लोगों और मजदूरों की भलाई हो सकती है। आप शहरों में बड़े बड़े कारखाने बना रहे हैं। मेरी आप से यह प्रार्थना है कि इस इलाके के रहने वालों के लिये भी कुछ न कुछ अवश्य होना चाहिये। पानी का सबसे बड़ा प्रश्न है। बिना पानी के आदमी नहीं रह सकता। पीने के पानी की समस्या को हल करने के लिए जल बोर्ड का प्रबन्ध किया है लेकिन इसमें भी एक हिस्सा लोगों को देना पड़ता है और दो तिहाई सरकार देती है। हमारे इलाके में बिल्कुल अकाल है। रुपया देकर पानी का प्रबन्ध कर सकें, ऐसी हालत हमारे वहां की नहीं है। हम पाकिस्तान के बोर्डर पर रहने वाले हैं और हमारा देश रेगिस्तान है इसलिए हमारी कम से कम सरकार से यह मांग है कि पीने के लिए पानी तो हमें जरूर मिलना चाहिए। कहा यह जाता है कि जो ग्रूप खुले हैं उनमें काफी काम हुआ है। लेकिन मैं सिवाना और नागौर से अच्छी तरह से वाकिफकार हूँ। गवर्नमेंट ने जो जीप भेजी है जलबोर्ड के लिये वह जलबोर्ड का खर्चा जीप में हो रहा है। मैंने बहुत कहा लेकिन हमारी बात पर कौन ध्यान देता है। सरकारी आदमी बिल्कुल जनता की परवाह नहीं करते। मैं यह कहूंगा कि हम भी एक लाख आदमियों द्वारा चुने हुये आये हैं। लेकिन हमारी जो बातें होती हैं वे कोई वकत नहीं रखती हैं। हम बार बार यह चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि जलबोर्ड में कोई काम नहीं हो रहा है, फिजूल पैसा बरबाद हो रहा है। सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। मैं कोई इसका विरोध करने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूँ।

हमारे वहां की जो आर्थिक हालत है उसके प्रति जो सरकार का रवैया है उससे लोगों में बड़ी निराशा है, सरकार के जो चुने हुए आदमी हैं, उनको इस पर सोचना चाहिए। वे सामन्तवादी राज्य में थे, आपके पास आते हैं तो आप उन चीजों को ठुकराते है तो फिर हमारी क्या दशा होती है? सच्ची बात बताते हैं तो उसका नतीजा निकलना चाहिए। अतः मेरी यह प्रार्थना है कि वे लोग रेगिस्तानी इलाकों में रहते हैं, उनको रियायत मिलनी चाहिए और पूरी मदद मिलनी चाहिए ताकि हम इसको कल्याणकारी राज्य समझें।

श्री अध्यक्ष—श्री जगत सिंह झाला।

श्री जगत सिंह—माननीय अध्यक्ष, बजट के ऊपर तीन दिनों से बहस हो रही है। मैं भी अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं।

राजस्थान में भूस्वामी समस्या एक भयंकर समस्या है और सदन में सब ओर से सदस्यों ने अपने विचार प्रगट किये है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में भूस्वामी समस्या को पोलिटिकल रूप दे रहे है जब कि यह समस्या है वह केवल रोटी के सवाल को लेकर है, उसको राजनै-

[श्री जगतसिंह]

तिक बनाने का श्रेय सरकार को हो। सरकार इसको किस तरह से पोलिटिकल बना रही है इसके विषय में चन्द बातें निवेदन करना चाहता हूं।

सरकार जागीरदारी समाप्त करना चाहती है लेकिन उसके साथ साथ नये २ जागीरदार पैदा कर रही है। सरकार ने उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में नये जागीरदार बनाये हैं। जो व्यक्ति कांग्रेस में हैं, खेती नहीं करते हैं, कांग्रेस में नौकरी करते हैं, जिनका व्यवसाय खेती के मुत्तल्लिक नहीं है उनकी एक फेहरिश्त आपके सामने पेश करना चहता हूँ

श्री जनार्दन राय नागर, अमृतलाल वैद्य, भवानी शंकर भट्ट, गिरधरलाल शर्मा, हनुमान प्रसाद प्रभाकर, फूलकंवर. रामप्रताप, नंदलालजोशी, देवीलाल महता, रमेशचन्द्र, रोशनलाल बोर्दिया, माणिक्यलाल वर्मा, श्रीमती नरायणी देवी [माणिक्यलाल जी वर्मा की पत्नी], (अश्रव्य) जगदीशचन्द्र सेठी।

इन लोगों को नाहरा मगरा की भूमि दी गई है। उस भूमि के लिए स्वर्गीय महाराणा साहब जो महाराज प्रमुख थे उनसे निवेदन किया था कि यह भूमि दे दीजिये, यह किसी काम की नहीं है और उस भूमि को उन किसानों को देंगे जिनके पास भूमि नहीं है, लेकिन हुआ क्या है कि जितने व्यक्तियों को यह गई है वे कांग्रेस के व्यक्ति हैं, जो कांग्रेस में नौकर हैं उनको नये सिरे से ये जमीन दी गई।।केवल जमीन ही नहीं दी गई लेकिन हजारों रुपयों तकावी भी देदी गई, मकान बना दिये गये हैं, चारों तरफ हरा होगया है, नयी कालोनी हो गई है। फिर मैं आपसे निवेदन करना चहता हूं कि केवल कोलोनी ही नहीं है उसके लिए वहां जनता कालेज बना दिया गया है और जनता कालेज के साथ साथ एरोड्रोम कायम कर दिया गया है। ये सारी बातें ऐसी हैं जो नई जागीरदारी कायम करना है। मैं स्पष्ट रूप से निवेदन करना चाहता हूँ और चैलेंज के साथ निवेदन करना चाहता हूँ कि इनमें से एक भी व्यक्ति खेती करने वाला नहीं है, ये उस तरह के व्यक्ति है जो रात दिन कांग्रेस में काम करते हैं, जो कांग्रेस के चार आने से लेकर क्रियात्मक सदस्य हैं, एक एम.पी. हैं। इस प्रकार के लोगों को जमीनें दे दी गई हैं। मेरा निवेदन करने का मतलब यह है कि कांग्रेसियों को जमीनें दी जांय उसका हमें विरोध नहीं है लेकिन जो जागीरदार खेती को उठाते हैं, खेती करते हैं उन जागीरदारों को जमीन नहीं देना और इस प्रकारके लोगों को जमीन देना कहां तक वाजिब कहा जा सकता है? मेरे एक प्रश्न के उत्तर में मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि दो सौ जागीरदारों को दूसरी जगह जमीन दी जा रही है। उनको बहुत दूर दूर भाखरा और नागल की जमीन बताई जा रही है, कहा जा रहा है कि वहां जाकर जमीन लो। अतः मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि आपको चाहिए तो यह था कि जितनी जमीन है गोचर भूमि के सिवाय, गोचर भूमि को छोड़ने के बाद उन लोगों को देना चाहिए था और दिया जाय जो कि अब जागीरदार नहीं रहे हैं। अगर इस समस्या को इस तरह से हल किया होता तो यह समस्या इतनी जटिल नहीं हुई होती, लेकिन आपने ऐसा किया नहीं।

भूस्वामी समस्या पर श्री तनसिंह जी का जो भाषण है उसमें से कुछ अंश पढ कर सुना देना चाहता हूं, "सत्य तो यह है कि कभी कभी काश्त न करने वाले कांग्रेस के व्यक्तियों को, सगे

[श्री जगतसिंह]

सम्बन्धियों को सबसे ज्यादा जमीन दी है और इस तथ्य को ओझल किये जाने का प्रयत्न किया जा रहा है। भूस्वामी भूमि के लाल है........"

(अश्रव्य)

सामाजिक सुधार की ओर प्रयत्न किया जा सकता है। मैं मानता हूं कि उनका तथ्य बिलकुल सही है। जो उन्होंने कहा है वह सही है, लेकिन सरकार इसको उलझाना चाहती है। उन्होंने ही नहीं बल्कि कई लोगों ने मुख्य मंत्री को पत्र देकर इस बात का निवेदन किया था और....खुले पत्र के रूप में जो कि छपा हुआ है और जो मुख्य मंत्री के नाम दिया हुआ है। पत्र इस प्रकार है........

'साथ ही कई कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं जो खेती नहीं करते हैं जिनका जीवनोपार्जन का कार्य नौकरी है, उदयपुर में रहते हैं, उनको भूमि और तकावी दी गई है। जनार्दनरायजी नागर, अमृत लालजी वैद्य, भवानीशंकर भट्ट, गिरधारलाल शर्मा, फूलकुंवर, हनुमानप्रसाद प्रभाकर, फूलकुंवर रामप्रसाद, नंदलाल, देवीलाल मेहता, रामचंद्र आदि। परन्तु ये मुख्य नाम हैं, जो कांग्रेस के पदाधिकारी है। अमृतलालजी वैद्य जिनके पास कि लाखों की संपत्ति है, माइनिंग है, कारखाना है, उन्होंने उदयपुर में भूमि प्राप्त की जब कि दूसरी तरफ लोग भूमि के लिए तड़फ रहे हैं, भूमि नहीं मिल रही है। इनको भूमि देकर हजारों रुपयों की तकावी दी गई है, लेकिन इस लूट में उन जागीरदारों की जिनके पास भूमि नहीं है, कौन सुने ?'

अत: मैं निवेदन करना चाहूँ कि इस प्रकार की कार्यवाही जो आप कर रहे हैं वह बिल्कुल पक्षपातपूर्ण है और मैं समझता हूं भू-स्वामी जागीरों से अलग हुए हैं जिनके जीवन को चलाने का और कोई आसरा नहीं हैं, जो खेती करना चाहते हैं, उनको खेती के लिये भूमि अपने डिविजन में जहां कि वे रहते हैं उनके आस पास दें। आप तो इस प्रका की भूमि बताते हैं जो बहुत दूर है, भाखरा और नागल आप उनको बताते हैं, यह उनके साथ सरासर अन्याय है।

एक बात मैं और निवेदन करना चाहता हूँ जो कि इरीगेशन डिपार्टमेन्ट की उलझन से सम्बन्ध रखने वाली है। मैंने जब कानून पास हो रहा था तो एक प्रस्ताव रखा था कि हमारे उयपुर डिविजन में, खास कर जागीरों में जागीरदारों के साधन जो थे वे तालाब ही थे और उन तालाबों से अपनी उदर पूर्ति करना था। जिस तालाब से इरीगेशन नहीं होता था वह तालाब जागीरदार का रहने दिया जाय। उसको टाल दिया गया। जिन तालाबों से इरीगेशन नहीं होता है, इरीगेशन विभाग के अधिकारी उन तालाबों से पानी नहीं निकालने देते, इससे जागीरदारों में रोष उत्पन्न होता है, खास तौर से भीलवाड़ा और चित्तौड के जिले में यह है। भूस्वामियों के सम्बन्ध में पुलिस की घटनाओं का उल्लेख नहीं करूंगा क्योंकि मेरे मित्रों ने काफी कह दिया है। एक बात की ओर मैं आपका खास तौर से ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा जिस पर किसी सदस्य ने कोई प्रकाश नही डाला है।

[श्री जगतसिंह]

राजस्थान के अन्दर गो निकासी की समस्या एक बहुत बडी विकट समस्या है। राजस्थान सरकार ने सितम्बर के महीने में विज्ञप्ति निकाल कर कहा कि गो निकासी समस्या पर हम नियंत्रण करना चाहते हैं लेकिन हम चाहते हैं कि नियंत्रण का प्रश्न नहीं है किन्तु गो की निकासी पर पूर्ण रूप से प्रतिबन्ध लगावें। तीन चार लाइन एक पत्र की पढ देना चाहता हूं जिससे आपको स्पष्ट हो जायगा कि राजस्थान में यह समस्या किस तरह से विकट होती जा रही है।

यह गो दान पत्र है जो दिल्ली से गौ के सिलसिले में निकलता है।

उस पत्र में यह लिखा है कि राजस्थान सरकार की विज्ञप्ति द्वारा राजस्थान से बाहर गायों को ले जाने की इजाजत देकर थोडी आय के लिये गो निकासी पर प्रतिबन्ध नहीं, इस विज्ञप्ति से कोई प्रभाव नहीं। यहां से बछडे बछडियां बेचने के तौर पर छूट दी गई है और गायें भी प्रगट रूप में लेजाई जा रही हैं। राजस्थान की परम्परा को देखते हुए जहां कभी गो हत्या नहीं हो सकती थी आज वहां से गौओं का निकास होकर वे गायें बाहर जाकर काटी जाती हैं। यह समस्या आज जटिल है। पहले राजाओं के समय में नियम थे, हमारे प्रान्त में गो वध नहीं होता था। हमें उन्हें धन्यवाद देना चाहिये कि जिन्होंने गोवध को कानूनन बन्द रक्खा, उसके बाद पुराना राजस्थान बना। उसमें भी उसी कानून को जारी रखा गया यदि कोई गोवध करता था दस साल तक की सजा का उसमें प्रोवीजन था। जब टीकाराम जी पालीवाल का मंत्रीमडल आया उसके बाद व्यासजी का मंत्री मंडल बना, उसमें भी उसी प्रकार कानून कायम रहा। मुझे दुख के साथ कहना पडता है कि सुखाड़िया जी की सरकार जब आई इन बातों की ओर ध्यान आकर्षित करने के बावजूद भी इस ओर तवज्जोह नहीं दी गई। आज हालत यह है कि राजस्थान से सैकडों मील दूर जाकर गायें बाहर के इलाकों में कटती है। अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी से मैं इस बारे में खास तौर से अर्ज करूंगा कि वे इस ओर खास तौर से ध्यान दें।

इसके अलावा में एक दो बातें और निवेदन करना चाहता हूं। आज जो बढ़े हुए भाव हैं यह हमारे लिये एक नयी समस्या पैदा कर रहे हैं। इससे राजस्थान में रहने वाले मध्यम वित्त लोगों को काफी तकलीफ होती है। ऐसी स्थिति में सरकार का यह फर्ज हो जाता है कि सस्ते भावों की दुकानें खुलवाने और मध्यम वर्ग व गरीब लोगों को राहत पहुंचाने का प्रयत्न करे। इस बात की उपेक्षा यह बताती है कि आप उन लोगों के प्रति सहानुभूति नहीं रखते हैं। मैं आशा करता हूँ सरकार इस ओर भी ध्यान देगी।

श्री छीतरलाल शर्मा—माननीय अध्यक्ष, बजट के सिलसिले में जो माननीय वित्त मंत्री ने भाषण दिया उस संबन्ध में मैं भी कुछ शब्द निवेदन कर देना चाहता हूं। इस भाषण के मद नंबर ५ में बतलाया गया है कि इस बजट के सिलसिले में आगे जाकर हम करीब १० लाख लोगों को रोजगार दिलाने का प्रयत्न करेंगे। लेकेन यह बात जाहिर नहीं हुई कि किस तरह से हम दस

[redacted]

[श्री छीतरलाल शर्मा]

लाख लोगों को काम दिलायेंगे। वह काम आप क्या खोलेंगे जिसके जरिये दस लाख आदमियों को रोजगार मिल सकेगा। इसके अलावा में यह भी अर्ज करना चाहता हूँ जो ग्रेड्स रिवाइज किये गये हैं उसके सिलसिले में बहुत से साथियों ने बहुत सी बातें कह दी हैं, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ; सहकारी विभाग के अन्दर जिस तरह ग्रेडों को रिवाइज किया गया है उसमें असिस्टेन्ट इन्स्पेक्टर का ग्रेड जहां पहले ६५ से शुरू होता था अब नये ग्रेडेशन के अनुसार यह ६० से शुरू होता है। क्या यह ग्रेड के रिवाइज करने जैसी बात हुई? यह जरूर हुआ कि इस ग्रेडेशन से बड़े अधिकारियों को काफी लाभ पहुँचा है, जहां छोटे कर्मचारियों को राहत नहीं मिली है।

इसके साथ साथ मैं यह भी अर्ज करना चाहता हूं, जहां तक सार्वजनिक निर्माण विभाग का संबन्ध है टोंक से जयपुर जाने वाली जो सड़क है उसके बीच बनास नदी के ऊपर हर मोटर पर टैक्स लिया जाता है। क्या वह टैक्स सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा वसूल किया जाता है, जो वैधानिक है? आज भी इस प्रकार का भ्रष्टाचार हो रहा है उसे सरकार की ओर से रोका जाना चाहिये। पुलिस के जितने भी मुलाजिम हैं वे बगैर टिकट के बसेज में बैठ जाते हैं, इसके बाबत भी सरकार कोई इन्तजाम नहीं कर पाई है।

जहां तक न्याय और प्रशासन का संबन्ध है कई जगह मुन्सफी और सिविल जजी नहीं रही है। प्रार्थना पत्र देने पर भी सरकार द्वारा कोई इन्तजाम नहीं किया गया। ऐसी स्थिति में जो बजट के अन्दर मांग की गई है गवर्नमेन्ट को वह एड नहीं मिलनी चाहिये। इतना कहकर में अपना भाषण समाप्त करता हूँ।

श्री मोतीलाल चौधरी—अध्यक्ष महोदय, सन् ५६-५७ का बजट जो सदन के सामने प्रस्तुत किया गया उस पर गत दो-तीन दिन से बहस चल रही है उस पर अपनी राय देने के लिये खड़ा हुआ हूँ। बजट को देखते हुए मैं सरकार को धन्यवाद दे रहा हूँ। वास्तव में जितने भी बजट आज तक पेश हुए हैं, उन सब को इस बजट के मिलाने से यह प्रतीत होता है कि वास्तव में यह बजट प्रगतिशील है। यद्यपि इसमें बहुत सी कमियां है जिस उद्देश्य को लेकर हम चलना चाहते हैं, वह आवड़ी अधिवेशन के बाद जो नीति कांग्रेस ने अपनायी उसी नीति को अपनाने के लिये उसको व्यवहारिक रूप देने के लिये हमें काम करना चाहिये। इस लिहाज से यदि इस बजट को देखा जाय तो बहुत कमियां हैं, तथापि जो भी बातें रखी गई हैं. पहले के बजटों से काफी अच्छा होने के कारण मैं माननीय वित्त मंत्री को इसके लिये मुबारिकबाद देता हूँ। साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहता हूँ जिस दृष्टिकोण का बजट में समावेश होना चाहिये जिस नीति को हमने वित्त मंत्री के बजट भाषण में श्रीमन् राजप्रमुख के भाषण में आधार बनाया गया है वह है सोशलिस्टिक पेटर्न। उसको पूर्ण रूप से लाने के लिये, उस दृष्टिकोण को बजट में लाने के लिये काफी कमियां रह गई हैं। यह कमियां किस तरह की रही हैं, वह में बताउंगा। या तो सरकार ने इस बारे में अन्धानुकरण किया या सरकार इस सोशलिस्टिक पेटर्न को समझ ही नहीं पाई। माननीय मंत्री महोदय ने इसे व्यवहारिक रूप में नहीं लिया होगा। समाज के ढांचे को सुधारने के लिये समाजवादी रचना के आधार पर देश का निर्माण करने के लिये मैं यह

[redacted]

[श्री मोतीलाल चौधरी]

समझ नहीं पाया कि हम आहिस्ते २ गरीब आदमी को ऊपर लाना चाहते हैं। तो फिर आज जो अन्तर हम करने जा रहे हैं क्या वह समाजवादी समाज की ओर बढ़ने वाला कदम है ? बजट के पहले पेज पर जो नक्शा दिया हुआ है उसे देखते तो माननीय सदस्यों को यह पता चलता कि हमारे यहां रुपया कहां से आता है, किस जगह जा रहा है ? पहले पेज को देखने से यह अन्दाज होता है, इसके अन्दर बहुत सी कमियां रह गई हैं। इसमें इनकम के जो सोर्स बताये गये हैं उसमें जिन आदमियों से इनकम ज्यादा होती है उसमें किस परसेन्टेज से उनको मदद की जाती है, ये दोनों बातें हैं। गरीब जनता ज्यादातर राजस्थान के गांवों में रहती है। शहरों में रहने वाली जनता को काफी राहत दी हुई है जो इस बजट से जाहिर होता है; जो यह बताता है कि अभी समाजवादी ढांचा जो हम बना रहे हैं उसकी ओर व्यवहारिक कदम बहुत कमजोरी से उठाया है। जिस तरह खर्चे का ढांचा दिया गया है कल्याणकारी राज्य के निर्माण के लिये क्या चीजें की जानी चाहिये, खर्चे का सोर्स और जहां से इनकम आती है उसके अनुसार किस आदमी पर कितना खर्च किया गया है यह देखने से विपरीत सा पाया जाता है। मैं बराबर कहता आया हूं कि आज राजस्थान की १ करोड ५५ लाख की आबादी है उसमें अरबन एरिया में २५ लाख जनता रहती है और बाकी सब गांवों और कस्बों में रहती है। जहां तक इनकम का सोर्स है वह रूरल एरिया से ज्यादा है, अगर हम उस जनता पर जो खर्च हो रहा है उसका परसेन्टेज का विचार करें तो यह पता लगेगा कि हम ज्यादा परसेंट खर्च शहरी जनता के लिये खर्च कर रहे हैं। ज्यादा हमें ध्यान देना चाहिये गांवों की ओर जहां की जनता गरीब है। समाजवादी समाज में आपको इस नीति को अपनाना चाहिये इस नीति के अनुसार जितनी मदद की जानी चाहिये वह नहीं हो रही है।

इसके अलावा मैं सरकार से यह भी निवेदन करूंगा कि यहां शहरों में जहां पानी आदि की पूर्णव्यवस्था है वहां गांवों में जहां पानी की व्यवस्था के लिये खर्च उतना नहीं हो रहा है जितना कि शहरों के लिये। उनकी इस समस्या की ओर भी ध्यान अवश्य दिया जाना चाहिये।

माननीय, इसके बाद जो हाउस में इस बजट पर बोलते हुए कई चर्चायें हुई उस ओर भी ध्यान दिलाना चाहता हूं वास्तव में हमने चार साल इस हाउस में परम्परा निभाते हुए बिताये हैं, यह हमारा आखिरी वर्ष है। इसके बाद चुनाव होने वाले हैं मन की बातें जो गरमा गरमी में निकल रही है वह वास्तव में बहुत ही खेदजनक है।

मुझे खास कर इसका दुख हुआ कि जो बातें जिम्मेदार लोगों ने जो पहले सरकार में थे, और अब सरकार में न होने के कारण कहीं........

श्री अध्यक्ष—आप बजट पर कहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आपके ऊपर तो कोई बात नहीं कही गई।

श्री मोतीलाल चौधरी—अध्यक्ष महोदय, मेरे बारे में भी हैं।

श्री अध्यक्ष—तो उसका जवाब दे दीजिये केवल ।

श्री मोतीलाल चौधरी—डेगाने और परबतसर से आये सदस्यों को कुछ ऐतराज थे । मैं कहता हूँ वे सदस्य कभी अपनी कान्स्टीट्यूएन्सी में काम नहीं करते, जाते नहीं और कभी उसे सम्भालते ही नहीं हैं । उन्होंने चार्ज लगाया किसान बोर्डिंग हाउस को तीन हजार दिये गये, तो इसमें क्या पक्षपात सरकार ने किया । सरकार ने राजपूत बोर्डिंग हाउस को भी रुपया दिया ।

तीसरे सदस्य ने सोशल वेलफेयर बोर्ड के बारे में कुछ बातें कहीं । अफसोस इस बात का है कि सरकार भी पूरा जवाब नहीं देती । यह इन्डिपेन्डेन्ट बोर्ड है, भारत सरकार के नियन्त्रण में हैं और अच्छा काम कर रहा है । माननीय सदस्य ने कहा कि उन्होंने खाटू में जाकर इसका काम देखा है । मैं कहता हूं उन्होंने खाटू पहले भी कभी आंखों से नहीं देखा होगा और यहां कह दिया खाटू में गये थे । कन्वीनरों के बारे में भी उन्होंने कहा । मैं कहना चाहता हूं कि कन्वीनरों को इसके लिये कोई भत्ता नहीं मिलता । बल्कि उनको व्यवस्था करनी पड़ती है १।४ हिस्सा गांव से लेकर देने की । जो इतनी जिम्मेदारी लेकर चलते हैं वे एक कमेटी के मेम्बर होते हैं, रजिस्टर्ड संस्थाओं को रिप्रेजेन्ट करते हैं और उस कमेटी का डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी मेम्बर होता है । इतना होने पर भी माननीय सदस्य गैर जिम्मेदारी की बातें करते नहीं थकते ।

माननीय अध्यक्ष, एक सदस्य ने बजट अधिवेशन में मेरी कान्स्टीट्यूएन्सी के एक गांव में आने की चर्चा की । मेरे ख्याल से उनको उस गांव की शक्ल भी मालूम नहीं है, आने की बात तो दूर रही ।

किसी गांव के पंचायत इलेक्शन में तहसीलदार को पीटने की भी बात कही गई, मैं कहना चाहता हूं कि यह बात सरासर झूठ है । नागौर जिले में किसी भी अफसर पर हाथ नहीं उठाया गया । सरासर भ्रम पैदा करने के लिए कहते हैं ।

भू-स्वामी आंदोलन के बारे में बहुत सी बातें कही गईं । यह एक राजनैतिक हथकंडा है । सिर्फ कुछ आदमी राजपूतों को बहका बहका कर इस आंदोलन में ले आते हैं और राजनैतिक षडयंत्र के रूप में उनका उपयोग करते हैं । हम व्यक्तिगत रूप से इसकी जानकारी रखते हैं । जिनकी जागीरें नहीं थी ऐसे आदमी भी इसमें लाये जाते हैं । एक गज भी जमीन जिसके पास नहीं थी वे लोग भी इसमें आते हैं । आर्थिक दृष्टिकोण भी इस आंदोलन का नहीं है । दो सौ, तीन सौ की पेन्शन पाने वाले आदमी इसमें हैं । मैं नागौर जिले की कहानी कह दूं । लोग जाते हैं, लोगों से आंदोलन में चलने को कहते हैं जिस घर से कोई जाने को तैयार नहीं होता उसके साथ क्या करते हैं वे, यह भी सुनें आप । वे लोग अपने साथ कुछ चूड़ियां और ओढ़नी ले जाते हैं । घरों घरों में लोगों से इस आंदोलन में भाग लेने के लिए कहते हैं, इन्कार करने पर कहते हैं कि ये ओढ़नी ओढ़ लो और हाथों में चूड़ियां पहन लो नहीं तो हमें साठ रुपया दे दो हम भाड़े पर, करके आदमियों को वहां भेजेंगे । जो पैसा भी नहीं देना चाहते वे सोचते हैं चलो अभी तो जेल हो आवेंगे, वहां से माफी मांगकर आ जावेंगे और यही होता है, लोग जबर्दस्ती जेल भेजे जाते हैं पर वहां जाकर

[श्री मोतीलाल चौधरी]

आत्मसमर्पण करके छूट कर आ जाते हैं। यह कटु सत्य है। यह तो राजनैतिक दृष्टि से एक खेल खेला जा रहा है।

एक भूतपूर्व मंत्री महोदय ने एक बात कही क्योंकि आज वे कुर्सी पर नहीं हैं इसलिए गैर जिम्मेदारी से बातें कहते है। अपने साथियों पर छींटाकसी की। पर एक बात मेरे सुनने में बराबर आ रही है कि पालीवालजी जब मिनिस्टर थे तो पावर हाउस में एक टेण्डर लिया गया और इसके सम्बंध में ऐसी चर्चा है कि सबसे ज्यादा रेट का टेन्डर जिसका था उसको मंजूर किया गया और इसके बाद में ऐसा भी सुना जाता है कि ए. जी. ने ओब्जेक्शन भी किया और बीस तीस पेज की इस पर रिपोर्ट भी दी कि रुपया गलत तरीके से काम में लिया गया है। यह भी सुना है कि सरकार ने हाई पावर कमेटी बिठाई है। कमेटी की रिपोर्ट क्या है, मालूम नहीं। तो वे जिस प्रकार से बोलते हैं कि हाउस में वे ही ईमानदार हैं बाकी तो कोई है ही नहीं, तो उनकी ईमानदारी का यह सबूत है। इसलिए निवेदन करूंगा माननीय अध्यक्ष, कि इसका भी स्पष्टीकरण किया जावे कि क्या बात है यह।

(घंटी)

श्री श्रीदास गोयल--माननीय अध्यक्ष, सबसे पहले तो जिस तरह से सरकार चल रही है वह मेरे गले की आवाज से जाहिर होगा कि जिस गवर्नमेंट होस्टल में हम रहते हैं वह शायद हैदराबाद जेल का एक अच्छा सा नमूना है जहां कि स्लोप्वॉइजनिंग होता है हम सब लोगों का। माननीय मुख्य मंत्रीजी से मैंने जब कि काटजू साहब वहां तशरीफ लाये थे तो मैंने खुद ने कहा था कि यहां किस तरह का फूड दिया जाता है कि उससे हमारे स्वास्थ्य पर कितना बुरा असर पड़ रहा है। उन्होंने वायदा किया था कि वे स्वयं आकर, अनएक्सपेक्टेड आकर खाना खायेंगे और उसको ठीक करेंगे। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि शायद उन्हें समय न मिल सका। मैं समझ नहीं सका कि स्लो-प्वाइजन का तरीका एम. एल, ए. के प्रति क्यों अख्त्यार किया जा रहा है? क्या भावना है? क्या आधार है? तो मैं निवेदन करूंगा कि इस एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा यह बात पैदा हो गई और आज यह हालत हो रही हैं। तो मैं निवेदन करूंगा अध्यक्ष महोदय, कि जहां इतने बड़े बजट को पेश करने जा रहे हैं और एम० एल० एज० के सम्बंध में इस प्रकार का एडमिनिस्ट्रेशन रहे तो वह बहुत बड़ा प्रतीक है इन तमाम बातों का।

अध्यक्ष महोदय, यह प्रार्थना करूंगा कि जो कुछ सरकार द्वारा बजट बनाया गया है, जो कुछ किया गया है, जहां तक बजट को देखा उसके संबंध में बहुत से दोस्त कह चुके हैं कि वह वास्तव में बड़ा सुंदर है। उसका अगर इम्प्लीमेंट सही ढंग से किया जा सकता है तो कोई शिकायत बनी नहीं रह सकती है। लेकिन जो शिकायतें हैं उन शिकायतों को आज दरगुजर नहीं कर सकते तो मैं निवेदन करूंगा कि इम्प्लीमेंट करने में मशीनरी वास्तव में अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह नहीं निभा पाती है। एक उदाहरण के तौर पर छोटी सी बात में निवेदन करूंगा कि नये बजट में १०००-५०-१५०० की ६ नई पोस्टें कायम की गई हैं। वह इसलिए की गई हैं कि वे आई. ए. एस. आफिसर्स नहीं बन

[श्री शूरदास गोयल]

सके। कुछ आर० ए० एस० अधिकारियों को चूंकि मौजूदा सरकार प्रमोशन्स देना चाहती थी उन्हें जो कि किन्हीं ऐसे कारणों से या जिनके कुछ कारनामे ऐसे रहे हैं कि वे आई० ए० एस० कमेटी के सामने कामयाब नहीं हुए हैं। तो उनके लिए यह एक बेकडोर का रास्ता अख्त्यार किया गया कि उन्हें भी १५०० रु० तक की तनख्वाह दी जाय जिन्हें कि ८००) रु० या १२००) रु० मासिक मिल रहे हैं। तो सही रास्ता तो यह था कि वे आई० ए० एस० के योग्य नहीं थे, उनकी मौजूदा तनख्वाह रिटायरमेंट के पीरियड तक वही रख देते और जिस जगह के लिए वे उपयुक्त थे वहीं उनको रख दिया जाते। मैं निवेदन करूंगा कि हमारे माननीय राजस्व मंत्रीजी को ऐसे अधिकारियों के नाम भी मालूम हैं कि जो किस प्रकार का व्यवहार करते हैं सही बात कहने वालों के प्रति और किस प्रकार अपने डिपार्टमेंट के अन्दर जिम्मेदारी को निभा पाते हैं उनको, अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कलेक्टर से प्रमोशन मिलता है और जयपुर में लाये जाते हैं और एक अच्छे डिपार्टमेंट के हैड बनाये जाते हैं। संभवतः वह इस कारण से कि किसी जमाने में वे सेक्रेटरी रहे हैं और सेक्रेटरी रहते हुए लोकल सेल्फ डिपार्टमेंट में उनको कुछ नाजायज फायदे पहुँचाये हैं। आज के केबिनेट में बैठने वाले साथियो, मैं प्रार्थना करूंगा कि जो इस प्रकार की कार्यवाहियां करते हैं और इस प्रकार के आदमियों को सरकार प्रोत्साहन देना चाहती है तो उन्हें थोड़ा सोचना पड़ेगा कि क्या यह सोशलिस्टिक पेटर्न का काम है। क्या हम इसी आधार पर कांग्रेस सरकार को प्रगतिशील पुकार सकते हैं ? क्या इसी आधार पर कांग्रेस सरकार का नाम ऊंचा उठेगा ? पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि संसार के ख्याति प्राप्त और मशहूर व्यक्ति हैं जिनको पूरी शक्ति देकर हमें ऊंचा उठाना है, उस उद्देश्य को क्या हम पूरा कर सकेंगे ? मैं निवेदन करूंगा कि सरकार ने जो कुछ किया और आर० ए० एस० के न्यू ग्रेड्स नियत किये और उन पदों पर जिन अधिकारियों को रखा है तो क्या उस जिम्मेदारी को निभाने के लायक हैं ? उनके पुराने रेकार्ड्स को देखते हैं, उनके कारनामों को देखते हैं, कि वे लोगों से किन तरीकों से देखते हैं, संभवतः मिनिस्टर्स उन बातों को खुद नजदीक से जानते हैं। वे नहीं चाहते हैं कि किसी मिनिस्टर को नावाजिब तरीकों से खुश करने के लिए वे तरीके अख्त्यार करें, लेकिन जो कुछ तरीके अपनाये वे इतने दूषित और गैरजिम्मेदाराना थे कि अगर माननीय राजस्व मंत्रीजी जिनके नोटिस में ये बातें आई हैं, मैं दोहराना नहीं चाहता, वास्तव में उन्हें सही मानते हैं तो ऐसे अधिकारी को वे प्रोत्साहन नहीं देंगे और स्वयं उनसे अलग हो जायेंगे। उन आदमियों के मुकाबिले सरकार के कामों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी मानेंगे, और आशा करता हूं कि वे इस चीज को मानते हैं।

मैं इसके आगे निवेदन करूंगा, माननीय अध्यक्ष, कि जहां तक सोशलिस्टिक पेटर्न का सवाल है बहुत सी बातें बहुत से माननीय मित्रों ने कहीं। एक बात रूरल डिपार्टमेंट के मुताल्लिक मैं कहना चाहता हूँ कि मेरा इसमें मानना है, और उसके सिलसिले में आज भी अर्ज कर रहा हूँ कि जैसा अभी हुआ है कि कुछ कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को एक्स्टेन्शन ब्लॉक्स में परिवर्तित किया गया है तो वहां के केवल आंकड़े देखकर ही निर्णय ले लिया गया लेकिन इस पते पर कोई नहीं पहुँचा कि वे आंकड़े वास्तव में दुरुस्त हैं या नहीं। वहां के ब्लाक डेवलपमेंट अधिकारी ने गलत

Page No.148

[श्री श्रीदास गोयल]

आंकड़े कम्युनिटी प्रोजेक्ट को ब्लॉक में परिवर्तित कराने के लिए तो नहीं दे दिये हैं। लेकिन जो कुछ मैंने देखा कि आंकड़ों के ही आधार पर तत्काल उन्हें डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स बना दिया गया और बहुत गलत कार्यवाही हुई, उन स्थानों के लिए जहां के सही और तथ्यपूर्ण आंकड़े आये; मैं निवेदन करूंगा कि जिस प्रकार करौली के ब्लॉक को डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, लेकिन यदि दूसरे राजस्थान के ब्लाक्स के वहां के आंकड़े सही ढंग से देखें जायं तो बहुत गलत मालूम होंगें। लेबर करने के लिए कितने आदमी बढ़ाकर लिखे गये कि करौली की जनसंख्या ही नहीं होगी। वे वास्तविकता के आधार पर बिल्कुल गलत हैं। इसी प्रकार खेती के मामले में या खाद के गड्ढों के मामले में तमाम गलत आंकड़े आ रहे हैं, लेकिन उन आंकड़ों को केवल देखते हुए निर्णय ले लिया। तो मैं निवेदन करूंगा कि सरकार तमाम बातों के लिए जिम्मेदारी से काम करे और जो अधिकारी इस प्रकार की बातों को करते हैं उन लोगों पर कोई न कोई अंकुश रक्खे।

दूसरा मुझे निवेदन करना है कि जहां तक बहुत सी बातें माननीय सदस्यों ने फरमाई कि बजट को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है सोशलिस्टिक पेटर्न की ओर उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए देखना यह है कि राजस्थान का वातावरण कैसा है, यहां की सर्विसेज का क्या हाल है ? वे जिम्मेदारी को किस प्रकार निभा रहे हैं ? किस प्रकार की कार्यवाहियां सर्विसेज़ कर रहीं है ? कुछ मित्रों ने कहा कि भ्रष्टाचार बढ़ा नहीं है लेकिन मैं कहता हूँ कि यह बढ़ा है घटा नहीं है। सवाई माधोपुर के बार एसोसियेशन ने प्रस्ताव पास किया; अपनी जिन्दगी में पहली बार और मि० घोष वहां पर गये और उन्होंने वहां की वास्तविकता मालूम की और उन्होंने क्या कहा उसे मैं ऐसा मानता हूँ कि यहां कहना उपयुक्त नहीं है। उसके बाद उन तमाम कागजों पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। पता नहीं कि वे कहां दबे रखे हैं इसलिए कि सेक्रेटरी जो एन्टीकरपशन के अन्दर हैं वे उसमें इन्ट्रेस्टेड हैं एक पर्टीक्यूलर व्यक्ति में और दूसरे पर्टीक्यूलर व्यक्ति के अन्दर एक ऐसे महानुभाव इन्ट्रेस्टेड हैं जो सवाई माधोपुर के कलेक्टर रह चुके हैं, जो हमेशा से भले नागरिकों को दबाते रहे और कुछके काले कारनामों पर चुप्पी लगाते रहे, और वहां बड़े बड़े जंगल काटे गये लगातार और हजारों दरख्त काटे गये जब कि सारे जिले की इस कार्यवाही को कलेक्टर देखते रहे हैं और वे एस० डी० ओ० एडिशनल क्लेक्टर बनाए गए उदयपुर में। यह अगर तरीका रहा है सोशलिस्टिक पेटर्न की तरफ जाने का, कि जो आदमी अपनी जिम्मेदारी को न निभाये और जो करप्शन की ओर ले जाये और जो गैर जिम्मेदारी की कार्यवाहियां करें उनको हमेशा हक मिले और जो ईमानदारी से रहा है, भले काम करता रहा है वह वहीं का वहीं पड़ा रहे तो मैं निवेदन करूंगा कि केबिनेट की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी का ख्याल करते हुए उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए सोचना चाहिए गम्भीरता से। मुझे खुशी हुई कि माननीय मुख्य मन्त्री महोदय ने कहा कि महकमाना बातें हैड आफ दी डिपार्टमेंट पर छोड़ दी हैं। हम इन्टरफियर नहीं करते हैं। यह सही परम्परा है। इंग्लैड की डेमोक्रेसी से हमें वह सीखना चाहिए। वहां रोजाना की एडमिनिस्ट्रेटिव बातों में मिनिस्टर इन्टरफियर करने लगता है। पोलिसी से आगे जाकर वह छोटी

[श्री श्रीदास गोयल]

छोटी बातों को देखने लगता है तो उसे अपने काम के लिए एक्स्प्लेनेशन देना पड़ता है और संभवतः इस्तीफा भी देना पड़ता है। तो हमें हमारी नवजात डेमोक्रेसी के लिए इस बात को बहुत गम्भीरता से सोचना चाहिए (समय समाप्ति सूचक घंटी) और ख्याल करता हूँ कि इस प्रकार के आगे जाने के वास्ते हमारी बुनियाद अच्छी मजबूत बने तो इस प्रकार की मिसाल पैदा करें कि जिससे सब लोग यह कहें कि केबिनेट जो कि राजस्थान में मौजूदा चल रही है वह एक उच्च स्तर की है और वह एडमिनिस्ट्रेशन को ऊंचा उठाये हुए है। इस बात की चिन्ता न करें कि उनसे कुछ एम० एल० एज० खुश हुए हैं या नहीं उनके लिए शुभ कार्य किये गये या नहीं। मेरे एक माननीय मित्र ने फरमाया कि एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए सरकारी मशीनरी की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है उसी तरह ? १६० एम० एल० एज० की भी है। जो केबिनेट में साथी भेजे हैं वे उन्हीं एम० एल० एज़० ने चुनकर भेजे हैं तो १६० एम० एल० एज़० की जिम्मेदारी उन्हीं के कन्धों पर है कि वे शुभ कार्य करें और जिम्मेदारी से कार्य करें तो सारे राजस्थान का हित होगा।

मैं जैसे आपको निवेदन करूं कि हमने पब्लिक में जाकर तकावी बांटने की प्रथा डाली। गांवों में जाकर तकावी बांटी। इससे गांव वालों की परेशानी दूर हो गई और वे लोग बहुत खुश हुये। लेकिन यह हुआ कब ? जब कि कलेक्टर दूसरे आये। पहले वाले कलेक्टर आने वाले लोगों को खुश नहीं रखते थे। इस तरह के आदमियों को जो खुद काम न करना चाहते हैं और गड़बड़ करने वाले हैं उनको जिम्मेदार पदों पर लगाया। लीडर महोदय की १६० एम० एल० एज० के प्रति जिम्मेदारी है और वे कह सकते हैं कि आप को हमने चुनकर भेजा है तो आप को यह देखना है कि काम ठीक तरह से चलता है या नहीं ? यदि मशीनरी ठीक है, तरीका ठीक है तो किसी का काम आज होगा तो किसी का कल होगा और किसी का परसों होगा। देरी से होगा लेकिन होगा जरूर। इससे लोगों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी।

मैं इस बात का उल्लेख किये बिना नहीं रह सकता कि पुलिस की प्रोसिक्यूशन ब्रान्च बहुत खराब हो गई है। मुल्जिमों को जमानत दिलाने के लिये उनसे रुपये लेते हैं। आप यदि उनके खिलाफ कोई कार्यवाही करना चाहते हैं तो भेष बदल कर मेरे साथ चलिये तो मैं उनको सही रूप से दिखा सकूंगा। किसी न किसी तरह से लोगों को हेरेस किया जाता है, चाहें जिस तरीके से चालान पेश कर देते हैं। यह तरीका अख्त्यार किया जाता है। मैं प्रार्थना करूंगा कि बहुत बड़ा जिम्मा है मंत्रियों पर और यह देखना है कि जो ५५, ५६ में काम हुआ उससे सबक सीख कर इस प्रकार की कार्य प्रणाली रखें कि उनका मस्तिष्क ऊंचा हो। वे कर्मचारी जो कर्त्तव्य परायण नहीं हैं और बेकार हैं उनको हटा कर उनके स्थान पर अच्छे कर्त्तव्य परायण लोगों को रखा जाय जो दूसरों को राहत पहुँचा सकें। यही मेरा निवेदन है।

श्री जवानसिंह—माननीय अध्यक्ष, हमारी प्रथम पंचवर्षीय योजना का अंतिम साल समाप्त हो रहा है और दूसरी पंचवर्षीय योजना की हम शुरूआत करने जा रहे हैं। लेकिन

[श्री जवानसिंह]

इस सदन में जो वाद-विवाद हुआ उस चीज को हमने देखा और आगे आने वाली द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिये इसे पृष्ठ भूमि मानें तो वह शायद अच्छी पृष्ठ भूमि नहीं है। हमारे इस सदन में होने वाले वाद-विवाद में सुबह, अभी और कल हमने इस चीज को पाया कि यदि केन्द्रीय सरकार की ओर से वही सलाह दी जाती है, जो इस सदन के बाहर जाते हैं तो हम सलाह देते हैं कि हमको मिल जुल कर सम्मिलित हो कर सबको काम करना चाहिये ताकि हमारी पंचवर्षीय योजना सफल हो सके और हम ज्यादा से ज्यादा कार्य कर सकें। लेकिन इन सबको सबक देने के बजाय, ऊपर से सबक लेने के बजाय क्या ही अच्छा होता यदि इस सदन में हम ठोस पोइन्ट रखते, कुछ सजेशन रखते कि बजट में यह चीज होनी चाहिये थी या इस चीज की कमी है और उस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिये और जो रह गई है उनको भविष्य में लाना चाहिये। यदि यह दृष्टिकोण होता है इस सदन का भविष्य निर्माण के लिये, आगामी पंचवर्षीय योजना को बनाने के लिये तो हरेक राजस्थानी का यह ख्याल होता कि हम इस सदन में बैठकर वाकई कुछ कार्य कर रहे हैं। लेकिन यह चीज सामने नहीं आई। एक दूसरे पर लांछन डाला गया। क्या यह सही है कि इस प्रकार लांछन डालने से क्या हम उन्नति कर सकते हैं? क्या हमारा हित इस में है कि हम एक दूसरे पर लांछन डालें? आज जो सरकार में बैठे हैं, बहुत से जो पहले इस स्थान को ग्रहण किये हुये थे उनके बीच में यदि इस तरह की चीज चलती रही तो मेरा ख्याल है इन चीजों का अंत नहीं होगा और इस तरह के लांछन बढ़ते रहेंगे।

क्या मैं सदन के नेता से मांग करूं कि सन् ५४ में इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेन्ट में जो गड़बड़ियां हुई उनका जबाव देने को तैयार हैं कि उन्होंने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की?

(श्री अध्यक्ष पदासीन)

कोयलों की खरीद में जो गोलमाल किया गया था उसका क्या हुआ? कम कीमत पर सप्लाई करने का टेन्डर देने वाले को आर्डर न देकर ज्यादा कीमत पर सप्लाई करनेवाले को आर्डर दिया गया था क्या इस मामले में जांच करने की कोशिश की गई? मैं सदन के नेता से खास तौर से पूछना चाहता हूँ और कल में उनसे उत्तर की आशा करूंगा कि इस बारे में उन्होंने अब तक क्या किया, इसका उत्तर दें। मैं ऐसे मामलों में जाना पसन्द नहीं करूंगा। मैं एक दूसरे के ऊपर लांछन डाल कर बोलने के बजाय ज्यादा उपयुक्त यह समझता हूं कि हम सरकार को यह बतावें कि आगे आने वाले साल के लिये जो रकम रखी गई है उसको किस तरह से खर्च करें। साथ ही इस ओर बैठनेवाले माननीय सदस्य विरोधी पक्ष के नेता और दाता रामगढ़ से आनेवाले सदस्य ने जो बातें सामने रखी हैं, सरकार की कमजोरियें सदन के सामने रखी हैं उनको कैसे दूर किया जाय यह सुझाव दें। मैं अवश्य यह चाहूंगा कि जो कम जोरियां रह गई है, हो सकता हैं कि गलतियें जानकारी में न रहने की वजह से, रह गई हैं, यह आवश्यक नहीं है कि सारी बातें सरकार की जानकारी में आवें ही, हालां कि हम उम्मेद करते है कि वे सारी जानकारी रखें लेकिन हरेक चीज ध्यान नहीं आ सकती। बहुतसी चीजें उनके ध्यान में

[श्री जवानसिंह]

नहीं आने से रह सकती हैं। इन चीजों को हम उनके ध्यान में लावें और यह बतावें कि हमारे सामने यह नक्शा है इन चीजों को पूरा करना है।

सिरोही के बारे में २-४ चीजें हैं। उनके बारे में हम कोशिश करते आ रहे हैं कि उनको सुलझाना है लेकिन हम उन्हें नहीं सुलझा सके। मैं फिर भी सरकार में विश्वास करता हूँ, उनका ध्यान दिलाऊंगा कि अब तक उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन साथ ही आशा करता हूँ कि भविष्य में उन चीजों की ओर ध्यान देंगे और पूरा करने की कोशिश करेंगे। एक मामला है सिरोही के बिजलीघर का और दूसरा मामला है कृषि स्कूल शिवगंज का। हमारे यहां का बिजलीघर पुराना है उसको अगर सरकार लेना चाहे तो ले सकती है। बिजली कंपनी पर ७५,००० रू० का कर्जा है। इसका विवरण आया है। उसका कर्जा पूरा कर दिया जाय तो सरकार २५,००० रू० और देकर उसको अपने कब्जे में ले सकती है। लेकिन सरकार ने क्या प्रगति की है, मैं नहीं कह सकता। आज से चार महीने पहले बिजलीघर के पार्टनर्स को बुलाया गया था और उनसे बातचीत हुई थी लेकिन कोई निर्णय नहीं हुआ और भविष्य के लिये टाल दिया गया, यह मेरा ख्याल है। उसको ठीक तरह से तय नहीं कर रहे है। इसका पूरा सोल्यूशन होना चाहिये। इसको टालना सोल्यूशन नहीं है। यदि सरकार इसका कुछ सोल्यूशन निकाले तब हम कह सकते हैं कि सरकार इस में सफल हुई है। मैं निवेदन कर रहा हूँ कि सिरोही के बिजलीघर का मामला काफी अर्से से विचाराधीन है। इसको टालने की कोशिश न करके; सोल्युशन निकाला जाय। या तो यह सरकार के अधिकार में रहे या ठीक तरह से चलाया जाय।

अभी हाल ही में मुझे सुनने को मिला कि शिवगंज में जो कृषि स्कूल है और इसको उठाने की कार्यवाही हो रही है। हम बड़ी मुश्किल से यह तय करा पाये थे कि यहां डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर का मुकाम सिरोही में रहे और जो ४-६ महीने ही नहीं बल्कि ८. १० महीनों से वहां ऑफिस नहीं रहने के बाद अब यह तय किया गया है कि वहां डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर रहेगा। यदि पाली में डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर रह सकता है जहां मुश्किल से ११. १२ हजार रुपयों का सालाना खर्चा है तो जहां ५ लाख से ऊपर की आमदनी हो तो क्या वजह है कि वहां डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर का मुकाम नहीं रखा जाय और दूसरी जगह रखा जाय।

तो अब इस चीज को अगर आप माने कि जब कृषि का काम सिरोही में ज्यादा हो रहा है और अच्छा हो रहा है बनिस्बत और जगहों के तो वहां पर से एग्रीकल्चर स्कूल को हटाया क्यों जावे जहां पर एक दफा काम शुरू कर दिया जाता हैं और काम की व्यवस्था की जाती है तो फिर ऐसा कोनसा इन्ट्रेस्ट इसमें दखल देने लग जाता है कि वहां से दूसरी जगह उसको बदल दिया जावे और फिर परेशानी उठानी पड़े। इस प्रकार की चीज के लिये में निवेदन कर रहा था कि यह फेर-बदल न दिया जावे।

इसके अलावा सिरोही कॉलेज के लिये हम काफी दिनों से परेशान हैं। इतना बड़ा कॉलेज होते हुए भी वहां पर साइन्स Section नहीं खोला जाता है, यह मौका है। इस अवसर बजट पर पेश हुआ है।

[श्री जवानसिंह]

हम अपनी मांग करते हैं कि सरकार उसकी तरफ ध्यान क्यों नहीं दे रही है ? वहां पर बिल्डिंग मौजूद हैं तो फिर सरकार को क्या ऐतराज है ?

(घंटी)

समझ में नहीं आता कि इसके लिये क्या कोई दूसरा माप हो सकता है ? घंटी समय समाप्त होने की सूचना दे रही है। इसलिये में अपना भाषण समाप्त करता हूँ ।

एक माननीय सदस्य—मुझे भी बोलना है।

श्री अध्यक्ष—६ बजे तक बैठ जाइयेगा। श्री कंवरलाल जेलिया।

श्री कंवरलाल जेलिया—माननीय अध्यक्ष, हमारे माननीय फाइनेन्स मंत्री ने जो बजट सदन के सामने पेश किया है और उसे समाजवादी व्यवस्था का बतलाते हुए जो अपना भाषण दिया है उसे सुना। अगर उसको गौर से देखा जावे तो इसमें संदेह है कि राज्य के विकास के लिये इसको रखा हैं। जो नकशा रखा गया हैं उसको देखते हुए वे बधाई के पात्र हैं अवश्य लेकिन देखना यह है कि वाकई में वे बधाई के पात्र हैं या नहीं ? वास्तव में काम होता है या नहीं ? में यह आपको अपने डिविजन की बात बताऊंगा और बताना चाहता हूँ कि प्रथम पंच वर्षीय योजना में किस प्रकार संतोषजनक काम हुआ है और जिस प्रकार संतोष प्रकट किया गया है उस प्रकार प्रथम पंच वर्षीय योजना में काम नहीं किया गया है। माननीय अध्यक्ष, मैं बता देना चाहता हूँ कि कोटा से इटावा के लिये सड़क का टुकडा बनने वाला था पहली योजना में। यह इलाका ऐसा है जो सरकार को आमदनी देने वाला है, गल्ला देने वाला है। जो अभी तक ४८ मील टुकडा हो पाया है। में नहीं समझ पाया कि अगर इस प्रगति से काम होता रहा तो हमारे जैसे व्यक्तियों को जनता के सामने जवाब देने में बड़ी कठिनाई होगी कि किस प्रकार से सरकार ने समाजवादी व्यवस्था कर दी।

इसी प्रकार मांगरोल से इटावा जानेवाली सड़क है। यह ऐसी रोड है जिससे काफी पैसा पैदा होता है। मगर कुछ नहीं।

इसके अलावा प्रथम पंच वर्षीय योजना में यह रखा गया था कि कोटा में एक पॉवर हाउस लगाया जावेगा और एक टरबाइन लगाया जावेगा। एक डेढ साल से लगातार यह कहा जा रहा है कि आर्डर दिया जा रहा है टरबाइन के लिये। प्रथम पंच वर्षीय योजना समाप्त हो रही है। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कोटा में पानी की व्यवस्था होते हुए भी पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता। माननीय चीफ मिनिस्टर ने अपने भाषण के दौरान में इस समस्या पर प्रकाश डाला है। देखते हैं यह कब

[श्री कंवरलाल जेठिया]

संभव सकता है ? इसके इस संबन्धमें पॉवर हाउस आता है। पॉवर हाउसकी क्या दशा है। वह किसी संभव हो छुपी नहीं है। इसके लिये समय समय पर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया मगर कोई ध्यान नहीं दिया गया। पी० डब्ल्यू० डी० मिनिस्टर से एक प्रश्न में पूछा गया आया कि यह बिजलीघर नफा देता है या घाटा, तो उत्तर दिया गया कि नफा देता है। जब वह नफा देता है तब उसकी यह दशा है, इसको सुधारा जाना चाहिये। अगर इस प्रकार सही बात कहने से आलोचना होती है तो मैं यह कहूँगा कि हमें दिये तले अन्धेरा नहीं रखना है। कोई भी व्यक्ति जो राजस्थान का भला चाहता है तो वह अन्याय और पक्षपात बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर हम अपनी पब्लिक की मांग को रखें जहां से कि हम चुनकर आए हैं उस मांग के लिए वे कहें कि सरकार की बड़ी आलोचना होती है तो मैं समझता हूँ कि मेरे जैसा व्यक्ति जनता की आवाज को सरकार के सामने रखने का कोई हक नहीं रखेगा।

इसके साथ साथ में राजस्थान के बजट को देखते हुए जो सोशियलिस्टिक पेटर्न की बात हमारे माननीय फाइनेन्स मिनिस्टर ने कही है उसके लिये मैं उनका ध्यान राज्य कर्मचारियों के वेतन की तरफ दिलाना चाहूँगा। उसको सुन कर आपको काफी दिलचस्पी होगी। मैं बड़े बड़े अधिकारियों की तरफ आपका ध्यान नहीं दिला कर छोटे छोटे कर्मचारियों के वेतन की तरफ आपका ध्यान अवश्य दिलाना चाहूंगा क्योंकि दूसरे बड़े बड़े अफसरों को तो टी० ए० और डी० ए० आदि बहुत पैसे प्राप्त हो जाते हैं लेकिन एक पुलिस मेन या पटवारी, चपरासी को देखिये। आपको कम से कम इतना वेतन तो उनका करना चाहिये जिससे उनका पेट भर सके और अपने स्तर को कायम रख सकें।

इसके साथ साथ में हमारी इन्डस्ट्रीज़ को सहकारी सोसाइटीज द्वारा प्रोत्साहन देने से ज्यादा अच्छी उन्नति होगी। मगर हम देखते हैं कि पिछले तीन वर्षों से सहकारी विभाग की क्या स्थित है और पिछले साल से सहकारी विभाग के रजिस्ट्रार को हटा दिया जाता है और साल भर में रजिस्ट्रार की नियुक्ति नहीं हो पाई और अभी पिछले दो महीनों में यह तय किया गया है कि इस पोस्ट पर किस केडर का व्यक्ति रखा जावे। एक रजिस्ट्रार की व्यवस्था करने में सरकार को पूरा एक वर्ष लग जाता है तो फिर हम क्या उम्मीद करें कि इस सहकारी विभाग से उद्योग का कोई भला होगा ? हमारे सामने जो आंकड़े हैं उनको देखते हुए इसको संतोषजनक कहना चाहिये लेकिन मैं आपको अपनी जानकारी के आधार पर कह रहा हूं कि जो धन राशि उद्योग और घरेलू धन्धों में दी गई वह कोई पर्याप्त मात्रा में नहीं है। केवल इतना करने से मेरा विश्वास नहीं कि हम अपने लक्ष्य को जा सकेंगे।

(घंटी)

अगर उनका अर्थ यही है तो मैं हमारे माननीय फाइनेन्स मिनिस्टर से कहता हूँ कि वे इस पर प्रकाश डालें।

समाज कल्याण विभाग के लिये मैंने पिछले दिनों कोटा के हरिजनों के बारे में बताया था कि वहां पर क्या कार्य हो रहा है ? मैं तो यह कहूंगा कि वहां पर कुछ नहीं हो रहा है। अगर हम

[श्री कंवरलाल जेलिया]

समाज कल्याण की बात कर रहे हैं और दावा करते हैं कि हरिजनों के लिये काम किया है तो हमें सब जिलों में हरिजनों के लिये रुपया खर्च करना होगा। मगर आज की वहां की व्यवस्था यह है कि हरिजन बस्ती में लोग हर साल बीमार होते हैं, उनको निमूनिया की बीमारी होती है। यह वहां की दशा संतोषजनक नहीं होने से होता है और यह हर साल होता है। अगर इसी तरह की व्यवस्था समाज कल्याण की रही तो समाज कल्याण विभाग का किस तरह से कल्याण होगा। मैं नहीं समझ सकता। माननीय मंत्री महोदय ही इस पर संतोष प्रकट कर सकते हैं। मैं तो इस पर संतोष प्रकट करने के लिये तैयार नहीं हूँ।

तीसरी बात, मैं आपका ध्यान चम्बल की ओर दिलाना चाहता हूं कि इस चंबल बांध को तैयार करने में मजदूर लोग हुए हैं और आए दिन वहां पर चंबल के कार्य को करते समय दुर्घटनाएं हो जाती हैं; उन लोगों को कम्पेन्सेशन मिले और दूसरी जो सुविधाएं कानूनन मिलनी चाहिये मिलें। इसलिये सरकार को इसकी ओर ध्यान देना चाहिये।

चूंकि टाइम कम है इसलिए यही कहूँगा और शहरों में जो जल की व्यवस्था के लिए धन राशि रखी गई है, ४० लाख रखी गई है उसमें कोटा के लिए भी इस साल धन राशि नियत करके व्यवस्था चालू की जाय।

श्री अध्यक्ष—श्री हिम्मतसिंह।

श्री कंवरलाल जेलिया—मैं अस्पतालों के सम्बन्ध में और थोड़ा सा निवेदन कर दूं।

श्री अध्यक्ष—बाद में बोलियेगा।

राज श्री हिम्मतसिंह (अटरू)—अध्यक्ष महोदय, कुछ समय मैं भी आपका लेना चाहता हूँ और वैसे तो इस बजट के बारे में बहुत कहा जा चुका है और ऐसी बातें कहीं गई हैं कि जिनको सुन कर सब ही हैरान हैं। मैं उन बातों पर नहीं जाना चाहता किन्तु यह जो समाज कल्याणकारी या सोशलिस्टिक पेटर्न का जो बजट बना है उसका जिक्र करना चाहूँगा। इसमें संदेह नहीं है कि बजट पेश हुआ ही नहीं लेकिन इसका अमल शुरू हो गया है। मैं आपको एक घटना वर्णन करना चाहता हूँ। श्री कोटा महाराव साहब जो यू. एन. ओ. में आल्टरनेट डेलीगेट की हैसियत से गये थे वे इसी ५ मार्च को वापिस तशरीफ लाये थे। कोटा की पब्लिक ने उनका स्वागत किया और स्वागत बड़े जोर शोर से किया। लेकिन वैसे भी देखा जावे तो वे उपराजप्रमुख भी हैं और यू. एन. ओ के आल्टरनेट डेलीगेट भी हैं। स्वागत के अवसर पर ख़ास देखने की बात यह थी कि वहां के कलेक्टर और कमीश्नर एब्सेन्ट (अनुपस्थित) थे। पुलिस के सुपरिन्टेन्डेन्ट जरूर मौजूद थे लेकिन पुलिस का इन्तजाम किसी काम का नहीं था। शायद मैं समझता हूँ कि वे उतने ऊंचे स्टेन्डर्ड के आदमी हैं और जो इस सोशलिस्टिक पेटर्न में फिट न होते हों और सोशिलिस्टिक पेटर्न

[राज श्री हिम्मतसिंह (अटरू)]

समझ कर बजट इन्ट्रोड्यूस होता है उसके लिए उनका स्वागत करना सरकार ने मुनासिब न समझा हो, लेकिन उपराजप्रमुख के नाते और यू. एन. ओ. के ऑल्टरनेट डेलिगेट के नाते तो सरकार के कर्मचारियों को स्टेशन पर उपस्थित होना चाहिए था। यही नहीं उपस्थित होना तो दूर रहा, जानते हुए भी उन्होंने कलेक्टर्स की मीटिंग कॉल की। और यह भी कहा गया है कि हमें पता नहीं कि आप कोटा दरबार वापिस आ रहे हैं। शहर में तैयारी हो रही है, जगह जगह आर्चेज़ बन रहे हैं और हमारे सरकारी कर्मचारियों को पता भी नहीं है कि श्रीमन् उपराज प्रमुख तशरीफ ला रहे हैं। यह एक बड़ी शोचनीय घटना है, जिसके लिए मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। क्या पता है, इसका क्या कारण हो सकता है। सरकार ही इसकी छानबीन करेगी और इस पर कुछ न कुछ अवश्य एक्शन लेगी।

८० फी सदी राजस्थान की जनता गांवों में रहती है और गांव के स्टेन्डर्ड को ऊंचा करने के लिए इस बजट के अन्दर काफी प्रोविजन्स रखे गये हैं यह मानना पड़ेगा। इरीगेशन वर्क्स और और डेवलपमेंट वर्क्स और चल रहे हैं। बहुत सारे सदस्यों ने कहा कि उनके क्षेत्रों में एक्स्टेन्शन वर्क, डेवलप्मेन्ट वर्क्स, कम्युनिटी ब्लॉक्स नहीं खोले गये हैं। संभव है नहीं खोले गये होंगे लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता खोल दिये जावेंगे।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—आपके तो है।

श्री हिम्मतसिंह—बृजसुन्दरजी साहब कहते है कि मेरी कोन्स्टिटुएन्सी में तो डेवलप्मेन्ट ब्लाक खुला हुआ है। मैं नहीं समझता कि किस तरह से खुल गया। यह भी इत्तिफाक की बात है। यह तो नहीं चाहते थे कि खोला जावे लेकिन खोलना लाजमी हो गया। अनएवोइडेबल सरकम्सटान्सेज ऐसी थीं कि उनको खोलना पड़ा। और भी जगह थीं जहां खोल सकते थे लेकिन यहां तो खोलना पड़ा। मैं इसके लिए उनको श्रेय नहीं देता यह तो सरकम्स्टान्सेज की वजह से खोलना पड़ा।

ज्यादा समय नहीं लूंगा। मेरा अर्ज करने का तात्पर्य यह था कि........

श्री अध्यक्ष—Courtesy demands thanks.

(हंसी)

श्री हिम्मतसिंह अटरू—हमने हमारे टिनेन्सी एक्ट में एक स्टेन्डर्ड कायम कर दिया और वह है स्टेन्डर्ड १२००) का। हर व्यक्ति के पास कम से कम खर्चा निकालने के बाद १२००) बच जाने चाहिए। यह स्टेन्डर्ड सब जगह लागू किया जावेगा तो कितनी अच्छी बात है और सोशलिस्टिक पेटर्न पर हम कर सकते हैं। लेकिन वह स्टेन्डर्ड केवल कागजों पर ही है, अमल में नहीं आता है। मैं आशा करता हूं कि इस पर अमल किया जावेगा और जो छोटे २ कर्मचारी हैं उनको भी इसी स्टेन्डर्ड से तोला जावेगा। खाली यह कह देना कि फ्री मेडीकल एड दे दी जावेगी या

[श्री हिम्मतसिंह अटरू]

बच्चों को एजुकेशन फ्री मिल जावेगी इससे तो काम नहीं चल सकता है और इससे उनकी उदर पूर्ति नहीं हो सकती है। मैं यह अर्ज करूंगा कि इस पर सरकार को जरूर ध्यान देना चाहिए।

सर्विसेज़ की तनख्वाहों के बाबत कहा कि १५००) से २०००) तक हो गई। जमाने को देखते हुए १५००), २००० कुछ नहीं। जो मंहगाई है और जिस तरह का जमाना है उसको देखते हुए १५००), २०००) कुछ नहीं, अच्छा होता कि उनकी तनख्वाहें और बढ़ाई जाती और मिनिस्टर लोग अपनी तनख्वाहों को बिल्कुल कटा लेते। जिस तरह से औरंगजेब बादशाह टोपियां बना बना कर काम चलता था उसी तरह से हमारे मिनिस्टर लोग सूत कात कात कर काम चलावें तो मैं समझता हूँ कि उदाहरण कायम हो सोशलिस्टिक पेटर्न करने का। मजे की तनख्वाहें लिये जाओ और गुलछर्रे उड़ाये जाओ और दूसरों के लिए कहो कि हमारे पास नहीं। आयन्दा हमारे मंत्री महोदय जरूर इस बात की एक्जाम्पल सेट करेंगे।

एक बात और जरूर अर्ज करना चाहता हूँ रोडस के बारे में। मेरे को अभी काम पड़ गया इसलिए अर्ज कर देना चाहता हूँ। अजमेर से देवली आते समय रोड्स का हिस्सा राजस्थान सरकार का भी आता है और जगह जगह लिखा है राजस्थान; इससे भी मालूम पड जाता है कि जब राजस्थान शुरू हुआ और इससे कोई आदमी मिस नहीं कर सकता है। मैंने भी देखा और मिस नहीं किया। अजमेर की जो सड़क है वह टार्ड है और ब्युटिफुल है और राजस्थान की जो आई तो उसमें खड्डे पड़े हुए थे। औरंगजेब बादशाह की बनाई हुई समझी जाय। वह जनरल रोड है ट्रंक रोड है, कोई आदमी सफर करता है और जब राजस्थान का नाम पड़ता है तो उसको स्ट्राइक होता है कि राजस्थान गवर्नमेंट की यह दशा है। चांवल एक देखा जाता है, हर चांवल को पीस पीस कर और मसल मसल कर नहीं देखा जाता है। राजस्थान गवर्नमेंट का नमूना दुनियां भर को वहां मालूम हो जाता है कि राजस्थान गवर्नमेंट कैसी चल रही है। हमारे मंत्री महोदय का ध्यान दिलाऊंगा कि २० मील का टुकड़ा पड़ता है जिसको ठीक करवा दें। इससे राजस्थान गवर्नमेंट की बदनामी होती है।

एक बात और अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से कहना चाहूँगा। अभी गवर्नमेंट पब्लिसिटी के बारे में नागौर के बारे में, एक पुस्तक देखने में आई। उसमें नागौर में मेला जो हुआ उसका जिक्र आया है और और बातें भी गवर्नमेंट की पब्लिसिटी की हैं।

बहुत अच्छी किताब बनायी हुई है। एक बात इसके अन्दर जो रखी वह मुझे स्ट्राइक हुई, वह मुझे बहुत बुरी लगी। मैं समझता हूँ हर आदमी की वह बुरी लगेगी। मैं समझता हूँ हर आदमी को वह बुरी लगेगी। उसके अन्दर एक चित्र दिया गया है एक बुल को काउ को कवर करता हुआ इसमें बताया गया है और यह जो चित्र जो प्रकाशित किया गया है यह तो सभ्यता की हद हो गई। ऐसे चित्र राजस्थान सरकार के पब्लिकेशन द्वारा आने चाहिये। यह दिखने में तो छोटी बात है लेकिन इन छोटी छोटी बातों पर निगाह बहुत जल्दी पड़ती है अतः सावधानी

Page No.157

[श्री हिम्मतसिंह अटरू]

से इस प्रकार के कार्य करे तो ज्यादा बहतर होगा। मैं इन शब्दों के साथ चूंकि समय भी मुझे आखिरी में मिला है और बोलने वाले भी और है अतः मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ।

श्रीमती यशोदा देवी:—अध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने का समय नहीं दिया गया।

श्री अध्यक्ष:—श्री प्रभुदयाल

श्री प्रभुदयाल:—माननीय अध्यक्ष, आज तीन रोज से लगातार इस बात पर बहस चल रही है। जहां तक मेरा ख्याल है यह बजट उन सब बजटों से अच्छा है जो पिछले सालों से पेश होते चले आ रहे हैं। यह बजट सोशिलिस्टक पेटर्न का बजट है। इस पर काफी लोगों को मौका दिया गया है बोलने का। जहां तक में समझ पाया हूँ विरोधी पक्ष के द्वारा जितनी भी बातें कही गई, जितने सरकार के प्रति कटु बातें कही गई उनमें बजट पर कम ध्यान दिया गया। मैं समझता हूँ इस प्रकार की बातें वित्तमंत्री के भाषण पर नहीं होनी चाहिये। अपने दिल के अन्दर जो भी जचा वह कह दिया यह अच्छी परम्परा नहीं है।

श्री अध्यक्ष—आप भी तो वही कह रहे हैं।

श्री प्रभुदयाल—जहां तक समझ पाया हूं इस तरह की परम्परा नहीं डालनी चाहिए। जातिवाद के जो आरोप लगाते है कोई किसी की दल बन्दी कहता है, कोई किसी को जीवनसिंह बताता है, कोई किसी को बलवन्तसिंह कहता है; यह चीजें असेम्बली में कहना ठीक नहीं है। यह हमारे राजस्थान के लिए अच्छी बात नही है। यह हमारे भविष्य के लिए अच्छे उदाहरण पेश करने वाली मिसालें नहीं हैं।

तनखाओं के बारे में बतलाना चाहता हूं तनखायें बढ़ीं, ग्रेड्स रिवाइज हुए; यह मैं मानता हूं। कई लोगों के साथ इसमें अन्याय भी हुआ है। मैं जहां तक समझ पाया हूँ हर ग्रेड वाले के बारे ध्यान दिया गया है तनखाएं बढ़ाई गई, अलउन्सेज़ भी दिये गये। यह बहुत अच्छा है। द्वितीय पंच वर्षीय योजना के लिए हम अच्छे कारीगर है, एग्रीकलचरिस्ट है जो मेकेनिस्ट है जो टेकनीकल आदमी है, उनको अच्छे ग्रेड देना चाहिये ताकि हमारी द्वितीय पंच वर्षीय योजना में जो हम काम करने जा रहे हैं वह ठीक तरह से हो सके। आज का जमाना है उसे देखते हुए अनाज की समस्या रही उस समस्या को देखते हुए पंजाब में जिस प्रकार ग्रेडों के बारे में ध्यान दिया गया वहां लोअर ग्रेड को तरक्की दी गई, उसी प्रकार यहां पर भी नीति बरती जानी चाहिए। आशा है यहां पर भी लोअर ग्रेड के बारे में विशेष प्रकार से ध्यान देने की कृपा करेंगे।

बिजली के बारे में यह कहना चाहता हूं कि मेरे इलाके में करीब डेढ़ साल से टरबाइन पड़ा हुआ है लेकिन उसके पूरे पुरजे नहीं मिल सके है। उसके लिए असेम्बली में भी सवाल पूछा गया था यह कहा गया कि पुरजे यहां पर मिलते नहीं हैं, नये लाये जायेंगे। मेरी समझ में नहीं आता

[श्री प्रभुदयाल]

कि यहां सारे अफसर मौजूद हैं तो फिर रद्दी टरबाइन क्यों खरीदा गया ? जिन अफसर ने इस प्रकार का टरबाइन खरीदा है उसके लिए उसके खिलाफ एक्शन लिया जावे ।

वन विभाग के बारे में इस बजट में काफी रकम रखी गई है । मिसाल के तौर पर मैं अरज करूं बीकानेर के पास गोरबीड फोरेस्ट है, जिसका एरिया करीब १०-१२ मील का है । वहां से पिछले दो-तीन सालों में ५० हजार पेड़ काटे गये है । एक तरफ तो वन विभाग पेड़ों के लगाने में इतनी बड़ी बड़ी रकमें खर्च कर रही है और दूसरी ओर इस प्रकार से पेड काटे जाते हैं । आज जब कि हम रेगिस्तान को रोकने के लिए काफी रकम पेडों को लगाने में खर्च कर रहे हैं वहां इस प्रकार से पेड़ों को काटने देना अन्याय है । इस सम्बन्ध में इन्क्वायरी होकर जो सजा दी जावे वह दी जानी चाहिए । अगर मेरी यह बात गलत हो तो जांच की जाय, अगर मैं गलती पर हूं तो मुझे आप जो भी सजा दे मैं भुगतने के लिए तैयार हूं ।

जहां तक औषधालय का सम्बन्ध है मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारी ओर औषधालयों की बहुत कमी है, जो कोटा हमारे डिवीजन के लिए मन्जूर किया गया है वह नाकाफी है । या तो माननीय स्वास्थ्य मंत्री यह समझते होंगे वहां बीकानेर में कोई लोग बीमार ही नहीं पड़ते होगें या वहां औषधालय बहुत हैं । इसलिए मेरा यह निवेदन है कि इस ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिए ।

तीसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, जहां जोधपुर और उदयपुर में इंस्पेक्टर रखे गये हैं बीकानेर में कोई इंस्पेक्टर नहीं रखा गया है । मेरा यह कथन है कि वहां भी इन्स्पेक्टर रखा जाना चाहिये ।

इसके अलावा मेरा इलाका है, वह बेकवर्ड ईलाका है । वहां भेड़ और पशुपालन का ज्यादा व्यापार होता है । इस बजट में नहीं बताया गया है कि सारे जिले के अन्दर कहीं पशु पालन के लिए इतनी रकम रखी गई हो । इसलिए मैं प्रार्थना करूंगा कि यह जो कमी रह गई है माननीय मंत्री महोदय उसकी पूर्ति करेंगे ।

मेरी चूरू और राजगढ़ तहसील है जहां पर खारा पानी है । इस बजट में यह नहीं बतलाया गया है कि खारा पानी जिन गांवों में है वहां मीठा पानी मिलेगा या नल के जरिये पहुँचाया जायगा इस बात का इस बजट में उल्लेख नहीं है । मिसाल के तौर पर मैं बताऊं, मैं तारानगर जितनी भी बार गया वहां इतना खारा पानी है, मैं वहां हमेशा जाता हूँ १५ रोज में, वहां मुझे बीमार हो जाना पड़ता है । कारण वहां का खराब पानी है । इसलिए मेरा यह निवेदन है कि इस बजट में ऐसे इलाकों के लिए मीठा पानी मिल सके, इस प्रकार की व्यवस्था होना जरूरी है ।

सड़कों के बारे में वैसे ही वह बेकवर्ड एरिया है । वहां पर कोई आवागमन का स्थान नहीं है । मैं खुश होता यदि यह साफ बताया जाता कि तुम्हारे इलाके में सड़कों का इतना विकास किया जा

[श्री प्रभुदयाल]

रहा है कि उसके लिए इतनी रकम मंजूर की जा रही है। मैंने इस बजट को अच्छी तरह से पढ़ा यह प्रश्न बराबर चार साल से मैं यहां चिल्ला रहा हूँ कि तारानगर और राजगढ़ रोड पर बीसों बार गुजरता हूं, उस सड़क को कम से कम पक्की बनाया जाय। आज चार साल हो गये। मैं बराबर इस प्रश्न को सदन में रखता आ रहा हूँ, लेकिन इस ओर ध्यान नहीं दिया जाता। इससे कम से कम सरकार को साल में लाख रुपये की आमदनी होती है। आमदनी पर ही सरकार गौर करे तो इस सड़क की मरम्मत करवा कर इस पर डामर बिछवा दिया जाय तो हमेशा के लिये दिक्कत रफा हो सकती है। इस ओर विशेष रूप से ध्यान देने के लिये मैं सरकार से निवेदन करता हूं।

उद्योगों के बारे में मैं बतलाऊं, इसकी ओर भी हमारे यहां कम ध्यान दिया गया है। हमारे राजस्थान में चमड़े का बहुत उत्पादन होता है। यहां बजट में नहीं बतलाया कि चमड़े के उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिये सरकार क्या कर रही है और यह भी नहीं बताया कि फलां फलां जगह चमड़े के उद्योग को बढ़ावा देने के लिये इतनी रकम रखी गई है। जो कुछ कमी रह गई है वह पूरी की जायगी।

अब मैं कुछ राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंड के बारे में बताऊंगा। सरदार शहर के बारे में मैं बतलाता हूँ कि वहां पर एक राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंड का उद्घाटन करने के लिए श्र कुम्भारामजी को बुलाया गया, वहां पर मुझे भी जाने का काम पड़ा। मैंने वहां देखा चार साल में एक राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंड खुला है, उस राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंड को दूसरी जगह बदल दिया गया है। तो बदलने में एतराज नहीं। यह पिछले साल जो कमी रह गई है वह द्वितीय पंचवर्षीय योजना में पूरी कर दी जावेगी। इतना कह कर मैं उम्मीद करता हूं कि इसके लिए वित्तमंत्रीजी गौर फरमावेंगे।

श्री अध्यक्ष—श्री धर्मपाल। आप पांच मिनिट में समाप्त कर दें।

श्री धर्मपाल—पांच मिनिट में तो समाप्त करना सम्भव नहीं होगा साहब। अधिक समय दीजियेगा साहब।

श्री अध्यक्ष—पांच मिनिट में समाप्त करने वाले बहुत हैं।

श्री गोपीलाल यादव—समय हो गया है साहब।

श्री अध्यक्ष—तीस आदमी बोल चुके हैं बजट पर। अब जो लोग पांच मिनिट में बोलें उन्हें अवसर दिया जा सकता है।

श्रीमती यशोदा देवी—मुझे कुछ समय दिया जावे।

श्री अध्यक्ष—आप बोल चुकी हैं राजप्रमुख के भाषण पर।

जिनको बोलना है वे हाउस में उपस्थित नहीं रहते हैं। Yes, Shri Hans Raj.

श्री हंसराज—अध्यक्ष महोदय, बजट पर दो दिन से वाद-विवाद चल रहा है। राजस्थान विधान सभा के सदस्य सभी अपने अपने क्षेत्र के कामों के बारे में मांग करते रहे हैं। मेरा भी नम्र निवेदन है कि धौलपुर सब डिवीजन में सड़कों की बहुत कमी है और उनमें छः सड़कें बनने के लिये मैंने बतलाई थीं सरकार को, वे तो कम से कम बनाई जावें।

श्री अध्यक्ष—श्रीमती यशोदा देवी।

श्रीमती यशोदा देवी—माननीय अध्यक्ष, बजट पर चल रही बहस दो दिन से सुन रही हूँ। मेरे माननीय सदस्यों ने बड़ी योग्यता से और बड़े सुन्दर ढंग से अपनी अपनी बातों का वर्णन किया। मैंने माननीय वित्तमन्त्रीजी का बजट भाषण भी पढ़ा। इधर से भी पढ़ा और पीछे से भी पढ़ा और यह पढ़कर एक छोटा सा श्लोक याद आ गया कि "पात्राधारे घृतम् वा घृताधारे पात्रम्"। पात्र ने घृत को धारण कर रखा है या घी ने पात्र को धारण कर रखा है। हमारा समाजवादी बजट पेश हुआ, इसे समाजवादी कहा गया इस लिए समाजवादी कह रही हूं। उस पर भाषण दिया वित्तमन्त्री महोदय ने तो उस भाषण ने समाजवाद को धारण करके रक्खा या समाजवाद ने उस भाषण को धारण करके रक्खा। उसका सुन्दर नक्शा, उसका बड़ा बड़ा नक्शा इन बड़े बड़े भाषणों से प्रतीत नहीं होगा।

आप मानते हैं माननीय अध्यक्ष, कि मैं इस सदन में एक विरोधी दल की मेम्बर हूं और कभी कभी कड़वी बात बोलने वाले भी अच्छे सुझाव दे जाते हैं। आप देखें कि कुछ मेरे माननीय सदस्य जो आज शासन को गलत रास्ते पर ले जाने के लिए और अपने चन्द दिनों के स्वार्थ के लिये शासन को अन्धकार के रास्ते पर ले जाते हैं, उनकी निर्माण कार्य में किये गये कारनामे देखिये। मैंने राजप्रमुख के भाषण पर कहा था, जिस पर उधर के कुछ सदस्यों ने मजाक उड़ाई। पर उस बांसवाड़ा क्षेत्र की हालत देखिये जिससे हमारे माननीय बुजुर्ग मित्र आदिवासी भी अपरिचित नहीं हैं। व्यासजी भी बम्बई आये थे तब वहां की हालत देख चुके हैं। उन्होंने तो उस पर वहां की हालत पर एक गाना भी तैयार किया था। उदाहरण के तौर पर मैं बताऊं जिसमें लिखा है 'कुछ टुकड़े इधर गिरे कुछ उधर गिरे'। वहां की सड़कों का उन्होंने वर्णन किया। तो बासवाड़ा क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है कि जिसमें आवागमन चौमासे में तो बिलकुल बन्द रहता है, तो इस विषय में कई सुझाव मैंने सरकार के सामने रक्खे, प्लानिंग कमीशन के सामने भी रक्खे। बांसवाडा से कुशलगढ और कुशलगढ़ से बामनिया आने वाली डूंगरे तक तो सड़क बनी और डूंगरे से कुशलगढ़ बिलकुल कच्ची सड़क है। प्रतापगढ़ से बांसवड़ा जाने वाली सड़क पर कोई योजना नहीं, इसी तरह से वहां और भी कई सडकें बन सकती हैं, पर उन पर कोई ध्यान नहीं। तो इधर इस तरफ सरकार को पूरा पूरा ध्यान देना चाहिये। हमारी यातायात की बड़ी भारी समस्याएं हैं। इनको हल किया जाना

Page No.161

[श्रीमती यशोदा देवी]

चाहिये। उधर बैठने वाले मेरे माननीय भील साथी आदिवासी भाई भले ही इसके लिए सरकार को कुछ न कहें पर मैं भी भील क्षेत्र में जन्मी हूँ और वहां मैंने कार्य किया है इसलिए मुझे भी पूरा पूरा कहने का हक है और उसी अधिकार से मैं यहां हमारी यातायात की समस्याओं के लिए सरकार से निवेदन करती हूँ। हम ठीक बात कहते हैं और वे उधर बैठने वाले भाई आदिवासी भाई कहते हैं कि गलत बात कह जाते हैं, हमारी सरकार ने यह किया वह किया। पर मैं कहती हूं कि वे ऐसा कहते वक्त सही नहीं कहते। सरकार हमारी भी है। हमने भी उसे बेच नहीं दिया है। सरकार हमारी बात मन्जूर करे या नहीं पर हम सही कहते हैं या गलत, इसकी रिपोर्ट तो उस क्षेत्र से अपने आदमियों से मंगावे। इसमें कुओं के लिए तालाबों के लिए सड़कों के लिए कलेक्टर से रिपोर्ट मंगाकर तो देखे कि कहां कहां यह वास्तव में कोई काम हुआ है या नहीं।

श्रमदान का जो किस्सा हमारे सामने है उसमें भी बड़ा गोलमाल है। इसमें लोगों ने अपने घर बनाये हैं और वे हैं चवन्नी सदस्य उस पार्टी के, इससे मैं यह नहीं कहती कि इससे कांग्रेस शासन बदनाम होता है। वे जिस पार्टी के सदस्य हैं वह चोरी करेंगे तो वह पार्टी बदनाम होगी।

आज कांग्रेस शासन है। पहले राजाओं का शासन था और अंग्रेजों का शासन था। इन्हीं गल्तियों के कारण हम उनके खिलाफ खड़े हुए हैं। आज आपका है, चाहे समाजवादी शासन हो, चाहे कम्युनिस्ट शासन होगा लेकिन यदि उसके विरोधी दल सामने नहीं हुआ तो वह शासन चल नहीं सकता। तो सच्चाई पर कभी पर्दा पड़ नहीं सकता है। मैं एक ही नहीं कहती लेकिन आज आपने दो दिन से सुना है। वह गलत था, सब ने कहा। मैं उधर बैठने वालों के लिए एक बात कह दूं कि एक राजा के घर में एक ब्राह्मण पुरोहित रहता था। वह ऐसा स्वार्थी था कि रोज भागवत की कथा महाराज को सुनाने जाता था, तो उसमें एक श्लोक आता था कि 'मांस भक्षणम् नरकम् गच्छामि, यदि उस श्लोक को पंडितजी सही बता देते हैं, उनका जो भरण पोषण होता था उनको जागीर शासन की तरफ से दी हुई थी वह छिन जाय। तो पंडितजी ने एक तरकीब निकाली नहीं तो इसके बिना अपना काम नहीं चलेगा तो उन्होंने उस श्लोक को उल्टा कर दिया अपने स्वार्थ के लिए मांस भक्षणम् नरकं गच्छामि, के बजाय उन्होंने 'मांस भक्षणम् स्वर्ग गच्छामि, कर दिया, तो चन्द लोग उधर बैठने वाले अपने स्वार्थ साधन के लिए 'स्वर्ग गच्छामि' का नारा लगाते हैं, तो शासन को अन्धकार में डालना चाहते हैं। हमारे सामने मत कहो। लेकिन हम कहते थे कि आप लोग पक्षपात करते हैं, सौतेली मां का जैसा व्यवहार करते हैं तो आप लोग नहीं मानते थे, लेकिन जब घर में ही फौड़ा फूटा (समय समाप्ति सूचक घंटी) जब घर में ही पोल दिखने लगी, यहां आकर कहने लगे

श्री अध्यक्ष— ५ मिनिट में ही कहियेगा।

श्रीमती यशोदा देवी— आजकल, माननीय अध्यक्ष, जो शिक्षा की पद्धति है तो व शिक्षा के लिए हमको भारतीय संस्कृति को नहीं खोना है। उसके ऊपर हमको कायम रहना है।

[श्रीमती यशोदादेवी]

और वह शिक्षा ऐसी शिक्षा है कि वह हमारी राजनीति को चला सकती है, और उस शिक्षा से हम राजनैतिक कार्य कर सकते हैं, सामूहिक शिक्षा का कार्य कर सकते हैं लेकिन आज जो शिक्षा का ढंग है, माननीय अध्यक्ष, वह बिल्कुल गलत है। आप कालेजों में देखिये, अस्पतालों में देखिये क्या अन्धकार है। अस्पतालों में लड़के-लड़कियां रहती हैं, नर्सेज व डाक्टर रहते हैं, वहां कितना गन्दा वातावरण हो रहा है। वहां के डाक्टर और कम्पाउन्डर वहां की नर्सेज के साथ क्या व्यवहार करते हैं; यह अगर आप जांच करेंगे तो पता चलेगा। मैं अभी पिछले दिनों अस्पताल में भर्ती थी, और कितना अन्धकार वहां मुझे महसूस हुआ। वहां की नर्सेज व लड़के-लड़कियां किस गन्दे वातावरण में फिर रहे हैं। उसको रोकने के लिए वास्तव में प्राचीन कालीन शिक्षा को पहुंचाए। वहां जो गंदा वातावरण है उसको खत्म करना चाहिए। वह हमारे राष्ट्र की उन्नति के लिए बाधक होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमारी नीति यह हो कि डाक्टरों और विद्यार्थियों के लिए शराबखोरी और वैश्यागामीपन को रोकना चाहिए। पढ़ने वाले लड़के शराब पीते हैं और वे कॉलेज में जाते हैं। यदि जयपुर में इनक्वायरी की जाय तो पता लगेगा कि कालेजों के लड़के किस प्रकार से शराब पीते हैं और वैश्याओं के यहां जाते हैं और कॉलेजों की लड़कियों की छेड़छाड़ करते हैं........

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

डॉक्टर वहां की नर्सेज के साथ ऐसी भद्दी बातें करते हैं। तो ये सारी शिक्षा की जो बुराइयां हैं तो उनको खत्म करना चाहिए।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

श्री अध्यक्ष— (श्रीमती यशोदा देवी के बैठ जाने पर) हो गया भाषण समाप्त।

(अनेक सदस्यों के बोलने के लिए खड़े होने पर) और ज्यादा बोलने की इच्छा है तो कल क्यों न रख लिया जाय।

श्री हिम्मतसिंह— दो चार ही रहे हैं बोलने वाले, तो कल क्यों रखें।

श्री अध्यक्ष—We will meet tomorrow at 8. 15 A. M. The question hour is suspended. From 9. 30 Government reply will begin.

(सदन की कर्यवाही ८ बजकर १६ मिनिट पर गुरुवार, दिनांक १५ मार्च, १६५६ के ८. १५ बजे प्रातः तक के लिए स्थगित हुई।)

विधान सभा भवन,
जयपुर,
दिनांक-१४ मार्च, १६५६

मन्साराम पुरोहित
सचिव,
राजस्थान विधान सभा